राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 3 अंक 274

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, गुरुवार, 12 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

रूस में पुतिन ताजिंदगी रहेंगे राष्ट्रपति !

>> 13

सरोकार

महिला कर्मियों को सौंपा जिम्मा तो हो गया कमाल

गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाने की तस्वीर बदल गई है। प्रबंधन ने महिलाओं को ट्रिमिंग शॉप का जिम्मा क्या सौंपा, कमाल हो गया। जो लक्ष्य पुरुषों के साथ मिलकर नहीं सध पा रहा था, अब उससे कहीं अधिक हासिल हो रहा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

'वंडर किड' को मिल ही गया 'दादा' का साथ

कोलकाता : क्रिकेट के 'वंडर किड' शेख शाहिद को बीसीसीआइ बॉस सौरव गांगुली का साथ मिल गया है। गांगुली ने शाहिद को अपने मशहूर गेम शो 'दादागीरी अनलिमिटेड' में खास मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। गांगुली की क्रिकेट अकादमी ने भी उसे दाखिला दे दिया है। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कांग्रेस के सातों लोकसभा सदस्यों का निलंबन रद

नई दिल्ली : लोकसभा से कांग्रेस के सातों सदस्यों का निलंबन बुधवार को खत्म होते ही इस मुद्दे को लेकर सदन में बना सियासी गतिरोध खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अगुआई में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद सदन में प्रस्ताव लाकर सातों सदस्यों को निलंबित करने का फैसला वापस लिया गया।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

बीज कंपनी से फसल खरीद का करार करने वाला उपभोक्ता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बीज कंपनियों की याचिका रद करते हुए कहा है कि कंपनी से वापस फसल खरीद का करार करने वाला किसान उपभोक्ता है और उसे उपभोक्ता कानून के तहत माना जाएगा। कोर्ट ने किसानों को मुकदमेबाजी में फंसाने पर बीज कंपनी को 25000 रुपये हर्जाना भी अदा करने का आदेश दिया है।

देश-विदेश ▶ पृष्ठ 13

पांच हजार तालिबान कैदियों को रिहा करेगी अफगान सरकार

काबुल: अफगानिस्तान सरकार अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते के तहत पांच हजार कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान कैदियों की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत आगामी 15 दिनों में 1,500 कैदी रिहा किए जाएंगे। बाकी की रिहाई शांति वार्ता में प्रगति और देश में हिंसा के मामले में कमी दिखने के बाद होगी।

बदला
पहला वनडे
भारत vs द. अफ्रीका
दोपहर 1:30 बजे से
स्थान
धर्मशाला
प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

सिंधिया ने थामा कमल, कांग्रेस के रवैये पर उठाए सवाल

बोले महाराज ▶ मप्र में पिछले 15 माह में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, राज्य में तबादला बन गया उद्योग, रेत खनन का बड़ा माफिया सक्रिय

कहा, मोदी के हाथ में देश सुरक्षित, कांग्रेस वास्तविकता को नकारती है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस के कद्दावर युवा नेताओं में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों ने कमल थाम लिया है। होली के मौके पर कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्टी का रंग उड़ा देने वाले सिंधिया ने भाजपा के रंग में हाथ रंग लिए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के साथ ही भाजपा में आने का संकेत दे चुके सिंधिया ने बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ले ली। इस मौके पर उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी की नीतियों पर जमकर गुस्सा निकाला।

भाजपा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा को धन्यवाद देते हुए सिंधिया ने पीएम मोदी के हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित होने का भरोसा जताया। इस दौरान कांग्रेस से उनकी निराशा भी झलक रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वास्तविकता को नकारने लगी है। ऐसा पहले नहीं था। ध्यान रहे कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरोध पर उन्होंने कांग्रेस को पुनर्विचार करने की नसीहत दी थी। हाल में उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 'कांग्रेस' शब्द हटा लिया था। महाराज के नाम से पुकारे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार से नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बने 15 महीने हो गए हैं और लोगों की सेवा करने का उनका सपना टूटा है। 10 दिन में ऋण माफी की बात की गई थी, लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया है। रोजगार के अवसर नहीं हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर नई सोच को आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में दो तिथि अहम हैं। पहला, 2001 का वह वक्त जब उनके पिता माधवराव सिंधिया गुजरे थे और दूसरा, 10 मार्च, 2020 जो उनकी 75वीं जन्म तिथि थी। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बाय-बाय कहकर भाजपा के साथ चलने का संदेश दिया।

लंबे समय से चल रही थी कवायद : यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी अरसे से यह संदेश दे रहे थे कि वह कांग्रेस से नाराज हैं लेकिन खुले तौर पर भाजपा की ओर झुकाव का संकेत देने से बच भी रहे थे। माना जा रहा है कि पिछले एक पखवाड़े में जब उनकी नाराजगी चरम पर थी, तब भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से संपर्क साधा गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान का नाम प्रमुखता से आ रहा है। पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने भी अहम भूमिका निभाई। दरअसल जफर सिंधिया के मित्रों में से रहे हैं और इसकी झलक उस वक्त दिखी भी जब भाजपा के मंच से सिंधिया ने दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ जफर का भी नाम लिया। बाद में मंच से उतरते हुए भी जफर उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए देखे गए। जफर 2014 से पहले मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में आए थे। उससे पहले वह एक सफल बैंकर थे। बताते हैं कि पिछले कुछ महीनों में सिंधिया और जफर के बीच कई मुलाकातें हुईं। जब सिंधिया भाजपा में आने के लिए तैयार दिखने लगे तब पार्टी नेतृत्व ने तोमर और प्रधान को आगे बढ़ाया। जब उस स्तर पर बातचीत बढ़ी तब जाकर जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल हुए। वैसे सूत्रों का कहना है कि सिंधिया कुछ और पहले ही भाजपा में आ गए होते अगर बीमारी के कारण पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का निधन न हुआ होता।

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के दौरान। उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। प्रेट्र

नड्डा बोले, परिवार का सदस्य लौट आया है

अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा और जनसंघ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयाराजे सिंधिया के योगदान को याद करते हुए उनका पार्टी में स्वागत किया। नड्डा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना परिवार के एक सदस्य के आने जैसा है। ध्यान रहे कि सिंधिया की दोनों बुआ वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे भाजपा की सक्रिय सदस्य व वरिष्ठ नेता हैं।

मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया

पार्टी में शामिल होने के साथ ही भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का एलान कर दिया है। माना जा रहा है कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद संभावित कैबिनेट विस्तार में सिंधिया को केंद्र सरकार में भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखेगा जहां सिंधिया खेमे के लगभग दो दर्जन विधायकों की बगावत ने कमलनाथ सरकार की नींव हिला दी है।

मप्र में सियासी उठापटक (विशेष पेज)

- भाजपा नेताओं ने विस अध्यक्ष को सौंपे कांग्रेस के 19 विधायकों के इस्तीफे >> पेज 4
- सरकार बचाने के लिए नेताओं को छिपाने का खेल, जयपुर पहुंचाए गए 83 विधायक >> पेज 4
- अब राजस्थान बचाने की चुनौती, सचिन पायलट पर टिकीं सबकी निगाहें >> पेज 4
- सोनिया, राहुल को नहीं थी उम्मीद कि कांग्रेस छोड़ देंगे सिंधिया >> पेज 5

दिल्ली में भी दंगाई ही करेंगे नुकसान की भरपाई : शाह

- शाह लोस में बोले, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में बनेगा रिकवरी कमीशन
- कहा-दंगे की जांच को बनाएंगे नजीर, बिना भेदभाव के होगी कार्रवाई
- आइबी अफसर अंकित शर्मा के हत्यारे की भी हो रही है पहचान

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में दिल्ली दंगे पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सभी आरोपों का जवाब दिया। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में हुए दंगे में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। इसके लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एक मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में रिकवरी कमीशन बनाने का अनुरोध किया गया है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि दिल्ली दंगे की जांच को नजीर बनाया जाएगा और वैज्ञानिक तरीके से आरोपितों की पहचान कर बिना भेदभाव के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दंगे के पीछे बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हुए उन्होंने 36 घंटे के भीतर उसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की। शाह ने बताया कि किस तरह उन्होंने खुद पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को दंगा ग्रसित क्षेत्रों में दौरे पर भेजा था।

लोकसभा में अमित शाह ने दिल्ली के दंगे को लेकर विपक्ष के एक-एक आरोपों का बिंदुवार जवाब दिया, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश से जल्द ही पर्दा उठाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के दौरान हिंसा फैलाने के लिए भड़काऊ बयान दिए गए। खासतौर पर इसके लिए 22 फरवरी को सोशल मीडिया पर 60 से अधिक एकाउंट खोले गए और 26 फरवरी को बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस इनकी पहचान करने में जुटी है। इसके साथ ही फेशियल रिकगनिशन तकनीक की मदद से 300 ऐसे दंगाइयों की पहचान की गई है, जो उत्तरप्रदेश से आए थे। फेशियल रिकगनिशन से अब तक दिल्ली दंगे में शामिल 1100 लोगों को पहचान की गई है। 2647 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की 40 टीमें इनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हैं।

शाह के अनुसार, दंगे के लिए अलग से फंडिंग के सुबूत मिल रहे हैं और ऐसे फंडिंग पाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ कर फंडिंग करने वाले असली लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, दंगा भड़काने की गहरी साजिश रची गई थी, जिसकी परतें खुल रही हैं।

'हेट स्पीच' की जांच दिल्ली पुलिस करेगी : दंगे में मारे गए लोगों को धर्म के आधार पर देखने के लिए विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए शाह ने कहा, इसमें 52 भारतीयों की मौत हुई है। इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दंगे के पीछे भाजपा नेताओं पर 'हेट स्पीच' को जिम्मेदार ठहराने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग का जवाब देते हुए शाह ने कहा, पुलिस जांच कर रही है, पर सीएए को लेकर युवाओं और एक समुदाय को गुमराह करने वाले इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में सोनिया-राहुल के 'आर-पार की लड़ाई' और 'घर से बाहर निकलो' के साथ-साथ एएमआइएएम नेता वारिस पठान के 15 बनाम 100 करोड़ के बयान का भी हवाला दिया।

दंगा रोकने पर पुलिस की प्रशंसा पेज>>3

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी घोषित

डब्ल्यूएचओ ने इसके प्रसार को रोक पाने में असमर्थता पर चिंता जताई

इटली में 827 की मौत, 117 देशों में फैला वायरस, एक लाख 20 हजार संक्रमित

ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री डोरिस, ईरान के उप राष्ट्रपति व दो मंत्री भी चपेट में

जेनेवा, एजेंसियां : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। संगठन ने इसके खतरनाक स्तर पर प्रसार और गंभीरता और इसे रोक पाने में असमर्थता पर गंभीर चिंता जताई है। चीन के बाद जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज्यादा प्रभावित इटली में अब तक 827 मरीजों की मौत हो चुकी है। वायरस संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी दस हजार के पार पहुंच गया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नदीन डोरिस भी संक्रमण की चपेट में आ गई हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उनका मंत्रालय यह पता लगाने में जुट गया है कि वह किस तरह वायरस की चपेट में आईं। ईरान के उप राष्ट्रपति इशाक जहानगिरी, संस्कृति मंत्री अली असगर मौनेसन और उद्योग मंत्री रेजा रहमानी भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस (कोविड-19) अब तक दुनिया के 117 देशों में पहुंच चुका है। दुनियाभर में करीब एक लाख 20 हजार लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है और 4298 लोगों की जान जा चुकी है। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि चीन के बाहर यह वायरस पिछले दो हफ्ते के दौरान 13 गुना ज्यादा तेजी से फैला है। हालांकि, संगठन ने इस वायरस को लेकर पहले से जारी एडवाइजरी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। (पेज-13 भी देखें)

अमेरिका में अस्पताल में जाता स्वास्थ्यकर्मी। एपी

देश में एक दिन में 10 नए मरीज, कुल संख्या 60

नई दिल्ली, एजेंसियां : देश में बुधवार को कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए। इनमें केरल के आठ और दिल्ली व राजस्थान का एक-एक मामला शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 60 हो गई है। यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना के 10 मामलों की पुष्टि की है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह संख्या दो बताई है। सरकार ने टूरिस्ट समेत सभी तरह के वीजा 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिए हैं। आदेश 13 मार्च मध्यरात्रि से लागू होगा।

मंत्रालय के मुताबिक संक्रमितों में केरल के सबसे ज्यादा 17 मामले हैं। इनमें पहले के तीन पॉजिटिव केस भी हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नौ, दिल्ली के पांच व इटली के 16 सैलानी हैं। कर्नाटक में चार, महाराष्ट्र व लद्दाख में दो-दो मामलों की पुष्टि हुई है। राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में एक-एक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 (आठ पुणे, दो मुंबई) बताई है। उन्होंने 20 मार्च तक चलने वाले राज्य के बजट सत्र में भी कटौती करने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के जयपुर के जिस 85 वर्षीय बुजुर्ग में कोरोना की पुष्टि हुई है वह 28 फरवरी को ही पत्नी संग दुबई से लौटे थे। उन्हें, उनकी पत्नी व बेटे को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं, कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस से 76 वर्षीय व्यक्ति की मौत की खबरों का खंडन किया है।

हर्षवर्धन ने मंत्रियों के साथ की बैठक: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मंत्रियों के समूह के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। हर्षवर्धन ने मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता और दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कोरोना पीड़ितों से वीडियो काल के जरिए बात की थी। (पेज-6 भी देखें)

दंगे के आरोपित ताहिर हुसैन पर कसा ईडी का शिकंजा

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली दंगे में आरोपित आम आदमी पार्टी (आप) से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन और कट्टर इस्लामी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) समेत कुछ और लोगों के खिलाफ दंगे के दौरान धन मुहैया कराने और मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। पुलिस को जांच के दौरान पूछताछ में इस बात का पता चला कि कुल 450 लोगों को दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए धन मुहैया कराया गया। हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने हुसैन के खिलाफ इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के अधिकारी की हत्या का केस भी दर्ज किया है। हुसैन इस समय दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। (पेज-2 भी देखें)

पेट्रोल 2.69, डीजल 2.33 रुपये सस्ता

जेएनएन, नई दिल्ली

क्रूड ऑयल के भाव में गिरावट का असर घरेलू ऑयल मार्केट पर दिखने लगा है। बुधवार को पेट्रोल 2.69 रुपये प्रति लीटर सस्ता होकर नौ माह के निचले स्तर पर बिका। वहीं, डीजल 2.33 रुपये प्रति लीटर गिरकर 13 माह के निचले स्तर पर आ गया। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 70.29 और डीजल की 63.01 रुपये प्रति लीटर रह गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते पेट्रोल के दाम में पांच रुपये प्रति लीटर तक की और कटौती हो सकती है।

देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक अधिकारी ने कहा, गत तीन दिनों में कच्चे तेल का भाव 30 फीसद गिरा है। पेट्रोलियम कंपनियां आमतौर पर पिछले 15 दिनों के औसत के आधार पर पेट्रोल-डीजल के दैनिक भाव तय करती हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल का भाव मौजूदा स्तर (35 डॉलर प्रति बैरल) के आसपास रहा, तो कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम पांच-छह रुपये तक घटा सकती हैं।

पेट्रोल-डीजल के भाव में 27 फरवरी से गिरावट शुरू हुई थी। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और अन्य निर्यातक देशों के बीच उत्पादन में कटौती की सहमति नहीं बनने के चलते क्रूड ऑयल लगातार सस्ता हुआ है।

पेट्रोल नौ महीने और डीजल 13 महीने के निचले स्तर पर

प्रतीकात्मक फोटो

राणा कपूर के पास दिल्ली के पॉश इलाके में पांच कोठियां

नई दिल्ली: यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और उसके परिवार की अवैध तरीके से बनाई संपत्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय को राणा कपूर की पत्नी और तीन बेटियों के नाम दिल्ली में चार नई संपत्तियों का पता चला है। दिल्ली के पॉश इलाकों में राणा कपूर के परिवार के आलीशान बंगलों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। (पेज-3)

बंगाल में एक अप्रैल से नहीं रहेगी कोई चेकपोस्ट : ममता बनर्जी

कोलकाता: बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कृषकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक अप्रैल से सूबे की सभी 109 चेकपोस्ट हटाने का फैसला लिया है। ममता ने कहा, कृषि उत्पादों से लदे वाहनों को अब चेकपोस्टों पर नहीं रुकना पड़ेगा। एक अप्रैल से सभी 109 चेकपोस्टों को हटा लिया जाएगा। (पेज-10)

सीधा संदेश

सिंधिया प्रकरण से उजागर हुई शीर्ष नेतृत्व की कमजोरी, असमंजस खत्म नहीं हुआ तो सुनाई देने लगेंगे विद्रोह के सुर, सिंधिया की तरह कई नेताओं का धैर्य जवाब देता दिख रहा

नेतृत्व की 'दुविधा' को लेकर कांग्रेस में खलबली

संजय मिश्र, नई दिल्ली

निर्णायक फैसले लेने में हो रही देरी के चलते लगातार सियासी खामियाजा भुगत रही कांग्रेस में अब शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर असंतोष सिर उठाने लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के घटनाक्रम ने पार्टी में ऐसी खलबली मचा दी है कि कई नेताओं का धैर्य जवाब देने के कगार पर पहुंचता दिख रहा है। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति से बेचैन पार्टी के तमाम नेता अब हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाने लगे हैं कि नेतृत्व पर जारी असंमजस जल्द खत्म नहीं हुआ तो पार्टी में विद्रोह जैसी नौबत पैदा हो सकती है।

कांग्रेस के कई नेताओं ने साफ कहा, सिंधिया के जाने को सामान्य घटना नहीं माना जा सकता क्योंकि उनकी गांधी परिवार से करीबी थी। संसद भवन परिसर में अनौपचारिक चर्चा में पार्टी के कई नेताओं ने कहा, इस प्रकरण से मौजूदा नेतृत्व की दुविधा व कमजोरी का संदेश गया है। सिंधिया जहां गांधी परिवार के करीबी थे, तो मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पुराने भरोसेमंद। ऐसे में संदेश स्पष्ट है कि मौजूदा अंदरूनी राजनीतिक हकीकत में हाईकमान साहसी व निर्णायक फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। यूपीए सरकार में मंत्री रहे एक नेता का कहना था कि नए अध्यक्ष पर जारी दुविधा हाईकमान की सबसे बड़ी कमजोरी है। कई नेता हाईकमान की इस दुविधा का फायदा उठाते हुए अपने हितों के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सलमान खुर्शीद फाइल

डूबते जहाज को लोग छोड़ देते हैं : खुर्शीद

ज्योतिरादित्य प्रकरण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा, 'पार्टी से मिले सम्मान को देखते हुए सिंधिया को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। उन्हें पार्टी की विफलता के बारे में हमें बताना चाहिए था। पार्टी पहली बार बुरे दौर से नहीं गुजर रही है। लोग डूबते जहाज को छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। लोग छोड़कर जाते हैं और समय बदलने पर फिर लौट आते हैं।'

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने की इच्छुक नहीं और वह पार्टी की कमान फिर राहुल गांधी को सौंपने के पक्ष में हैं। राहुल फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का मसला इसी दुविधा में फंसा है। एक नेता ने कहा, करीब एक दर्जन वरिष्ठ नेताओं की आपसी चर्चा में अधिकांश ने माना कि अब हाईकमान को स्पष्ट रूप से यह बताने का समय आ गया है कि दुविधा का यह दौर जल्द खत्म नहीं हुआ तो खुले तौर पर कांग्रेस में नए नेतृत्व की मांग उठ सकती है। शायद यही कारण है कि बुधवार को नेतृत्व ने दिल्ली और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर सक्रियता का संदेश देने की कोशिश की।

छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का कहना है, 'इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या अकेले सिंधिया जिम्मेदार थे कि हालात इस मोड़ तक पहुंच गए कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। यह घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है।' पुनिया हाईकमान के भरोसेमंद लोगों में गिने जाते हैं। युवा नेता सचिन पायलट ने कहा, 'कांग्रेस से सिंधिया का अलग होना दुर्भाग्यपूर्ण है। काश पार्टी के भीतर ही मिल-जुलकर सब सुलझा लिया गया होता।' हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई व कर्नाटक के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने कहा, कई नेता सिंधिया की तरह बेचैनी महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कराने का सुझाव रखा था। वीरप्पा मोइली, अभिषेक मनु सिंघवी और संजय निरुपम सरीखे नेता भी ऐसी राय दे चुके हैं।

एसबीआइ का लोन सस्ता, न्यूनतम बैलेंस रखने का झंझट खत्म

बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया होली का तोहफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने बुधवार को अपने ग्राहकों को होली का तोहफा दिया। होम व ऑटो जैसे लोन को सस्ता करने के साथ बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। एसबीआइ के ग्राहकों को अब एसएमएस सेवा के लिए भी कोई शुल्क नहीं देना होगा। बैंक ने बचत खाते पर ब्याज दर एकसमान तीन प्रतिशत तय कर दी है।

एसबीआइ ने बुधवार को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ट लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में 10-15 आधार अंक तक की कटौती की घोषणा की। इस घोषणा से एमसीएलआर 7.85 फीसद से घटकर 7.75 फीसद हो गई। नई घोषणा 10 मार्च से प्रभावी होगी। इससे ग्राहकों को होम लोन व ऑटो लोन पर पहले के मुकाबले कम ब्याज देना होगा जिससे ईएमआइ में राहत मिलेगी। एसबीआइ के मुताबिक इस कटौती से 30 साल की अवधि वाले होम लोन लेने वाले ग्राहक को प्रति एक लाख रुपये पर पहले के मुकाबले सात रुपये कम ईएमआइ देना होगा। सात साल के ऑटो लोन पर ग्राहकों को प्रति एक लाख पर 5 रुपये का फायदा होगा।

एसबीआइ ने टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में भी कटौती का एलान किया। एक साल या उससे अधिक समय वाले टर्म डिपॉजिट की मौजूदा ब्याज दर में 10 आधार अंक की कटौती की गई। 45 दिन वाले टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरों में 50 आधार अंक की कटौती की गई।

धाता धारकों को फायदा पेज>>12

6.5 करोड़ रुपये की मदद कर चुकी है दिल्ली सरकार उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा पीड़ितों की। सरकार की तरफ से अभी जांच जारी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 मार्च 2020

कोरोना पर विस का विशेष सत्र कल

तैयारी ▶ एनआरसी और एनपीआर पर भी प्रमुखता से चर्चा कराएगी केजरीवाल सरकार

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

देश सहित दिल्लीभर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 13 मार्च को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र कोरोना वायरस के मुद्दे पर बुलाया गया, लेकिन इस विशेष सत्र में केजरीवाल सरकार एनआरसी और एनपीआर पर भी प्रमुखता से चर्चा कराएगी। ऐसी संभावना है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी), राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण (एनपीआर) पर सरकार कुछ दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में लागू करने के विरोध में सदन में प्रस्ताव लाए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र को लेकर अहम फैसला हुआ।

23 से शुरू हो सकता है दिल्ली का बजट सत्र : विधानसभा का बजट सत्र आगामी 23 मार्च से शुरू हो सकता है, जबकि 25 मार्च को बजट पेश होने की संभावना है। इस बार बजट पांच से दस प्रतिशत तक बढ़ने की भी संभावना है। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट 60 हजार करोड़ रुपये का था। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतरी के साथ जारी रखना चाहती है ताकि लोगों से किए गए वादे पूरे हो सकें। पहले की तरह सरकार का ज्यादा फोकस शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर रहेगा। लेकिन, सरकार अपनी दस गारंटी को भी बिना रोकटोक जारी रखेगी। लगभग पांच दिन चलने वाले इस बजट सत्र के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गत वर्षों में भी सरकार के बजट में बढ़ोतरी होती रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ऐसे काम को रुकने नहीं देना चाहती जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है।

एनआरसी पर चर्चा का भाजपा ने किया विरोध

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि एनआरसी पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना अनुचित है। यदि सरकार दिल्ली को लेकर गंभीर है तो यहां के मुद्दों पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए।

बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में स्पष्ट किया था कि सीएए कानून देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ नहीं है। इसके लागू होने से मुस्लिम सहित किसी भी धर्म को मानने वाले नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यह कानून पड़ोसी देशों में आस्था के आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वालों नागरिकता देने वाला

रामवीर सिंह बिधूड़ी। (फाइल)

है। इसी प्रकार एनआरसी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी पूरी योजना कांग्रेस के शासन काल में बनी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको असम में लागू किया गया। देश के अन्य किसी भी हिस्से में इसे नहीं लागू किया जा रहा। प्रधानमंत्री कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। बावजूद इसके विरोधी पार्टियां इसे लेकर भ्रम फैला रही हैं।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सिर्फ राजनीति करने के मकसद से एनआरसी पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सरकार को बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने, चरमराती परिवहन व्यवस्था को ठीक करने और दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर विधानसभा में चर्चा करनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि दिल्ली गैस चैंबर बन गई है।

भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि सीएए और एनआरसी को लेकर विरोधी पार्टियां झूठ का प्रसार कर रही हैं। हिंसा के बाद दिल्ली का माहौल सुधर रहा है। किसी भी पार्टी या सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाया चाहिए जिससे कि आपसी भाईचारा को नुकसान पहुंचे।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं लगेगी वाहनों की भीड़

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : यदि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपना वाहन लेकर जाते हैं और वहां आठ मिनट से ज्यादा देर तक रुकते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर यह व्यवस्था शुरू की गई है। स्टेशन परिसर में आने वाले वाहनों को सिर्फ आठ मिनट तक रुकने की इजाजत होगी। इससे ज्यादा देर तक रुकने पर शुल्क और जुर्माना देना होगा। निजी वाहनों की तुलना में व्यवसायिक वाहनों से ज्यादा शुल्क लिया जाएगा।

नई पार्किंग व्यवस्था में आने वाले निजी वाहनों के लिए अपने यात्रियों को उतारने या फिर उन्हें बैठाने के लिए सिर्फ आठ मिनट का समय होगा। इससे एक मिनट भी ज्यादा हुआ तो 50 रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क 15 मिनट तक के समय के लिए मान्य होगा। इसके बाद 15 मिनट से ज्यादा 30 मिनट तक गाड़ी ठहरती है तो चालक को दो सौ रुपये शुल्क देना होगा। इससे ज्यादा देर तक वाहन रोकने की अनुमति नहीं होगी और ऐसे वाहनों को क्रेन से उठा लिया जाएगा। वाहन चालक से पार्किंग शुल्क के साथ ही एक हजार रुपये जुर्माना भी वसूला जाएगा। ओला, उबर सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों को स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए 30 रुपये शुल्क देना होगा। उसके बाद निजी वाहनों की तरह समय के अनुसार उनसे शुल्क व जुर्माना लिया जाएगा।

पूर्व विधायक अनिल चौधरी दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक अनिल चौधरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटपड़गंज से विधायक रहने के साथ-साथ वह दो बार पार्षद और दिल्ली युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की करारी हार के बाद तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से पार्टी की दिल्ली इकाई नेतृत्वविहीन चल रही थी।

पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से बुधवार शाम जारी एक बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही पांच उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। उपाध्यक्ष बनाए गए अभिषेक दत्त मौजूदा समय में पार्षद हैं और विधानसभा चुनाव में वह कस्तूरबा नगर से चुनाव लड़े थे। पूर्व विधायक जयकिशन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल, पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे अली हसन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाते हुए 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, भाजपा के हिस्से में आठ सीटें आई हैं जबकि कांग्रेस पहले की तरह एक बार फिर खाता तक नहीं खोल सकी। चौधरी ने अपनी नियुक्त के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार जताते हुए दिल्ली कांग्रेस को मजबूत एवं पुनर्गठित करना अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि वह सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करेंगे और जो युवा उनके साथ काम करना चाहेंगे, उन्हें भी यथोचित स्थान दिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि पिछले छह साल से दिल्लीवासी स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस इस माहौल को खत्म कर एक बार फिर दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करेगी।

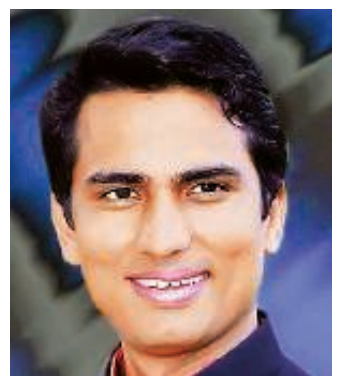

अनिल चौधरी। (फाइल)

न्यूज गैलरी

निर्भया के दोषी ने पुलिसकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप

नई दिल्ली : निर्भया कांड के दोषियों में शामिल पवन एक और पैंतरा चला है। उसने कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया है कि मंडोली जेल में बंद रहने के दौरान दो पुलिसकर्मियों ने उसे जमकर पीटा था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने जेल प्रशासन से इस पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। पवन के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट हर्ष विहार थानाध्यक्ष को निर्देश दे कि वह सिपाही अनिल कुमार और एक अन्य अज्ञात सिपाही के खिलाफ एफआइआर दर्ज करे। पवन को फांसी होने वाली है इसलिए उसे दोनों पुलिसकर्मियों की पहचान के लिए गवाह के रूप में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। अर्जी के मुताबिक 26 और 29 जुलाई 2019 को पवन मंडोली जेल में बंद था। उस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे पीटा था। पवन के सिर में गंभीर चोट आई थी। इलाज के लिए उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया था। उसके सिर में 14 टांके आए थे। (जासं)

छह डीसीपी के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस के छह डीसीपी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को डीसीपी हेडक्वार्टर बनाया गया है। मनजीत सिंह को डीसीपी मेट्रो का कार्यभार सौंपा गया है। डीसीपी लैंड एंड बिल्डिंग के तौर पर तैनात मो. अख्तर रिजवी को एडिशनल डीसीपी उत्तर-पूर्वी दिल्ली बनाया गया है। उनके स्थान पर डीसीपी राइट सेल जितेंद्र मनी को भेजा गया है। डीसीपी मेट्रो के पद पर तैनात विक्रम कुमार पोरवाल को पुलिस आयुक्त के एसओ के तौर पर तैनात किया है। एडिशनल डीसीपी स्वाट के पद पर तैनात निशांत गुप्ता को एडिशनल डीसीपी नियुक्ति का कार्यभार सौंपा गया है। (जासं)

आप ने दिनेश मोहनिया को बनाया उत्तराखंड का प्रभारी

नई दिल्ली : आप ने दिल्ली के संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया है। मोहनिया गुरुवार को उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, जहां प्रदेश संगठन के साथ बैठक के बाद जिला और ब्लॉक स्तर की बैठकें करेंगे। आम आदमी पार्टी ने फरवरी में दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। मोहनिया ने कहा कि पार्टी ने उत्तराखंड का प्रभारी बनाकर उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वह पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। (जासं)

दंगे के आरोपित ताहिर पर कसा ईडी का शिकंजा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ दंगा भड़काने के लिए 450 लोगों को धन बांटने का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली दंगे में आरोपित आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, कट्टर इस्लामी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) समेत कुछ और लोगों के खिलाफ दंगे के दौरान धन मुहैया कराने और मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान पूछताछ में पता चला कि कुल 450 लोगों को दंगा भड़काने के बाबत धन मुहैया कराया गया। हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ताहिर मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से आप का पार्षद है। पार्टी ने उसे पहले ही निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने हुसैन के खिलाफ इंटेलीजेंस ब्यूरो (आइबी) के अधिकारी की हत्या का आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया है। हुसैन इस समय दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। केंद्रीय एजेंसी ने हुसैन, पीएफआइ और अन्य के खिलाफ कथित मनी लांड्रिंग और अवैध धन मुहैया करवाने के मामले की जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामलों का संज्ञान लिया है। विस्तृत पूछताछ के लिए ईडी जल्द ही दिल्ली पुलिस से हुसैन को अपनी हिरासत में लेना चाहेगी।

पीएफआइ के खिलाफ पहले से ही पीएमएलए के तहत जांच जारी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) खिलाफ हिंसक आंदोलन फैलाने में लिप्त था। उस पर 120 करोड़ रुपये देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को बांटकर हिंसा फैलाने का आरोप है। इस संबंध में जांच एजेंसी ने पिछले एक पखवाड़े में पीएफआइ के आधा दर्जन पदाधिकारियों से पूछताछ पूरी कर ली है। मालूम हो कि दिल्ली हिंसा के दौरान ताहिर के घर से तेजाब, गुलेल और ईंट-पत्थर बरामद किए गए थे। हिंसा में ताहिर हुसैन की संलिप्तता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद वह फरार हो गया था, लेकिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

पार्षद के सहयोगी को न्यायिक हिरासत में भेजा

जासं, नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी जिले में हुए दंगे के दो आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आप से निष्कासित नेहरू विहार के पार्षद ताहिर हुसैन के साथ हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार रियासत अली और दिलबर नेगी के हत्यारोपित शाहनवाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले कोर्ट ने रियासत को दिन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। न्यायाधीश ऋचा परिहार की कोर्ट में पुलिस ने रियासत व शाहनवाज को पेश किया। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 24-25 फरवरी को चांदबाग में रियासत पार्षद ताहिर के घर की छत पर था। उसने छत से पथराव किया था और पेट्रोल बम फेंके थे। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि रियासत ने आइबी जवान अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर का साथ दिया था। ये दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने रियासत और शाहनवाज को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले कोर्ट ने सोमवार को शाहनवाज की पुलिस रिमांड दो दिनों के लिए बढ़वाई थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शाहनवाज ने दंगों के दौरान बृजपुरी रोड पर मिठाई की दुकान पर काम करने वाले दिलबर नेगी की हत्या कर दी।

नेताओं के भड़काऊ भाषणों के खिलाफ याचिका दायर

जासं, नई दिल्ली : दिल्ली में हिंसा से पहले अलग-अलग दलों के नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषणों के खिलाफ हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की गई है। दीपक मदन की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, सलमान खुर्शीद और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, स्थानीय नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर एसआइटी से जांच करानी चाहिए।

हिंसा, शाहीन बाग, सिमी से जुड़े ड्रग्स सिंडिकेट के तार !

इनवेस्टीगेशन ब्यूरो, नई दिल्ली

उप्र के बरेली जिले से ऑपरेट होने वाले अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का दिल्ली हिंसा से कनेक्शन सामने आ चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग में हुए धरना-प्रदर्शन के तार भी यहां से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। सिमी के सात पूर्व कार्यकर्ताओं का पीएफआइ से कनेक्शन तलाशने में भी खुफिया टीमें जुटी हुई हैं। हालांकि पुलिस स्पष्ट तौर पर कुछ कहने से बच रही है, लेकिन इनपुट जुटाए जाने की बात स्वीकार कर रही है।

24 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर में भड़की हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल पर पिस्टल तानने वाले दंगाई शाहरुख पठान ने भागकर बरेली का रुख किया था। मीरगंज में रहने वाले एक ड्रग्स माफिया के संपर्क में वह रहा। शाहरुख को संरक्षण देने और मदद करने वाले कैराना निवासी जिस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, वह भी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर है। उसके खिलाफ दिल्ली की नारकोटिक्स सेल में मामला दर्ज है।

जागरण पड़ताल

▶ सिमी के सात पूर्व कार्यकर्ताओं का पीएफआइ से कनेक्शन तलाशने में जुटीं खुफिया टीमें

ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि शाहीन बाग धरना-प्रदर्शन और दिल्ली हिंसा में ड्रग्स माफिया का बड़ा रोल हो सकता है। खुफिया टीमें इसकी जांच में जुट गई हैं।

आशंका इसलिए भी गहरा रही हैं क्योंकि खुफिया टीमों को शाहीन बाग प्रदर्शन में बरेली से मूवमेंट का इनपुट मिला है। फरवरी में पांच लोगों के नाम खुफिया टीम के हाथ लग चुके थे। इनमें बिहारीपुर और कोहाड़ापीर में रहने वाले व्यापारी शामिल थे। नवाबगंज कस्बे के भी लोग थे जो अकसर धरना में शामिल होते थे और यहां के अन्य लोगों को वहां जाने के लिए उकसाते थे। फरवरी के पहले सप्ताह में जब यह इनपुट मिला था, तब शाहरुख प्रकरण नहीं हुआ था। बाद में

शाहीन बाग प्रदर्शन में बरेली के कुछ लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली थी। फरवरी में मिले उस इनपुट के आधार पर पीएफआइ का कनेक्शन भी खंगाला गया था। मगर पुख्ता सूचना नहीं मिली।

-राजेश कुमार पांडेय, डीआइजी, बरेली

उसका पश्चिमी उप्र के ड्रग्स माफिया से कनेक्शन सामने आने के बाद बरेली के मीरगंज और फतेहगंज पश्चिमी के उस इलाके पर ध्यान गया, जो नशा तस्करों का गढ़ है। शाहरुख का पिता भी नशा तस्करी में लिप्त था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बरेली के कस्बा आंवला के मुहल्ला बजरिया का रहने वाला आरिफ दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रहने लगा था। 30 जनवरी को पत्नी नाजिया और चार माह के बच्चे के साथ शाहीन बाग धरना में शामिल हुआ था। रात में ठंड लग जाने से अगले दिन बच्चे की मौत हो गई थी। जब उसका बरेली कनेक्शन सामने आया, तभी फरवरी के पहले सप्ताह में पुलिस ने यहां से शाहीन बाग जाने वालों की जानकारी जुटाई थी।

बरेली में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के स्लीपिंग मॉड्यूल रह चुके हैं। यहां की दो महिलाएं व पांच पुरुष इस संगठन के लिए काम करते थे। सिमी प्रतिबंधित हो गया मगर इंटेलीजेंस इनकी निगरानी लगातार करती है। इन लोगों में एक व्यक्ति कटरा चांद खां मुहल्ले में रहता है। वह इस वक्त मोबिल ऑयल की दुकान चला रहा है। पीलीभीत बाईपास की एक कॉलोनी में रहने वाला युवक दवा की दुकान चला रहा है। वहीं एक महिला सदस्य भी रहती है। इसी रोड की एक अन्य कॉलोनी में एक और महिला है जो कि दवा की दुकान चलाती है।

बारादरी क्षेत्र में ही तीन अन्य युवक भी हैं, जो सिमी से जुड़े रहे थे। दिल्ली हिंसा से जब पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) का नाम जुड़ा तब सिमी के पूर्व सदस्यों की लोकेशन भी तलाशी गई थी। सभी अपनी जगह पर मिले थे। पीएफआइ से कनेक्शन का आरंभिक इनपुट नहीं मिला मगर ये लोग निगरानी पर हैं। पीएएफआइ को सिमी का विस्तार माना जाता है।

पुलिस ने राजधानी स्कूल की सील खोली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : शिव विहार तिराहे स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल पर लगी सील को बुधवार को दिल्ली पुलिस ने खोल दिया। शुक्रवार से इस स्कूल में छठी कक्षा से लेकर 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी है। सील खोले जाने के कुछ ही देर बाद स्थानीय लोग स्कूल के बाहर जुट गए और पुलिस और स्कूल संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सील खुलने से लोगों में रोष है। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि स्कूल को दोबारा सील किया जाए। दंगों में स्कूल का योगदान रहा है।

बता दें कि इस स्कूल की छत से गुलेल के साथ ही पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ व अन्य सामान बरामद हुआ था। आरोप है कि इस स्कूल की छत पर चढ़कर दंगाइयों ने तबाही मचाई थी। दंगों के दौरान शिव विहार तिराहे के पास राहुल सोलंकी नाम के युवक की मौत हो गई थी। राहुल के परिजनों ने छह मार्च को भी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन करके स्कूल को सील करने की मांग की थी। पुलिस ने उसी दिन स्कूल को सील भी किया था। इसके बाद आठ मार्च को स्कूल प्रशासन ने प्रेस कांफ्रेंस करके शिक्षा निदेशालय और पुलिस ने स्कूल पर लगी सील को खोलने की मांग की थी।

सेवा गुणवत्ता में आइजीआइ लगातार तीसरी बार अव्वल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइजीआइ (इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय) एयरपोर्ट को बेहतरीन सेवा गुणवत्ता के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम (एएसक्यू) के तहत लगातार तीसरी बार एशिया पैसेफिक के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब हासिल हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल ने इसकी घोषणा की।

इस खिताब की दौड़ में विश्व के 150 से ज्यादा एयरपोर्ट शामिल हुए थे। इनमें आइजीआइ ने बाजी मारी। यह खिताब प्राप्त कर आइजीआइ एयरपोर्ट सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट व शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समकक्ष आ गया है। वहीं, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एक श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है।

एयरपोर्ट को पुरस्कार मिलने पर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने खुशी जाहिर की। डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरिया ने कहा कि एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में आइजीआइ एयरपोर्ट को मिल रही निरंतर पहचान से उन्हें गर्व है। नया खिताब पाकर आइजीआइ एयरपोर्ट ने विश्व के विमानन मानचित्र पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। उन्होंने कहा कि आइजीआइ एयरपोर्ट को 2016 में प्रति वर्ष चार करोड़ से अधिक यात्रियों की श्रेणी में नंबर दो का खिताब मिला था। बाद में 2017 और 2018 में एयरपोर्ट ने पहला स्थान पा लिया था। 2019 में भी इसने अपना पुरस्कार बरकरार रखा।

डायल प्रवक्ता ने बताया कि रैंकिंग के लिए विश्वभर के एयरपोर्ट शामिल होते हैं। इसमें वहां यात्री सुविधा, एयरपोर्ट बिल्डिंग, इमिग्रेशन और कस्टम सेवा के साथ ही वहां दी जाने वाली सुविधाओं का आकलन किया जाता है। इसके बाद एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल पुरस्कार की घोषणा करता है।

सीआइएसएफ की मदद से अव्वल आया आइजीआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

आइजीआइ एयरपोर्ट को एशिया पैसेफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड जीतने में सीआइएसएफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्यू) सर्वे के तहत कुल 36 मानकों की परख की गई। इनमें चार मानक सुरक्षा से संबंधित थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के प्रवक्ता ने बताया कि सभी मानकों पर बल के जवानों की कार्रवाई संतोषजनक रही। सर्वे में यात्रियों ने सीआइएसएफ के जवानों के मददगार व्यवहार की सराहना की। वहीं, जांच के दौरान यात्रियों ने संतुष्टि जताई। इसके अंतर्गत हर महीने यात्रियों की राय ली जाती है। सर्वे के दौरान एक प्रश्नावली हवाई यात्रियों में वितरित की जाती है। यात्री प्रश्नावली पूरी कर संबंधित अधिकारियों को सौंप देते हैं। यात्रियों से 36 मापदंडों पर प्रतिक्रिया लेने के बाद इसका विश्लेषण और ऑन-साइट ऑडिट के बाद अवार्ड का निर्णय लिया जाता है। एयरपोर्ट पर यह देखा जाता है कि बल के जवानों का व्यवहार कैसा है। इसके अलावा सुरक्षा जांच के लिए प्रतीक्षा समय और सुरक्षा जांच के दौरान जवानों का व्यवहार कैसा था। दरअसल, देश में दिल्ली और मुंबई सहित महत्वपूर्ण एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआइएसएफ की तैनाती है।

▶ विश्व के 150 से ज्यादा एयरपोर्ट को पीछे छोड़ आइजीआइ ने बाजी मारी

▶ यात्री सुविधा, एयरपोर्ट बिल्डिंग, इमिग्रेशन आदि का किया जाता है आकलन

उपलब्धि

एफएसएसआइ ने की इस स्टेशन को 'ईट राइट स्टेशन' का प्रमाण पत्र और फाइव स्टार की रेटिंग देने की घोषणा, यात्रियों के लिए कसरत, मसाज और दवा की सुविधा भी उपलब्ध

सेहतमंद भारत का प्रतीक बना आनंद विहार टर्मिनल

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

आनंद विहार रेलवे टर्मिनल को सेहतमंद भारत के प्रतीक के तौर पर विकसित किया जा रहा है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों को कसरत, मसाज और दवा की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें शुद्ध व सेहतमंद भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टेशन परिसर में स्थित खानपान के स्टॉल पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की ओर से निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। यही कारण है कि एफएसएसआइ की ओर से इस स्टेशन को 'ईट राइट स्टेशन' का प्रमाण पत्र और फाइव स्टार की रेटिंग देने की घोषणा की गई है। आनंद विहार टर्मिनल पर खानपान के 15 स्टॉल बनाए गए हैं। इन सभी स्टॉल पर उपलब्ध सुविधाओं व मानकों के पालन के आधार पर रेटिंग की गई है। अधिकारियों ने बताया कि कैटरिंग एंड फूड (भोजन किस तरह से बनाया जाता है और उसकी गुणवत्ता), स्वच्छता व साफ-सफाई और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के लिए तय किए गए मानक का जांच पड़ताल करने के बाद एफएसएएसआइ की ओर से 92 फीसद अंक दिए गए। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आइआरएसडीसी) की ओर से राजधानी के इस रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

आनंद विहार टर्मिनल। फाइल फोटो

ईट राइट इंडिया अभियान

शुद्ध, सुरक्षित और संपूर्ण भोजन की समझ बढ़ाने के लिए एफएसएसएआइ ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिये लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि यदि स्वस्थ व बेहतर जीवन जीना है तो अपने भोजन में तेल, चीनी व नमक की मात्रा कम करें। इन चीजों के ज्यादा सेवन से रक्तचाप, मधुमेह, व हृदय रोग जैसी बीमारी होने का खतरा रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और राष्ट्रीय पोषण संस्था के आंकड़ों के आधार पर तैयार विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपने भोजन में तेल, नमक और चीनी अनुशंसित मात्रा से अधिक खा रहे हैं।

गुरुवार को स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में आइआरएसडीसी के प्रबंध निदेशक एसके लोहिया को एफएसएसएआइ की चेयरपर्सन रीटा तेवतिया प्रमाण पत्र देंगी।

उठक-बैठक करने पर मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है : देश में पहली बार इस रेलवे स्टेशन पर उठक-बैठक करके मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करने की योजना भी पिछले माह शुरू की गई है। इसके लिए स्टेशन परिसर में मशीन लगाई गई है। मशीन पर खड़े होकर 180 सेकेंड में 30 बार उठक-बैठक करना होता है। 'फिट इंडिया' अभियान के तहत प्रयोग के तौर पर यह मशीन लगाई गई है। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में हेल्थ एटीएम, फुट मसाज, मसाज चेयर व मेडिकल स्टोर भी खोले गए हैं। हेल्थ एटीएम से 50 रुपये में 16 तरह की जांच कराकर रिपोर्ट ली जा सकती है।

हाइड्रोजन सीएनजी से दौड़ेंगी बसें

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसें जल्द ही हाइड्रोजन सीएनजी (हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) से दौड़ेंगी। वर्तमान में सीएनजी से चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिल्ली में बसों में एचसीएनजी का प्रयोग पहली बार होगा। पहला हाइड्रोजन सीएनजी स्टेशन राजघाट स्थित क्लस्टर डिपो में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि प्लांट तैयार है। जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में क्लस्टर की 50 बसों को छह महीने तक दिल्ली की सड़कों पर चलाया जाएगा। इसकी निगरानी ईपीसीए द्वारा की जाएगी।

क्लस्टर बसों में इसका परीक्षण सफल रहने के बाद अन्य बसों में भी हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। इस नए ईंधन के प्रयोग से यह पता लगाया जाएगा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने में कितनी मदद मिल सकती है और यह सीएनजी से कितना बेहतर साबित हो सकता है। ट्रायल के तौर पर बसों में छह महीने तक प्रयोग की जाने वाली हाइड्रोजन सीएनजी की रिपोर्ट की सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करेगा। परिणाम बेहतर साबित हुए तो अन्य वाहनों में भी इसका प्रयोग शुरू हो सकता है। सीएनजी का मुख्य स्रोत मीथेन गैस है, जबकि हाइड्रोजन सीएनजी का मुख्य स्रोत कई गैसों का मिश्रण है। इसमें 4-9 प्रतिशत हाइड्रोजन होती है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए कंप्रेस्ड किया जाता है। मिक्स फ्यूल में 18 फीसद हाइड्रोजन और 82 फीसद सीएनजी होगी।

दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान बढ़ती गाड़ियों का है। हाइड्रोजन फ्यूल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को मिलाकर बना है। कैलिफोर्निया में 2015 से हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है।

विपक्ष-सत्तारूढ़ दल ने एक-दूसरे को कहा जिम्मेदार

दिल्ली दंगा ▶ तीन दिन तक होता रहा हिंसा का तांडव, पर गृह मंत्री नहीं गए : अधीर

मीनाक्षी लेखी ने कहा कि सोनिया, राहुल, प्रियंका के भाषणों के कारण भड़का दंगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली दंगे पर जिस चर्चा को लेकर पिछले एक सप्ताह से हंगामा चल रहा था वह खत्म भी हो हंगामा और वाकआउट से ही हुआ। दिल्ली दंगों को लेकर विपक्ष ने लोकसभा में सरकार की खिंचाई की तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। परंतु भाजपा ने हिंसा को सीएए विरोधियों द्वारा पूर्व नियोजित बताते हुए विपक्षी दलों पर स्थिति का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। अचरज की बात यह थी कि कांग्रेस ने गृह मंत्री के जवाब के बीच ही वाकआउट कर दिया। हालांकि विपक्ष के कई दल सदन में मौजूद रहे।

'राजधानी के कुछ हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति' पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि देश की सबसे अच्छी पुलिस होने के बावजूद दिल्ली में तीन दिनों तक हिंसा का तांडव होता रहा। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से

लोकसभा में बुधवार को बजट सत्र के दौरान दिल्ली दंगों पर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जवाब देते समय कांग्रेस ने वॉकआउट किया। एएनआइ

इस पर स्पष्टीकरण की मांग की। अधीर ने 'जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था' कहावत के जरिये प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं हिंसा में हिंदू जीते तो कुछ कह रहे कि मुस्लिम जीते। परंतु हकीकत ये है कि मानवता हार गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते ही स्थिति नियंत्रण में आ गई। आखिर गृह मंत्री क्यों नहीं गए? उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस. मुरलीधर के ट्रांसफर का भी सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस की विफलता पर सवाल उठाए थे। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय तथा आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने भी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली हिंसा की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की।

विपक्ष के हमले पर भाजपा सदस्यों ने पलटवार किया। भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि मुरलीधर का ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के आदेश पर हुआ था। मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हिंसा का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने आइबी अफसर अंकित शर्मा की नृशंस हत्या का जिक्र करते कहा कि उनके शरीर पर चाकू के 400 घाव पाए गए हैं। 'ये कैसी घृणा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। 'आप' के एक पार्षद के घर में पत्थर तथा गुलेलें पाई गईं। जबकि उनके एक विधायक ने भाषणों के जरिये घृणा फैलाई। मीनाक्षी ने अपनी पार्टी के अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा का ये कहकर बचाव किया उनके भाषण अप्रासंगिक हैं, क्योंकि दंगा 23 फरवरी को शुरू हुआ। इसी प्रकार उन्होंने भाजपा नेता कपिल मिश्रा के बजाय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रामलीला मैदान में तथा राहुल और प्रियंका गांधी के अन्य जगहों के भाषणों को दंगों के लिए दोषी ठहराया। नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे धरने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा तीन महीने से लोग सड़कों पर बैठे हैं। लोगों को भड़काने और उग्रवाद फैलाने के लिए लंबे समय से काम चल रहा है। जबकि ये सरकार विकास की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में हुए सैकड़ों छोटे-बड़े दंगों के आंकड़े गिनाए। इसी बीच बीजद ने बहुत प्रासंगिक सवाल उठाया कि दंगा दिल्ली मे ही क्यों हुआ? जबकि सत्तापक्ष की ओर से आशंका जताई गई दिल्ली को इसीलिए चुना गया ताकि इसे सुर्खियों में लाया जा सके।

36 घंटे में दंगा रोकने पर पुलिस को सराहा

प्रथम पृष्ठ से आगे

दंगे को रोकने में विफलता के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को बताया कि हिंसा की पहली वारदात 24 फरवरी को दोपहर दो बजे दर्ज की गई थी और 25 फरवरी के बाद एक भी वारदात नहीं हुई। दंगे को केवल 12 थाना क्षेत्रों तक रोकने और 36 घंटे में पूरी तरह लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि होली तक संसद के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराने के सरकार के फैसले को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए यह जरूरी था। उन्होंने बताया कि किस तरह 24 फरवरी को शाम साढ़े बजे दिल्ली आने के बाद वे लगातार दंगे को रोकने के लिए बैठक करते रहे। इस कारण उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया।

संसद प्रश्नोत्तर

सांसद निधि के 5,275 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए

▶ केंद्र ने इस मद में 53,704.75 करोड़ धनराशि जारी की थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि चार मार्च, 2020 तक सांसद निधि के 5,275.24 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने इस मद में कुल 53,704.75 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की थी।

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को लोकसभा में अपने लिखित जवाब में बताया कि संसद सदस्यों के अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कुल रकम में से खर्च की जाने वाली धनराशि 51,267.75 करोड़ रुपये है। सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिए आंकड़ों के अनुसार 5,275.24 करोड़ रुपये की रकम खर्च नहीं की गई है। सांसद निधि की खर्च नहीं की जाने वाली धनराशि 31 मार्च,

राव इंद्रजीत सिंह। फाइल फोटो

2019 तक 4,103.97 करोड़ रुपये, 31 मार्च, 2018 तक 4,877.71 करोड़ रुपये और 31 मार्च, 2017 तक 5029.31 करोड़ रुपये थी।

रेलवे ग्रुप सी के लिए एक लाख से अधिक लोगों का चयन

लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले तीन सालों में रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक लाख से अधिक उम्मीदवारों को रेलवे में भर्ती किया है। अपने लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि आनेवाले महीनों में तीन भर्ती परीक्षाएं होनी भी हैं। उन्होंने बताया कि रेल भर्ती बोर्ड के जरिये पिछले तीन सालों में 2017-2018 से 2019-2020 (पांच मार्च तक) कुल 1,47,620 उम्मीदवारों का चयन हुआ है।

पीयूष गोयल फाइल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास के लिए समयसीमा तय नहीं : पीयूष गोयल ने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का विकास का काम रेल भूमि विकास प्राधिकरण के अधीन होना है। इसके लिए कोई समयसीमा तय नहीं की गई है। चूंकि यह अपनी तरह का पहला परिसर होगा। आरएलडीए ने इस मामले में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मास्टर प्लान और बोली संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। इस परियोजना में विस्तृत तकनीकी-वित्तीय संभाव्यता शोध होने हैं। साथ ही शहरी निकायों से भी मंजूरी लेनी है।

अरुणाचल, कश्मीर, लद्दाख भारत के अभिन्न अंग

विदेश मंत्रालय ने लोकसभा को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं,यह बात विभिन्न अवसरों पर चीन को स्पष्ट की जाती रही है। एक सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी .मुरलीधरन ने कहा कि चीन पूर्वी क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में भारत की करीब 90 हजार वर्ग किमी जमीन पर दावा करता है। लद्दाख में वह 38 हजार वर्ग किमी क्षेत्र पर अपना दावा करता है।

वी .मुरलीधरन फाइल

बांग्लादेश, नेपाल, पाक और श्रीलंका में 1,487 भारतीय कैदी : विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि करीब 1,487 भारतीय कैदी बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की विभिन्न जेलों में बंद हैं। उन्होंने बताया कि युद्धबंदियों समेत 83 भारतीय सैन्य अफसर पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। जबकि पाकिस्तान में 337 भारतीय कैदी बंद हैं जो मुख्यत: मछुआरे हैं। भारत सरकार इस मसले को पाकिस्तान के समक्ष लगातार उठा रही है। बांग्लादेश में मछुआरों समेत 157 भारतीय कैदी बंद हैं। वहीं,नेपाल में 886 भारतीय कैदी हैं।

132 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों से डीआरडीओ को छोड़ा

रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने बताया कि पिछले पांच सालों में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के कुल 132 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों का हवाला देकर इस सरकारी संस्थान को छोड़ दिया है। 2015 में 37, 2016 में 38, 2017 में 22, 2018 में 17 और 2019 में 18 वैज्ञानिकों ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है।

'सड़क जाम कर धरना देने पर रोक का नहीं ला रहे कानून'

नई दिल्ली, प्रेट्र : शाहीन बाग की तरह सड़क जाम कर धरना देने जैसी भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कानून लाने नहीं जा रही है। गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को रास में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। शाहीन बाग क्षेत्र में सीएए के विरोध में लोग दो महीने से धरने पर बैठे हैं।

22 दिनों से भागे-भागे फिर रहे भाजपा विधायक, पुलिस ने दर्ज किए कई मुकदमे

जागरण संवाददाता, धनबाद : ढुलू महतो। बाघमारा के भाजपा विधायक। महज तीन माह पहले की बात है जब ढुलू महतो के एक इशारे पर सारा तंत्र उनके सामने नतमस्तक हो जाता था। उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास के दुलारे थे। तब भी उनके खिलाफ शासन को कई शिकायतें मिली थीं। नजरंदाज हो गईं। हेमंत सरकार आई तो हालात बदल गए। दनादन ढुलू, उनके परिजन और समर्थकों पर मुकदमे होते गए। दो बार अंधकार में ढुलू महतो के आलीशान आशियाने में पुलिस के बूटों की आवाज गूंज चुकी है। वक्त ने कुछ यूं करवट ली है कि पिछले 22 दिनों से ढुलू महतो फरार हैं। पुलिस ने उन पर छह मुकदमे कर दिए हैं। उनके भाई एवं समर्थकों पर एक दर्जन मुकदमे हो चुके हैं अथवा स्टेशन डायरी अंकित की गई है।

बगैर मर्जी कोयले का उठाव नहीं : ढुलू महतो के उत्थान की कहानी बिल्कुल फिल्मी कथानक की तरह है। कोयला खदान से किसी तरह गुजारा करने वाले एक असंगठित मजदूर से जीवन की शुरुआत करने वाले ढुलू महतो ने एकबारगी बीसीसीएल की खदानों से कोयला के सारे कारोबार को नियंत्रित कर लिया।

कांग्रेस के सातों लोस सदस्यों का निलंबन खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ स्पीकर ओम बिरला की पहल पर सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति, सरकार के प्रस्ताव को सदन ने दी मंजूरी

लोकसभा ने कांग्रेस के सातों निलंबित सदस्यों का निलंबन बुधवार को खत्म होते ही इस मुद्दे को लेकर सदन में बना सियासी गतिरोध खत्म हो गया। स्पीकर ओम बिड़ला की अगुआई में हुई सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद सदन में प्रस्ताव लाकर सातों सदस्यों को निलंबित करने का फैसला वापस लिया गया।

सियासी विवाद सुलझते ही स्पीकर ओम बिड़ला ने भी चार दिनों के बाद सदन संचालन की कमान फिर से संभाल ली। साथ ही स्पीकर ने सदस्यों को वाद-विवाद की गरमागरमी में संसद की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करने की नसीहत भी दी।

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने सातों सदस्यों गौरव गोगोई, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजाला, बेनी बेहानन, टी.एन. प्रथप्पन, डीन कुरियाकोस और आर. उन्नीथन का निलंबन वापस लेने की मांग उठाई। इसको लेकर हुए शोर-शराबे के बाद सदन स्थगित हुआ और गतिरोध तोड़ने के लिए स्पीकर ने अपने कक्ष में सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई।

कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बैठक में सदस्यों का निलंबन खत्म करने

लोकसभा में कार्यवाही का संचालन करते अध्यक्ष ओम बिरला। एएनआइ

की एक सुर से बात कही। स्पीकर ने भी कहा कि होली के बाद बीती बातों को भूलते हुए सदन चलाने के लिए निलंबन का पटाक्षेप किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से भी स्पीकर के सुझाव पर हामी भर दी गई।

स्पीकर की बैठक में बनी सहमति के अनुरूप संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा में कांग्रेस के सातों सदस्यों के निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया और सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पिछले हफ्ते 5 मार्च को सदन में इसी तरह का प्रस्ताव लाकर इन सातों सदस्यों को निलंबित किया गया था। हालांकि उस समय सदन का संचालन स्पीकर नहीं पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी कर रहीं थीं। इसीलिए विपक्ष का आरोप था कि उसके सदस्यों को स्पीकर ने नहीं सरकार ने निलंबित किया है। प्रस्ताव पारित किए जाने से पूर्व इस मुद्दे पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि स्पीकर के आसन और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात उनकी पार्टी सोच भी नहीं सकती। जहां तक सदन चलाने का सवाल है तो सरकार और विपक्ष की यह बराबर की जिम्मेदारी है। अधीर ने निलंबन वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि कबूतर मारने के लिए आप किसी को उम्रकैद की सजा तो नहीं दे सकते।

द्रमुक के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय के अलावा एनसीपी, शिवसेना के नेताओं और एनडीए के सहयोगी जदयू ने भी निलंबन वापस लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनी रहे इसमें सबकी भूमिका है। स्पीकर ने भी कहा कि बीते हफ्ते सदन में हुई घटनाओं से वे दुखी थे। हालांकि सांसदों को सदन से निलंबित किया जाए इसके पक्ष में भी वे नहीं हैं।

अघोषित स्वनिर्वासन से लौटने पर बिरला का स्वागत

नई दिल्ली, आइएएनएस : लोकसभा की कार्यवाही से तकरीबन एक हफ्ते तक दूर रहने के बाद स्पीकर ओम बिरला बुधवार को सदन में लौट आए। सदस्यों ने अघोषित स्वनिर्वासन से लौटने पर बिरला का स्वागत किया। सूत्रों ने बताया कि ओम बिरला दिल्ली हिंसा के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित किए जाने और उसके स्थगन से बहुत व्यथित थे। स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला के लौटने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, 'जो भी फैसला लिया जाएगा, भाजपा उसे स्वीकार करेगी और सभी नेता उसका पालन करेंगे। हम आपके अंतिम निर्णय का पालन करेंगे।' तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एन. नागेश्वर राव ने कहा, 'पिछले हफ्ते सदन में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। सदन से हमें देश को यह संदेश देना चाहिए कि हम एकजुट हैं। हमारी पार्टी आपके फैसलों को स्वीकार करेगी।' तेलुगु देसम पार्टी (तेदेपा) के जयदेव गल्ला ने कहा कि सभी कांग्रेस सदस्यों का निलंबन रद किया जाना चाहिए। भाजपा सदस्य निशिकांत ने कहा, 1952 के बाद पहली बार स्पीकर चार दिनों तक सदन में नहीं आए, यह शर्म की बात है।

सीएपीएफ व गृह मंत्रालय के बीच के मुद्दे सुलझाने को बनी समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से जुड़े मुद्दों से निपटने और उनके अनुमोदन के लिए दो विशेष समितियों का गठन किया है। सीएपीएफ के जिम्मे देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सीमाओं की सुरक्षा भी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि गृह सचिव की अध्यक्षता वाली पहली समिति उन मामलों को देखेगी जिनका समाधान मंत्रालय और सीएपीएफ के बीच होना है। जबकि, सचिव (सीमा प्रबंधन) के नेतृत्व वाली दूसरी समिति खरीद से जुड़े मामलों को देखेगी।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अर्धसैनिक बलों के रूप में भी जाना जाता है और इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) शामिल हैं। यद्यपि कि असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के तहत नहीं आती, लेकिन पिछले

अहम कदम

- अर्धसैनिक बलों के लिए खरीद मामलों के लिए भी विशेष समिति गठित
- गृह सचिव और सचिव, सीमा प्रबंधन करेंगे एक-एक समिति का नेतृत्व

हफ्ते गठित दोनों समितियां इससे जुड़े मामले भी देखेंगी। गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक ये समितियां विशेष हैं, इसलिए इनकी बैठकों में नियमित मामले नहीं उठाए जाएंगे।

समिति की बैठकों में इन अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और गृह मंत्रालय में पुलिस, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख, नक्सली ऑपरेशन, पूर्वोत्तर के मामलों और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों को देखने वाले संयुक्त सचिव ही शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि सीएपीएफ और गृहमंत्रालय के बीच अधिकारों को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है। सीएपीएफ इस संबंध में सरकार के समक्ष कई बात अपनी बात रख चुका है। वह खरीद से जुड़े मामलों पर निर्णय का अधिकार चाहते है।

महिलाओं को स्थायी कमीशन देने संबंधी आदेश का पालन होगा : सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेगी।

रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, 'हम किसी से भेदभाव नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पूरी तरह अनुपालन करेंगे। योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।'

सौगत राय ने कहा था कि सेना में सिर्फ 65 स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, जबकि नौसेना में इनकी संख्या सिर्फ नौ है। वायुसेना में स्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या 300 से कुछ ज्यादा है। इन परिस्थितियों में लैंगिक समानता कैसे होगी। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आदेश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें पुरुष अधिकारियों की तरह कमांडिंग अधिकारियों के रूप में तैनात भी किया जाना चाहिए।

'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के मौलिक अधिकारों का अपमान'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता, गरिमा के साथ जीने और किसी भी पेशे को अपनाने के उनके मौलिक अधिकारों का 'अपमान' है। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां कीं जिसने एक महिला बैंक कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश को रद कर दिया था। महिला ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाव के अलावा ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए लागू किया गया था। पीठ ने 25 फरवरी को दिए अपने आदेश में कहा, 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के तहत समानता के महिलाओं के मौलिक अधिकार और संविधान के अनुच्छेद

▶ सुप्रीम कोर्ट ने महिला बैंक अधिकारी के तबादले को रद करने के फैसले को बरकरार रखा
▶ महिला अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारी पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीने के उसके अधिकार तथा किसी भी पेशे, व्यापार या कारोबार को अपनाने के अधिकार का अपमान है।'

पीठ ने कहा कि उसके सामने रखा गया मामला दिखाता है कि महिला अधिकारी ने बैंक की इंदौर शाखा में अपनी तैनाती के दौरान अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर शराब ठेकेदारों के खातों के प्रबंधन में गड़बड़ी की तरफ ध्यान खींचा था और भ्रष्टाचार के खास आरोप लगाए थे। पीठ ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी (महिला अधिकारी) को प्रताड़ित किया गया है। शाखा में अनियमितता की उनकी रिपोर्ट पर बदला लिया गया है। उनका स्थानांतरण कर दिया गया और ऐसी शाखा में भेजा गया जिसमें स्केल-1 के अधिकारी को जगह मिलनी चाहिए थी।' महिला अधिकारी को दिसंबर 2017 में इंदौर से जबलपुर जिले के सरसावा शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों को एक प्रतिवेदन सौंपा और इंदौर में ही तैनात रहने देने का अनुरोध किया था।

महिला अधिकारी ने आरोप लगाया था कि एक वरिष्ठ अधिकारी देर रात उसे घर पर फोन किया करता था और ऐसे कार्यों की चर्चा करता था जिनपर तत्काल गौर किए जाने की जरूरत नहीं होती थी। पीठ ने निर्देश दिया कि महिला अधिकारी को एक साल के लिए फिर से इंदौर शाखा में पोस्ट किया जाए।

राज्यसभा में विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का किया विरोध

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बुधवार को राज्यसभा में विरोध का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने पटल पर रखे गए दस्तावेज को पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कथित विवादास्पद नारे को लकेर टीका-टिप्पणीशुरू कर दी।

सभापति एम. वेंकैया नायडू ने ठाकुर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के स्थान पर वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसके बाद विपक्ष ने टीका-टिप्पणी शुरू कर दी। हालांकि, वित्त राज्यमंत्री ठाकुर ने अपनी बात जारी रखी। इसे लोकसभा में पिछले सप्ताह ही रखा जा चुका है। कांग्रेस सदस्यों ने पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया व कुछ विधायकों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में पैदा राजनीतिक संकट के लिए भाजपा पर आरोप लगाए। इस पर नायडू ने आदेश दिया कि इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए। कांग्रेस सदस्यों ने हंगामा जारी रखा तो सभापति ने नामित करने की चेतावनी दी। सभापति की तरफ से नामित सदस्य सदन की बाकी कार्यवाही में शामिल होने से वंचित हो जाता है।

रिश्वत की कमाई

अमृता शेरगिल मार्ग, एसपी रोड, कौटिल्य मार्ग, जोर बाग और हौज खास में हैं बंगले, अपने बैंक से दिए लोन के एवज में मिली रिश्वत से इन बंगलों के खरीदे जाने का आरोप

राणा कपूर के पास दिल्ली के पॉश इलाकों में पांच कोठियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और उसके परिवार की अवैध तरीके से बनाई संपत्तियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय को राणा कपूर की पत्नी और तीन बेटियों के नाम दिल्ली में चार नई संपत्तियों का पता चला है। इस तरह दिल्ली के अलग-अलग पॉश इलाकों में राणा कपूर के परिवार के आलीशान बंगलों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग पर एलएम थापर की कोठी को अवैध तरीके से अपने नाम करने के साथ ही राणा कपूर के परिवार के पास एसपी रोड, कौटिल्य मार्ग, जोर बाग और हौज खास में एक-एक बंगला होने के सुबूत मिले हैं। ईडी के अधिकारी इन बंगलों से जुड़े दस्तावेज जुटाने की कोशिश में लगे हैं। इसके साथ ही ईडी दिल्ली के पांच बंगलों की कीमत का आकलन भी कराएगा, जिनकी कीमत हजारों करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसके अलावा, राणा कपूर के परिवार

यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर बुधवार को मनी लांड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत में पेश हुए। प्रेट्र

के पास एक यॉट होने के भी दस्तावेज सामने आए हैं। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन संपत्तियों के दस्तावेज जुटाने और यस बैंक से दिए गए लोन के बदले में ली गई दलाली की रकम से इनके खरीदे जाने के सुबूत मिलने के बाद इन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार निजी बैंकों से विभागीय खाते बंद कर सरकारी बैंकों में रही खोल

मुंबई, आइएएनएस : यस बैंक घोटाले में तीन स्थानीय निकायों का 1,125 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। लिहाजा, महाराष्ट्र सरकार निजी बैंक के विभागीय खाते बंद कर सरकारी बैंकों में खोल रही है। सूत्रों ने बताया कि यस बैंक में घोटाला उजागर होने के बाद ऐहतियातन महाराष्ट्र सरकार ने एक्सिस बैंक में एक खाता बंद कर दिया है। एक्सिस बैंक की नरीमन प्वाइंट की शाखा में राज्य सरकार का साइकिल रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट का एकाउंट अब एसबीआइ की चर्चगेट स्थित शाखा में ट्रांसफर कर दिया गया है।

पिछले साल सितंबर में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक और उसके बाद इस साल यस बैंक घोटाले का पता चलने के बाद राज्य सरकार ने यह तय किया है कि वह जनता के पैसे की सुरक्षा के लिए केवल नामचीन बड़े बैंकों पर ही भरोसा करेगी। इसी के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते संबंधित अधिकारियों और विभागों को कहा था कि वह उचित फैसले लें। इसीलिए सरकार ने सभी सरकारी विभागों, निकायों, कारपोरेशनों व स्वायत्त संस्थाओं समेत उन सभी विभागों का ब्योरा मांगा है जिनके खाते निजी क्षेत्र के बैंकों में हैं।

यस बैंक मामले में राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद ठाकरे ने एक बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई कि किसानों के कर्ज माफी की उन योजनाओं का क्या होगा जिनका यस बैंक के ग्रामीण इलाकों में खाता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

107 विधायक हैं भाजपा के पास मप्र में। इनमें से 106 विधायकों को भाजपा ने मंगलवार रात ही भोपाल में पार्टी मुख्यालय से बसों में बैठाकर एयरपोर्ट भेज दिया और दिल्ली रवाना कर दिया। मंगलवार देर रात इन्हें दिल्ली पहुंचने के बाद गुरुग्राम के आइटीसी ग्रैंड होटल ले जाया गया।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 12 मार्च 2020

भाजपा नेताओं ने विस अध्यक्ष को सौंपे कांग्रेस के 19 विधायकों के इस्तीफे

मप्र में बदलते सियासी रंग ▶ अब तक सत्तादल के 22 विधायकों के हो चुके हैं इस्तीफे

कांग्रेस का दावा- हमारे ही नहीं भाजपा के विधायक भी संपर्क में

राज्य ब्यूरो, भोपाल

पूरे देश में मंगलवार को जब लोग रंगों का त्योहार मना रहे थे, उसी दौरान मध्य प्रदेश में सियासी रंग हर पल बदल रहा था। सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे की खबर आई। फिर एक-एक कर उनके समर्थक विधायकों के इस्तीफे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। शाम ढलते-ढलते भाजपा के वरिष्ठ नेता विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति से मिलने पहुंचे। भाजपा नेताओं के हाथ में सिंधिया समर्थक 19 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे थे। तीन अन्य विधायक अलग से इस्तीफे दे चुके हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 22 के इस्तीफे हो चुके हैं। उधर, कांग्रेस का दावा है कि हमारे विधायकों को गुमराह कर बेंगलुरु ले जाया गया है। वह हमारे संपर्क में हैं। भाजपा के भी कुछ विधायक हमसे संपर्क बनाए हुए हैं।

मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे। भार्गव ने दावा किया कि सभी इस्तीफे विधायकों द्वारा खुद लिखे गए हैं।

नियमानुसार कार्रवाई होगी : प्रजापति : विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों पर सिर्फ इतना कहा है कि उन्हें विधायकों के त्यागपत्र मिले हैं। विधानसभा के जो भी नियम हैं, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं सिंधिया समर्थक 19 विधायक : तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसौदिया, मुन्नालाल गोयल, गिरिराज दंडोतिया, ओपी भदौरिया, जजपाल सिंह जच्ची, कमलेश जाटव, राज्यवर्धन सिंह, रघुराज कंषाना, हरदीपसिंह डंग, ब्रजेंद्र यादव, सुरेश राजखेड़ा, रक्षा सिरोनिया, जयवंत जाटव और रणवीर सिंह जाटव।

बेंगलुरु के रिसॉर्ट में ठहराए गए कांग्रेस के बागी विधायकों ने बुधवार को अपने इस्तीफे दिखाए। प्रेट्र

विधानसभा की मौजूदा स्थिति

कुल सदस्य संख्या	230
प्रभावी सदस्य संख्या	228
बहुमत	115
कांग्रेस	114
निर्दलीय	04
बसपा	02
सपा	01
भाजपा	107

भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह द्वारा 19 विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए हैं। इन पर विधानसभा अध्यक्ष विचार कर रहे हैं।

- एपी सिंह, प्रमुख सचिव, मप्र विधानसभा

यूं गिर सकती है सरकार

22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए या वे विधानसभा से गैर हाजिर रहे तो प्रभावी संख्या होगी 206

ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 104 रह जाएगा।

भाजपा के पास अभी 107 विधायक हैं।

फ्लोर टेस्ट में हम बहुमत साबित करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, उन्हें गुमराह किया गया है। वे हमारे संपर्क में हैं। भाजपा के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं।

- शोभा ओझा, अध्यक्ष, कांग्रेस मीडिया सेल मप्र

हरियाणा के होटल में ठहराए गए मप्र भाजपा के 106 विधायक

जागरण संवाददाता, तावडू (नूंह) : गुरुग्राम और नूंह जिले की सीमा पर स्थित होटल आइटीसी ग्रैंड भारत एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन के साथ मंगलवार देर रात भाजपा के 106 विधायक यहां पहुंचे। कयास है कि मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट होने तक ये विधायक यहीं रहेंगे। पांच दिनों के लिए होटल के कमरे बुक कराए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के इन विधायकों को मंगलवार रात विमान से दिल्ली लाया गया। वहां से दो बसों में सभी को गुरुग्राम के नजदीक नूंह जिले में स्थित होटल पहुंचाया गया।

इन्होंने भी दिए इस्तीफे : 19 विधायकों के इस्तीफे से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बिसाहुलाल सिंह ने भी अपना त्यागपत्र विस अध्यक्ष को भेज दिया था। सिंह ने इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल स्थित निवास पर की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार में विधायकों का कोई मान-सम्मान नहीं है। इसके बाद एदल सिंह कंषाना और मनोज चौधरी ने भी इस्तीफा सौंप दिया।

सिंधिया समर्थक मंत्रियों को अयोग्य करने की गुहार : उधर, कांग्रेस ने सिंधिया समर्थक और अपनी ही सरकार के छह मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति को बुधवार देर रात याचिका सौंपी है। इन पर सरकार को गिराने में विपक्षी दल भाजपा की मदद करने के आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 191(2) का हवाला देते हुए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। मप्र कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री डॉ. गोविंद सिंह व पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव के नाम से अध्यक्ष को सौंपी याचिका में मंत्री-तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसौदिया, डॉ. प्रभुराम चौधरी व प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप लगाया गया है कि उक्त कांग्रेस के टिकट पर विस चुनाव जीते हैं। अब वे सरकार को गिराने के लिए मंत्री रहते हुए विपक्षी दल भाजपा के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं।

कांग्रेस ने जयपुर पहुंचाए 83 विधायक

जागरण संवाददाता, जयपुर

- मुकुल वासनिक और हरीश रावत भी साथ आए
- तीन दिन तक दो रिसोर्ट में रहेंगे सभी विधायक

मध्य प्रदेश के 83 कांग्रेस विधायक बुधवार दोपहर भोपाल से जयपुर पहुंचा दिए गए। कांग्रेस विधायकों सहित कुल 91 लोग विमान से जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर पहुंचे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी जयपुर आए हैं। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों का स्वागत किया और फिर इन्हें दो बसों से जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर दिल्ली रोड स्थित दो अलग-अलग रिसोर्ट में पहुंचाया दिया गया। गहलोत खुद विधायकों के साथ रिसोर्ट तक गए । 42 को ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में और 40 विधायकों को ट्री हाउस रिसोर्ट में ठहराया गया है। एक विधायक जयपुर शहर में ठहरें हैं। इनमें एक विधायक की तबीयत खराब हो जाने की सूचना है।

हवाई अड्डे पर वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया ने दैनिक जागरण से चर्चा करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है । हम तो यहां भ्रमण करने आए हैं। सरकार स्थिर है। भाजपा के नेता कांग्रेस विधायकों को धोखे से बेंगलुरु ले गए थे, वे जल्द वापस आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दबाव में भाजपा में शामिल हुए हैं। सज्जन सिंह ने कहा कि तीन दिन तक यहां रहकर वापस भोपाल चले जाएंगे। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस कितनी सजग है, इसका अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि वासनिक,रावत और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे तीन दिन तक विधायकों के साथ ही रहेंगे। रावत और वासनिक ट्री हाउस रिसोर्ट का जिम्मा संभाल रहे हैं, वहीं ब्यूना विस्ता रिसोर्ट की जिम्मेदारी गहलोत के पास है। पांडे गुरुवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे।

बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जा रहा : विधायकों को किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जा रहा है। वे मोबाइल पर भी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। दोनों रिसोर्ट के बाहर राजस्थान पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, उपमुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी एवं विधायक अमिन कागजी सहित एक दर्जन नेताओं को दोनों रिसोर्ट में व्यवस्थाएं संभालने की जिम्मेदारी दी गई है ।

कांग्रेस के लिए लकी है ब्यूना विस्टा रिसोर्ट : कांग्रेस नेताओं की मानें तो ब्यूना विस्ता रिसोर्ट पार्टी के लिए लकी है। इससे पहले महाराष्ट्र में सियासी संकट के दौरान भी वहां के 40 विधायकों को इसी रिसोर्ट में ठहराया गया था। इसके बाद वहां सरकार बनी थी। कमलनाथ, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल यहां गहलोत, वासनिक और रावत के संपर्क में हैं।

गहलोत बोले-सिंधिया ने किया विश्वासघात : इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर धनबल, आयकर विभाग, सीबीआइ और ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अवसरवादी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सिंधिया ने विश्वासघात किया है।

एक विधायक की तबीयत बिगड़ी : जयपुर के ब्यूना विस्ता रिसोर्ट में ठहरे एक कांग्रेस विधायक की बुधवार रात तबीयत बिगड़ गई। विधायक का ब्लड शुगर कम होने के कारण उन्हें घबराहट महसूस हुई। इस पर सवाईमानसिंह अस्पताल के डॉक्टर संदीप माथुर को रिसोर्ट में बुलाया गया। उन्होंने विधायक का चेकअप कर दवा दी। विधायक का नाम पता नहीं चल सका है।

मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस ने बुधवार को अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए भोपाल से विशेष विमान के जरिये जयपुर भेज दिया। विधायक बहुमत परीक्षण तक यहीं रहेंगे। प्रेट्र

नई दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनका स्वागत किया। वसुंधरा राजे रिश्ते में ज्योतिरादित्य की बुआ हैं। एएनआइ

वसुंधरा ने कहा- राजमाता गर्व करतीं

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे ने एक बयान जारी कर कहा कि यदि आज राजमाता हमारे बीच होती तो ज्योतिरादित्य के इस निर्णय पर जरूर गर्व करतीं। ज्योतिरादित्य ने राजमाता द्वारा विरासत में मिले उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हुए देशहित में फैसला लिया है, जिसका मैं व्यक्तिगत और राजनीतिक तौर पर स्वागत करती हूं।

MP में सियासी उठापटक के बीच क्या बच पाएगी कमलनाथ सरकार, देखें वीडियो

कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन भी कर ली। इन बड़े सियासी बदलावों के बाद अब सबकी जुबान पर यह सवाल तैर रहा है कि क्या अब राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी सरकार बचा पाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए देखें यह वीडियो।

देखें, मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

राजभवन पर टिकीं सभी की निगाहें

राज्य ब्यूरो, भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद सभी की निगाहें मध्य प्रदेश के राजभवन पर टिक गईं हैं। गुरुवार को राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ से भोपाल लौटेंगे, जिसके बाद प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलने की उम्मीद है। सबसे पहले तो उन छह सिंधिया समर्थक मंत्रियों पर फैसला होगा, जिन्हें हटाने की सिफारिश मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दो दिन पहले की है। इस बीच 16 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें खासी गहमा-गहमी की आशंका है। भाजपा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) की मांग भी कर सकती है।

जानकार बताते हैं कि भाजपा नेता प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से वाकिफ कराने के लिए राजभवन जा सकते हैं। साथ ही विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सरकार को बहुमत सिद्ध करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सारा दारोमदार राज्यपाल टंडन पर रहेगा।

इन मंत्रियों को हटाने को सीएम ने लिखा है पत्र : मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया समर्थक महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी, स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी को पद से हटाने के लिए राज्यपाल को विधिवत पत्र लिखा है।

सरकार के लिए 16 मार्च होगा निर्णायक : आगामी सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सूत्र बताते है कि राज्यपाल के अभिभाषण के पहले ही भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग उठा सकती है। इस मांग से राज्यपाल सहमत हुए तो सत्र शुरू होने से पहले ही फ्लोर टेस्ट की नौबत आ सकती है।

अभिभाषण के पहले विस में शक्ति परीक्षण संविधान विरुद्ध : वरिष्ठ संविधानविद् सुभाष कश्यप कहते हैं कि आजकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन विधानसभा सत्र शुरू होने या सदन में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले शक्ति परीक्षण कराने का फैसला होता है तो वह परंपरा और संविधान के विरुद्ध होगा। 22 विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं। क्या माना जा सकता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है? इस सवाल के जवाब में कश्यप कहते हैं कि विधायकों के इस्तीफे अभी तक मान्य नहीं हुए हैं, इसलिए फ्लोर पर आने तक नहीं कहा जा सकता कि सरकार अल्पमत में आ गई है। अब विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका क्या रहेगी? इस सवाल के जवाब में कश्यप कहते हैं कि विधायकों के इस्तीफों को लेकर विस अध्यक्ष खुद को संतुष्ट करेंगे कि किसी विधायक ने दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया है। वे विधायकों को बुलाकर बात करेंगे। चर्चा में सामने आता है कि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं, तो वे मंजूर कर लेंगे।

लालजी टंडन फाइल

- आज लखनऊ से भोपाल लौटेंगे राज्यपाल लालजी टंडन
- सिंधिया समर्थक छह मंत्रियों को हटाने पर होगा फैसला

16 मार्च को विस सत्र में भाजपा कर सकती है शक्ति परीक्षण की मांग

टंडन ने टिप्पणी से किया इन्कार

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर गहराए संकट को लेकर राज्यपाल लालजी टंडन ने टिप्पणी करने से इन्कार किया। लखनऊ प्रवास पर आए टंडन ने कहा कि अभी मैं छुट्टी पर हूं। गुरुवार को राजभवन पहुंचने पर ही कोई निर्णय लूंगा। अभी मैं यहां दर्शक हूं। हालांकि, जो पत्र आए हैं और लोगों ने जो शिकायतें की हैं, उन सभी को वहां पहुंचकर देखने के बाद ही कोई टिप्पणी कर सकता हूं। अभी मैं होली पर सब से मिलने घर पर बैठा हूं। अलबत्ता, स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हूं।'

दिग्विजय बोले, बहुमत साबित कर देगी कमलनाथ सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार के बहुमत साबित करने का विश्वास जताते हुए बुधवार को दावा किया कि 22 बागी विधायकों में से 13 ने कांग्रेस नहीं छोड़ने का भरोसा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं से यह समझ पाने में गलती हुई कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ने जैसा कदम उठा सकते हैं।

दिग्विजय सिंह ने कहा, 'यह गलती हमसे हुई कि हम यह नहीं समझ पाए कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे। कांग्रेस ने उन्हें क्या नहीं दिया। चार बार सांसद बनाया, दो बार केंद्रीय मंत्री बनाया और कार्यसमिति का सदस्य बनाया।' मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि सिंधिया के भाजपा में जाने का षड्यंत्र तीन महीने से चल रहा था और वह कैबिनेट मंत्री बनने की 'अति महत्वाकांक्षा' के चलते भाजपा में शामिल हुए हैं। सिंह ने कहा, 'क्रोनोलॉजी यह है कि सब कुछ तब शुरू हुआ जब गुरुग्राम के एक होटल से अपने विधायकों को वापस भोपाल ले आए।' उन्होंने यह दावा भी किया कि जब प्रदेश भाजपा के नेता कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने में विफल रहे तब अमित शाह ने सिंधिया को इस काम में लगाया। यह पूछे जाने पर कि क्या कमलनाथ सरकार बचेगी तो सिंह ने कहा, 'हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। हम किसी भी समय शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं।' इस्तीफा देने वाले 22 विधायकों के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'ये 22 विधायक कांग्रेस के हैं। हम इनके परिवारों के संपर्क में हैं। हम चुप नहीं बैठे हैं, हम सो नहीं रहे हैं। 10 विधायक और दो-तीन मंत्री कह रहे हैं कि वे कांग्रेस से अलग नहीं होंगे।' सिंधिया को अहमियत नहीं देने संबंधी सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के समय सिंधिया को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके नामित व्यक्ति को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बन जाइए तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके किसी चेले को उपमुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा।'

भाजपा पर कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए सिंह ने कहा, 'भाजपा कहती है कि यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन विधायकों को चार्टर्ड विमान से कौन ले गया? भाजपा के लोग ले गए। यहां तक कि विधायकों के इस्तीफे भी भाजपा के एक पूर्व मंत्री बेंगलुरु से लेकर आए। यह भाजपा की ओर से प्रायोजित है और इसके लिए भाजपा की ओर से पैसे दिए गए हैं।' यह पूछे जाने पर कि क्या सिंधिया की कांग्रेस में वापसी संभव है तो सिंह ने कहा, 'मुझे पहले भी कोई एतराज नहीं था और आज भी नहीं है।' सिंह ने यह भी कहा कि ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया के मुताबिक काम हुए हैं और उनको किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया है।

नई परेशानी

पार्टी के विधायकों के साथ निर्दलियों के संपर्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

अब राजस्थान बचाने की चुनौती, सचिन पायलट पर सबकी निगाहें

जागरण संवाददाता, जयपुर

मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान पर भाजपा नेतृत्व की नजर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे सक्रिय हो गए हैं। गहलोत कांग्रेस के 101 विधायकों के साथ ही पार्टी को समर्थन देने वाले 12 निर्दलीय विधायकों के संपर्क में हैं। गहलोत ने अपने सिपहसालारों को एक-एक विधायक के पीछे लगा दिया है । हालांकि, पार्टी विधायक दल और निर्दलियों में अपने समर्थकों की अधिक संख्या को देखते हुए गहलोत पूरी तरह से आश्वस्त हैं ।

कांग्रेस के दिग्गजों का मानना है कि गहलोत ने अपने राजनीतिक कौशल से पूर्व सीएम दिवंगत हरिदेव जोशी, दिवंगत शिवचरण माथुर, दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा, चंदन मल बैद और पंडित नवल किशोर शर्मा को दरकिनार कर पूर्व में दो बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली। प्रदेश में जातिगत आधार होने के बावजूद ये नेता गहलोत के राजनीतिक कौशल से मात खा गए और प्रदेश में गहलोत एकछत्र नेता बनकर उभरे, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने वाले गहलोत को सचिन पायलट से शुरू से ही चुनौती मिल रही है। पहले मुख्यमंत्री पद के चयन को लेकर कई दिन तक कशमकश चली। आखिरकार गहलोत कुर्सी पर बैठने में तो कामयाब हो गए, लेकिन 14 माह के कार्यकाल में वे निश्चिंत होकर कभी नहीं बैठे। उन्हें हमेशा पायलट का भय सताता रहा। पायलट एकमात्र प्रदेश के ऐसे नेता हैं, जो कई सालों से गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से सरकार से जुड़े विभिन्न फैसलों में खुद को दरकिनार किए जाने से पायलट नाराज चल रहे हैं। वे अपनी नाराजगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंचा चुके हैं। पायलट समर्थक मंत्री और विधायक भी दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं तक अपना पक्ष रख कर आए हैं, लेकिन गहलोत ने उनकी एक नहीं चलने दी। अब पार्टी नेतृत्व को इस बात का भय जरूर होगा कि कहीं पायलट सिंधिया की राह पर नहीं निकल जाएं। इसीलिए पार्टी के लिए चुनौती बढ़ गई है। ऐसे मे पायलट पर सभी की निगाहें हैं।

भाजपा बोली-सीएए के विरोध का परिणाम : प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बिखराव का कारण सीएए है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएए का समर्थन किया था। उनके जैसे कई कांग्रेसी नेता सीएए के समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी शीघ्र ही कांग्रेस का आंतरिक घमासान साफ नजर आएगा।

सचिन कई बार सरकार को घेर चुके : कांग्रेस के दिग्गजों का मानना है कि राजस्थान में करीब 14 माह पूर्व सत्ता संभालने के बाद से ही गहलोत और उपमुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच तकरार चल रही है। कई अवसर ऐसे आए, जब पायलट ने अपनी ही सरकार को घेरा। चाहे कोटा में बच्चों की मौत का मामला हो या फिर बाड़मेर, नागौर में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट का प्रकरण हो, पायलट ने हमेशा अपनी ही सरकार को घेरा। भ्रष्टाचार और विधायकों एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सरकार में सुनवाई नहीं होने के मुद्दे को लेकर भी पायलट ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की, लेकिन गहलोत ने एक मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह पायलट के बयानों का कोई जवाब नहीं दिया।

सचिन पायलट फाइल

'प्रदेश सरकार को कोई मुश्किल नहीं है'

गहलोत के निकट माने जाने वाले प्रदेश के खेल राज्यमंत्री अशोक चांदना और निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ का दावा है कि प्रदेश में कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस की सरकार गहलोत के नेतृत्व में पांच साल पूरे करेगी।

मप्र के बाद अब राजस्थान की बारी

भाजपा विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी है ।

झारखंड में नहीं चलेगी भाजपा की सेंधमारी : हेमंत सोरेन

राज्य ब्यूरो, रांची : मध्यप्रदेश में सत्तापक्ष में भाजपा की सेंधमारी को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक सुगबुगाहट बढ़ गई है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह आश्वस्त हैं। बुधवार को राज्यसभा के लिए शिबू सोरेन का नामांकन पत्र दाखिल कराने विधानसभा पहुंचे हेमंत सोरेन से जब पूछा गया कि मध्यप्रदेश के बाद भाजपा की नजर राजस्थान और झारखंड पर है, तो उन्होंने भाजपा की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए राजनीतिक शुचिता की बात करती है। भाजपा की ओर से लगातार गैर भाजपा सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। झारखंड के मुद्दे पर उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यहां भाजपा की इस तरह की कोशिश नहीं चलेगी। भाजपा चाहे तो आजमा कर देख ले। कहा, झारखंड की तरफ उन्हें आने तो दीजिए। उन्हें यहां दूसरा दृश्य दिखेगा। हर राजनीतिक गतिविधि पर हमारी नजर है।

सोनिया-राहुल को नहीं थी उम्मीद कि कांग्रेस को छोड़ देंगे सिंधिया

राहुल ने कहा ▶ ज्योतिरादित्य इकलौते ऐसे शख्स थे जिनके लिए हमेशा खुले रहते थे दरवाजे

संजय मिश्र, नई दिल्ली

कांग्रेस हाईकमान से संवाद नहीं होने के ज्योतिरादित्य सिंधिया के दावे को राहुल गांधी ने खारिज कर दिया है। राहुल ने कहा है कि ज्योतिरादित्य ही एक ऐसे शख्स थे जिनके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कांग्रेस हाईकमान के करीबी सूत्रों ने तो यह भी कहा कि पारिवारिक निकटता के चलते ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उम्मीद नहीं थी कि सियासी खींचतान के इस प्रकरण में सिंधिया पार्टी छोड़ने तक का बड़ा फैसला कर सकते हैं।

दस जनपथ से जुड़े करीबी सूत्रों के अनुसार सिंधिया को हाईकमान से मुलाकात और संवाद का समय नहीं दिए जाने की बात बिल्कुल गलत है। यह दावा भी सच्चाई से परे है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का समाधान निकालने के लिए सिंधिया को कोई विकल्प नहीं दिया गया।

हकीकत यह है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में विदेश दौरे पर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ जारी तनातनी खत्म करने का फार्मूला निकालने के लिए राहुल गांधी ने सीधे ज्योतिरादित्य से बात की थी। राहुल इसके लिए सिंधिया को अपने साथ बाहर लंच पर लेकर गए थे, जहां दोनों की लंबी बातचीत हुई थी।

इसमें राहुल ने सिंधिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने का भरोसा दिया क्योंकि तब राज्यसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई थी। हालांकि राहुल के इस आश्वासन के बाद भी सिंधिया संतुष्ट नहीं थे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मिलकर सूबे की सियासत में उनको किनारे लगाने का काम नहीं करेंगे। इसके बाद सोनिया गांधी ने भी सिंधिया को बुलाकर उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। सिंधिया ने खुद इस पेशकश को लेकर रुचि नहीं दिखाई।

हाईकमान के इस करीबी सूत्र का यह भी कहना है कि सिंधिया के करीब एक साल से असंतुष्ट होने की बात से नेतृत्व वाकिफ था। इसीलिए उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष बनने दोनों का विकल्प दिया गया। इस पर राजी नहीं होने का मतलब साफ है कि सिंधिया ने पार्टी छोड़ने का मन पहले ही बना लिया था। हालांकि हाईकमान से उनका संबंध इतना करीब का था कि सोनिया और राहुल दोनों अपनी पेशकश ठुकराए जाने के पीछे सिंधिया के इरादों को नहीं भांप पाए। कमलनाथ और दिग्विजय की सिंधिया के खिलाफ गोलबंदी की बात कुछ हद तक हाईकमान को भी सही लग रही थी। इसीलिए हाईकमान सिंधिया को समाधान का विकल्प दे रहा था और तभी सोनिया-राहुल दोनों को आखिरी वक्त तक भरोसा नहीं था कि ज्योतिरादित्य पार्टी छोड़ देंगे। सोनिया और राहुल ही नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सिंधिया के अच्छे संबंध थे और सभी से उनकी सीधी बात होती थी।

पवार ने कहा, महाराष्ट्र में नहीं मध्य प्रदेश जैसी स्थिति

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं का मानना है कि उनके राज्य में मध्य प्रदेश जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि राज्य की महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार बहुत अच्छी चल रही है। राकांपा प्रमुख ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। राज्यसभा के लिए 26 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत का भी मानना है कि 'मध्य प्रदेश वायरस' महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेगा।

बुधवार को महाराष्ट्र विधान भवन में शरद पवार ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की क्षमताओं पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कमलनाथ की क्षमताओं पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि चमत्कार हो सकता है। एक-दो दिन में पता चल जाएगा कि ऐसा होगा कि नहीं। च्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर पवार ने कहा कि यदि राजा साहब (सिंधिया) के साथ बातचीत की गई होती, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। पवार ने कहा कि सिंधिया लोकसभा चुनाव हारने के तुरंत बाद अपना पुनर्वास चाहते थे। लेकिन कांग्रेस की ऐसी संस्कृति नहीं है। इसलिए ऐसा होना आसान नहीं था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के असर के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि पार्टी के पास कई अच्छे नेता हैं।

इसी प्रकार महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के सांसद एवं प्रवक्ता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को मध्य प्रदेश के असर से अछूता बताया। उन्होंने मजाक का पुट देते हुए ट्वीट किया है कि 'मध्य प्रदेश वायरस' महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेगा। राउत का कहना है कि महाराष्ट्र की शक्ति अलग है। यहां 100 दिन पहले एक ऑपरेशन फेल हो चुका है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने एक बाईपास सर्जरी से महाराष्ट्र को बचा लिया। राउत का इशारा देवेंद्र फड़नवीस के साथ शपथ ले चुके राकांपा नेता अजीत पवार की कुछ ही घंटों के अंदर वापसी की ओर था।

ज्योतिरादित्य को भाजपा खेमे तक लाने में सहायक बने जफर इस्लाम

नई दिल्ली, आइएएनएस : ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से 18 साल पुराना नाता तुड़वाने और उन्हें भाजपा खेमे तक लाने में भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम पार्टी के सहायक बने। जफर मीडिया में भाजपा का बेहद चर्चित चेहरा हैं।

राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक में काम करते थे और अच्छा खासा वेतन पाते थे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति से प्रभावित होकर वह भाजपा में शामिल हो गए। बताते हैं कि मृदुभाषी जफर के प्रधानमंत्री मोदी से अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ज्योतिरादित्य को पार्टी में लाने की जिम्मेदारी भाजपा हाईकमान ने उन्हें सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार, जफर ज्योतिरादित्य को लंबे समय से जानते हैं। जब भी ज्योतिरादित्य दिल्ली में होते हैं तो दोनों की मुलाकात होती रहती है। ज्योतिरादित्य को भाजपा खेमे में लाने के लिए पिछले पांच महीने के दौरान वह अक्सर ही उनसे मिलने लगे थे।

पिछले कुछ दिनों में ही उनकी पांच मुलाकातें हुई थीं। इन मुलाकातों के बाद जफर भाजपा हाईकमान को उसके निष्कर्षों से अवगत कराते थे। इन मुलाकातों और उनके निष्कर्षों के अध्ययन के बाद ही ज्योतिरादित्य को भाजपा खेमे में लाने की कोशिशें शुरू की गईं।

इस पूरे अभियान में भाजपा ने सिर्फ सहायता की, जबकि पूरे अभियान को ज्योतिरादित्य के मुताबिक अंजाम दिया गया। जफर की भूमिका को ऐसे समझा जा सकता है कि सोमवार और मंगलवार को ज्योतिरादित्य की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान वह सात, लोक कल्याण मार्ग में मौजूद थे। जब ज्योतिरादित्य के साथ गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर गए थे तो जफर भी कार में मौजूद थे।

कांग्रेस को भविष्य की सीख दे गए हैं सिंधिया

त्वरित टिप्पणी
प्रशांत मिश्र

- बढ़ती जा रही है पार्टी से युवा नेताओं की नाराजगी
- दूर जाने पर मजबूर कर रही शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी

सिंधिया परिवार का आखिरकार पूर्णतया भाजपा विचारधारा में विलय हो गया। राजमाता विजयाराजे सिंधिया तो खैर जनसंघ और भाजपा की संस्थापक सदस्य ही थीं। उनकी दो पुत्रियां वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे पहले से भाजपा में प्रमुखता से रची बसी हैं, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस में रह कर वह जनसेवा का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर कांग्रेस में हंगामा बरपा है और भाजपा में उत्साह है। भाजपा के उत्साह का कारण जाहिर है कि अब मध्य प्रदेश में वापसी का द्वार खुलता दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस की मायूसी सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है। दरअसल सिंधिया के रुख ने कांग्रेस नेतृत्व को इसका अहसास दिला दिया है कि नहीं सुधरे तो आगे की राह बहुत मुश्किल है। खासकर युवा वर्ग पार्टी की सोच और कामकाज के तरीके से नाखुश है।

याद होगा कि लगभग तीन साल पहले असम के युवा कांग्रेसी हेमंत बिश्व सरमा ने प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ राहुल गांधी का दरवाजा खटखटाया था। हेमंत की बातों को तवज्जो देने के बजाय राहुल अपने कुत्ते से खेलते रहे थे। उसी वक्त हेमंत ने कांग्रेस को बाय-बाय करने का फैसला ले लिया था और बिना शर्त भाजपा में शामिल हो गए। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जौहरी की तरह हेमंत की खूबी को परख लिया था। उसके बाद से असम समेत पूरे उत्तर पूर्व में जो कुछ हुआ है, वह इतिहास है। सभी सात राज्यों में भाजपा और राजग की सरकार है। बताया जाता है कि सिंधिया भी बार-बार केंद्रीय नेतृत्व को इशारा कर रहे थे लेकिन वही हुआ जिसकी शिकायत कांग्रेस के अधिकतर नेता करते हैं - अनसुना कर दिया। अब सिंधिया को गाली देने वाले कांग्रेस में कई सुर उभर रहे हैं। साथ ही पार्टी के अंदर ही मंद-मंद मुस्कुराने वालों की भी कमी नहीं है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस नेतृत्व की निष्क्रियता फिर जाहिर हुई है और इसका अंदेशा बढ़ गया है कि युवा नेता अब बेचैन होने लगे हैं। पहला नतीजा तो मध्य प्रदेश में ही दिखने वाला है। कमलनाथ सरकार की विदाई और कमल वाली सरकार का आगमन लगभग तय माना जा रहा है।

वैसे भाजपा के अंदर अभी यह संशय बरकरार है कि भाजपा के मुख्यमंत्री कौन होंगे - शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा...? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संभवतः एक-दो दिन में इसका पटाक्षेप कर देंगे। शाह लगातार इस पर बारीकी से नजर रख रहे थे। सवाल यह है कि जो कुछ हुआ उसमें भाजपा का कितना हाथ है? कांग्रेस और दूसरे दलों की ओर से सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया जा रहा है, वह कितना सच है? यह कहकर नहीं बचा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सीटें भले ही कांग्रेस से कम आई थीं लेकिन वोट ज्यादा मिले थे। यह भी सच्चाई है कि राजनीति में हाथ मोड़कर बैठना क्या उचित होता है? अगर विरोधी दल में बेचैनी है और सामने अवसर है तो क्या चुप रहना राजनीतिक रूप से सही फैसला होता है। कर्नाटक में ही कांग्रेस ने दिखाया था कि अलग-अलग लड़कर और भाजपा के मुकाबले काफी पीछे रहने के बावजूद जद (एस) के साथ उसने कैसे सरकार बनाई थी। महाराष्ट्र में राकांपा ने इसकी झलक दिखाई थी कि किस तरह अजीत पवार ने भाजपा को झांसा दिया था और यह सभी जानते हैं कि इसकी जानकारी राकांपा सुप्रीमो शरद पवार को थी।

लिहाजा छाती पीटने के बजाय कांग्रेस के लिए यह गंभीर चिंतन का वक्त है। जल्द से जल्द अपनी खामी दूर करने और युवा वर्ग को समझने का वक्त है। सबसे ज्यादा यह तय करने का वक्त है कि पार्टी चिरंतन काल के लिए मनोनीत अध्यक्ष के भरोसे नहीं चल सकती है।

कमलनाथ सरकार अल्पमत में, इस्तीफा दें या बहुमत सिद्ध करें : शिवराज

साक्षात्कार

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के 23 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। नैतिक रूप से मुख्यमंत्री कमलनाथ को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या विधानसभा में बहुमत हासिल करना चाहिए। हम मांग करेंगे कि अभिभाषण को स्थगित कर पहले सरकार विश्वास मत हासिल करे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष **शिवराज सिंह चौहान** ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन 'नईदुनिया' के **धनंजय प्रताप** सिंह से विशेष बातचीत में कही। चौहान ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेश है चौहान से बातचीत के मुख्य अंश...।

● क्या मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के लिए भाजपा जिम्मेदार है?

-इस संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। यह कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया उनका आंतरिक संकट है। भाजपा का इससे कोई लेना-देना नहीं है। हमने तो विस चुनाव 2018 के परिणाम आने के बाद ही कह दिया था कि जनादेश का हम सम्मान करेंगे। तब कांग्रेस के 114 विधायक आए थे और हमारे 109 थे। हालांकि, कांग्रेस से ज्यादा वोट भाजपा को मिले थे। इसके बावजूद हमने कहा कि आप सरकार बनाओ।

● क्या भाजपा ने ही पर्दे के पीछे रहकर सरकार गिराने की साजिश रची है?

-नहीं, कांग्रेस सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी। पूरा प्रचार अभियान उन्होंने संभाला था। सिंधिया के कारण ही कांग्रेस पर जनता ने भरोसा किया था। वे चुनाव प्रचार में दिन-रात लगे थे। अब तो वही कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। इस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए। कर्जमाफ नहीं किया। बोनस नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। रोजगार नहीं दिया। इसके लिए भाजपा जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कहता ही हूं, लेकिन अब तो खुद सिंधिया ने बोल दिया कि भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड कमलनाथ सरकार ने तोड़ दिए हैं। कांग्रेस विधायक और नेता ही इस सरकार से दुखी हैं, इसलिए सिंधिया ने मोदी के नेतृत्व में भरोसा व्यक्त किया है।

● क्या कमलनाथ सरकार अल्पमत में है? विस में भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाएगी?

-कांग्रेस के 23 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं। विस में उसकी सदस्य संख्या मात्र 91 बची है। कमलनाथ सरकार विश्वास मत खो चुकी है। ऐसे हालात में उसे नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर विस में बहुमत हासिल करना चाहिए।

● बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण होना चाहिए या नहीं?

-राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी बहुमत वाली सरकार का होता है। अब जिस सरकार के पास बहुमत ही नहीं तो कौन-सा अभिभाषण? कौन-सा बजट सत्र? सबकुछ स्थगित करके पहले सरकार चर्चा कराए। विश्वास मत हासिल करे।

● क्या भाजपा शक्ति परीक्षण की मांग करेगी?

-हम मांग करेंगे कि बजट सत्र को स्थगित कर पहले शक्ति परीक्षण कराया जाए।

● क्या यह माना जाए कि शिवराज मप्र में चौथी बार सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं?

-कोई सवाल ही नहीं, ऐसा सोचा नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, हम उसका निर्वहन करते हैं। अभी सबकी नजरें प्रदेश के सियासी हालात पर हैं।

● क्या मप्र मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है?

-अभी ऐसे हालात नहीं हैं। आवश्यकता भी नहीं है। वैसे भी चुनाव का इतना बड़ा बोझ डालना ठीक नहीं है। यदि 23 सीट पर चुनाव होंगे तो भी यह मिनी चुनाव जैसा ही होगा।

● क्या भाजपा में सिंधिया का समन्वय बेहतर तरीके से बन पाएगा?

-यह तो सिंधिया की घर वापसी है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने जनसंघ को मप्र में स्थापित किया था। उन्हीं के पोते अब भाजपा में आए हैं।

डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस ने डीके शिवकुमार को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिवकुमार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही ईश्वर खंडरे, सतीश झारकीहोली और सलीम अहमद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। शिवकुमार दिनेश गुंडू राव की जगह लेंगे। अजय सिंह विधानसभा में और एम. नारायणस्वामी विधान परिषद में मुख्य सचेतक होंगे।

दीपेंद्र हुड्डा की दावेदारी से हरियाणा में बन गए मध्य प्रदेश जैसे हालात

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

राज्यसभा चुनाव के चलते हरियाणा कांग्रेस में भी मध्यप्रदेश जैसे हालात बन गए हैं। 90 सदस्यीय विधानसभा वाले हरियाणा में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने हैं। चूंकि कांग्रेस के 31 विधायक हैं इसलिए माना जा रहा है कि एक सीट वह आसानी से जीत लेगी।

दीपेंद्र हुड्डा फाइल

पार्टी हाईकमान द्वारा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का नाम लगभग तय कर लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोर्चा खोल दिया है। हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भिजवाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 31 में 24 विधायकों को दिल्ली में एकत्र कर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को सोनिया गांधी और गुलाम नबी आजाद से मिलवाने का समय मांगा मगर दोनों नेताओं की व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। अब गुरुवार को मुलाकात हो सकती है। वहीं, भाजपा ने अभी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष संजय टंडन और राष्ट्रीय सचिव सुधा यादव के नाम सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश में हाथ जला चुकी कांग्रेस हुड्डा की सक्रियता से चिंतित है। बताते हैं कि गत 9 मार्च को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए राज्यसभा की सीट की मांग की थी। सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया ने साफ इन्कार कर दिया था। हुड्डा ने मंगलवार शाम संदेश भेजकर अपने समर्थक विधायकों को दिल्ली स्थित आवास पर बुलाया। इस बैठक में कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी सहित तीन अन्य सैलजा समर्थक विधायकों को आमंत्रित नहीं किया गया। बैठक में 24 विधायकों के पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इन विधायकों ने साफ कर दिया है कि वे दीपेंद्र की दावेदारी के लिए हाईकमान से भी मिलने को तैयार हैं।

कांग्रेस के 31 विधायकों में से एक विधायक श्रीकृष्ण हुड्डा अस्वस्थ हैं। शेष 30 विधायकों में से यदि दो विधायकों को भी भाजपा क्रॉस वोटिंग या वोट नहीं डालने के लिए तैयार कर लेती है तो तीसरी सीट पर भी उसका कब्जा हो सकता है। इसी समीकरण को हुड्डा खेमा अपने दावे का आधार बना रहा है। उसका कहना है कि यदि दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू व सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा भी समर्थन दे देंगे, जबकि सैलजा के लिए कांग्रेस के 30 विधायकों की भी गारंटी नहीं ली जा सकती।

भाजपा ने राज्यसभा के लिए नौ प्रत्याशी घोषित किए

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए नौ प्रत्याशियों का एलान कर दिया है। इसमें मध्य प्रदेश से पार्टी ने बुधवार को भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी बनाया है। 17 राज्यों के लिए राज्यसभा की 55 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना है। भाजपा ने असम से भुवनेश्वर कलिता, बिहार से विवेक ठाकुर, महाराष्ट्र से उदयनराजे भोसले और राजस्थान से राजेंद्र गहलोत को प्रत्याशी बनाया है। गुजरात से पार्टी ने अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा, झारखंड से दीपक प्रकाश और मणिपुर से लीशेंबा सनजाओबा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने दो सीटें सहयोगी दलों को दी हैं। इनमें महाराष्ट्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले और असम से बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के बिश्वजीत दायमेरी शामिल हैं। भाजपा ने अगले महीने कार्यकाल पूरा करने जा रहे विजय गोयल और प्रभात झा का नाम प्रत्याशियों में नहीं शामिल किया है। राज्य विधानसभाओं में भाजपा की स्थिति को देखते हुए सभी नौ प्रत्याशियों का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है।

चार साल बाद मुलायम परिवार एक मंच पर

बीपी सिंह, इटावा

समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल सिंह यादव द्वारा अपनी पार्टी बनाने के बाद बिखरा मुलायम परिवार इस बार होली पर फिर साथ दिखाई दिया। सैफई में आयोजित होली मिलन समारोह में मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव व प्रो. रामगोपाल यादव एक मंच पर नजर आए। अखिलेश ने जहां शिवपाल के पैर छुए, वहीं शिवपाल ने प्रो.रामगोपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी एक-दूसरे से गले मिले तो गिले-शिकवे भी मिट गए। हालांकि, इस बीच चाचा-भतीजा जिंदाबाद के नारे लगते ही अखिलेश के तेवर बेहद तल्ख हो गए।

समाजवादी पार्टी में चाचा-भतीजे का झगड़ा जगजाहिर है। नई पार्टी बना कर शिवपाल यादव अपनी राह अलग कर चुके हैं, लेकिन होली के दिन सैफई में अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छूए। प्रेट्र

हर साल की तरह सैफई में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के दौरान मंच पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे और फाग गायन का आनंद लिया। इसके बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंचे। एक घंटे बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बेटे अंकुर उर्फ आदित्य यादव के साथ पहुंच गए। कुछ देर में सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव भी अपने पुत्र अक्षय यादव के साथ आ गए। अखिलेश ने चाचा शिवपाल सहित बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और होली की बधाई दी। वहीं शिवपाल यादव ने प्रो. रामगोपाल के पैर छुए।

अखिलेश के तेवर बेहद तल्ख : इस बीच कार्यकर्ताओं ने चाचा-भतीजा जिंदाबाद के नारे लगाए तो अखिलेश के तेवर बेहद तल्ख हो गए। उन्होंने मंच से एलान कर दिया कि ये नारे ही माहौल बिगाड़ते हैं, यदि नारे बंद नहीं किए तो अगली दफा यहां की होली से दूरी बना लूंगा। सभी को मर्यादा में रहना चाहिए। इस पर पंडाल में सन्नाटा छा गया। सैफई में इस बार भी फूलों की होली की धूम रही।

तैयारी

रामनाथ ठाकुर को भी दूसरी बार उच्च सदन भेजेगी पार्टी, राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने की घोषणा

हरिवंश को फिर राज्यसभा भेजेगा जदयू

राज्य ब्यूरो, पटना

राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और जदयू के राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर को दूसरी बार जदयू राज्यसभा भेजेगा। बुधवार को जदयू बिहार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) आरसीपी सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में यह एलान किया। अप्रैल में दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। रामनाथ ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं। पूर्व में वह नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भी रह चुके हैं। अप्रैल अप्रैल 2014 में जदयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। रामनाथ ठाकुर के बहाने जदयू ने अपने अति पिछड़ा वोट बैंक का ख्याल रखा है। आरंभ से ही यह चर्चा थी कि जदयू हरिवंश और रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा के लिए रिपीट करेगा।

अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश : हरिवंश का जन्म 30 जून 1956 को उप्र के बलिया में हुआ है। पेशे से पत्रकार रहे हरिवंश का कर्मक्षेत्र मूल रूप से बिहार और झारखंड रहा है। एक समय वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अतिरिक्त मीडिया सलाहकार भी थे। 2014 में जदयू ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। 8 अगस्त 2018 को वह राजग के उम्मीदवार के तौर राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुने गए।

हरिवंश फाइल

जदयू ने रखा पद का ख्याल : हरिवंश को भेजकर जदयू ने एक साथ कई समीकरण साधे हैं। अति पिछड़ा के साथ एक सीट सवर्ण समाज को भी गई है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा के उपसभापति के पद का भी ख्याल रख जदयू ने हरिवंश को रिपीट किया है। हरिवंश देश में हिंदी के चुनिंदा पत्रकारों में भी शुमार हैं। कहकशां परवीन का भी राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। पर गठबंधन की मजबूरी यह थी कि जदयू को दो ही सीट के लिए अपने प्रत्याशी देने थे। एक सीट भाजपा को मिलनी है। जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कहकशां परवीन को विधान परिषद के लिए खाली हो रही सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। मई में परिषद की कई सीटें खाली हो रही हैं।

26 को होगा चुनाव : 26 मार्च को राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव होना है। नामांकन की आखिरी तारीख 13 मार्च है। 16 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होनी है और 18 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 26 मार्च को सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होना है। उसी दिन परिणाम भी घोषित हो जाएंगे।

लालू के आग्रह पर कांग्रेस ने छोड़ा दावा

राज्य ब्यूरो, पटना

- पांच सदस्य रहने पर ही बचेगी दल की मान्यता
- कांग्रेस को फिर मिला भरपाई का आश्वासन

कांग्रेस ने अघोषित तौर पर राज्यसभा की एक सीट पर अपना दावा वापस ले लिया है। लिहाजा, राज्यसभा की बिहार से भरी जाने वाली पांच सीटों में से दो पर राजद के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तीन सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कांग्रेस ने एक सीट पर अपना दावा किया था। आधार यह था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सीट यह कह कर कम कर दी गई थी कि भरपाई राज्यसभा में कर दी जाएगी। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने तीन दिन पहले राजद से अपेक्षा की थी कि वह अपना वादा पूरा करे। लेकिन कांग्रेस ने बुधवार तक अपने किसी उम्मीदवार का नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास नहीं भेजा। प्रदेश मुख्यालय में इसको लेकर कोई सुगबुहाहट भी नहीं है।

बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा ने बुधवार को कहा कि शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। इधर कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राजद के आग्रह पर कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट से अपना दावा वापस ले लिया है। कांग्रेस में करीब आधे दर्जन उम्मीदवार राज्यसभा जाने की तैयारी में जुटे थे। इनमें राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के भी उम्मीदवार थे।

राजद ने बताई मजबूरी : सूत्रों ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कांग्रेस को उपकृत करने के मामले में फिलहाल लाचारी दिखाई है। उनका कहना है कि अगर अभी दो सदस्य राज्यसभा में नहीं गए तो सदन में राजद सदस्यों की हैसियत निर्दलीय की रह जाएगी। दलीय मान्यता के लिए राज्यसभा व लोकसभा मिलाकर पांच सदस्य होने की अनिवार्यता है। इस समय डा. मीसा भारती, डा. अशफाक करीम और प्रो. मनोज झा राज्यसभा में राजद के सदस्य हैं। झारखंड के राजद सदस्य प्रेम गुप्ता का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। राजद के एक अन्य राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी का देहावसान हो गया। लोकसभा में उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। बिहार से दो नए सदस्यों के जाने के बाद राज्यसभा में राजद सदस्यों की संख्या पांच हो जाएगी। तभी राजनीतिक दल के तौर पर उसकी मान्यता बरकरार रहेगी।

फिर भरपाई का वादा : राज्यसभा की सीट पर दावा छोड़ने के एवज में कांग्रेस के साथ इसकी भरपाई करने का वादा किया गया है। कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को उसके कोटे से कुछ अधिक सीटें दी जा सकती हैं। विधानसभा के पिछले चुनाव में कांग्रेस को 41 सीटें दी गई थीं। इनमें 27 पर उसकी जीत हुई। लेकिन, दावे की वापसी में भरपाई के आश्वासन को महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। असल में मध्य प्रदेश प्रकरण के बाद कांग्रेस में उत्साह की कमी आई है। वह राज्य में सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी राजद से रार नहीं ठानना चाह रही।

न्यूज गैलरी

जर्मनी, फ्रांस व स्पेन के नागरिकों को भी प्रवेश नहीं

महराजगंज : कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब जर्मनी, फ्रांस व स्पेन के नागरिकों को भी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। चीन, कोरिया, ईरान, जापान व इटली के नागरिकों पर प्रतिबंध पहले से लगा हुआ है। नेपाल से लगी सोनौली व ठूठीबारी सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। चिकित्सकों की टीम 24 घंटे जांच कर रही है। आव्रजन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब तक आठ देशों के नागरिकों पर प्रतिबंध लग चुका है। बुधवार की सुबह प्रतिबंध की जानकारी मिलने के बाद सोनौली सीमा पर पहुंचे जर्मनी, फ्रांस व स्पेन के कई नागरिकों को नेपाल वापस लौटना पड़ा। अत्याधुनिक थर्मल स्कैनर खराब हो गया था। टेक्नीशियन के काफी प्रयास के बाद भी स्कैनर ठीक नहीं हो सका और वापस भेजना पड़ा। इसे एसएसबी की मेटल डिटेक्टर मशीन के पास लगाया गया था। जब चालू किया गया तो वह हर व्यक्ति का तापमान 95 डिग्री या इससे कम बताने लगा। (जासं)

तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय को अग्रिम जमानत

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड में भाजपा नेता मुकुल राय को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला 2010 में वीरभूम जिले का है। कोर्ट ने हालांकि उन्हें अगले आदेश तक उस जिले के लाभपुर, बोलपुर और शांतिनिकेतन थाना इलाकों में प्रवेश नहीं करने की भी हिदायत दी है। इसके साथ ही उन्हें नियमित जमानत प्राप्त करने के लिए चार हफ्ते के अंदर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने और 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि भी जमा देने को कहा है। (राब्यू)

तृणमूल विधायक हत्याकांड में भाजपा सांसद को अग्रिम जमानत

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल विधायक सत्यजीत विश्वास की पिछले साल हुई हत्या मामले में नदिया के राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने भाजपा सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 50,000 रुपये की दो निजी मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें हर महीने एक बार राज्य सीआइडी के जांच अधिकारी के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया। (राब्यू)

जनमत
मुद्दा

क्या कोरोना का टीका अगर मौजूद होता तो इस बीमारी के प्रति हम सब इतने भयाक्रांत होते?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

ईरान से 58 भारतीयों को लाया गया स्वदेश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए वायुसेना का सी-17 ग्लोबमास्टर विमान मंगलवार सुबह ईरान से 58 भारतीयों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। मेडिकल प्रोटोकॉल लागू कर स्टेशन स्थित एयरफोर्स अस्पताल में सभी की जांच की जा रही है। जांच निगेटिव आने के बाद इन्हें घर भेजा जाएगा।

तमाम देशों में कोराना वायरस से हड़कंप है। ईरान में भी कोरोना वायरस से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसे देखते हुए विदेश मंत्रालय ने वहां रह रहे भारतीयों को वापस लाने की योजना बनाई की थी। सोमवार को सी-17 ग्लोबमास्टर विमान को ईरान की राजधानी तेहरान के लिए रवाना किया गया था। मंगलवार को विमान तेहरान से 58 भारतीयों को लेकर हिंडन लौट आया। एयरफोर्स अधिकारियों ने बताया कि भारत पहुंचे लोगों में 31 महिलाएं, 25 पुरुष और दो बच्चे हैं। वहां सभी की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई थी। इसके बाद सभी को भारत लाया गया है। ईरान में रह रहे भारतीयों के 529 सैंपल भी लाए गए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने ट्वीट कर मामले की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि सी-17 ग्लोबमास्टर विमान से 58 भारतीयों का पहला समूह हिंडन पहुंच चुका है। सभी को भारत लाने के लिए वायुसेना को बधाई।

वायुसेना का विशेष विमान कोरोना वायरस से प्रभावित ईरान से भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। यहां यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। प्रेट्र

कोरोना प्रभावित देशों से भारतीयों को वापस लाने पर जोर

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा, भारत अपने नागरिकों की जांच के लिए आज इटली भेजेगा डॉक्टरों का दल

ईरान समेत दूसरे देशों से कोरोना मुक्त भारतीय पहले लाए जाएंगे वापस

नई दिल्ली, एजेंसियां : केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बताया कि इटली और ईरान जैसे कोरोना प्रभावित देशों से भारतीयों को वापस लाने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीयों में कोरोना की जांच के लिए डॉक्टरों का एक दल गुरुवार तक इटली भेजा जाएगा। ईरान से 529 भारतीयों के सैंपल जांच के लिए लाए गए हैं। प्रभावित देशों से उन भारतीयों को पहले स्वदेश लाया जाएगा, जो कोरोना से संक्रमित नहीं हैं।

कोरोना प्रभावित देशों में फंसे भारतीयों के बारे में राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि ईरान से मंगलवार को 58 भारतीयों को वापस लाया गया है, इनमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। ईरान में फंसे अन्य भारतीयों को वापस लाने को लेकर भी वहां के अधिकारियों से बात चल रही है। ईरान में कुल छह हजार के लगभग भारतीय हैं। इनमें 1,100 तीर्थयात्री, 300 छात्र और लगभग एक हजार मछुआरे शामिल हैं, जिन्हें वापस लाया जाना है। बाकी लोग वहां नौकरीपेशा और शिक्षा हासिल करने वाले हैं। तीर्थयात्रियों और छात्रों में ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं। ईरान में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को देखते हुए भारत ने वहां छह डॉक्टरों की टीम भेजी है, जिसने वहां जांच और सैंपल एकत्र करने का काम कर रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर इटली और ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर है, क्योंकि चीन के बाद ये दोनों देश कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ईरान से 529 लोगों के सैंपल लाए गए हैं। जिनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आएगी, अगली फ्लाइट से उन्हें लाया जाएगा। सबसे पहले तीर्थयात्रियों, फिर छात्रों और उसके बाद मछुआरों को वापस लाने की प्राथमिकता है। बता दें कि विदेश मंत्री अचानक श्रीनगर गए थे और ईरान में फंसे लोगों के परिजनों से मिले थे।

बुधवार को राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

वैश्विक स्तर पर भारत की नजर

जयशंकर ने बताया कि कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में सचिवों का दल और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का समूह कोरोना वायरस के वैश्विक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। देश में भी कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा कुछ देशों के लिए ई-वीजा सुविधा को भी फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। देश की सभी सीमाओं और बंदरगाहों पर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट क्यों?

जयशंकर ने सदन को बताया कि इटली से लौटने वाले भारतीयों के लिए कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट को अनिवार्य बनाने को लेकर एडवाइजरी इसलिए जारी की गई है, क्योंकि वहां वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन इटली में स्वास्थ्यकर्मियों की व्यस्तता को देखते हुए भारतीयों के लिए यह सर्टिफिकेट हासिल करना मुश्किल है। इसलिए भारत गुरुवार तक डॉक्टरों का एक दल इटली भेज रहा है, जो वहां भारतीयों की जांच करेगा। जो भारतीय कोरोना मुक्त पाए जाएंगे, उन्हें जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा।

समय पर उठाए गए कदमों से कोरोना को फिलहाल रोकने में हुए सफल

बड़ी कामयाबी ▶ भारत में कोरोना का एक भी गंभीर मरीज नहीं, तीन हो चुके हैं ठीक

80 फीसदी मरीज विदेशों से ग्रसित होकर आए थे भारत

नीलू रंजन, नई दिल्ली

दुनिया के सौ से अधिक देशों में कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। समय पर उठाए गए कदमों के कारण कोरोना वायरस भले ही दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में विकराल रूप धारण नहीं कर पाया हो, लेकिन इसका खतरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इसे रोकने के लिए सरकार कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है और पूरी तैयारियों की पांच-छह स्तरों पर मानिटरिंग की जा रही है।

पूरी दुनिया में जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या एक लाख को पार कर गई है। चीन के बाहर अमेरिका, यूरोप और खाड़ी के देशों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में भारत जैसी बड़ी और सघन आबादी वाले देश में अभी तक 60 से कुछ ज्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का मिलना निश्चित रूप से राहत की बात कही जा सकती है। यहां कुल पीड़ितों में से लगभग 80 फीसदी मरीज वे हैं, जो विदेशी धरती पर कोरोना वायरस से ग्रसित होकर भारत आए थे। भारत में कोरोना वायरस के कारण अभी तक एक भी मौत नहीं हुई और किसी मरीज की हालात नाजुक नहीं है। वहीं जनवरी में ही चीन से कोरोना से ग्रसित होकर भारत आने वाले केरल के तीन लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं।

दरअसल भारत दुनिया के उन चंद देशों में है, जिसने कोरोना के खतरे को पहचानते हुए शुरुआत में ही रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 जनवरी को पहली एडवायजरी जारी करते हुए चीन से आने वाले यात्रियों के लिए सात हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, जो अब बढ़कर सभी देशों से आने वालों पर लागू कर दी गई है। इसके अलावा हालात और उससे निपटने के लिए तैयारियों पर नजर रखने के लिए कई स्तरों पर मानिटरिंग की व्यवस्था भी गई है। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन हर दिन राज्यों के स्वास्थ्य व मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसकी समीक्षा करती हैं, तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हर दो-तीन दिन में स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरीये बैठक करते हैं। इसके अलावा तैयारियों पर नजर रखने और जरूरत के मुताबिक समन्वित तरीके से तत्काल कदम उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समूह अलग से बनाया गया है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन समिति भी स्थिति की लगातार समीक्षा कर रही है। अभी तक इस समिति की 16 से अधिक बार बैठक हो चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी कई बार हालात की समीक्षा के लिए बैठक बुला चुके हैं। साथ ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब तक दो बार सभी राज्यों व विभागों के साथ बैठक कर जरूरी हिदायत दे चुके हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद भारत में कोरोना को लेकर व्यापक जन-जागरण अभियान शुरू किया गया है।

इतने स्तरों पर तैयारियों की समीक्षा के बारे में पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में जरा सी चूक भारी साबित हो सकती है। यही कारण है कि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज के पाए जाने की स्थिति में उससे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की तत्काल पहचान कर निगरानी शुरू कर दी जाती है।

कोरोना वायरस को लेकर देश भर में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के शिरडी स्थित साईंबाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस से जांच की जा रही है। प्रेट्र

बगैर स्क्रीनिंग इटली से आया विमान, मचा हड़कंप

आइजीआइ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग में सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई

जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शैक्षणिक संस्थान 31 तक बंद

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

बुधवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर इटली के मिलान से बगैर स्क्रीनिंग एयर इंडिया की फ्लाइट आने से हड़कंप मच गया। विमान को पार्किंग-बे में सुनसान स्थान पर ले जाकर सभी 80 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं मिला। एहतियातन सभी को मानेसर स्थित सेना के आइसोलेशन सेंटर भेजा गया है।

एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि कोरोना प्रभावित देशों से अन्य देशों के लिए हवाई सफर पर जाने वालों की सफर से पूर्व स्क्रीनिंग अनिवार्य है। एयर इंडिया की फ्लाइट एआइ-138 इटली के मिलान शहर से बुधवार की सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पर आई थी। इसमें 80 भारतीय व विदेशी यात्री सवार थे। सूचना मिली कि विमान में सवार यात्रियों की मिलान में स्क्रीनिंग नहीं की गई है। इसके बाद विमान को एयरोब्रिज के बजाय पार्किंग-बे में सुनसान स्थान पर ले जाया गया। वहां पर उनकी स्क्रीनिंग हुई, जिसमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई।

कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जम्मू-कश्मीर के निजी व सरकारी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाएं तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। एहतियातन जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में सिनेमा हाल बंद कर दिए हैं। जम्मू संभाग पांच जिलों और कश्मीर के सभी जिलों के आंगनबाड़ी सेंटरों को बंद किया गया है। लेह व कारगिल जिलों में भी 31 मार्च तक विश्वविद्यालय व कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को गत सप्ताह ही बंद कर दिया गया था। ईरान से लौटे जिस बुजुर्ग की मौत हुई थी, उसकी जांच में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। वहीं पॉजीटिव पाए गए दो मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक भूपेंद्र कुमार ने जम्मू में बताया कि नियमित समीक्षा की जा रही है। विदेशों से आए 1211 संदिग्धों को निगरानी में रखा गया है। इसमें 150 ने अपनी निगरानी की 28 दिन अवधि को पूरा कर लिया है। 12 लोगों को अस्पतालों में निगरानी में रखा गया है। कुल 64 संदिग्धों के मामलों को जांच के लिए भेजा गया, जिसमें 28 में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए हैं।

आइटीबीपी के जवान के सैंपल जांच को भेजे : दिल्ली से स्थानांतरित होकर श्रीनगर आए आइटीबीपी के एक जवान के नमूने लिए गए हैं और उसे शहर के बाहरी क्षेत्र पंथाचौक में स्थित एक क्वांनटाईन सेंटर में रखा गया है। यह जवान दिल्ली में स्थापित क्वार्नटाईन केंद्र में दो माह तक तैनात रहा था। दूसरी ओर पंजाब में मंत्रियों के समूह ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह किसी भी बड़े जलसे की इजाजत न दें।

भय फैलाने पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक को किया निलंबित

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी वॉट्सएप पर शेयर करना एक शिक्षक को महंगा पड़ गया। कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। उधर, केरल में कोरोना का भय फैलाने पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा किया गया है।

मामला छत्तीसगढ़ के कांकेर का है, जहां व्याख्याता हिमन कोर्राम ने वॉट्सएप ग्रुप में कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी वायरल की थी। हिमन ने लिखा कि बायलर मुर्गा खाने की वजह से कांकेर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कलेक्टर ने इसे सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा का उल्लंघन बताया है। हिमन को सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

डॉक्टर फैला रही थी फर्जी सूचनाएं

त्रिशूर, एएनआइ : केरल पुलिस ने कोरोना वायरस के संदिग्ध अनिवासी भारतीय को लेकर फर्जी सूचनाएं फैलाने के आरोप में महिला डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जिला चिकित्सा अधिकारी त्रिशूर ने थलीकुलम स्थित एक निजी अस्पताल की डॉक्टर शीनू श्यामलन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि डॉ. शीनू पर समाज में बेवजह दहशत पैदा करने का आरोप है। डॉ. शीनू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उनके अस्पताल में पहुंचे कोरोना वायरस के संदिग्ध के बारे में सरकारी अधिकारियों को सूचना देने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने दावा किया था कि संदिग्ध मरीज ने मास्क पहनने आदि एहतियाती उपाय भी नहीं कर रखे थे और थोड़ी ही देर बाद वह कतर के लिए रवाना हो गया।

दो जांच नतीजों के बाद होती है पुष्टि

प्रथम पृष्ठ से आगे

किसी संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि के लिए दो बार जांच की जाती है। अगर दोनों ही जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तभी उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित घोषित किया जाता है।

स्वतः कोरंटाइन का आग्रह : सरकार ने चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, इटली, थाइलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की हाल में यात्रा करने वाले लोगों से खुद को 14 दिनों तक स्वतः कोरंटाइन का आग्रह किया है। सरकार ने कंपनियों से भी इन देशों से लौटने वाले अपने कर्मचारियों से 14 दिनों तक घर से ही काम लेने को कहा है।

गुजरात में 56 मामले निगेटिव मिले : गुजरात में कोरोना के 56 संदिग्ध मामलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। राज्य सरकार ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्य के स्वास्थ्य व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि राज्य में कोरोना प्रभावित देशों से दो हजार से ज्यादा लोग आए थे। इनमें से 12 सौ से ज्यादा लोगों ने अनिवार्य कोरंटाइन अवधि पूरी कर ली है। राज्य में भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है।

कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने का आग्रह : केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर इटली से लौटने वाले भारतीयों के लिए कोरोना मुक्त सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि लोगों को यह सर्टिफिकेट हासिल करने में मुश्किलें हो रही हैं, जिससे वो जल्द लौट नहीं पा रहे।

निजी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की योजना : महाराष्ट्र सरकार राज्य के निजी अस्पतालों में जांच केंद्र और आइसोलेशन वार्ड बनाने की योजना बना रही है। इसी को लेकर निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ बैठक की। इनमें जसलोक, लीलावती, नानावती और हिंदुजा अस्पताल के प्रतिनिधि शामिल थे।

क्रूज जहाजों को इजाजत नहीं : भारत ने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के बंदरगाहों पर एक फरवरी या उसके बाद ठहरने वाले क्रूज जहाजों के भारत में प्रवेश पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। जहाजरानी मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले चालक दल के सदस्यों के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी।

दुनियाभर में कोरोना की दहशत

- केरल में मंगलवार को लौटे 45 लोगों को निगरानी में रखा गया है। इनमें से 35 को उनके घरों और 10 को अस्पताल में रखा गया है।
- लोगों से चीन, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी नहीं जाने की अपील
- बहुत जरूरी नहीं होने पर विदेश की यात्रा करने से बचने का भी लोगों से आग्रह
- महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैठन में वार्षिक 'नाथ शष्टि यात्रा' को निलंबित कर दिया है। यह यात्रा 14-18 मार्च के बीच होनी थी
- कर्नाटक सरकार ने लोगों से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करने का आग्रह किया है। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान में इसे शामिल किया गया है।
- एयर इंडिया के पायलटों के संगठन ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से उड़ान से पहले और बाद में पायलटों की सांस की जांच से राहत देने की अपील की है।
- चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कोरोना वायरस के केंद्र वुहान शहर का दौरा किया और चिकित्सा स्टाफ व अधिकारियों के प्रयासों की तारीफ की।
- अमेरिका में 30 से ज्यादा राज्यों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।
- दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के नए मामलों में 11 दिन की गिरावट के बाद फिर तेजी आ गई है। बुधवार को 242 नए मामलों की पुष्टि हुई।

लोअर बर्थ पाने के लिए यात्री बना कोरोना रोगी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : नंदादेवी एक्सप्रेस में एक यात्री ने लोअर बर्थ पाने के लिए खुद को कोरोना वायरस से पीड़ित बताया। इससे यात्रियों में दहशत फैल गई। रेलवे प्रशासन ने हरिद्वार में यात्री को उतारा। जांच में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई, तब लोगों के जान में जान आई।

देहरादून से मंगलवार रात 11 बजे कोटा जाने के लिए नंदादेवी एक्सप्रेस चली। एसी थ्री के कोच संख्या बीई टू की बर्थ संख्या 53 (मिडिल बर्थ) पर समरजीत सिंह की मथुरा तक बर्थ आरक्षित थी। यात्री मास्क लगाकर कोच में पहुंचा और यात्रियों से कहा कि उसे लोअर बर्थ दे दें क्योंकि वह कोरोना पीड़ित है। इतना सुनते ही अन्य यात्रियों में दहशत फैल गई। लोगों ने हंगामा करते संबंधित यात्री को उतराने की मांग की। टीटीई ने इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल रूम को दिया। ट्रेन के हरिद्वार पहुंचते ही रेलवे के अपर मंडल चिकित्साधिकारी, आरपीएफ व जीआरपी सुरक्षा कवच पहनकर पहुंचे। यात्री समरजीत को उतारा गया। कोच में दवा का छिड़काव कराया गया। इस कारण 50 मिनट तक ट्रेन हरिद्वार स्टेशन पर रुकी रही।

संयोग

शेख अब्दुला को 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने कश्मीर को अलग करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था

दादा की तरह उमर ने भी कैद में मनाया 50वां जन्मदिन

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कई बार इतिहास खुद को दोहराता है। नेशनल कान्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते मंगलवार (10 मार्च) को अपना 50वां जन्मदिन जेल में मनाया। उनके दादा शेख अब्दुल्ला ने भी 50वां जन्मदिन कैद में ही मनाया था। वर्ष 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने शेख अब्दुला को कश्मीर को अलग करने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही बाद में नेशनल कान्फ्रेंस की स्थापना की थी।

मालूम हो कि उमर अब्दुला को बीते पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू किए जाने के समय एहतियातन हिरासत में लिया गया था। गत जनवरी में उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत बंदी बनाया गया। वह घर से करीब दो किमी दूर स्थित हरि निवास में कैद हैं।

पिता फारूक अब्दुल्ला ने फोन पर दी उमर को बधाई

हरि निवास में केक व उपहार लेकर पहुंचीं मां और बहन

उमर अब्दुल्ला। (फाइल)

उमर मंगलवार को अपने 50वें जन्मदिन पर अधिकांश समय तक हरि निवास में अकेले ही रहे। इस दौरान उन्होंने पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला का बधाई संदेश का एक फोन रसीव किया। दोनों ने करीब 10 मिनट तक बातचीत की। शाम चार बजे उमर की मां मौली अब्दुल्ला, बहन साफिया व चार अन्य रिश्तेदार एक केक व कुछ अन्य उपहार लेकर पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला गुपकार स्थित अपने मकान में ही रहे। उमर के दोनों बेटे जमीन और जहीर भी नहीं पहुंचे। वे दिल्ली में अपनी मां पायल के पास ही हैं।

उमर का ट्विटर हैंडल संभालेंगी छोटी बहन

उमर की छोटी बहन सारा अब्दुल्ला ने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि वह उनका आधिकारिक टवीटर हैंडल संभालेंगी। सारा ने कहा कि जैसे ही वह रिहा होंगे, यह एकाउंट उनके हवाले कर दिया जाएगा।

दोस्तों को नहीं मिली इजाजत

बहन साफिया ने बताया कि उमर के कुछ अन्य दोस्त भी मिलना चाहते थे, लेकिन प्रशासन से इजाजत नहीं मिली। साफिया ने बताया कि उमर ठीक हैं। पिता फारूक बहुत परेशान थे कि बेटे उमर से उसके जन्मदिन पर नहीं मिल सके। उन्होंने फोन पर उसे मुबारकबाद दी।

मनीष तिवारी ने दी बधाई

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने उमर अब्दुला को ट्विटर पर मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, विश्वास बनाए रखो। भारत किसी भी व्यक्ति विशेष से कहीं ज्यादा विशाल है।

जैश व हिजबुल मुजाहिद्दीन के तीन-तीन ओजीडब्ल्यू पकड़े

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

पुलिस ने बड़गाम में सक्रिय जैश-ए-मुहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के माड्यूल को बेनकाब कर उसके तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, कुपवाड़ा के करालपोरा से हिजबुल से जुड़े तीन ओजीडब्ल्यू एजाज अहमद, मुहम्मद अल्ताफ और अब्दुल राऊफ को पकड़ा गया है। इनकी निशानदेही पर हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। आतंकी संगठन से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं।

पुलिस के मुताबिक कुछ दिनों से बड़गाम के चाडूरा इलाके में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे थे। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच तीन बार मुठभेड़ भी हो चुकी है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर जैश के तीन ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े। तीनों में से दो की पहचान दिलावर सोफी और समीर यूसुफ के रूप में हुई है। तीसरा आरोपित नाबालिग छात्र है। तीनों चाडूरा और साथ सटे इलाकों में जैश के आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकानों, उनके हथियारों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने, उनके लिए पैसे का बंदोबस्त करने के अलावा मुखबिरी भी करते थे। वहीं, कुपवाड़ा में भी पुलिस और सेना के जवानों ने हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़े तीन ओजीडब्ल्यू एजाज अहमद, मुहम्मद अल्ताफ और अब्दुल रौऊफ को काबू किया। इनकी निशानदेही पर सुरक्षाबलों ने करालपोरा में से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया है।

दूसरी ओर श्रीनगर के बर्बरशाह में बुधवार को ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैल गई। बम निरोधक दस्ते ने उसे निष्क्रिय कर दिया।

5.5 लाख की बांग्लादेशी मुद्रा जब्त की है बीएसएफ जवानों ने बंगाल के नदिया जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर। यह विदेशी मुद्रा साइकिल के टायर के अंदर छिपाकर रखी थी।

पोस्टर हटाने के आदेश के खिलाफ योगी सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट

लखनऊ हिंसा पोस्टर मामला ▶ प्रदेश सरकार की याचिका पर आज होगी सुनवाई

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दंगाइयों के पोस्टर हटाने का दिया था आदेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 9 मार्च को दिया था आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गत 9 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से लखनऊ हिंसा और उपद्रव में आरोपित लोगों के पोस्टर हटाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार को ऐसे पोस्टर लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट ने पोस्टर लगाने को निजता के अधिकार का भी हनन कहा था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया था कि इस फैसले को अंजाम देकर क्रियान्वयन रिपोर्ट भी 16 मार्च या उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपने का निर्देश है।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा करने वालों के पोस्टर लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तत्काल प्रभाव से पोस्टर हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में होली की छुट्टियों के दौरान अवकाशकालीन पीठ अर्जेंट (तत्काल) मामलों की सुनवाई के लिए बैठ रही है। यह पहला मौका है जबकि सुप्रीम कोर्ट में होली की एक सप्ताह की छुट्टियों को दौरान भी अवकाशकालीन पीठ बैठ रही है। अन्यथा अवकाशकालीन पीठ सिर्फ गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही बैठती थी। गुरुवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित और अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने दैनिक जागरण को बताया कि प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की है जिस पर गुरुवार को सुनवाई होनी ही। सिंह ने अपील में दिए गए आधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पोस्टर में नाम और फोटो छापने को हाई कोर्ट ने 'निजता के अधिकार' का हनन बताया है, जोकि ठीक नहीं है। चूंकि यह मामला निजता के अधिकार के तहत नहीं आता है। सिंह ने कहा कि जो चीजें पहले से सार्वजनिक हैं उन पर निजता का अधिकार नहीं लागू होता। इस मामले में पहले से सारी चीजें सार्वजनिक हैं। दूसरा आधार अपील में मामले को जनहित याचिका बनाए जाने को लेकर है। सिंह ने बताया कि यह मामला जनहित याचिका का नहीं माना जा सकता क्योंकि जनहित याचिका की अवधारणा उन लोगों के लिए लाई गई है जो किसी कारणवश कोर्ट आने में असमर्थ हैं। उनकी ओर से जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। या फिर जिन मामलों में आबादी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो रहा हो जैसे पर्यावरण संरक्षण आदि मामलों में जनहित याचिका हो सकती है लेकिन मौजूदा मामला ऐसा नहीं है।

एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह कहते हैं कि मौजूदा मामले में प्रभावित लोग कोर्ट जा सकते हैं और रिकवरी नोटिस के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट गए भी हैं। ऐसे में इस मामले को जनहित याचिका के तहत नहीं सुना जाना चाहिए। हालांकि सिंह ने याचिका का और ब्योरा व आधार साझा नहीं किए।

भड़काऊ खबरों को लेकर गूगल, फेसबुक व ट्विटर को नोटिस

आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने दायर की याचिका

जासं, नई दिल्ली : सोशल मीडिया के तीन बड़े प्लेटफार्म से भड़काऊ भाषण, लेख और फर्जी खबरें हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, फेसबुक, ट्विटर और गूगल से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया भड़काऊ भाषण फैलाने और फर्जी खबरों को वायरल करने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। पुलिस भड़काऊ विषयवस्तु पर रोक लगाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। सोशल मीडिया को इससे रोकने के लिए उचित कदम उठाने होंगे।

किरण बेदी के खिलाफ एकल पीठ का फैसला खारिज

चेन्नई, प्रेट्र: मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को अपनी एकल पीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि पुडुचेरी की उपराज्यपाल (एलजी) किरण बेदी केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। हाई कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभिन्नता की स्थिति में प्रशासक (किरण बेदी) द्वारा संदर्भित मामलों में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

केंद्र सरकार और प्रशासक (किरण बेदी) की अपीलों को अनुमति प्रदान करते हुए मुख्य न्यायाधीश एपी साही और जस्टिस सुब्रमनियम प्रसाद की पीठ ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री की अगुआई में राज्य सरकार और उपराज्यपाल अलग-अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करेंगे। पुडुचेरी में सरकार और प्रशासक की भूमिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं।

मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी और उपराज्यपाल के बीच कथित सत्ता संघर्ष को लेकर मुकदमेबाजी की श्रृंखला में यह ताजा आदेश है। पिछले साल यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से एकल पीठ के आदेश को हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती देने को कहा था।

जस्टिस आर. महादेवन की एकल पीठ ने 30 अप्रैल, 2019 को कहा था कि मंत्रिपरिषद के जरिये काम कर रही निर्वाचित सरकार में प्रशासक हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। उन्होंने यह आदेश कांग्रेस विधायक के. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर दिया था। याचिका में कांग्रेस विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जनवरी और जून, 2017 में जारी उन दो आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें प्रशासक की शक्तियों में इजाफा किया गया था। उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा दैनिक कामकाज में कथित हस्तक्षेप का हवाला भी दिया था। इनमें सरकारी अधिकारियों को वाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूर करने, वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप और निर्वाचित सरकार की अनदेखी करके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना शामिल है।

एलजी बनाम राज्य

- कहा, मिलकर काम करें पुडुचेरी सरकार और उपराज्यपाल
- मतभिन्नता की स्थिति में केंद्र सरकार का फैसला अंतिम होगा

किरण बेदी। फाइल

राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता नलिनी की रिहाई याचिका खारिज

चेन्नई, एजेंसियां : मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सजायाफ्ता नलिनी की अग्रिम रिहाई संबंधी याचिका खारिज कर दी। उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा था कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के अनुमोदन का इंतजार किए बिना तमिलनाडु कैबिनेट के फैसले के आधार पर उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

याचिका में नलिनी ने कहा था कि 9 सितंबर 2018 से उसके कारावास को अवैध माना जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु कैबिनेट ने सभी सातों सजायाफ्ता को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया था। उसका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत कैबिनेट ने सभी सातों की रिहाई की सिफारिश की थी, जिसे मानने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। जवाब में तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि नलिनी का कारावास अवैध नहीं है, क्योंकि कैबिनेट का प्रस्ताव अभी राज्यपाल के पास विचाराधीन है। सातों सजायाफ्ता में एजी पेरारीवलन, टी. सत्येंद्रराजा उर्फ संतन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन व उसकी पत्नी नलिनी शामिल हैं।

बाल अधिकार आयोग ने दर्ज किए मदरसा छात्रों के बयान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर

- उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कर रहा है जांच
- 20 दिसंबर के उपद्रव में बच्चों के शोषण से जुड़ा है मामला

सीएए के विरोध के नाम पर हुए उपद्रव के बाद मदरसा छात्रों के उत्पीड़न से जुड़ी खबरों पर जांच में जुटे उप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बुधवार को पीड़ित छात्रों के बयान दर्ज किए। तीन दिन पूर्व भी आयोग अध्यक्ष व सदस्य ने जांच की थी।

20 दिसंबर को उप्र के मुजफ्फरनगर में सीएए के विरोध की आड़ में उपद्रव हुआ था। थाना सिविल लाइन व शहर कोतवाली में पुलिस ने 259 लोगों के विरुद्ध नामजद तथा छह हजार अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आर्य समाज रोड स्थित सादात हास्टल में संचालित मदरसे में पढ़ रहे छात्रों को गिरफ्तार कर उनका भी चालान कर दिया था। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में विशेष जांच रिपोर्ट प्रेषित की थी। इसमें चार आरोपित छात्रों के विरुद्ध कोई साक्ष्य न मिलने की बात कही गई थी। चारों छात्रों को रिहा कर दिया गया था। एक दर्जन से अधिक आरोपित मदरसा छात्रों की धाराएं पुलिस रिपोर्ट के आधार पर काट दी गई थीं। कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आई इस तरह की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने का आदेश दिया था। तीन दिन पूर्व शासन के निर्देश पर आयोग अध्यक्ष डा. विशेष गुप्ता व सदस्य डा. जया ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर जांच शुरू की थी। आयोग ने मीनाक्षी चौक पर पहुंचकर आम नागरिकों से भी 20 दिसंबर की घटना के बारे में जाना था। लेकिन सादात हास्टल स्थित मदरसा में पीड़ित बच्चे नहीं मिले थे। बुधवार को मामले की जांच के लिए आयोग अध्यक्ष व सदस्य फिर से शहर में पहुंचे और सादात हास्टल मदरसा पहुंचकर छात्रों के बयान दर्ज किए।

पांच हजार करोड़ का बकाया, कटने लगी झारखंड की बिजली

जागरण संवाददाता, रांची : दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) ने झारखंड सरकार पर लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि के भुगतान को लेकर राज्य के अपने कमांड एरिया में चरणबद्ध बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। मंगलवार से डीवीसी ने जेवीवीएनएल (झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) को आठ घंटे तक बिजली कटौती करनी शुरू कर दी है। निगम ने आठ से 18 घंटे तक कटौती करने की बात कही है। निगम इससे पहले सरकार को कई बार अल्टीमेटम दे चुका है। डीवीसी प्रबंधन ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर 28 फरवरी तक बकाया पैसे की भुगतान करने को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक डीवीसी को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।

जब तक झारखंड सरकार बकाया पैसे का भुगतान नहीं करती, तब तक बिजली की कटौती ऐसे ही जारी रहेगी। पैसे के अभाव में बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा का प्लांट चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है।

मध्य प्रदेश के डीजीपी होंगे वीके जौहरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के प्रमुख वीके जौहरी मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उन्हें मूल कैडर में वापस भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी जौहरी ऐसे पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे जिन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बल से राज्य पुलिस में भेजा गया है।

आइटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल) के महानिदेशक एसएस देसवाल को बीएसएफ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बुधवार को उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का प्रभार ग्रहण कर लिया। वह नई नियुक्ति या अगले आदेश तक इस जिम्मेदारी को संभालेंगे।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुआई वाली सरकार ने आइपीएस अधिकारी जौहरी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का आदेश जारी किया था। इसी आदेश में मध्य प्रदेश सरकार ने निवर्तमान डीजीपी वीके सिंह को खेल एवं युवा कल्याण विभाग में उसके निदेशक के रूप में भेज दिया है। साइबर सेल के महानिदेशक (डीजी)राजेंद्र कुमार को जौहरी के प्रभार लेने तक डीजीपी का कामकाज देखने के लिए कहा गया है। जौहरी के गुरुवार को भोपाल पहुंचने और अगले कुछ दिनों में नई जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक यह भी उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम थमने के बाद मध्य प्रदेश में कुछ और भी तबादले हो सकते हैं। साथ ही अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो कई और विभागों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

आइटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल (बाएं) बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार ग्रहण करते हुए। बीएसएफ के मौजूदा महानिदेशक वीके जौहरी को मध्यप्रदेश का डीजीपी बनाया गया है। प्रेट्र

गंगा रक्षा को लेकर स्वामी शिवानंद ने शुरू किया तप

जासं, हरिद्वार

- कहा, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने तक जारी रहा रहेगा आंदोलन
- वह दिन में केवल पांच गिलास सादा पानी लेंगे।

मातृसदन परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद सरस्वती ने गंगा रक्षा को लेकर होली के दिन से तप (अनशन) शुरू कर दिया है। बुधवार को भी उनका तप जारी रही। इधर, मातृसदन के ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद ने फिलहाल अपना अनशन तोड़ दिया। शिवानंद ने डीजी (लॉ एंड आर्डर) अशोक कुमार पर मातृसदन के साथ हो रहे षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया है।

मातृसदन आश्रम में अनशन कर रहे स्वामी शिवानंद सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मलीन पूर्व प्रोफेसर ज्ञान स्वरूप सानंद के गंगा रक्षा संकल्प को पूरा कराने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू की है। वह दिन में केवल पांच गिलास सादा पानी लेंगे। धीरे-धीरे इस पानी की मात्रा को भी कम करके चम्मच में कर देंगे। अंत में जल भी त्याग करके वह अपनी आत्मा को परम तत्व में विलीन कर पूर्व प्रोफेसर ज्ञान स्वरूप सानंद, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद और ब्रह्मचारिणी पद्मवती के संकल्प को बल देने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने बताया कि मंगलवार को आश्रम पहुंचे संत गोपालदास ने जानकारी दी कि डीजी (लॉ एंड आर्डर) अशोक कुमार ने उन्हें मातृसदन के खिलाफ सरकारी गवाह बनने लिए मजबूर करने का प्रयास किया था। ऐसा न करने पर उनका 151 में चालान कर दिया गया। कहा कि, वह जल्द ही इसको लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजेंगे।

इधर, ब्रह्मचारी संत आत्मबोधानंद ने दिल्ली एम्स से लौटकर मातृसदन आश्रम में 40वें दिन अपना अनशन समाप्त कर विराम दे दिया। उन्होंने 20 दिन से जल त्याग रखा था। शिवानंद ने बताया कि साध्वी पद्मावती का अनशन दिल्ली एम्स में भी 88वें दिन जारी रहा।

संघ के प्रतिनिधियों को मिलेगा रामलला का प्रसाद

रमाशरण अवस्थी, अयोध्या

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक 15 से 17 मार्च तक कर्नाटक के चेनन हल्ली नामक स्थान पर होनी है। इस बैठक में संघ से जुड़े अनेक विषय आएंगे लेकिन, राममंदिर के निर्माण की खुशी सब पर भारी होगी।

इसका अंदाजा बैठक में देशभर से शामिल होने वाले 1450 प्रतिनिधियों को रामलला का प्रसाद दिए जाने की योजना से लगाया जा सकता है। अयोध्या से प्रसाद ले जाने का दायित्व डॉ. अनिल मिश्र को सौंपा गया है। डॉ. मिश्र मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य होने के साथ संघ की अवध प्रांत इकाई के कार्यवाह हैं। उन्होंने बताया कि संघ के प्रतिनिधियों को रामलला का वही प्रसाद दिया जाएगा, जो अर्से से रामलला को अर्पित होता रहा है।

इसमें इलायची दाना, मिश्री के साथ गरी, छुहारा और मखाना होगा। संघ का रामलला से सरोकार मंदिर आंदोलन से पूर्व का है। संघ के तत्कालीन नेतृत्व की ही प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने साढ़े तीन दशक पूर्व मंदिर आंदोलन का आगाज किया था। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व मंदिर आंदोलन पर बराबर नजर रखता रहा है और जरूरत पड़ने पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी राय भी जाहिर करता रहा है।

मंदिर के निर्माण में दिखेगा कारसेवा जैसा आंदोलन और उत्साह

रघुवरशरण, अयोध्या

श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कारसेवा जैसे आंदोलन का सबब बनेगा। निर्माण तो स्थापत्य के विशेषज्ञ करेंगे पर मौके पर रामभक्तों की फौज भी सहयोगी की भूमिका में होगी। इस दिशा में विहिप के अलावा शिवसेना भी पहल करती नजर आ रही है।

25 मार्च से शुरू हो रहे वासंतिक नवरात्र के दौरान विहिप के संयोजन में पूरे देश में राम महोत्सव प्रस्तावित है। इसके साथ विहिप पूरे देश को भगवान राम के प्रति अनुराग से जोड़ने के साथ मंदिर निर्माण की खुशी में शामिल करने की तैयारी में है। राम जन्मोत्सव यानी दो अप्रैल को राम महोत्सव की पूर्णाहुति के साथ पांच दिनों की छुट्टी के बाद विहिप नेतृत्व आठ अप्रैल को पड़ रही चैत्र पूर्णिमा से पुनः सक्रिय होगा। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा कहते हैं, मंदिर निर्माण कारसेवकों के शौर्य एवं बलिदान से संभव हो रहा है और हम इस अहम घड़ी में उन्हें नहीं भुला सकते हैं।

राम मंदिर का मॉडल। फाइल फोटो

बिहार में उग्र भीड़ ने दो लुटेरों को पीटकर मार डाला

जासं, सोनबरसा (सीतामढ़ी)

- एक व्यवसायी को लूटकर भाग रहे थे तीन लुटेरे
- लोगों ने खदेड़कर दो को पकड़ा, तीसरा भाग निकला

बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुलिस की सुस्ती से आक्रोशित लोगों ने सोमवार को कानून हाथ में ले लिया। उग्र भीड़ ने एक व्यवसायी को जख्मी करने के बाद रुपये लूटकर भाग रहे तीन बदमाशों को घेर कर पकड़ा। इनमें से दो को भीड़ ने ईंट-पत्थर व लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला। तीसरा किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। उसकी बाइक को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से लुटेरों के पिस्टल की मैग्जीन बरामद की। इसमें तीन गोलियां थीं। लेकिन पिस्टल हाथ नहीं लगी। पिस्टल की तलाश की जा रही है।

सोमवार सुबह करीब 6.20 बजे रामप्रवेश साह दुकान खोलकर बैठे थे। इसी दौरान बिना नंबर की अपाचे बाइक से तीन लुटेरे दुकान पर पहुंचे और पिस्टल की बट से मारकर व्यवसायी को जख्मी कर दिया। इसके बाद रुपये वाला बैग लूटकर बदमाश भागने लगे। रामप्रवेश ने शोर मचाया। होली को लेकर चौक पर चहल-पहल थी। लोग लुटेरों को खदेड़ने लगे। पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो की आवाज सुनकर हाईस्कूल के सामने जुटे लोगों ने आगे से ठेला लगाकर रास्ता रोक दिया। लुटेरे बाइक लेकर वहां गिर पड़े। इसके बाद भीड़ पर पिस्टल तान दी। यह देख लोग ईंट-पत्थर बरसाने लगे। तब तीनों लुटेरे तीन अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे। इस दौरान एक हाईस्कूल के प्रांगण में घिर गया। जहां लोगों ने पीट-पीटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं, दूसरा बस स्टैंड में मारा गया जबकि तीसरा भाग निकला।

एसपी अनिल कुमार ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों की पहचान की जा रही है। घटना में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पोंजी घोटाला : बंगाल में 16, हैदराबाद में एक जगह सीबीआइ ने मारा छापा

नई दिल्ली, एएनआइ : पोंजी स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले की जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने बुधवार को आरोपितों के बंगाल स्थित 16 विभिन्न परिसरों और तेलंगाना में हैदराबाद स्थित एक परिसर पर छापेमारी की।

सीबीआइ अधिकारियों के मुताबिक, 26 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैसर्स अशोक ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों के खिलाफ आइपीसी की धारा- 420, 406, 409 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में उनके बंगाल और तेलंगाना स्थित 16 से ज्यादा परिसरों पर छापे मारे गए। आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों से 20 करोड़ रुपये की जमाएं एकत्रित की थीं। जमाओं की

- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था मामला
- आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों के 20 करोड़ रुपये डकारे

निर्धारित अवधि पूरी होने पर आरोपितों ने भुगतान नहीं किया और निवेश की गई पूरी रकम का गबन कर लिया। सीबीआइ अधिकारियों ने कहा कि ग्रुप की कंपनियां लोगों से जमा एकत्रित करने के लिए अधिकृत नहीं थीं और बहुत ज्यादा ब्याज का प्रलोभन देकर उन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की। आरोपितों ने कथित रूप से मनी सर्कुलेशन स्कीमों का संचालन भी किया और पुराने जमाकर्ताओं को कुछ धनराशि लौटाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें और वे उन्हें ठग सकें।

मल्टी लेवल मार्केटिंग और पोंजी स्कीम से जुड़े एक अन्य मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने एक निजी कंपनी के निदेशकों-प्रमोटरों के बंगाल और कर्नाटक स्थित छह परिसरों पर छापेमारी की।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 26 मई, 2018 को मैसर्स पायस ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी और अन्य निदेशकों-कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 406, 409, 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने उच्च ब्याज दर का प्रलोभन देकर लोगों से 35 करोड़ रुपये एकत्रित किए थे। बाद में उन्होंने लोगों के पैसे नहीं लौटाए और अपना कार्यालय बंद कर दिया। सीबीआइ के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों मामलों में छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

पॉक्सो के आरोपित को सीएम योगी ने कराया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान पॉक्सो के एक आरोपित को गिरफ्तार करा दिया। आरोपित गोरखपुर के गुलरिहा पुलिस की शिकायत लेकर जनता दर्शन में पहुंचा था। डीएम और एसएसपी द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उसे गिरफ्तार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने आरोपित से पीड़ित दो बच्चियों को बालिका संरक्षण गृह में भेजने का भी निर्देश दिया। जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनने के लिए मुख्यमंत्री बुधवार सुबह सात बजे गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम पहुंचे थे। यहां बारी-बारी से फरियादियों की समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री सराय गुलरिहा के रहने वाले रामनारायण गुप्ता तक पहुंचे। रामनारायण ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुलरिहा पुलिस उसे परेशान कर रही है। तभी पास में बैठीं दो नाबालिक अनाथ बच्चियों ने बताया कि रामनारायण उन्हें परेशान करता है। बच्चियों के मुताबिक रामनारायण ने धोखे से उनके मकान की रजिस्ट्री करा ली है, जिससे रिहाइश का संकट खड़ा हो गया है।

डीएम और एसएसपी की जानकारी में यह मामला पहले से था। उन्होंने मुख्यमंत्री को रामनारायण पर पॉक्सो लगाए जाने की जानकारी दे दी। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया। साथ ही डीएम को निर्देश दिया कि वह दोनों अनाथ बच्चियों को बालिका संरक्षण गृह भेजने का इंतजाम करें। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में गोरखपुर और आसपास से आए करीब 150 लोगों की फरियाद सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने अधिकारियों को सक्रियता बरतने की हिदायत भी दी।

ट्रेन से यात्री का बैग चोरी, पीड़ित ने खुद को बताया शाह का भतीजा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद

खुद को गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बता रहे विराज नाम के युवक का बैग अहमदाबाद-लखनऊ एक्सप्रेस से चोरी हो गया। उसमें लैपटॉप, मोबाइल, नकदी व अन्य कागजात थे। बुधवार को फर्रुखाबाद जीआरपी में उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध बैग ले जाते दिख रहा है। विराज ने बताया कि ट्रेन के लखनऊ पहुंचने पर उन्होंने जीआरपी थाने में सूचना दी। वहां से उन्हें फर्रुखाबाद जाने की सलाह देकर टरका दिया गया।

अहमदाबाद के थाना सेटेलाइट क्षेत्र निवासी विराज मंगलवार को अहमदाबाद-लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन की कोच संख्या बी-2 में सवार हुए थे। वह लखनऊ जा रहे थे। फर्रुखाबाद से ट्रेन रवाना होने के बाद उन्होंने देखा तो उनका एक बैग गायब था। इसमें लैपटॉप, नकदी, मोबाइल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडी, आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम और क्रेडिट कार्ड थे। इसी बोगी की सीट नंबर 39 पर यात्रा कर रहे गुजरात के ही रहने वाले एक यात्री ने बताया कि 40 नंबर सीट पर यात्रा कर रहा युवक फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा था। वह उनका बैग ले गया। विराज बुधवार को फर्रुखाबाद जीआरपी थाने आए और खुद को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भतीजा बताया। कुछ देर बाद सदर विधायक मेजर सुनीलदत्त द्विवेदी भी थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर प्लेटफार्म नंबर पांच पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें एक युवक लैपटॉप ले जाते हुए दिखा। विराज ने बैग पहचान लिया। युवक का फोटो साफ नहीं है। जीआरपी प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि बैग की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।

दैनिक जागरण

धैर्य की भी एक सीमा होती है

कांग्रेस को एक और झटका

आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। चूंकि वह राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे इसलिए उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। यदि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार खुद को बचा नहीं सकी तो यह झटका और बड़ा हो सकता है। ज्योतिरादित्य तभी से असंतुष्ट से दिख रहे थे जबसे कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए थे। कमलनाथ ने उनके कुछ समर्थकों को मंत्री अवश्य बनाया, लेकिन वह खुद खाली हाथ रहे। राजनीति में महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत में कमलनाथ के साथ ही दिग्विजय सिंह की भी भूमिका थी। माना जाता है कि प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद न मिलने और राज्यसभा जाने के आसार कम हो जाने के बाद ज्योतिरादित्य का असंतोष और बढ़ गया। शायद इसी असंतोष के चलते उन्होंने बतौर कांग्रेसी नेता अपनी उपलब्धियों पर गौर नहीं किया। जो भी हो, उनके भाजपा में आते ही जिस तरह उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया उससे यह सवाल तो उभरा ही कि कहीं वह येन-केन-प्रकारेण उच्च सदन जाने के लिए आतुर तो नहीं थे?

ज्योतिरादित्य मौकापरस्ती की राजनीति का परिचय देने के आरोप से बच नहीं सकते। उन्हें भाजपा से तालमेल बैठाने में भी मुश्किल हो सकती है। आखिर यह छिपी बात नहीं कि अभी हाल तक वह भाजपा और मोदी सरकार की तीखी आलोचना करने के लिए जाने जाते थे। वैसे उनके कांग्रेस छोड़ने के साथ ही पूरा सिंधिया परिवार भाजपा का हिस्सा बन गया है। ज्योतिरादित्य का भाजपा में आना इसलिए अप्रत्याशित नहीं, क्योंकि उनके पिता माधवराव सिंधिया ने भी जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उनकी दादी विजयाराजे सिंधिया जनसंघ की नेता रहने के साथ ही भाजपा की संस्थापक सदस्य भी थीं। एक तथ्य यह भी है कि ज्योतिरादित्य ने अनुच्छेद 370 हटाने को उचित बताया था। फिलहाल यह साफ नहीं कि ज्योतिरादित्य के भाजपा में जाने के बाद कमलनाथ सरकार का क्या होगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही उठ रहे इस सवाल को ओझल नहीं किया जा सकता कि आखिर एक के बाद एक नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? कांग्रेस नेतृत्व इस सवाल का चाहे जो जवाब दे, इसमें दोराय नहीं कि वह जड़ता और अनिश्चितता से दो-चार है। विडंबना यह है कि कांग्रेस नेतृत्व अपनी दिशा-दशा को लेकर चिंतित नहीं दिखता। किसी को नहीं पता कि कांग्रेस अपने नेतृत्व के सवाल को सुलझाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर इस सवाल को सुलझाया नहीं गया तो कांग्रेस का बिखराव भी थमने वाला नहीं।

मौसम की मेहरबानी

उत्तराखंड के जंगलों पर इस बार मौसम की नेमत बरस रही है। नियमित अंतराल में हो रही बारिश और बर्फबारी का नतीजा है कि 15 फरवरी से फायर सीजन प्रारंभ होने के बावजूद जंगल की आग का कोई मामला सामने नहीं आया है। जंगलों में भरपूर नमी बनी हुई है और आग के लिहाज से फिलहाल जंगल महफूज हैं। निश्चित रूप से यह सुकून की बात है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठा जाए। गर्मी के दस्तक देने पर जंगलों की आग के सिर उठाने का संकट बरकरार है। ऐसे में आगे की तैयारियों को लेकर पूरी गंभीरता के साथ कदम उठाने की जरूरत है। असल में, हर साल ही उत्तराखंड में फायर सीजन यानी 15 फरवरी से मानसून के आगमन तक बड़े पैमाने पर जंगल धधकते हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर तबाह होती है वन संपदा। वन विभाग के 2010 से लेकर 2019 तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो हर साल औसतन करीब दो हजार हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। स्थिति यह रहती है कि जंगलों के धधकने पर बेबस वन महकमा आसमान की ओर ताकता रहता है। इस साल अभी तक के परिदृश्य को देखें तो बदरा खूब बरस रहे हैं। मार्च में भी नियमित अंतराल में वर्षा और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जंगलों में अच्छी-खासी नमी बरकरार है, जिससे फिलहाल वनों को आग का खतरा नहीं है। जिस हिसाब से नमी बनी है और आगे भी वर्षा-बर्फबारी का पूर्वानुमान है, उससे कुछ दिन और सुकून रहने की संभावना जताई जा रही है। अलबत्ता, मई-जून में पारे के उछाल भरने पर जंगलों पर आग का खतरा बना हुआ है। इसे देखते हुए वन विभाग को सिर्फ मौसम पर ही निर्भर रहने की परिपाटी को त्यागना होगा। फायर सीजन के मद्देनजर फायर लाइनों की सफाई का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। करीब 14 हजार किलोमीटर लंबी फायर लाइनों में से अभी करीब छह हजार किमी की सफाई होनी बाकी है। फायर लाइनों की जंगल की आग पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिहाजा, समय रहते फायर लाइनों की तत्काल सफाई कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही अन्य कदम भी उठाए जाने आवश्यक हैं, ताकि आग के लिहाज से किसी भी स्थिति से निबटने को प्रभावी कदम उठाए जा सकें। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम के सुकून के बावजूद वन महकमा सभी ऐहतियाती कदम उठाएगा।

कृषि उत्थान की नई पहल

आशीष चांदोरकर

किसान और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटने का मोदी सरकार का एक और प्रयास है एफपीओ। इनकी सफलता सुनिश्चित की जानी चाहिए

मोदी सरकार ने कुछ समय पहले वादा किया था कि वर्ष 2022 तक वह किसानों की आमदनी दोगुना करेगी। पिछले साल हुए आम चुनाव में यह वादा भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा भी बना। एक ऐसे वक्त में जब भारतीय कृषि तमाम संकट से जूझ रही हो तब किसानों की आमदनी में इस स्तर का इजाफा आसान नहीं लगता। लगातार छोटी होती जा रही जोत के चलते किसान मामूली उत्पादन ही कर पाते हैं। इससे तकनीक में निवेश के लिए कुछ खास नहीं बचता। वहीं बाजार तक पहुंच भी नहीं बन पाती। छोटे किसान खासकर बटाईदारों को अपनी फसल के लिए बड़े खरीदार नहीं मिल पाते। हालांकि उनके पास कृषि उत्पाद विपणन समितियों यानी एपीएमसी के जरिये अपने उत्पाद बेचने का विकल्प होता है, लेकिन बाजार तक यह पहुंच भी सीमित ही है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नैम जैसी पहल की, लेकिन इसमें राज्य सरकारों ने वैसा उत्साह नहीं दिखाया। इसकी एक वजह यही हो सकती है कि राज्यों में मंडी समितियां सियासी वर्चस्व का अखाड़ा बनी हैं। फिर भी ई-नैम के जरिये जो अंतर-मंडी और अंतरराज्यीय व्यापार बढ़ा उसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल जुलाई में आए बजट की एक अहम घोषणा को सिरे चढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उसमें पांच वर्षों के भीतर 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाने का एलान हुआ था। वित्त वर्ष 2020-21 में इसके लिए 6,865 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

जहां तक इस योजना की विधिवत शुरुआत की बात है तो प्रधानमंत्री ने इसी 29 फरवरी को इसका आगाज किया। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को चुना। स्थान का चयन भी कोई संयोग नहीं था। ठीक दो साल पहले नीति आयोग द्वारा देश के सबसे पिछड़े जिलों की जो सूची बनाई गई थी उसमें 101 जिलों में चित्रकूट 75वें स्थान पर था। इन जिलों को विकास के आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। अब प्रत्येक आकांक्षी जिलों के कम से कम एक विकास खंड में एक एफपीओ की स्थापना किए जाने की योजना है।

एफपीओ की यह अवधारणा कोई नई नहीं, बल्कि दशक भर पुरानी है, लेकिन चुनिंदा एफपीओ ही मुनाफे में हैं। तमाम एफपीओ लाभप्रेरित कंपनियों के तौर पर चल रहे हैं और शेष सहकारी संस्थाओं के रूप में। अपने परिचालन को संगठित रूप में चलाना और बड़े खरीदारों को लुभाना उनके लिए अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिर भी यह विचार शानदार है। एफपीओ से यही अपेक्षा है कि वे इनपुट उत्पादों की एकमुश्त खरीद, कृषि से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों एवं सेवाओं की किसानों और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच सुनिश्चित करें, साथ ही समय, अवरोध और लागत को कम करने का काम करें। एफपीओ अपने सदस्यों के लिए कर्ज एवं बीमा के मोर्चे पर भी बेहतर मोलभाव कर सकते हैं। इसी तरह आउटपुट के मोर्चे पर उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे उन्हें उन सदस्यों के लिए गुणवत्तापरक भंडारण एवं परिवहन नेटवर्क विकसित करना चाहिए जो इनका खर्च वहन नहीं कर सकते। पेशेवर क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग से वे गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित कर सकते हैं। एफपीओ अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हैं। वे संस्थागत खरीदारों को सीधे अपना माल बेच सकते हैं जहां तमाम राज्य एकमुश्त खरीदारी की अनुमति देते हैं।

एफपीओ चाहें तो कमोडिटी एक्सचेंज पर सक्रिय होकर कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ भी उठा सकते हैं। एफपीओ कई और तरीकों से भी अपने सदस्यों को लाभ पहुंचा सकते हैं जैसे कि वे एक कारोबार के रूप में कृषि को लेकर सामान्य समझ को और बेहतर बनाएं। उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग अपने अनुभव साझा कर सभी के लिए कारोबारी संभावनाएं बेहतर बना सकते हैं। अब एफपीओ कंपनियों, सहकारी इकाइयों या समितियों के रूप में स्थापित हो रहे हैं। उनके अपने नियम-कायदे होते हैं जिनका संचालन चुना हुआ बोर्ड करता है। किसी कंपनी की भांति संचालन के लिए वे पेशेवरों की भर्ती कर सकते हैं। इसमें उत्साही सामाजिक उद्यमियों और बड़े किसानों को भी साथ लिया जा सकता है, जो छोटे किसानों एवं कृषि विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ें ताकि कृषि को एक कारोबार की तरह चलाया जा सके। भारतीय ग्रामीण तंत्र में इसी नजरिये का अभाव है। कृषि को महज आजीविका के जरिये से एक कारोबार में तब्दील करने के कुछ सामान्य जोखिम हैं, लेकिन ऐसे जोखिम से मिलने वाला प्रतिफल एफपीओ का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है।

पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों में एफपीओ की शुरुआत 300 के बजाय 100 सदस्यों से हो सकती है। प्रत्येक एफपीओ के लिए केंद्र सरकार 15 लाख रुपये का अंशदान देगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की जाएगी। एफपीओ को कर्ज लेने की अनुमति मिलेगी। वहीं 'एक जिला-एक उत्पाद' जैसी योजना चलाने वाले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एफपीओ विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन एवं बिक्री पर जोर देंगे।

एफपीओ स्थापना में तीन एजेंसियां सहायक होंगी। पहली स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (एसएफएसी), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) और तीसरी नाबार्ड। राज्य सरकारों की ऐसी एजेंसियों को भी यह जिम्मा सौंपा जा सकता है। इसमें क्लस्टर आधारित कारोबारी संगठन भी स्थापित किए जाएंगे जो एफपीओ को परिचालन, तकनीक, विपणन और कानूनी सलाह मुहैया कराएंगे। वास्तव में सरकार एसएफएसी के तहत राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन अभिकरण यानी एनपीएमए की स्थापना पर भी विचार कर रही है जो एफपीओ की सफलता के लिए इस ढांचे का प्रबंधन करेगी।

वास्तव में एफपीओ किसानों और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटने का मोदी सरकार का एक और प्रयास है। ई-नैम, ग्रामीण हाट और अपनी सामूहिक मोलभाव की क्षमता से वे मंडी समितियों के प्रभाव को समय के साथ कम कर सकते हैं। देखने वाली बात यही होगी कि इसमें कितना वक्त लगता है? भारतीय ग्रामीण संकट को स्थायी समाधान चाहिए। भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान मात्र 15 प्रतिशत है, लेकिन देश की 60 फीसद आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी पर निर्भर है। देश को समृद्ध बनाने के लिए इस असंतुलन को दूर करना जरूरी है। ऐसे में सरकार सुनिश्चित करे कि एफपीओ के जरिये वह जो पहल करने जा रहा ही, उसमें सफलता मिले।

(लेखक नीति विश्लेषक एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

कांग्रेस से क्यों छिटके ज्योतिरादित्य

रशीद किदवई

ज्योतिरादित्य को यह महसूस होने लगा था कि राहुल और सोनिया कांग्रेस को बदलने में असमर्थ हैं

ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर जाना केवल राजनीतिक मौकापरस्ती नहीं, बल्कि गांधी परिवार से प्रतिस्पर्धा की भावना का भी नतीजा है। भाजपा में शामिल होते वक्त उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। कुछ समय पहले जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था तो सिंधिया उन कांग्रेसी नेताओं में प्रमुख थे जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं न कहीं अपने आप को राहुल गांधी से अधिक सक्षम मानते हैं और इसे वह देश के समक्ष प्रदर्शित भी करना चाहते हैं। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया बचपन से एक ही स्कूल-दून स्कूल में गए। इसके बाद दोनों सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आए। दोनों ही बीच में अपनी पढ़ाई छोड़कर विदेश चले गए और आगे की पढ़ाई अमेरिका में की। इसके बाद दोनों ही तकरीबन एक साथ ही सक्रिय राजनीति में आए। ज्योतिरादित्य अपने पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद 2001 में राजनीति में सक्रिय हुए और राहुल गांधी 2003 में। इसके बाद ज्योतिरादित्य टीम राहुल के एक सक्रिय सदस्य बन गए। राहुल मनमोहन सरकार का हिस्सा नहीं बने तो ज्योतिरादित्य भी शुरुआती दौर में मंत्री नहीं बने। गौरतलब यही है कि जहां राहुल स्वेच्छा से मंत्री नहीं बने वहीं सिंधिया मन मसोस कर मंत्री बने।

ज्योतिरादित्य को राहुल गांधी का अक्खड़पन अव्यावहारिक लगता रहा, किंतु मित्रता और शिष्टता के चलते वह अपनी भावनाएं व्यक्त नही कर सके। 2015 से 2019 के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी को और सक्रिय होने को कहते रहे, लेकिन राहुल कांग्रेस के अंदर के समीकरण और चक्रव्यूह को पार नहीं कर सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के चुनाव में बहुत जोश में थे और वह प्रियंका गांधी के साथ एक टीम बनाकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का नतीजा बहुत ही निराशाजनक रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही प्रभारी थे। इससे अधिक निराशाजनक यह रहा कि खुद सिंधिया अपना लोकसभा चुनाव भी हार गए। वह पहली बार अपना खुद का चुनाव हारे। सिंधिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वह गुना से चुनाव हार जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में सक्रियता के चलते वह अपने क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे सके। वह पत्नी और बेटे के भरोसे चुनाव लड़े। वह चुनाव हारे एक ऐसे आदमी से जो एक समय उनका संसदीय प्रतिनिधि था। उन्होंने उसे विधानसभा के लिए टिकट नहीं दिलाया था इसलिए वह उनसे अलग हो गया था। यह चुनावी हार सिंधिया के दिल और दिमाग पर गहरा असर कर गई। राहुल और सोनिया गांधी सिंधिया की मनःस्थिति समझ नहीं सके। यहीं से ज्योतिरादित्य भावनात्मक रूप से कांग्रेस से अलग होते गए। मध्य प्रदेश की राजनीति और खासकर कमलनाथ की अनदेखी ने आग में घी डालने वाला काम किया। कमलनाथ का वह बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सिंधिया चुनावी वादों को लागू कराने के लिए अगर सड़क पर उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं।

ज्योतिरादित्य को यह महसूस होने लगा था कि राहुल और सोनिया गांधी कांग्रेस को बदलने में असमर्थ हैं और पार्टी में सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। वह इस नतीजे पर भी पहुंचे कि युवाओं को कांग्रेस में अपनी जो जगह बनानी है वह आने वाले समय में नहीं बनने वाली और कांग्रेस भी भारतीय राजनीति में अपनी सही जगह बनाने में असमर्थ है। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया। उनके साथ उनके समर्थक माने जाने वाले कई विधायक भी कांग्रेस छोड़ने को तैयार हैं। इन विधायकों के कांग्रेस छोड़ने के कारण ही कमलनाथ सरकार संकट में है।

ज्योतिरादित्य अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया को अपना रोल मॉडल मानते रहे हैं। राजमाता का कांग्रेस से एक लंबा संघर्ष रहा। आपातकाल में राजमाता जेल में रहीं। यह एक ऐसा इतिहास का पन्ना है जिसे पलटते हुए सिंधिया परिवार को यह लगता था कि इंदिरा गांधी ने साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग करते हुए सिंधिया परिवार को नीचा दिखाया।

यह उल्लेखनीय है कि सिंधिया परिवार को राजनीति में लाने का काम खुद जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जब गांधी जी की हत्या के बाद देश के पहले आम चुनाव हो रहे थे तब नेहरू ने फैसला लिया कि सिंधिया परिवार को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने जीवाजीराव महाराज को संदेश भेजा कि वह चुनाव में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में ग्वालियर से चुनाव लड़ें। सिंधिया परिवार का झुकाव हिंदू महासभा की ओर था और कांग्रेस से चुनाव लड़ना उनके लिए कठिन निर्णय था। यह उस दौर की बात है जब गांधी हत्याकांड में तरह-तरह की बातें कही जा रही थीं। एक पिस्तौल का जिक्र हो रहा था जो कथित तौर पर ग्वालियर से आई थी। इसी माहौल में राजमाता दिल्ली गईं और नेहरू से मिलीं। नेहरू ने उनका परिचय इंदिरा गांधी, शास्त्री और गोविंद बल्लभ पंत से कराया और उन्हें सक्रिय राजनीति में आने को प्रोत्साहित किया। राजमाता कांग्रेस के लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में 1957 और 1962 में चुनाव जीतीं, लेकिन फिर उनके डीपी मिश्र से संबंध खट्टे हो गए और वह फिर भारतीय जनसंघ की तरफ चली गईं। 1967 का चुनाव उन्होंने जनसंघ से ही लड़ा। उस समय मप्र के कांग्रेसी मुख्यमंत्री डीपी मिश्र की भूमिका वही रही जो अभी सिंधिया कमलनाथ की देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य के पिता माधवराव भी 1971 में पहला चुनाव जनसंघ से लड़े थे। बाद में वह कांग्रेस में शामिल हो गए।

(लेखक ओआरएफ के फेलो एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन एक परीक्षा

परीक्षा का नाम सुनते ही एक असहज करने वाला भय परेशान करने लगता है। हमें बाल्यकाल से ही ऐसा बना दिया जाता है कि बड़े होने पर हम परीक्षा को सिर्फ परिणाम की दृष्टि से देखने लगते हैं। परीक्षा होने से परिणाम का आना एक प्रक्रिया है, किंतु परिणाम के प्रति अत्यधिक भय जीवन में हमारे सीखने की प्रक्रिया के आनंद को खत्म कर देता है। जीवन में शिक्षा का उद्देश्य भय, चिंता, बेचैनी, तनाव और अवसाद इत्यादि स्थितियों से साक्षात्कार करवाना कदापि नहीं होता है। हम स्वयं सीखने की प्रक्रिया को परिणाम के अर्थों में लेकर ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। नतीजे की चिंता को लेकर भय, तनाव, अवसाद आदि हमारे द्वारा ही निर्मित की जाने वाली स्थितियां होती हैं।

आज योग्यता का पैमाना अच्छी शिक्षा होती है। शिक्षा ही रोजगार, पारिवारिक प्रतिष्ठा, धन और वैभव आदि सुनिश्चित करती है। इन समस्त परिणामों को लेकर हम इतने चिंतित रहते हैं कि सीखने के आनंद को भुला बैठते हैं। सफलता के लिए प्रयास तो सिखाया जाता है, किंतु असफलता को स्वीकार करते हुए पुनः प्रयास करने के विषय में बताया ही नहीं जाता जो कि बहुत आवश्यक है।

सबसे जरूरी है कि हम सिर्फ अपना श्रेष्ठ करते जाएं। यह जीवन अनवरत चलने वाली एक यात्रा है जिसमें हर दिन हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस अध्ययन यात्रा को सीखने के आनंद के तौर पर ग्रहण करेंगे तो सफलता और असफलता, इन दोनो ही स्थितियों को हम स्वीकार कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि पहले प्रयास में लक्ष्य हासिल हो ही जाए, किंतु पहली असफलता अयोग्य साबित भी कतई नहीं करती है। पहली बार की नाकामी यह साबित नहीं करती कि हम सफल नहीं हो सकते, वह तो बस हमें अपनी कमजोरियों से परिचित कराती है। बताती है कि हम क्यों सफल नहीं हुए। बस जरूरत उन कमियों को पहचान पुनः प्रयास की होती है।

सौरभ जैन

चौतरफा चुनौतियां बढ़ाता कोरोना

विजय कपूर

जिन देशों के पास चीन जैसी प्रशासनिक मशीनरी और राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, वे कोरोना के कोप से कैसे बचें?

चीन से निकला कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है। इसे लेकर तमाम भ्रांतियां भी फैल रही हैं, लिहाजा उन्हें दूर किया जाना भी बेहद जरूरी है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय यही है कि इससे संक्रमित व्यक्ति को दूर ही रखा जाए ताकि वह अपने साथ दूसरे लोगों को भी अपनी चपेट में न ले।

बहरहाल चीन इस परंपरागत नियंत्रण के तरीके से भी आगे निकल गया है। वह कोर्डन सैनिटेयर को अपना रहा है, जिसका अर्थ यह है कि एक क्षेत्र को इस प्रकार बंद कर दिया जाए कि न कोई उसके भीतर जा सके और न कोई उससे बाहर आ सके। मुश्किल यही है कि अधिकांश देशों में यह योजना कारगर साबित नहीं होगी, खासकर जब अवधि लंबी और जनसंख्या भी अधिक हो। कम ही देशों के पास इसके लिए पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी ओर यह वायरस वक्त के साथ और विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसके कारण किसी स्थान पर फंसने के कारण पैदा होने वाला डर बहुत भयानक होता है। इससे चिंता व तनाव कई गुना बढ़ जाते हैं। हल्की सी खांसी, सर्दी या बुखार से भी अफरातफरी फैल जाती है। बहरहाल इसकी मानवीय व आर्थिक कीमत चाहे जो हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीन की इस योजना से वायरस के फैलने की गति बहुत धीमी हुई है। यह धीमी गति चीन के भीतर भी है और वैश्विक स्तर पर भी।

फिलहाल इस वायरस का असर लगभग 72 देशों में देखने को मिल रहा है। भारत में भी लगातार इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। भारत इस समस्या से कैसे निपटेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिन देशों के पास चीन जैसी प्रशासनिक मशीनरी व राजनीतिक नियंत्रण नहीं है, वे इसे रोकने के लिए क्या करें? इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि नियमित योग करने से कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि योग की भारतीय परंपरा से व्यक्ति मानसिक व शारीरिक तौर पर फिट रहता है और इस प्रकार वह योग से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, गुर्दे फेल होना या कोरोना वायरस से बचा रहता है। इस प्रकार के विचारों से हमारा मखौल उड़ना स्वाभाविक ही था, लेकिन अफसोस यह है कि इन विचारों पर अभी भी विराम नहीं लगा है।

अब जब हाल में ही एक और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस गुजरा है तो समय आ गया है कि हम उन सोशल मीडिया मैसेजों को फॉरवर्ड करना बंद कर दें जो गोमूत्र या योग से कोरोना वायरस के उपचार का दावा करते हैं। वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक पर उतनी ही है, जितनी सरकार और विभिन्न संबंधित एजेंसियों की। लिहाजा इस बारे में संजीदगी अपनाने की जरूरत है। तभी हम इस आपदा से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। - ईआरएस

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

मेलबाक्स

बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल

बैंकिंग तंत्र के लिए खतरा शीर्षक से लिखे आलेख में भरत झुनझुनवाला ने देश की बैंकिंग प्रणाली की कमियों का विश्लेषण किया। लेखक ने माना कि हाल ही में जो यस बैंक के घाटे और गड़बड़ी ने बैंकिंग प्रणाली को कटघरे में खड़ा किया, उस कारण अन्य बैंकों की साख पर आंच नहीं आएगी, लेकिन लेखक यह क्यों भूल गए कि दूध का जला छाछ को भी फूक-फूक कर पीता है, यस बैंक के मामले से अब लोगों का विश्वास बैंकों से जरूर कम हुआ होगा। मोदी सरकार ने देश में कालेधन पर प्रहार करने के लिए नोटबंदी का कड़वा फैसला तो ले लिया था, लेकिन शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहां तो चिराग तले ही अंधेरा है। जिस देश में भ्रष्टाचार की जहरीली जड़ें काफी गहराई तक जा चुकी हैं उस देश के बैंकों में घोटाला होना कोई हैरत की बात नहीं है। मोदी सरकार ने जब अपनी पहली पारी में नोटबंदी का फैसला लिया था, तब भी कुछ बैंकों में हेराफेरी की खबरे सामने आई थी, मोदी सरकार ने अगर उन खबरों पर गंभीरता दिखाई होती तो आज बैंकों में एक बार फिर से गड़बड़ घोटाले कि खबरें न आती। बैंक अधिकारियों से पहले सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सरकार क्यों नहीं गड़बड़-घोटाले रोकने के लिए सख्त कानून बनाती? क्यों बार-बार बैंकों में गड़बड़ घोटाले हो रहे? रिजर्व बैंक क्यों नहीं बैंकों की कार्यप्रणाली पर सख्ती से नजर रखता? बैंकों में बार-बार होने वाली अनियमितताएं यह भी इशारा करती हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि सारी दाल ही काली है? इस स्थिति को बदलना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बैंकों का फेल होना

यस बैंक की आड़ में अर्थव्यवस्था को तबाह करने का आरोप मोदी सरकार पर लगाने वाले मनमोहन सिंह भूल रहे हैं कि उनके समय में कितने बैंक बंद हुए थे। उनके पहले कार्यकाल के 5 वर्षों में निजी क्षेत्र के 11 बैंकों का भट्ठा बैठा था। यही नहीं 2008-2009 के दौरान 19 सहकारी बैंक भी दिवालिया हुए। इतने बैंको के बंद होने का का एकमात्र कारण सत्ता के दबाव में बांटे गए वे अनुचित ऋण थे, जो शीघ्र ही एनपीए हो गए। यस बैंक के डूबने की वजह भी 2014 तक दिए गए अपात्र ऋण ही हैं, किंतु मोदी सरकार ने स्टेट बैंक के माध्यम से स्थिति बहुत जल्द काबू कर ली। डेढ़ वर्ष से यस बैंक को सरकार और रिजर्व बैंक चेता रहे थे। उस पर जुर्माने भी किए गए थे, पर बैंक-प्रबंधन लापरवाह या यूं कहिए कि अपराध-सहभागी बना रहा और चेतावनियां अनसुनी करता रहा। अब भारत से भाग जाने की जुगत में था, जो वित्त मंत्रालय ने असफल कर दिया।

पूनम मित्तल, मोहनपुरी, मेरठ

कोरोना का मंडराता खतरा

कोरोना वायरस का खतरा दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। इलाज के अभाव में पूरी दुनिया इसके समक्ष बेबस सी नजर आ रही है। यदि देखा जाए तो अपने देश में जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं, वो सब या तो विदेश से घूम कर आए थे या वहां वे लोग पढ़ रहे थे या फिर विदेश में कोई काम धंधा कर रहे थे। भारत में लोग बिना वजह इस रोक के शिकार बन रहे हैं। विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना जांच कराए बाहर नहीं जाना चाहिए। लापरवाही भारी पड़ सकती है।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

भरोसा तोड़ता दलबदल

मध्यप्रदेश में दल बदल की राजनीति लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। इसके पहले कर्नाटक में भी इसी तरह से कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। वहीं अनेक राज्यों में चुनाव बाद के गठबंधन और सत्ता के लिए विधायकों को लालच देने की परिपाटी लोकतंत्र और आम जनता के लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकती है। सत्ता हासिल करने के लिए जोड़ तोड़कर सरकार गिराने से जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ होता है। पक्ष-विपक्ष को सत्ता हथियाने के लिए दल बदल की राजनीति से दूर रहना चाहिए। लोकतंत्र में जनता द्वारा दिए गए बहुमत का सम्मान करते हुए विधायकों को भी पार्टी बदलने से परहेज करना चाहिए।

skcbe9@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

70 रुपये अलग से रखना यानी प्रोविजनिंग आवश्यक है प्रत्येक सौ रुपये के डूबे कर्ज के लिए बैंकों को, भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार। इसे पीसीआर यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहते हैं।

भुवन भास्कर
आर्थिक मामलों के जानकार

आजकल

यस बैंक ने पैदा किया साख का संकट

कोरोना वायरस का कोई मरीज यदि अपनी खांसी-सर्दी-बुखार के हर संकेत को मामूली वायरल बताते हुए डॉक्टर के पास जाने से इन्कार कर दे तो इसका नतीजा क्या होगा? इससे और भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। हो सकता है कि जब तक बीमारी अपने भयावह रूप में जाहिर होकर पहचानी जाए, तब तक देर हो चुकी हो और कुछ जानें भी चली जाएं। एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर यस बैंक के पराभव को कोरोना वायरस के इस प्रतीक से समझा जा सकता है

प्रतीकात्मक।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच मार्च को जब यस बैंक के बोर्ड के अधिकारों को निरस्त कर उसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया, उसके बहुत पहले यानी चार साल पहले से यस बैंक की बैलेंस शीट में अनियमितता होने के तमाम संकेत सामने आने लगे थे। लेकिन बैंक के कर्ता-धर्ता राणा कपूर ने न केवल इन संकेतों को नकारा, बल्कि निवेशकों और नियामक रिजर्व बैंक से इसे छिपाने की तमाम कोशिश करते हुए बही-खाते में गड़बड़ी करने से भी नहीं चूके।

शंका के दायरे में रही बैंक के प्रदर्शन में तेज बढ़ोतरी : आम लोगों के लिए इस आशंका की सबसे स्पष्ट चेतावनी सात जुलाई 2015 को सामने आई, जब वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी यूबीएस ने यह आशंका जताई कि यस बैंक के लोन बुक में सबसे तेज बढ़ोतरी उन कंपनियों के कारण आई है जिनकी आर्थिक हालत बेहद खराब है। यूबीएस ने साफ शब्दों में कहा कि यदि दिए गए कमजोर कर्ज का चक्र लंबे समय तक चला तो यस बैंक खतरे में आ सकता है। इसी आधार पर उसने बैंक के शेयरों की साख घटाते हुए निवेशकों के लिए उसे बेचने की सलाह जारी की। यूबीएस की 2015 में दी गई इस चेतावनी का अपना एक इतिहास है जिसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों में यस बैंक के दो में से एक प्रमोटर अशोक कपूर की हत्या हो गई थी जिसके बाद से बैंक का प्रबंधन पूरी तरह राणा कपूर के हाथों में आ गया। फिर शुरू हुआ कर्ज देने का सिलसिला। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उलटा, किसी भी कंपनी के प्रबंधन के लिए यह अच्छा है कि वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मेहनत करे। राणा कपूर ने कंपनी की बागडोर पूरी तरह संभालने के बाद मेहनत की और उसके नतीजे भी आने लगे। महज पांच साल पहले अस्तित्व में आए एक निजी बैंक का बही-खाता तेजी से बढ़ने लगा और अगले एक दशक में यानी रिजर्व बैंक के यस बैंक के बोर्ड को भंग कर उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेने तक यह पांचवां सबसे बड़ा निजी बैंक बन चुका था। फिर गड़बड़ कहां हुई? आखिर तेज गति से बढ़ता बैंक क्यों पटरी से उतर गया, क्यों 2015 में यूबीएस को यस बैंक की साख डाउनग्रेड करनी पड़ी, क्यों अगस्त 2018 में रिजर्व बैंक को राणा कपूर को यस बैंक से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा और फिर क्यों आखिरकार बीते पांच मार्च को इसका बोर्ड भंग करना पड़ा?

वर्ष 2008 से 2018 तक की कारोबारी यात्रा : इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक बार फिर 2008 से 2018 तक की यस बैंक की कारोबारी यात्रा के सूत्र तलाशने की जरूरत है। इस दौरान यस बैंक की ओर से दिए गए कारोबारी कर्जों का विवरण देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेक्टर को 10,366 करोड़ रुपये, स्टील सेक्टर को 10,810 करोड़ रुपये, निर्माण सेक्टर को 35,218 करोड़ रुपये और बिजली सेक्टर को 21,710 करोड़ रुपये के ऐसे कर्ज दिए गए जिनके लिए पर्याप्त गारंटी या गिरवी नहीं रखा गया। यह जानना रोचक है कि 2008 के संकट के बाद से ही दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती का जो माहौल है, उसमें बड़ी से बड़ी कंपनियां भी बैंकों से कर्ज लेने से बच रही हैं, क्योंकि उन्हें सुस्त पड़ी मांग के उठने का भरोसा नहीं है और इसलिए वे कोई नया निवेश करना नहीं चाहते। तो जाहिर है कि उन्हें किसी कर्ज की जरूरत भी नहीं है और इसलिए बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ भी सुस्त पड़ा है। लेकिन यस बैंक पर इस वैश्विक माहौल का कुछ खास असर नहीं दिखा। यहां तक कि 2016-17 के आखिर में बैंक के पास 1.32 लाख करोड़ का जो लोन बुक था, वह 2018-19 में बढ़कर 2.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2019 तक के स्टेटमेंट के मुताबिक यस बैंक ने कुल 3.79 लाख करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर बांटे थे जिसमें सिर्फ चार प्रतिशत कर्ज के बदले ही गारंटी रखी गई है। कंपनियों की लिस्ट देखी जाए यस बैंक के कर्जदारों में कंपनियां शामिल हैं जो या तो दिवालिया हो चुकी हैं या जिन पर दिवालिएपन की तलवार लटक रही है। इनमें आइएलएंडएफएस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आदि शामिल हैं।

प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो : यस बैंक की दूसरी समस्या यह थी कि उसने बहुत ऊंची दरों में फंड जुटाया था। यस बैंक जिस तरह ज्यादा ब्याज दर देकर जमा एकत्रित कर रहा था, उसी तरह ऐसी कंपनियों को ज्यादा ब्याज दरों पर कर्ज बांट रहा था जिनका वित्तीय प्रबंधन पहले से ही सवालों के घेरे में था। डूबे कर्ज का अनुपात तेजी से बढ़ने पर यस बैंक के प्रबंधन ने अपना मुनाफा गिरने से बचाने के लिए बही-खाते में गड़बड़ी शुरू की। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक हर 100 रुपये के डूबे कर्ज के लिए बैंकों को कम से कम 70 रुपये अलग रखना यानी प्रोविजनिंग आवश्यक है। इसे पीसीआर यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो कहते हैं। यह 70 रुपये बैंक के मुनाफे में से निकाल कर रिजर्व में रख दिए जाते हैं। जाहिर है इससे बैंक का मुनाफा कम होता है, जिससे उसकी आय प्रति शेयर घटती है और इसका सीधा असर उसके शेयर भाव पर पड़ता है। तो शेयरों का वैलुएशन ऊंचे स्तर पर रखने के लिए यस बैंक ने 2018-19 के दौरान महज 43.1 प्रतिशत पीसीआर रखा, जबकि इस साल आइसीआइसीआइ बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई का पीसीआर क्रमशः 70.6, 71.36, 77, 71.9 और 78.73 प्रतिशत था। बढ़ते एनपीए के कारण बैंक की मुनाफा कमाने की क्षमता, जिसे रिटर्न ऑन एसेट से मापा जाता है, साल दर साल गिरती जा रही थी। साल 2017-18 में जहां बैंक अपने हर 100 रुपये की परिसंपत्ति पर 1.78 रुपये मुनाफा कमा रहा था, वहीं 2018-19 में यह अनुपात घट कर 52 पैसे पर आ टिका। नतीजतन बैंक ग्राहकों और निवेशकों, दोनों का ही भरोसा खोने लगा। वर्ष 2014-15 में जहां इसका कर्ज-जमा अनुपात 77 प्रतिशत के आसपास था, वहीं 2018-19 के बीच यह बढ़ता हुआ 106 प्रतिशत हो गया। यानी बैंक में जहां 100 रुपये जमा हो रहे थे, वहीं यह 106 रुपये से ज्यादा कर्ज दे रहा था। परिणामस्वरूप शेयर बाजार में बैंक के शेयर फिसलते गए और 20 अगस्त 2018 को 394 रुपये की ऊंचाई पर बंद हुए शेयर मार्च 2020 में 16-20 रुपये तक लुढ़क गए।

रिजर्व बैंक के अनिर्णय का परिणाम

वर्तमान परिस्थितियों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब यस बैंक के ग्राहकों और निवेशकों को आने वाला संकट दो साल पहले ही दिख गया था तो फिर रिजर्व बैंक की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी रही? दरअसल यह कहना सही नहीं होगा कि रिजर्व बैंक ने यस बैंक के मामले की अनदेखी की। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक अनिर्णय का शिकार हुआ। राणा कपूर की रीति-नीति और यस बैंक के कामकाज को निकट से देखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि अगस्त 2018 में कपूर को हटाए जाने के लिए 31 जनवरी 2019 तक की समयसीमा तय करना रिजर्व बैंक के लचर प्रशासनिक फैसले का एक उदाहरण है। कपूर ने जिस तरह यस बैंक की बैलेंस शीट को कमजोर किया था, उसमें गड़बड़ी की थी और कई आवश्यक जानकारियां छिपाने की कोशिश की थी, उसे देखते हुए बहुत पहले उनकी विदाई हो जानी चाहिए थी। रिजर्व बैंक की नाक के नीचे घटिया बैलेंस शीट वाली कंपनियों को यस बैंक कर्ज देता रहा, उसके एनपीए में बढ़ोतरी होती रही, उनका पीसीआर रिजर्व बैंक द्वारा तय सीमा से बहुत नीचे चलता रहा और रिजर्व बैंक को हस्तक्षेप की जरूरत महसूस नहीं हुई, यह आश्चर्यजनक है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में यस बैंक ने पहली बार एनपीए को कारण बताते हुए घाटा दर्ज किया। एनपीए का अनुपात बढ़ता हुआ 10 प्रतिशत के पार पहुंच गया और रिजर्व बैंक का धैर्य तब टूटा जब अक्टूबर-दिसंबर 2019 के तिमाही नतीजे जारी करने में यस बैंक की ओर से देरी की जाने लगी। कई विशेषज्ञों ने अनुमान जताया कि बैंक का वास्तविक एनपीए 30 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया है। यह एक ऐसा भयानक आंकड़ा है, जिसके सच साबित होने की स्थिति में यस बैंक का भी आइएलएंडएफएस की गति को प्राप्त होना तय था। पहले से ही सुस्ती झेल रहे भारतीय आर्थिक ढांचे के लिए पांचवें सबसे बड़े निजी बैंक का धराशायी होना एक ऐसी परिस्थिति होती जिसे संभालना सरकार और आरबीआइ के लिए बहुत मुश्किल होता। इसीलिए आखिरकार रिजर्व बैंक ने एक ऐसा कदम उठाया जो अपने आप में असाधारण है। नियामक को यह भी पता है कि यदि तीन जुलाई से पहले जमाकर्ताओं में यह भरोसा नहीं बैठाया गया कि यस बैंक में जमा उनकी रकम सुरक्षित है तो उसमें जमा करीब दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निकालने की होड़ मच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो यस बैंक ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग तंत्र के लिए इस झटके को झेल पाना कठिन होगा। इसीलिए बिना समय गंवाए रिजर्व बैंक और सरकार ने मिलकर भारतीय स्टेट बैंक को यस बैंक की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार कर लिया है। इसके लिए एसबीआइ 10 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यस बैंक के दो रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर खरीदेगा और इस तरह उसमें करीब 12,000 करोड़ रुपये निवेश करेगा। लेकिन यस बैंक को बचाने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपयों की तुरंत जरूरत है। ऐसे में 18,000 करोड़ रुपये की शेष रकम की व्यवस्था करना अब एसबीआइ की जिम्मेदारी है। रिजर्व बैंक और सरकार को भरोसा है कि एसबीआइ जैसे विश्वसनीय नाम के यस बैंक से जुड़ जाने से निवेशकों की तलाश आसान होगी। पर इस घोषणा के बाद एसबीआइ के शेयरों में आइ एक दिन में 10 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट यह समझने के लिए काफी है कि सरकार और रिजर्व बैंक के लिए अभी चैन से बैठने का समय नहीं आया है। और यदि यह मान भी लिया जाए कि यस बैंक को बचा लिया जाएगा तो असल चुनौती भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और यस बैंक के असली गुनहगारों को कानून के शिकंजे में लाने की होगी।

खरी-खरी

'हरे चारे' की मंडी में बिकते बे-चारे घोड़े

राजेश सेन

मंडी में घोड़ा मुंह लटकाए खड़ा है। कोई उसकी हुंकार सुन ही नहीं रहा। सहसा वह रस्सी तोड़ने के लिए हिनहिनाने लगता है। उधर, घोड़े का 'नामालूम-मालिक' और 'जबरिया-खरीदार' आपस में झगड़ने लगते हैं। मालिक बोलता है- हमारा घोड़ा कोई बिकाऊ नहीं है। खरीदार कहता है- सौदे की मंडी में आकर खड़ा होने वाला हर घोड़ा बिकाऊ ही होता है।

मालिक- किंतु आप मेरे घोड़े को इस तरह बरगला नहीं सकते।

खरीदार- यह पूरी मंडी इसी बात पर तो टिकी है कि कौन कितना बरगलाने में कुशल है।

मालिक- लेकिन जब एक बार घोड़े हमारे अस्तबल में बंध चुके, तो फिर आप उन्हें घास क्यों डाल रहे हैं?

खरीदार- ये तो आप अपने घोड़े से ही पूछ लीजिए?

मालिक- घोड़े से क्या पूछना? उसे तो घोड़ा हमने बनाया, वरना गधा था वो। हमने उस पर दांव लगाया, उसका रंगरोगन करवा घोड़ा बनाया। उसकी क्या औकात कि खुद बिकने लगे?

खरीदार- लेकिन मंडी में लोकतंत्र लागू है और लोकतंत्र में चुना हुआ घोड़ा तो खुद का मालिक होता है।

मालिक- मेरा घोड़ा अबोध है! आप उसे बहला रहे हैं!

खरीदार- मगर उसकी आत्मा अबोध नहीं। वह बाजार में फायदे के हिसाब से बिकना चाहता है!

मालिक- आत्मा को खुद बिकने का अधिकार नहीं होता। उसे बेचना पड़ता है। आप जानते ही हैं सब।

खरीदार- हां, वो तो है, लेकिन घोड़े की आत्मा को बंधक बनाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है।

मालिक- घोड़ा हमारा है। वह हमारे आदेश का लोकतंत्र-खरीद गुलाम है।

खरीदार- आप उसे 'हरा चारा' नहीं खिला रहे, इसलिए उसकी आत्मा जाग उठी है। वह मुक्ति चाहता है।

मालिक- अरे, 'हरा चारा' हम खाएं कि उनको खिलाएं? चारा सीमित है और घोड़े-गधे बहुत हैं।

खरीदार- तभी तो हम उसे होटल ले जा रहे हैं। वहां उससे पक्का करेंगे कि उसे कितना चारा खिलाने वाले हैं।

मालिक- लेकिन हमारे घोड़े में इतनी नैतिकता है कि वह अपने मालिक की वफादारी ही करेगा।

खरीदार- अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

ट्वीट-ट्वीट

इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता है कि कांग्रेस आलाकमान ने कभी भी गांधी-नेहरू परिवार से इतर किसी भी लोकप्रिय युवा नेता को उभरने नहीं दिया। दरअसल उन्हें यह असुरक्षा घेरे रही कि इससे राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेंगे।

यशवंत देशमुख@YRDeshmukh

बड़ी बेशर्मी से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पूरा मुल्क देख रहा है। इतनी बेशर्मी से हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ये पता नहीं देश को कहां ले जाएंगे... जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं वो सबके सामने है। पूरा देश देख रहा है और समय आने पर इनको सबक सिखाएगा।

अशोक गहलोत@ashokgehlot51

भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। इसमें तीन प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से आए हैं। भुवनेश्वर कलीता कांग्रेस से आए। उदयन राजे एनसीपी से और ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो आप जानते ही हैं।

रूबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

कुछ लोग नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि दिल्ली में दंगों पर चर्चा के बजाय वह नेहरू और कांग्रेसी राज में हुए दंगों पर चर्चा कर रही है। ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि दंगों पर बात करते हुए आपकी सुई भी तो अक्सर वर्ष 2002 पर अटक जाती है।

अद्वैता काला@AdvaitaKala

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जम्मू-कश्मीर में नए राजनीतिक दलों की स्थापना से राज्य का सियासी परिदृश्य बदलेगा?

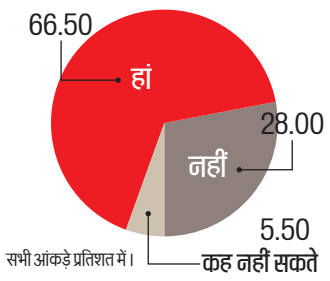

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ज्योतिरादित्य के कांग्रेस छोड़ने से कमलनाथ सरकार का अस्तित्व संकट में पड़ गया है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

सोचो-सोचो क्यों हुए वह इतने नाराज,
गए छोड़कर पार्टी आखिर क्यों महराज ?
आखिर क्यों महराज 'कमल' क्यूं उनको भाया,
कमलनाथ का साथ उन्हें क्यूं रास न आया??
मचती भगदड़ देख खोपड़ी अपनी नोचो,
दिल पर रखकर हाथ पतन पर अपने सोचो!

- ओमप्रकाश तिवारी

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश डायरी

फर्जी डिग्रियों की बुनियाद पर कैसी इमारत

यह हिलती हुई बुनियाद की पुकार सुनने का समय है। बुनियाद जीवन की...। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में पहले दवाइयों पर सवाल उठे, अब शिक्षा जगत में कुछ तत्वों के खिलाए गए गुल शर्म का विषय बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अब फर्जी डिग्रियों के कारण चर्चा में है। प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करता हरियाणा का एक व्यक्ति इतना प्रयोगधर्मी निकला कि बीस वर्षों में उसके दो विश्वविद्यालय शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश व राजस्थान में। फर्जी डिग्रियां बेचने का धंधा इतना चमकाया कि अब पुलिस तलाश रही है।

शिक्षा क्षेत्र में राज्य पहले भी चर्चा में आ चुका है जब करोड़ों का छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। नए मामले की भी जांच जारी है, लेकिन जांच की सीमा है कि जिस हिस्से में तकलीफ हो, उसी की होती है। जिस दिन हिमाचल प्रदेश में ईमानदार प्रयास शुरू हो जाएंगे, नीति नियंताओं और कार्यकारी अधिकारियों के जमीर जिस दिन जाग जाएंगे, उस दिन बहुत कुछ निकलेगा। अच्छा भवन उस दिन सुनिश्चित होगा जिस बुनियाद में मक्कारी का मसाला नहीं भरा जाएगा।

मानव भारती विश्वविद्यालय के बाद इंडस विश्वविद्यालय पर भी मामला दर्ज हुआ है। मजे की बात यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चेताए जाने और हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की चिट्ठी के बावजूद वीरभद्र सिंह सरकार चुपचाप बैठी रही। क्या यह प्रभाव था? अब जबकि जयराम सरकार के अधीन कार्रवाई हो रही है तो काफी कुछ निकलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने इससे जुड़े बयान में निष्पक्ष जांच के इरादे जाहिर कर दिए हैं। सवाल यह है कि एक जिम्मेदार संस्थान के पत्र पर कार्रवाई करने के लिए पौने तीन साल क्यों लग गए? तबका सत्ता पक्ष तो निद्रा में था, विपक्ष (अब पक्ष) ने शोर क्यों नहीं मचाया? अब भी फर्जी दवाइयों पर विपक्ष की चुप्पी समझ से बाहर है। विपक्ष का काम क्या यह है कि फॉर्च्युनर गाड़ी पर बवाल करना और खुद सत्ता पक्ष में रहते हुए उसी गाड़ी के इस्तेमाल के रास्ते खोलना? 2013 में किसने हटवाई थी कैमरी गाड़ियां? लेकिन विचार का अंतर क्या रह जाता है जब मौजूदा पक्ष भी फॉर्च्युनर के पक्ष में लेट जाए? सच यह है कि हादसे गाड़ियों के साथ नहीं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ हो रहे हैं। इनोवा में क्या बुराई थी? सिंधु नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का नाम बेशक शिक्षा बोर्ड है, काम केवल परीक्षा बोर्ड वाला है और उसमें भी कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर उसे गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। नकल के खिलाफ सिर्फ मौखिक और चुनिंदा मुहिम से क्या हासिल होगा? ऐसा क्यों है कि कुछ विद्यालयों में कैमरे न दुरुस्त हैं और न वे बोर्ड से जुड़े हैं? जिनके कैमरा नहीं चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? एक परीक्षा केंद्र अधीक्षक के रूप में प्रवक्ता का सेवाकाल पांच वर्ष होना चाहिए, तो फिर तीन साल वाले पर कृपा क्यों? जब प्रदेश आर्थिक घाटे में चल रहा है, तो एसओएस की परीक्षाएं निजी स्कूलों को क्यों दी जाती हैं? क्या अपने यानी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर भरोसा नहीं है व्यवस्था को? एसओएस परीक्षा शाम को क्यों? क्या वह खास कारण से सुबह के सत्र में दस जमा दो के साथ नहीं करवाई जा रही? जिन निजी स्कूलों में एसओएस के केंद्र हैं, वहां सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं? अगर एकाध कर्मचारी तैनात कर भी दें तो क्या वह इस स्थिति में होगा कि कुछ तत्वों की आर्थिक वास्तविकता से पगी अपेक्षा से अपने विवेक, ईमानदारी और अपनी सुरक्षा कर सके? चंबा जिले में तो पटवारी और राजस्व विभाग के दीगर लोग भी तैनात कर दिए गए। हालांकि बाद में उपायुक्त के हस्तक्षेप से मामला शांत हो गया। चंबा के उपायुक्त बाइक पर बैठ कर नकल रोकने गए। यह सराहनीय है, उन्हें निजी स्कूलों का जायजा भी लेना चाहिए। भला हो कुल्लू के एसपी का जिन्हें यह महसूस हुआ कि निजी केंद्रों में भी नकल हो सकती है... होती है और 71 मामले बनाए। नियोजित और सामूहिक नकल।

विश्वविद्यालय स्तर का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आवश्यक है कि छलनी को प्रारंभिक दौर से ही बारीक रखा जाए ताकि पढ़ाई वास्तव में काम आए। जहीर रहमती के शब्दों पर गौर करना आवश्यक है :

दिल लगा कर पढ़ाई करते रहे
उम्र भर इम्तिहां से डरते रहे।

प्रतीकात्मक।

प्रतीकात्मक।

मंथन

आंतरिक सुरक्षा का सवाल

भारत में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास पुराना तो है, लेकिन ऐसी घटनाओं का आसानी से घट जाना आधुनिक दौर में हमारी बौद्धिकता और आचरण पर सवालिया निशान खड़े करता है

रिजवान अंसारी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

हाल ही में दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में फैले सांप्रदायिक हिंसा के कारण 53 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस हिंसा और उपद्रव की चपेट में हजारों लोगों के आने से देश की राजधानी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इन सबसे बढ़ कर यह कि सांप्रदायिक दंगों में हुए करोड़ों रुपये की आर्थिक क्षति तो होती ही है, देश की आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इन दंगों में नागरिकों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल किया जाना बताता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा किस कदर खतरे में है। यकीनन अवैध हथियारबंद लोगों के चलते नागरिकों का भय के माहौल में जीने से देश की एकता व अखंडता खतरे में पड़ जाती है। गौर करें तो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा लोगों की संपत्ति, मौलिक और मानव अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे पहलुओं से भी जुड़ता है और सांप्रदायिक दंगे जैसी घटनाएं इन पहलुओं के लिए चुनौतियां बन कर उभर रही है।

दरअसल सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं, ऐसे में इस नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सांप्रदायिक दंगे युवाओं को राह से भटकाते हैं। नागरिकों में नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी अवैध गतिविधियों के प्रति आकर्षित होने की आशंका में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। कई राज्यों में नक्सलवाद कहें या फिर देश के अंदर आतंकी संगठनों के पैर पसारने की बात करें, कहीं न कहीं ऐसे दंगे भी जिम्मेदार हैं। सोचिए कि अगर देश के युवा ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होना प्रारंभ कर दें, तो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाना कितना मुश्किल हो जाएगा।

इसका एक पहलू यह भी है कि बारंबार तनाव की स्थिति पैदा होने से कानून एवं व्यवस्था के प्रति लोगों में अविश्वास की भावना का निर्माण होता है। हिंसात्मक घटनाओं को रोकने में नाकाम होने से प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है। इससे एक बात पता चलती है कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जरूरी कवायद होनी चाहिए, उसका अभाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद से ही भारत आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है।

इन चुनौतियों का समाधान कैसे हो? हिंसक घटनाओं की बड़ी वजह आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में व्याप्त खामियां हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीतियां जरूरी है ताकि मूल कारणों पर काम करके समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसी के साथ अल्पकालिक नीतियां भी बन जाती हैं जिससे तात्कालिक समस्याओं का निपटारा किया जाता है। लेकिन चिंता का विषय है कि भारत सरकार के पास ऐसी कोई मजबूत नीति नहीं है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए 2005 में तैयार किए गए सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक को कानूनी रूप नहीं दिया जा सका है। इसी तरह माओवादी हिंसा से निपटने के लिए भी भारत सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई पड़ती। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 'समाधान' नामक आठ सूत्री पहल की घोषणा जरूर की है। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लिए रणनीतियों पर जोर दिया गया है, पर अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि यह कितना कारगर साबित हुआ है। एक खामी यह भी है कि हमारी सरकारें पुलिस सुधार की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहीं हैं। हालिया दिल्ली दंगे में पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान इसी का एक पहलू है। आधुनिक प्रशिक्षण के अभाव में पुलिस दंगाई से निपटने में सक्षम नहीं हो पाती।

केंद्र- राज्य में समन्वय का अभाव : कानून-व्यवस्था के मसले पर राज्य- केंद्र संबंधों में सशक्त भागीदारी का अभाव भी देखा जा रहा है। कानून-व्यवस्था राज्य का मसला है, पर कभी-कभी मामले इतने ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं कर पाती। लिहाजा, केंद्र-राज्य संबंध की जड़ता भी आंतरिक सुरक्षा की राह में एक बड़ी खामी है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था को राज्य सूची से बाहर कर समवर्ती सूची में शामिल करने की जरूरत है। इससे यह होगा कि समय-समय पर केंद्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था की समीक्षा की जा सकेगी और आपातकालीन स्थिति में केंद्रीय बल मदद को तैयार रहेंगे।

हमें आंतरिक सुरक्षा को भी उतनी ही अहमियत देने की जरूरत है जितनी कि बाह्य सुरक्षा को देते हैं। आंतरिक सुरक्षा को कम करके आंकना सुरक्षा के लिहाज से घातक सिद्ध हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा कई बार चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इस कड़ी में यह नहीं भूलना चाहिए कि नफरती या भड़काऊ भाषण देने वाले नेतागण भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितने कि कोई अपराधी। ऐसे में बिना भेदभाव के इन नेताओं पर कार्रवाई आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद अहम कदम हो सकता है।

आंतरिक सुरक्षा के लिए समेकित आंतरिक सुरक्षा नीति की भी जरूरत है जिसके तहत राज्य व केंद्र सरकार मिलकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इससे इतर, वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार भी बड़ा उपाय है। समझना होगा कि मामलों के निपटाने में देरी से अपराधों में इजाफा होता है। ऐसे में जजों की पर्याप्त नियुक्ति और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना महत्वपूर्ण है।

जम्मू कश्मीर

निजी स्कूलों की मनमानी

आम तौर पर निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतें तो साल भर आती ही रहती हैं, नया सत्र शुरू होने के समय इसकी संख्या में व्यापक बढ़ोतरी हो जाती है। अधिकांश स्कूल शिक्षा प्रदान करने के साथ वे तमाम रुख अख्तियार करते हैं या फिर कहें कि छात्रों-अभिभावकों को वे तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं जो कार्य मुख्य रूप से स्कूल का नहीं होना चाहिए। दिल्ली समेत देश के अधिकांश हिस्सों में निजी स्कूल नए सत्र में किताबों का पूरा सेट अभिभावकों को स्कूल से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं।

निजी स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसने के लिए शिक्षा निदेशालय का मुख्य शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाने का फैसला सराहनीय है। अब अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पोर्टल भी तैयार किया है, जिसमें स्कूलों को 15 दिन में फीस सहित तमाम ब्यौरा अपलोड करने के लिए कहा है। देखना यह है कि विभाग निजी स्कूलों की मनमानी रोकने में सफल हो पाता है या नहीं। इससे पहले भी विभाग ने निजी स्कूलों की फीस बढोतरी, री-एडमीशन, वर्दी और किताबें बेचने की शिकायतों पर टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। लेकिन शिक्षा विभाग की यह कवायद भी फलीभूत नहीं हो पाई। मनमानी फीस वसूलने पर शिक्षा विभाग हर वर्ष अकादमिक सत्र के दाखिले के बाद निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई का मन तो बनाता है, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। निजी स्कूलों को जो करना होता है, वह फीस बढ़ोतरी सहित सभी खेल कर जाते हैं। यह किसी से नहीं छुपा कि हर वर्ष कई निजी स्कूल मनमानी फीस बढ़ोतरी कर एडमिशन के नाम पर बच्चों व अभिभावकों को प्रताड़ित करते हैं। अभिभावक प्रताड़ना से निजात के लिए वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से कोर्ट तक चली लड़ाई में उन्हें कागजों में तो राहत मिलती है मगर स्कूलों की मनमानी के आगे जमीनी स्तर पर वह बेबस नजर आते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को चाहिए कि वे निजी स्कूलों के लिए कोई पुख्ता नीति बनाएं, ताकि कोई भी स्कूल फीस बढ़ाने में मनमर्जी नहीं कर सके। कई निजी स्कूलों ने वर्दी और किताबें बेचने के लिए दुकानदारों के साथ सांठगांठ की है। उनका मकसद बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराने के स्थान पर सिर्फ रुपये कमाना है। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। यह अच्छी बात है कि इस बार शिक्षा विभाग ने नई कक्षा में दाखिलों से पहले निजी स्कूलों की स्टाफ संख्या, मान्यता, इमारत की सुरक्षा के प्रमाणपत्र पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य किया है। इससे स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। देखना है कि क्या स्कूल शिक्षा विभाग हर वर्ष की तरह केवल कागजपत्रों में ही कार्रवाई करता रहेगा या फिर अभिभावकों को न्याय दिलाने में सक्षम होगा।

> अधिकांश निजी स्कूल आज की तारीख में कारोबार की तरह मुनाफे के दृष्टिकोण से संचालित हो रहे हैं जो शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक है

बंगाल

पार्टी मजबूत करने की भाजपा की कवायद

लगभग सभी राजनीतिक दलों की यह मंशा होती है कि उसके समर्थकों की संख्या अधिक से अधिक हो। इसके लिए वे अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों पर लगातार नए नए तरीकों से डोरे भी डालते रहते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति रहती है। सभी दल इस प्रयास में रहते हैं कि अन्य राजनीतिक दलों के अच्छे जनाधार वाले नेता उनकी पार्टी में शामिल हो सकें। इससे रणनीतिक रूप से पार्टी को मजबूती प्रदान करने में भी मदद मिलती है तथा नैतिक रूप से दूसरी पार्टी को कमजोर करने की भी कोशिश होती है। बंगाल में निकाय चुनावों से पहले भाजपा भी अपने जनाधार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है।

बंगाल में आगामी कुछ माह में होने वाले निकाय चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में तृणमूल के लिए एक भी ईंच जमीन छोड़ने के पक्ष में नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व लगातार बंगाल में पार्टी की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए नई-नई रणनीति बना रहा है। यही वजह है कि पार्टी के हर छोटे व बड़े नेताओं को सक्रिय करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी तत्पर है।

इस बीच तीन दिन पहले तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की पत्नी रत्ना चटर्जी को बेहला पूर्व विधानसभा क्षेत्र

शोभन चटर्जी। फाइल फोटो

का दायित्व सौंप दिया है। शोभन का पत्नी रत्ना के साथ तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। पिछले कुछ माह से चर्चा यह चल रही थी कि शोभन की तृणमूल में वापसी हो सकती है। परंतु, रत्ना को उनके विधानसभा क्षेत्र का दायित्व देने के बाद से शोभन क्षुब्ध हैं। अब भारतीय जनता पार्टी फिर शोभन को सक्रिय करने में जुट गई है।

खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव (संगठन) बीएल संतोष की शोभन से बात हुई है। उन्होंने उन्हें सक्रिय होने का निर्देश दिया है। दरअसल, शोभन ने पिछले वर्ष अगस्त में अपनी महिला मित्र बैशाखी बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली जाकर शामिल हुए थे। परंतु, वहां से आने के कुछ दिनों बाद से ही वह पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। भाजपा के किसी कार्यक्रम में नहीं जाना और न ही किसी गतिविधि में शामिल हो रहे थे। पिछले वर्ष जब भैया दूज पर शोभन और बैशाखी तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके आवास पर गए तो कयास लगने लगा कि शायद शोभन की तृणमूल कांग्रेस में वापसी हो रही है। परंतु, इस बीच उनकी पत्नी रत्ना को आगे कर दिए जाने के बाद से स्थिति बदल गई है।

मंगलवार को शोभन की महिला मित्र बैशाखी ने तृणमूल कांग्रेस महासचिव व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से मुलाकात की थी। परंतु, उन्होंने इस मुलाकात को लेकर कुछ नहीं कहा है। बैशाखी से यह पूछे जाने पर कि क्या वह तृणमूल में लौटेंगे या उनसे पार्थ से इस बाबत कुछ बात हुई है, उन्होंने कहा कि सब कुछ तो पार्थ चटर्जी पर निर्भर नहीं करता है। परंतु, एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शोभन किस दल के लिए सक्रिय होंगे? दूसरी ओर अब भारतीय जनता पार्टी भी शोभन को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, ताकि निकाय चुनाव में शोभन दांव भी चला जा सके। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दांव कितना प्रभाव दिखाता है और चुनावों में उसका किस तरह का असर सामने आता है।

झारखंड

सच हो मॉडल सिटी का सपना

किसी शहर को बसाना और वह भी व्यवस्थित रूप से बसाना, अपने आप में बहुत ही मुश्किल और व्यापक निवेश वाला कार्य होता है। देश में औद्योगिक रूप से विकसित किए गए अधिकांश शहरों को बेहतर माना जाता है, लेकिन जमशेदपुर शहर का नाम उनमें भी प्राथमिकता में रखा जाता है।

देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों में शुमार टाटा समूह ने शहरी विकास के मामले में झारखंड को वैश्विक पहचान व प्रतिष्ठा हासिल करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने हालिया झारखंड दौरे के दौरान वैश्विक स्तर पर जमशेदपुर को मॉडल सिटी बनाने के अपने जिस सपने का इजहार किया वह पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है।

वैसे भी राज्य को इस बात के लिए गर्व है कि जमशेदपुर जैसा व्यवस्थित शहर उसकी औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। टाटा समूह की ओर से इसे वैश्विक मॉडल सिटी बनाने की बात कही गई है तो सबको इसके अमली जामा पहनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। चंद्रशेखरन की इस राय से असहमति जताने का कोई कारण नजर नहीं आता कि मॉडल सिटी का सपना तभी मूर्त रूप ले सकेगा, जब जिला प्रशासन और राज्य सरकार के साथ-साथ आम जनता का भी सक्रिय सहयोग-समर्थन मिलेगा। व्यापक विचार-विमर्श के बाद इसके ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया जाए। ब्लूप्रिंट सामने आने पर शासन-प्रशासन और सरकार की भूमिका शुरू होगी। कंपनी की इच्छा, आवश्यकता के अलावा जनभावना का भी ध्यान रहे। ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं को मंजूरी प्रदान करने से लेकर अन्य तकनीकी और वैधानिक पहलुओं का खास ध्यान रखना होगा। बेहतर होगा कि सरकार के स्तर से इसके लिए एक अलग सिंगल विंडो सिस्टम ही लागू कर दिया जाए। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रभावी प्राधिकार गठित किया जाए जो कंपनी और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कामकाज को सही दिशा प्रदान करे। अपने नामकरण के 100 साल पूरा होने के बाद जिस नए जमशेदपुर को विकसित करने की बात हो रही है उसमें हवाई अड्डे का निर्माण शहर के इर्द-गिर्द हो जहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की भी सुविधा रहे। शहर को रिंग रोड से जोड़ते हुए मैट्रो ट्रेन चलाने के सपने को आत्मसात किया जाए। सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए फ्लाइओवर या नदियों पर पुल निर्माण में तेजी लाई जाए। जलमार्ग सेवा को हकीकत बनाने की संभावना भी तलाशी जानी चाहिए। नए जमशेदपुर के विकास के क्रम में सूरत के साथ-साथ यहां रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर देना होगा।

जमशेदपुर शहर के विस्तार की व्यापक योजना को अमलीजामा पहनाने का एक बड़ा फायदा यह भी हो सकता है कि इसे अन्य कई औद्योगिक शहरों के लिए नजीर के तौर पर पेश किया जा सकता है।

> टाटा समूह जमशेदपुर को वैश्विक स्तर पर मॉडल सिटी बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह वास्तव में झारखंड के लिए बड़ी बात होगी।

हिमाचल प्रदेश

स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली

लोग बेहतर उपचार की उम्मीद लेकर अस्पताल आते हैं। यदि स्वास्थ्य संस्थानों में अव्यवस्थाएं हों तो मरीजों का मर्ज बढ़ता है। स्थिति उस समय गंभीर हो जाती है जब किसी को आपात स्थिति में अस्पताल में पहुंचाया जाता है और वहां पर डॉक्टर ही न मिले। ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में तो यह बात समझ में आती है कि लेकिन यदि ऐसी स्थिति किसी शहर के सिविल अस्पताल में ऐसा हो तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है।

हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के मामले में अव्वल राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन अव्यवस्थाएं इसे धक्का पहुंचाती हैं। जिस अस्पताल में छह डॉक्टरों की तैनाती हो और वहां पर भी आपात स्थिति में मरीज को डॉक्टर न होने के कारण समय पर उपचार न मिल पाए तो लोगों में रोष पनपना स्वाभाविक है। ऐसी ही स्थिति हमीरपुर जिला के सुजानपुर स्थित सिविल अस्पताल में पिछले दिनों उत्पन्न हुई थी। यह सुखद है कि उपमंडल अधिकारी के समय पर पहुंचने से स्थिति को बिगड़ने

प्रतीकात्मक।

से संभाल लिया और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से चिकित्सकों को बुलाकर सड़क हादसे के घायलों को उपचार मिल गया, लेकिन इस तरह की अव्यवस्थाओं ने सवाल जरूर खड़े कर दिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी यह मामला उठा है। बेशक ऐसी स्थिति यदा कदा ही होती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अस्पताल में कभी भी इस तरह के हालात न बनें। डॉक्टरों की कमी से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज भी अछूते नहीं हैं।

ऐसी ही स्थिति राज्य के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में भी है। यहां स्थित कई स्वास्थ्य केंद्रों में अब भी चिकित्सकों, नर्सों व पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है। किसी भी व्यवस्था का आधार गांव ही होते हैं, ऐसे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो लोग शहरों में स्थित बड़े अस्पतालों की ओर रुख कम ही करेंगे। सरकार ने पिछले दिनों चिकित्सकों की नियुक्तियां भी की हैं, लेकिन अब भी कई स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की आवश्यकता है। अस्पताल प्रशासन को भी स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए निरंतर अपनी ओर से प्रयासरत रहना चाहिए। अव्यवस्था के कारण ही लोगों के लिए आई दवाएं स्वास्थ्य संस्थानों में ही खराब हो गईं। इस बात को समझा जाना चाहिए कि अगर व्यवस्था सही तरीके से संचालित हों, तो ही सभी को सुविधाएं मिल पाती हैं।

क्रिकेट के 'वंडर किड' को मिल ही गया 'दादा' का साथ

जागरण विशेष

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

क्रिकेट के 'वंडर किड' शेख शाहिद को बीसीसीआइ बॉस सौरव गांगुली का साथ मिल गया है। गांगुली ने शाहिद को अपने मशहूर गेम शो 'दादागीरी अनलिमिटेड' में खास मेहमान के रूप में आमंत्रित किया। साथ ही गांगुली की क्रिकेट अकादमी में भी कोलकाता निवासी इस तीन वर्षीय बल्लेबाज को दाखिला मिल गया है।

अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाले तीन साल के शेख शाहिद की तारीफ दिग्गज क्रिकेटर कर चुके हैं। आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी शाहिद की बल्लेबाजी के मुरीद हैं, जो बीते दिनों उससे मिलने खुद चलकर उसके कोलकाता स्थित घर पहुंचे थे। स्टीव इस वंडर किड पर अपनी आगामी किताब में पूरा अध्याय लिख रहे हैं। गांगुली के टीवी गेम शो 'दादागीरी अनलिमिटेड' के सीजन-8 में शाहिद नजर आएंगे। सौरव ने शूटिंग के दौरान शाहिद के साथ क्रिकेट खेला। उसकी बल्लेबाजी स्टाइल को देख वह भी दंग रह गए। शाहिद का सिर्फ सौरव से मिलना ही नहीं हुआ, बल्कि उसका उनकी एकेडमी में प्रशिक्षण सुनिश्चित हो गया, जिसका सौरव की ओर से वादा किया गया था।

शाहिद के पिता शेख शमशेर ने दैनिक जागरण को बताया- हमें गत दो मार्च को सौरव के गेम शो को प्रसारित करने वाले चैनल की तरफ से फोन करके सूचित किया गया कि शो में शाहिद खास मेहमान होगा। सात मार्च को हमें शूटिंग के लिए बुलाया गया। शूटिंग जब शुरू हुई तो सौरव ने शाहिद को स्टेज पर बुलाते हुए कहा- अब मैं स्टेज पर जिस बच्चे को बुलाने जा रहा हूं, उसे उसकी बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद स्क्रीन पर शाहिद का डायपर पहनकर बल्लेबाजी करने वाला पुराना वीडियो दिखाया गया। साथ ही माइकल वॉन, केविन पीटरसन, ब्रेड हॉग समेत विभिन्न नामचीन क्रिकेटरों द्वारा शाहिद की तारीफ में सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स भी दिखाए गए।

कोलकाता के एक सैलून में काम करने वाले शाहिद के पिता शमशेर ने बताया, आंखों के सामने शाहिद को बल्लेबाजी करता देखने को सौरव इतने लालायित थे कि उन्होंने शाहिद को स्टेज पर बुलाते ही बल्लेबाजी की शैडो प्रैक्टिस करके दिखाने को कहा। इसके बाद शाहिद से कहा- अब तुम बल्लेबाजी करो। मैं गेंद डालता हूं। उन्होंने शाहिद को पहली जो तीन गेंदें डालीं, उन पर शाहिद ने कोई शॉट नहीं लगाया। बेताब सौरव ने कहा- शॉट मारो। मुझे तुम्हारी बल्लेबाजी देखनी है। इसके बाद शाहिद ने सौरव की गेंदों पर करारे शॉट लगाए, जिसे देखकर दादा खुद भी दंग रह गए। शाहिद के साथ सौरव ने करीब एक घंटे शूटिंग की। इस खास एपिसोड का प्रसारण जल्द होगा। बता दें कि दादागीरी अनलिमिटेड मशहूर बांग्ला गेम शो है, जिसके होस्ट सौरव गांगुली हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सितारे की शुरुआत...

- अपने मशहूर गेम शो 'दादागीरी अनलिमिटेड' में खास मेहमान के रूप में बुलाया, क्रिकेट अकादमी में भी दिया दाखिला
- शाहिद की बल्लेबाजी स्टाइल को देखकर दंग रह गए गांगुली
- इससे पहले केविन पीटरसन से लेकर विराट कोहली तक, दिग्गज क्रिकेटर कर चुके हैं वंडर किड की तारीफ
- बीते दिनों पूर्व आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ मिलने पहुंचे थे घर, शाहिद पर लिख रहे हैं अपनी किताब में अध्याय

दादागीरी अनलिमिटेड के सेट पर शेख शाहिद के साथ सौरव गांगुली। सौजन्य : शेख शमशेर

अब हमारी उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। मुझे हमेशा डर सताता था कि आर्थिक तंगी के कारण कहीं मेरे बेटे की प्रतिभा बर्बाद न हो जाए, लेकिन अब मैं काफी निश्चिंत हूं। पहले शाहिद सोशल मीडिया पर सगल बन कर रह गया था, लेकिन दैनिक जागरण ने जब उसकी कहानी देश-दुनिया को पढ़ाई तो लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। खुद स्टीव वॉ मेरे घर पहुंचे और अब सौरव गांगुली ने मदद को हाथ बढ़ाया। इसके लिए मैं दैनिक जागरण का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

-शेख शमशेर, शाहिद के पिता

शाहिद में नैसर्गिक प्रतिभा : सौरव

सौरव गांगुली ने कहा, शाहिद में नैसर्गिक प्रतिभा है। खासकर शाहिद की बल्लेबाजी के लिए खड़े होने की शैली से वह काफी प्रभावित नजर आए। उन्होंने उसके ड्राइव और फॉलो थ्रू की भी काफी तारीफ की।

सौरव की एकेडमी से आया बुलावा

सौरव से मुलाकात के साथ ही शाहिद के लिए उनकी एकेडमी से भी कॉल आ गया। शाहिद के कोच अमित चक्रवर्ती ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें 21 मार्च को शाहिद के साथ एकेडमी आने को कहा गया है।

यूजी, पीजी व पीएचडी के छात्रों को आइसीएआर देगी वजीफा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि क्षेत्र में मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने तथा कृषि शिक्षा के प्रति छात्रों में रुझान पैदा करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) ने विशेष योजना शुरू की है। उसने अंडर ग्रेजुएट (यूजी), पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) और पीएचडी में दाखिला लेने वाले छात्रों को वजीफा देने का फैसला किया है। हालांकि, वजीफा उन्हीं को दिया जाएगा जो आइसीएआर की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे और दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेंगे।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मार्फत राज्य विश्वविद्यालयों की 15 फीसद यूजी, 25 फीसद पीजी और पीएचडी की सीटें भरी जाएंगी। बाकी पर दाखिले राज्य विवि अपने स्तर पर लेंगे। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में आइसीएआर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिला पाने वाले छात्रों को विशेष वजीफा देने की तैयारी है। इसके लिए छात्रों को दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा से 7,000 से अधिक दाखिले लिए जाएंगे। 40 हजार से अधिक छात्रों का दाखिला राज्यों के कृषि विवि अपने स्तर की परीक्षाओं के जरिये लेंगे।

आइसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. आरसी अग्रवाल ने बताया, 'अखिल भारतीय स्तर की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पांच से 35 हजार रुपये तक का वजीफा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आइसीएआर इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दे रही है।'

आइसीएआर के चार प्रमुख शोध संस्थानों- मुंबई के फिशरीज, दिल्ली के आइएआरआइ, बरेली के आइवीआरआइ और करनाल के एनडीआरआइ में होने वाले सभी दाखिले इसी प्रवेश परीक्षा के मार्फत होंगे। फिलहाल देश में कुल 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इनमें 63 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, जबकि तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और चार डीम्ड हैं।

आइसीएआर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है, जिसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। प्रवेश परीक्षा एक जून को ऑनलाइन होगी। परीक्षाफल 15 जून को घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा कराने का दायित्व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा गया है। उन विश्वविद्यालयों के छात्रों को प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं होगी, जिनकी गुणवत्ता को आइसीएआर ने संदिग्ध माना है।

बंगाल में एक अप्रैल से नहीं रहेगी कोई चेकपोस्ट : ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कृषकों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए कृषि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक अप्रैल से राज्य की सभी 109 चेकपोस्ट को हटाने यानी समाप्त करने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कृषि उत्पादों से लदे वाहनों को अब चेकपोस्टों पर घंटों-घंटों नहीं रुकना पड़ेगा। एक अप्रैल से कृषि उत्पादों के लिए राज्य की सभी 109 चेकपोस्टों को हटा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन लोगों के हित में उन्होंने यह फैसला लिया है। सीएम ने कहा कि पहले कृषि उत्पाद लदे वाहनों को चेकपोस्टों पर जांच के लिए तीन-तीन चार घंटे रुकना पड़ता था। इसके कारण कई बार कृषि उत्पाद सहित मछली, अंडे आदि खराब हो जाते थे। इसको लेकर लगातार मिल रही शिकायतों व किसानों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी चेकपोस्टों को हटाने का फैसला किया है। ममता ने कहा कि कृषि ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कृषि उत्पाद लदे वाहनों की पूरे राज्य में अब कहीं भी कोई जांच नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ममता ने इसके साथ ही कहा कि विभिन्न जिलों में स्थित इन चेकपोस्टों पर काम करने वाले कुल 649 कर्मचारियों में से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। उन्हें पास के कृषक बाजारों या अन्य जगहों पर काम दिया जाएगा।

बड़ा फैसला

- कृषि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही के लिए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
- सभी चेकपोस्टों को हटाने से सरकार को होगा 200 करोड़ का नुकसान

ममता बनर्जी। फाइल

रेलवे बनाएगा हाथियों के लिए अंडर पास और लंगूरों के लिए ओवर ब्रिज

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद : रेलवे हाथियों के लिए अंडर पास और लंगूरों के लिए फुटओवर ब्रिज बनाएगा। मुरादाबाद मंडल क्षेत्र के राजाजी नेशनल पार्क में यह व्यवस्था की जानी है। देशभर में कई स्थानों पर जंगलों के बीच से रेललाइन गुजरती है। इससे कई बार रेललाइन पार करते समय जानवरों की मौत हो चुकी है। राजा जी नेशनल पार्क में पांच साल में ट्रेन की टक्कर से तीन हाथियों की मौत हो चुकी है। इस पर वन विभाग ने ट्रेन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने चालक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी। इस मामले को लेकर रेलवे व वन मंत्रालय के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है। इसके बाद वन विभाग ने रेलवे से जंगल के बीच गुजरने वाली रेल लाइन पर अंडर पास, बंदरों व लंगूरों के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने को कहा था।

इसी क्रम में अब हाथियों के चलने वाले मार्ग पर रेल लाइन के दोनों ओर तार का घेरा बनाया जाएगा। मधुमक्खी की आवाज वाला उपकरण रेलवे ने तैयार किया है ताकि हाथी ट्रैक के पास आ सके। उत्तर रेलवे के मुख्य अभियंता हरपाल सिंह ने बताया कि हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर अंडर पास व ओवर ब्रिज बनेगा।

महिला कर्मियों को सौंपा जिम्मा तो हो गया कमाल

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर

नारी सशक्तीकरण

पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाने की तस्वीर बदल गई है। प्रबंधन ने महिलाओं को ट्रिमिंग शॉप का जिम्मा क्या सौंपा, कमाल हो गया। जो लक्ष्य पुरुषों के साथ मिलकर नहीं सध पा रहा था, अब उससे कहीं अधिक हासिल हो रहा है। कारखाने के ट्रिमिंग शॉप यानी सच्चा गृह में कार्य करने वाली इन 34 महिलाओं के बूते साख बचाने को जूझ रहे कारखाने को मजबूत सहारा मिला है। उत्पादन में दर्ज गुणात्मक वृद्धि ने अन्य सहकर्मियों को प्रेरित करने का काम किया है।

ट्रिमिंग शॉप में ट्रेन की जनरल बोगियों की सीटें तैयार होती हैं। एक साल पहले 200 सीटें भी समय से नहीं मिल पाती थीं, आज ये महिला कर्मी रोजाना और समय से गुणवत्ता के साथ लगभग 300 सीटें तैयार कर रही हैं। दिसंबर 2018 तक ट्रिमिंग शॉप में पुरुष और महिला दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते थे। उस समय उत्पादकता ही नहीं गुणवत्ता की समस्या अक्सर पैदा होती रहती थी। खामियां दूर करने के क्रम में सीटों को अक्सर दोबारा बनाना पड़ता था। लाख प्रयास के बाद भी गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ तो कारखाना प्रबंधन ने बड़ा कदम उठाते हुए जनवरी 2019 में शॉप को महिलाओं के हवाले कर दिया। प्रबंधन ने भरोसा जताया तो उन्होंने साबित भी कर दिखाया।

एक वर्ष के भीतर महिला कर्मचारियों ने शॉप की सूरत बदल दी है। कार्य का माहौल तैयार हुआ तो गुणवत्ता अपने आप बढ़ गई। अब सीटों को दोबारा नहीं बनाना पड़ता है। सुपरवाइजर रेमंड पौल बताते हैं कि अब सीटों को समय से बोगियों में लगाने में कोई समस्या नहीं होती है। सीटें भी बेहतर तैयार हो रहीं हैं। यहां अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाली महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाता है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

- पूर्वोत्तर रेलवे की 34 महिला कर्मियों ने यांत्रिक कारखाने की बदल दी तस्वीर
- जब पुरुष संभालते थे काम तो फिसड्डी था उत्पादन, अब गुणवत्ता भी बढ़ गई

पूर्वोत्तर रेलवे के यांत्रिक कारखाना में पैसेंजर कोच की सीटें तैयार करतीं महिला कर्मचारी। जागरण

प्रबंधन ने अवसर देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। सभी महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करती हैं। महिलाओं के लिए अति आधुनिक मशीनें और अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं।

-कविता सिंह, जूनियर इंजीनियर

कारखाने में 11 वर्ष से कार्य कर रही हूं। पहले स्थिति ठीक नहीं थी अब बेहतर माहौल मिला है। जितना लक्ष्य मिलता है, हम सब मिलकर उसे बेहतरी के साथ पूरा करते हैं। कारखाना प्रबंधन भी सुविधाओं पर ध्यान देता है।

- अनीता यादव, शॉप कर्मी

यांत्रिक कारखाना में कार्यरत महिलाओं ने अपनी क्षमता साबित की है। उनकी लगन का फायदा रेलवे को मिला है।

-पंकज कुमार सिंह, सीपीआरओ, पूर्वोत्तर रेलवे

दैनिक जागरण

सबरंग

साहित्य के...

नई दिल्ली, गुरुवार, 12 मार्च, 2020

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com

https://www.facebook.com/jagransabrang/

असमय चला गया एक प्रतिभाशाली कथाकार

स्मृति शेष

25 अगस्त 1965-10 मार्च 2020

लेखक प्रेम भारद्वाज

हिंदी के प्रतिभाशाली लेखक, कहानीकार और संपादक प्रेम भारद्वाज ने बहुत ही कम उम्र में दुनिया छोड़ दी। हिंदी साहित्य में जब राजेन्द्र यादव के संपादन में साहित्यिक पत्रिका 'हंस' अपनी कहानियों और पत्रिका में उठाए गए विवादों की वजह से चर्चा बटोर रही थी तब प्रेम भारद्वाज ने 'पाखी' के संपादन का बीड़ा उठाया था। अपने संपादकीय कौशल की वजह से प्रेम ने 'पाखी' को हिंदी साहित्य की एक ऐसी पत्रिका के रूप में स्थापित किया जो 'हंस' को चुनौती देने लगी थी। राजधानी के साहित्य जगत में बहुधा इस बात की चर्चा होती थी साहित्य में अब नोएडा और दरियागंज के बीच मुकाबला है। 'हंस' का प्रकाशन दरियागंज से जबकि 'पाखी' नोएडा से निकलती है। प्रेम भी अपने संपादकीयों में अक्सर विवाद उठाने की कोशिश करते थे लेकिन वो राजेन्द्र यादव की तरह खुलकर नहीं खेलते थे। वो परोक्ष रूप से अपनी बात कहते थे। प्रेम आज से करीब बीस-बाइस साल पहले पटना से दिल्ली आए थे। 'पाखी' में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। साहित्यिक पत्रिका में संसाधनों की कमी की बात हमेशा सामने आती है बावजूद इसके प्रेम भारद्वाज ने 'पाखी' की स्तरीयता को कभी कम नहीं होने दिया। पाखी में उन्होंने नए लेखकों को जोड़ा। मुझे याद पड़ता है कि पिछले वर्ष के विश्व पुस्तक मेला में प्रेम भारद्वाज की मांग सबसे अधिक थी। हमलोग मजाक में कहते भी थे कि वो घंटे के हिसाब से कार्यक्रमों में उपस्थित हो रहे हैं। लगातार किताबों पर होने वाले कार्यक्रमों का संचालन करना या फिर नई किताबों पर बोलना यह साबित करता था कि प्रेम के अध्ययन का दायरा बहुत विस्तृत था। कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया। फिर अप्रिय परिस्थियों में उनको 'पाखी' छोड़नी पड़ी थी जिसके बाद उन्होंने दिल्ली से ही 'भवन्ति' नाम की साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस पत्रिका के शुरुआती अंकों ने काफी चर्चा बटोरी थी। अचानक एक दिन खबर आई कि प्रेम नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती हैं। बाद में पता चला था कि कैंसर ने उनको अपनी चपेट में ले लिया है। नोएडा-दिल्ली और अहमदाबाद में उनका इलाज चला, वो ठीक होने लगे थे। सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए और उन्होंने पाठकों को भरोसा दिया कि जल्द ही 'भवन्ति' का नया अंक सामने होगा। अचानक एक दिन खबर फैली की उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके चंद दिनों बाद प्रेम के निधन की खबर से हिंदी जगत सन्न रह गया। उनका कहानी संग्रह 'फोटो अंकल' काफी चर्चित रहा था। उन्होंने सबरंग साहित्य के लिए कई बार लिखा था। उनको श्रद्धांजलि।

-अनंत विजय

दिल्ली में रहकर हिंदी की रोटी खाई है

परिवार भले बांग्ला भाषी हो लेकिन वर्ष 1936 में बंगाली परिवार में दिल्ली की धरा पर जन्में प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधुरी, इस शहर में अपनी पैदाइश होना, सौभाग्य मानते हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में बीते बचपन को जीवन का स्वर्णिम दौर बताते हैं। संस्कार भले बंगाली मिले, पर दिल ने हिंदी भाषी बना दिया। दिल्ली के साहित्यिक जीवन व दिल्ली विवि में पढ़ाने के अलावे प्रशासन व सांस्कृतिक तुलनात्मक साहित्य क्षेत्र से 50 वर्षों तक जुड़े रहे सो, इन्हीं से जुड़ी स्मृतियों पर इंद्रनाथ चौधुरी से रितु राणा की विस्तार से बातचीत हुई। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश

प्रसिद्ध लेखक इंद्रनाथ चौधुरी का जन्म भले ही बंगाली परिवार में हुआ हो पर दिल में तो हिंदी ही है। जागरण

बातचीत

• दिल्ली जन्म भूमि है, फिर तो अद्भुत यादें होंगी?

हां, मेरे पिता प्रोफेसर नरेश वर्ष 1926 में कोलकाता से दिल्ली आए थे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक थे। 1942 की बात है, मेरी उम्र करीब छह साल रही होगी। उन दिनों रामजस कॉलेज आनंद पर्वत इलाके में होता था। मुझे अपने बचपन की उम्र की वो घटना याद है जब वह पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया था और हम लोग दरियागंज में रहने चले गए थे। उस समय दरियागंज किले के माफिक चारों ओर से दीवारों से घिरा होता था। उसके बगल से यमुना नदी बहती थी। तब नदी बहुत सुंदर व साफ होती थी। पिताजी ने मेरा दाखिला रामजस स्कूल नंबर-1 में पांचवीं कक्षा में करा दिया था। मुझे अभी भी याद है उस स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम शादी लाल था। स्कूल के बाद दोस्तों के साथ साइकिल से दरीबा कलां चले जाते थे वहां बेडमी पूड़ी-सब्जी और जलेबी बहुत अच्छी मिलती थी। हम सारे दोस्त साइकिल से ही दरियागंज, दरीबा कलां, किनारी बाजार, भूत वाली गली, बल्लीमारान, चावड़ी बाजार तक घूमते थे। पुरानी दिल्ली की गलियों में मेरा बचपन बीता है, युवावस्था बीती है, वहां की हर गली आज भी याद है। इस शहर ने मुझे इतना अपनापन दिया बता नहीं सकता। मैं इसका कर्जदार हूं। वैसे तो मैं बांग्ला भाषी हूं लेकिन मैंने दिल्ली में रहकर हिंदी की रोटी खाई है।

• क्या आनंद पर्वत स्वतंत्रा की लड़ाई के कारण छावनी में तब्दील था?

हां, इसीलिए तो हम दरियागंज आ गए थे। 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्वीट इंडिया का नारा दिया तब चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई थी। हालांकि गांधी ने अहिंसा की बात की लेकिन फिर भी लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जोश अलग ही तरीके से हिलोरे लेने लगा था। वे स्ट्रीट लाइटें तोड़ने लगे, सड़कों पर जुलूस निकालते थे। फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तब दिल्ली की अलग ही फिजा थी। कहीं मारकाट मची थी तो कहीं लोगों के चेहरे पर आजादी की खुशी थी। हमलोगों ने बंदनवार से घर सजाया। स्कूल में हमें पीतल की तश्तरी मिली, जिसमें मिठाइयां रखी थीं। 15 अगस्त को स्कूल की छुट्टी हो गई थी तो हम लोग जवाहरलाल नेहरु का भाषण सुनने लाल किला भी गए थे। उनका भाषण सुनकर खूब उत्साहित हुए थे।

• आजादी की लड़ाई की स्मृतियां भी होंगी?

वर्ष 1947 में पंजाब से बहुत सारे लोग दिल्ली आए थे। उनमें से बहुत से बच्चों ने हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया था। वहां प्राचार्य के कमरे के साथ एक रेस्ट रूम होता था। गणित के एक प्रोफेसर शांति नारायण ने बच्चों को वहां शरण दी। बच्चों के सोने के लिए बिस्तर रखे गए। उनके लिए 24 घंटे लाइब्रेरी भी खोली गई। 1947 से पहले दिल्ली में हिंदू-मुस्लिम में खूब प्रेम व एकता थी, लेकिन बंटवारे ने उन्हें अलग कर दिया वर्ना अपने समय में हमने कभी इतनी नफरत नहीं देखी थी। एक किस्सा बताता हूं मेरे पिता के दोस्त के बेटे की शादी थी। वह मंडप में बैठ चुका था, लेकिन शादी की रस्में शुरू नहीं कर रहा था। सबने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा जब तक अकबर नहीं आ जाएगा मैं शादी कैसे कर लूं। अकबर उसका बहुत ही प्रिय मित्र था। भले ही दोनों एक-दूसरे के घर खाना नहीं खाते, लेकिन उनके बीच अटूट प्रेम था। अब काफी बदलाव आ गया है। मेरा भी एक जिगरी दोस्त कादीर जुमां मुस्लिम था वह रहता हैदराबाद में था, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की शादी में दिल्ली आया और मेरे घर पर ही रुका था।

• बंगाली परिवार में जन्म हुआ, फिर हिंदी में रुचि कैसे बनी?

अब जिसकी परवरिश दिल्ली की बोली-ठिठोली में होगी तो हिंदी भाषी होना स्वाभाविक है। स्कूल में भी हिंदी का ही माहौल मिला, जिससे मेरी हिंदी में रुचि पैदा होने लगी। मुझे दिल्ली विवि में दाखिला लेना था लेकिन तब मेरी उम्र साढ़े चौदह वर्ष थी और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उस समय सोलह वर्ष उम्र हुआ करती थी। फिर मैंने हिंदी की दो बड़ी परीक्षाएं प्रभाकर व प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित साहित्य रत्न की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इससे मैं हिंदी के और करीब हो गया। पिता की इच्छा थी कि मैं बांग्ला भी पढूं इसलिए मैंने रामजस कॉलेज से बांग्ला में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सेंट स्टीफंस कॉलेज से अंग्रेजी में एमए की, लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इसलिए हंसराज कॉलेज में दोबारा एमए हिंदी में दाखिला लिया। मैंने 1960-80 तक दिल्ली विवि में हिंदी पढ़ाई भी थी। उसके बाद तो हिंदी मेरी सबसे प्रिय भाषा बन गई।

• आप 20 वर्ष दिल्ली विवि में रहे वहां का माहौल कैसा था?

दिल्ली विवि में डॉ. नगेंद्र, उदय भानु सिंह, विजेंद्र स्नातक, ज्ञान प्रताप व विष्णु प्रभाकर मिले, उनके साथ काफी अच्छा समय बीता। उन दिनों दिल्ली विवि दो गुटों में विभाजित था। एक लेफ्टिस्ट जिसका प्रतिनिधित्व नामवर सिंह करते थे और दूसरा राइटिस्ट जिसका प्रतिनिधित्व डॉ. नगेंद्र करते थे। दोनों के पक्ष प्रबल थे, नगेंद्र सैद्धांतिक आलोचना तो नामवर सिंह व्यवहारिक आलोचना के आचार्य थे। मेरे दोनों से ही अच्छे संबंध थे। उन दिनों वहां बड़े-बड़े लेखक आते थे, खूब गोष्ठियां होती थीं। मेरी पत्नी ऊषा चौधुरी ने भी रामजस कॉलेज से पढ़ाई की। वह मेरे पिता की ही छात्रा थीं। वह इंद्रप्रस्थ कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं।

• एक बार फिर आपकी पुरानी दिल्ली के बचपन की तरफ लौटेंगे, वहां की कुछ और यादें बताइए?

मुझे दिल्ली में शादियों के आयोजन बहुत पसंद थे। गजब के स्वादिष्ट व्यंजन होते थे। उन दिनों शादी में एक तश्तरी मिलती थी, जिसमें इमरती, पिस्ता, बालू शाही, पीली बर्फी और चीनी वाला लड्डू होता था। इसके अलावा कचौड़ी, पूड़ी और तीखा वाला रायता। जामा मस्जिद के पास शमीम कबाब मिलता था उसके कबाब और गुलाब जामुन में कोई फर्क नहीं होता था।

• कभी दिल्ली पर कुछ लिखने के बारे में नहीं सोचा?

मैंने कभी रचनात्मक लेखन नहीं किया। मेरा विषय तो आलोचनात्मक लेखन का रहा है, लेकिन अब विवेकानंद पर मेरी एक पुस्तक आने वाली है, जिसमें कई जगह दिल्ली का जिक्र है। विवेकानंद की दिल्ली यात्रा का उसमें काफी विवरण है। सस्ता साहित्य मंडल द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में पाठक जरूर दिल्ली दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली को मैंने बहुत जिया तो खूब लेकिन शब्दों में उसे बुन नहीं पाया, अब कुछ लिख रहा हूं। अभी पुस्तक का नाम नहीं सोचा है, पर जल्द ही वो पाठकों को पढ़ने के लिए मिल जाएगी।

• उन दिनों दिल्ली में साहित्यिक अड्डे कहां-कहां होते थे?

दिल्ली में उन दिनों कई साहित्यिक अड्डे हुआ करते थे। खूब गोष्ठियां होती थीं। बड़े-बड़े साहित्यकार आते थे। दिल्ली विवि में एक बड़ा कॉफी हाउस हुआ करता था। वहां अमर्त्य सेन कॉफी पीने आते थे। आर्ट्स फैकल्टी में पहले वेंगर रेस्त्रां होता था जहां आज पुस्तकालय है। वहां पर साहित्यकारों की खूब तीखी बहस होती थी। सभी लेखक वहां एकत्र होकर वाद-विवाद किया करते थे। इसके अलावा कनॉट प्लेस में भी कॉफी हाउस होता था। विष्णु प्रभाकर के साथ हमलोग वहां अक्सर जाते थे। वहां की एक खास बात यह थी कि हम एक कप कॉफी के साथ दो घंटे आराम से बैठते थे। वहां यशपाल जैन, नागार्जुन, अमृत राय आदि आते थे। जनपथ पर टी हाउस भी बड़ा साहित्यिक अड्डा होता था।

• साहित्यकार मित्रों से जुड़े या उस परिवेश के संस्मरण भी होंगे?

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के घर तो खूब जाया ही करते थे। कवि केदारनाथ से भी मेरे घनिष्ठ संबंध थे। वह अक्सर मुझे कविता पाठ सुनाते थे। एक बार मैं उनके पास बैठा था मैंने उन्हें कविता सुनाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे कविता सुनाई हिमालय किधर है? 'मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उधर-उधर-उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी'। सच कहूं तो मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है? इस कविता की पंक्तियां मेरे दिल में बस गईं, जिन्हें मैं आज तक भुला नहीं पाया। इसी तरह एक एक किस्सा जब मैं साहित्य अकादमी का सचिव था तब का बताता हूं। हरिवंश राय बच्चन की 75वीं वर्षगांठ थी। तब मैंने उनके पुत्र अमिताभ बच्चन को साहित्य अकादमी में बुलाया था। पूरा हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। अमिताभ के साथ उनकी पत्नी जया बच्चन भी आई थीं। उज्जैन से शिव मंगल सिंह सुमन को बुलाया था। वह खद्दर के कपड़े पहन कर आए थे। स्वागत भाषण उन्हें देना था। मैंने उन्हें 30 मिनट का समय दिया। उनका भाषण शुरू हुआ तो 30 मिनट से ऊपर हो गया। उनका भाषण रुक ही नहीं रहा था जब एक घंटा से ऊपर हो गया तो मैंने उन्हें घड़ी दिखाकर इशारा किया तो उन्होंने स्टेज पर ही जोर से बोला इंद्रनाथ मुझे घड़ी दिखा रहा है तो अब मैं रुक जाता हूं, लेकिन बच्चन जी की 100वीं वर्षगांठ पर मैं अपना ये भाषण पूरा करूंगा।

• दिल्ली के कला, संस्कृति व साहित्यिक परिवेश का आप पर क्या प्रभाव पड़ा?

मुझे जो कुछ मिला वह सब दिल्ली में मिला है। मेरे जीवन पर यहां के साहित्यिक परिवेश ने ऐसा प्रभाव डाला कि मैंने अंग्रेजी व बांग्ला से ऊपर हिंदी को अपना माना है। दिल्ली विवि में मुझे बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच रहने का मौका मिला जिससे मेरा साहित्य के प्रति लगाव बढ़ता चला गया। बंगाली हूं तो नाट्य प्रेम मेरी रगों में था, इसलिए मंडी हाउस स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एनएसडी) में बच्चों को लेकर नाटक देखने जाता था।

• आपने दिल्ली शहर को कैसे बदलते देखा है?

नई दिल्ली में बंगाली ज्यादा रहते थे। वहां के सरकारी दफ्तर पहले बंगाली बहुल नजर आते थे। आप किसी भी बंगाली के घर जाते तो पानी के साथ दो बताशे से स्वागत किया जाता था अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दिल्ली में पहले बनियों की शादी देखने लायक होती थीं। उनकी शादी का एक अलग ही आकर्षण होता था। दिल्ली में पहले इतना प्रदूषण भी नहीं था। छुट्टी का दिन मतलब लाल किला, इंडिया गेट, चिड़िया घर आदि जगहों पर घूमना होता था, लेकिन अब तो चारों ओर प्रदूषण है। लोगों का कहीं भी आना-जाना दुश्वार हो गया है। प्रदूषण के कारण लोग बिमारियों से जकड़ गए हैं।

ज्यादा शराफत भारी पड़ी और फिर पिता जी की खूब डांट पड़ी

दिल्ली मेरी यादें

कविता लिखने की कोशिश में, टुकड़ा-टुकड़ा वक्त, मौन से संवाद (तीनों कविता-संग्रह) जैसी रचनाएं लिख चुकी डॉ शशि सहगल कई पंजाबी कविताओं का हिंदी अनुवाद भी कर चुकी हैं।

मेरे पिता मुझे पढ़ाने के लिए...अच्छी तालीम देने के लिए दिल्ली लेकर आए थे। ये सन् 1963 की बात होगी। हम राजौरी गार्डन में आकर रहे थे। अब स्कूल में दाखिला लेना था लेकिन मुझे गांव से समझ लिया गया और पढ़ाई में कमजोर भी इसीलिए कहीं भी दसवीं में दाखिला नहीं दे रहे थे। मैंने कहा टेस्ट लीजिए न पास करूं तब तय कीजिए। बहरहाल सरकारी स्कूल ने टेस्ट के बाद दसवीं में दाखिला दिया। एक और रोचक किस्सा बताती हूं, मेरे पिता बहुत सख्त मिजाज रहे, पढ़ाई को लेकर बहुत कठोर रहते थे। हम डरते भी थे उनसे। जब स्कूलिंग खत्म हुई तो तय किया कि कहीं घर से दूर दाखिला लिया जाएगा। अवसर तो कई कॉलेज में मिल रहा था लेकिन मैंने आइपी कॉलेज में दाखिला लिया, जो घर से दूर था। इसके लिए पिता जी को किसी तरह समझा दिया गया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में पढ़ना बहुत शान की बात होती है, पढ़ाई भी बेहतर होती है। कई लोगों ने समझाया तो वो मान भी गए। बस हमारी तो लॉटरी लग गई। कॉलेज का माहौल अच्छा लगने लगा। लेकिन सख्त हिदायत थी कि कॉलेज से इधर-उधर कहीं भी जाना है तो घर पर बताना जरूर है। अब एक बार हम सारी दोस्त फिल्म देखने चली गईं, और घर लौटकर शराफत से पिता जी को मैंने बता दिया, बस फिर क्या था खूब डांट लगी और तब तय किया फिल्म देखने तो जाएंगे लेकिन घर पर नहीं बताएंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से थे। मैं वैसे तो सीधी सादी थी लेकिन पूरे कॉलेज में हमारा ग्रुप शरारतों के लिए पहचाना जाता था। हमारे कॉलेज में पीछे का हिस्सा कच्चा था, वहां खूब आम के पेड़ थे, उन पर लगी अमिया खूब आकर्षित करती थीं, एक दिन उन्हें काटने के लिए घर से ब्लेड लेकर गई, और क्लास खत्म होने के बाद कई डेस्क को मिलाकर पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचकर ब्लेड से खूब अमिया काटीं। अब हमे पता नहीं था वहीं पीछे की तरफ ही अध्यापिकाओं का हॉस्टल भी है। वहां से हमारी एक कड़क मिजाज वाली प्रोफेसर ऊषा ने हमारे ग्रुप को देख लिया। उन्हें हंसी बिलकुल बर्दाश्त नहीं होती थी। अगले दिन क्लास में उन्होंने जो क्लास लगाई, फिर तो क्या कहना था। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सात जन्म में भी नहीं आए। अब जब चुप खड़ी रही तो बोली पढ़ोगी क्यों अमिया तोड़ो। ऐसे ही शरारतों के साथ धीरे-धीरे लिखना भी शुरू कर दिया था और बाद में एमए करने के लिए नॉर्थ कैंपस में आ गए थे। वहां भी मजेदार समय बीता। एक प्रोफेसर थे डॉ सरोज वो हमे बिहारी, रीति काल के कवि पढ़ाते थे। वो शृंगार रस को जितना रस लेकर पढ़ाते उनके उस अंदाज का हम सब खूब मजाक बनाया करते थे। वैसे भी उम्र का एक मौसम होता है, जब पढ़ाई भी खूब करते हैं और मौज मस्ती भी। हमने भी दिल्ली विवि के आर्ट फैकल्टी में खुश मिजाज जिंदगी जी है। इन्हीं दिनों डॉ प्रताप सहगल मिल गए ये विवि में ही शाम की क्लास में होते थे मुझे पता चला कि इन्होंने अच्छे अंकों से विवि में टॉप किया है अब मैं मिलने को उत्सुक हुई भई, देखें तो टॉप करने वाला लड़का पढ़ता कैसे है? बस ऐसे ही पढ़ते-पढ़ाते इश्क हो गया और फिर जिंदगी भर का ही साथ हो गया। एक बात दिल्ली शहर पर भी कहना चाहती हूं, दिल्ली में हम उन दिनों खूब घूमने जाया करते थे लेकिन तब घर से दूर होकर भी महफूज महसूस करते थे अब उस माहौल की कमी खलती है।

मनु त्यागी से बातचीत पर आधारित

दिल्ली की कहानियों को शब्दों में खूब बुना : मन्नू भंडारी

घर की लाठी बुजुर्गों के हाथों में रहती है तो परिवार सुकून में रहता है कि चलो अपनों का सान्निध्य बना हुआ है। साहित्य जगत के साथ भी ऐसा ही है, वह भी अपनी साहित्यिक धरोहर को संजोए रखना चाहता है, उन्हें साथ लेकर, आशीष के साथ आगे बढ़ना चाहता है। पिछले दिनों आयोजित साहित्योत्सव के मंच पर मन्नू भंडारी की उपस्थिति सुखद अनुभूति देने वाली थी। इसी दरम्यान उनसे मुलाकात हुई तो आइए उनके साहित्यिक दिल्ली के संस्मरण से रूबरू होते हैं। पेश हैं प्रियंका दुबे मेहता से बातचीत के प्रमुख अंश :

• मैम चलिए थोड़ा अतीत में चलते हैं, जहां दिल्ली शहर का और मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज में अध्यापन का रोमांच था, क्या कहेंगी उस दौर के बारे में?

सन् 1965 की बात है, जब मैं दिल्ली आई। तब दिल्ली शहर बहुत सुकून भरा और अच्छा होता था। खूब लंबी-चौड़ी तंदुरुस्त दिल्ली और यहां रहने वाले लोग कम। हमारा वास्ता कॉलेज कैंपस और पारिवारिक मित्रों से था। मेरी कहानियां छपीं, प्रचारित हुईं धीरे-धीरे और प्रकाशकों से साहित्यकारों से मेलजोल बढ़ा। विद्यार्थियों में साहित्य को लेकर खास रुचि नहीं थी लेकिन मैंने उन्हें हमेशा कोर्स से बाहर की पुस्तकें पढ़ने को प्रोत्साहित किया तो विवि में विद्यार्थियों के बीच भी साहित्यिक बीज रोपित होने लगा।

• तो क्या दिल्ली विवि में आपने साहित्यिक माहौल की कमी महसूस की?

नहीं ऐसा नहीं है, दिल्ली में साहित्यिक परिवेश था। बहुत से लेखक तो तब दिल्ली विवि में ही पढ़ा रहे थे। विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉ. नगेंद्र, अजित चौधरी और भी बहुत सारे नाम हैं। वो तो दिल्ली का साहित्यिक स्वर्णिम दौर था। लोग खूब पढ़ते-लिखते थे, साहित्यिक गतिविधियां भी बहुत होती थीं। साहित्य समाज के लोग मिलकर तरह-तरह के मंथन करते थे। हर क्षेत्र की बातें होती थी। मिलना जुलना काफी होता था। हां, विद्यार्थी वर्ग में पठन पाठन व लेखन को लेकर इतनी रुचि दिखाई नहीं देती थी जितनी कि जब मैं कोलकाता में थी वहां के स्कूलों में देखती थी।

• साहित्यिक परिवेश को परिपक्व बनाने वाले, संपूर्ण करने वाले साहित्यकारों के बारे में और बताइए?

वरिष्ठ लेखिका मन्नू भंडारी। जागरण

कमलेश्वर, मोहन राकेश, घनिष्ठ मित्रों में अजित, स्नेह आदि लोगों से मिलना होता था। हम सभी लोग मिलकर साहित्य की जमीन को समृद्ध करने की कोशिश करते थे। साहित्यिक बैठकियों का अड्डा कनॉट प्लेस का कॉफी हाउस था। बाद में हमारा घर भी साहित्य चर्चा का संगम बनने लगा। और (याद करते हुए...) नामवर जी से भी मिलना होता था। उनका मिलना अलग ही होता था... (फिर यादों के भंवरजाल में उलझ जाती हैं, चेहरे पर खुशी के भाव एक अलग ही चमक दे रहे थे)। निर्मला जैन से बाद में मुलाकातें बढ़ीं, सत्येंद्र शरद मिलते थे।

• तो आपको इन्हीं साहित्यिक चर्चाओं से लेखन की उमंग, ऊर्जा, दिशा मिलती थी?

लोगों से मिलना जुलना, बातचीत होती थी तो लेखन भी हो जाता था। हालांकि मैं लेखन के लिए अलग सी रहती थी। मेरी आदत ही नहीं थी कि बहुत ज्यादा लोगों या चीजों का प्रभाव मेरे लेखन पर पड़े। मैं वातावरण से विषय लेती थी लेकिन लिखने के लिए अपने मूल अंदाज का ही प्रयोग करती। दिल्ली की धरा से मेरी खूब कहानियां निकली, लेकिन मैंने उन्हें अपने शब्दों और अपने अंदाज में ढालकर लिखा। लेखन की प्रेरणा के लिए मुझे कभी बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं पड़ी।

• क्या लेखन को लेकर आपको विश्वविद्यालय से किसी तरह की प्रेरणा मिलती थी?

जब मैं लिखती थी तो घर से बाहर चली जाती थी। घर के दायित्व लेखन के लिए कहीं न कहीं बाधा बनते थे। ऐसे में महीनेभर घर से बाहर चली जाती थी। उस समय कॉलेज के होस्टल का सहारा मिलता था। 'आपका बंटी' लिखने के लिए महीनों तक मैं होस्टल में कमरा लेकर रही थी।

• पहले लोगों से खूब मुलाकात होती थीं, और अब कितना मिलना जुलना हो पाता है?

अब तो दूरियां बढ़ गई हैं। पहले सभी मित्र कॉलेज कैंपस के आसपास ही रहते थे। हम शक्ति नगर में थे। राकेश जी व कमलेश्वर जी राजेंद्र नगर में रहते थे। अजित कुमार मॉडल टाउन, निर्मला जी माल रोड पर रहती थीं, ऐसे में सभी आसपास ही थे। ज्यादा से ज्यादा दूरी कनॉट प्लेस तक की थी। कभी-कभार किसी रिश्तेदार से मिलना होता था तो बमुश्किल ग्रेटर कैलाश तक जाते थे, वह भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था।

अब सभी मित्र दूर-दूर हो गए हैं और उनसे मिलना जुलना भी कम हो गया, लेखन बंद सा हो गया। पिछले दस बारह सालों से तो केवल फोन पर ही बातें होने लगी।

गणेश और भैरो भी कर रहे आकर्षित

काम की दुकान

एक वक्त था जब महिलाएं सोने-चांदी की ज्वेलरी पसंद करती थीं, अब ट्रेंड बदल गया है और महिलाओं की पसंद भी। अब तो स्टोन से बने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जमाना है। उसमें भी ट्राइबल ज्वेलरी। तरह तरह की आकृतियों और मुखौटे वाली ज्वेलरी की अगर आप भी शौकीन हैं तो जनपथ तिब्बत मार्केट स्थित हिल क्यूरियो दुकान नंबर आठ पर एक बार पहुंच जाएं। यहां ट्राइबल ज्वेलरी कि इतनी वैरायटी है कि आपके लिए तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा लें। बीते 60 वर्षों से यह दुकान जनपथ पर अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी के विशेष कलेक्शन के लिए प्रसिद्ध है।

भारतीय हों या पश्चिमी सभ्यता के परिधान सभी के साथ ट्राइबल ज्वेलरी खूब फबती है। जागरण

मसूरी से आकर बसाई हिल क्यूरियो: कर्मा डोलमा कहती हैं वर्ष 1960 में उत्तराखंड के मसूरी से उनकी सास चंगा देवी रोजगार की तलाश में परिवार के साथ दिल्ली आकर बस गई। रोजी रोटी के लिए उन्होंने जनपथ पर छोटी-सी पटरी लगाकर स्टोन बेचने का काम शुरू किया। इसके लिए वे पहाड़ों से स्टोन इकट्ठे करके लातीं और उन पर तरह-तरह की कलाकारी कर यहां बेचा करती थीं। देखते ही देखते उनका काम चल पड़ा।

युवतियों को आकर्षित करते पूर्वोत्तर राज्यों के नेकलेस: यहां भारत के अलग-अलग ट्राइबल क्षेत्र की पारंपरिक ज्वेलरी से लेकर नेपाल, कनाडा, न्यूजीलैंड, मैक्सिको आदि क्षेत्रों की 10 हजार से अधिक ट्राइबल ज्वेलरी की वैरायटी उपलब्ध हैं। ट्रेंडी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी का खजाना वह भी आपके बजट में कहीं और नहीं मिलेगा।

खुलने का समय : रोजाना सुबह 11 से शाम सात बजे तक।

ऐसे पहुंचे : जनपथ मेट्रो स्टेशन से पैदल जा सकते हैं।

यहां पूर्वोत्तर राज्यों के मुखौटे वाले नेकलेस युवतियों को खूब आकर्षित करते हैं।

आकर्षित करते हैं मुखौटे: यहां एक से बढ़कर एक ट्रेंडी ज्वेलरी देख आप खरीदारी करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कर्मा देश-विदेश से रॉ मटेरियल लाते हैं। फिर अपने अनुसार उस पर कलाकारी करने के बाद डिजाइन भी तैयार करते हैं। यहां आपको नेकलेस, अंगुठी, ब्रेसलेट, हेयर स्टिक, चाबी के छल्ले, पायल, आदि ज्वेलरी एक से बढ़कर एक डिजाइन में मिल जाएंगी। यहां भैरो बाबा, गणेश भगवान सहित अफ्रीकन ट्राइबल के मुखौटे महिलाओं को खूब आकर्षित करते हैं।

-रितु राणा

राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 12 मार्च 2020
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

पेप्सिको ने की एनर्जी मार्केट की सबसे बड़ी डील

मार्च : एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट की अग्रणी कंपनी पेप्सिको ने रॉकस्टार बेवरेजज को 385 करोड़ डॉलर (करीब 28 हजार करोड़) में खरीद लिया है। इस सौदे के बाद एनर्जी मार्केट में कोकाकोला और पेप्सिको के बीच लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा में पेप्सिको को फायदा मिल सकता है। कंपनी के नए प्रमुख रेमॉन लैगुआर्ता इसकी चीनी और नमक आधारित पेय पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत कंपनी ने यह सौदा किया है। (रायटर)

पूरी बैंकिंग सेवा जल्द से जल्द शुरू करने के लिए आरबीआइ से लगातार विमर्श जारी है। अगले कुछ दिनों में निवेश पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

— प्रशांत कुमार
प्रशासक, यस बैंक

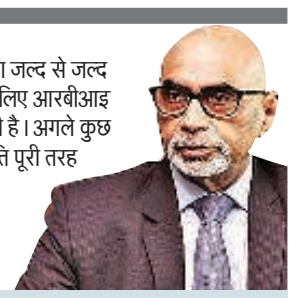

सेंसेक्स	35,697.40 ▲ 62.45	निफ्टी	10,458.40 ▲ 6.95	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 44,517 ▼ ₹516	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 47,234 ▲ ₹146	$ डॉलर	₹ 73.61 ▼ ₹0.56	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 35.95

पांच निर्यात क्षेत्रों में चीन को पछाड़ने की तैयारी

पहल ▶ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने गुरुवार को सभी साझेदारों की बैठक बुलाई है

फार्मा सेक्टर की सप्लाई चेन को सुगम बनाने के लिए तैयार पैकेज की समीक्षा

राजीव कुमार, नई दिल्ली

कोरोना ने जहां विश्व समुदाय को आशंकित-आतंकित कर दिया है, वहीं भारत इसके नकारात्मक असर में भी एक अवसर तलाश रहा है। विश्व निर्यात के पांच क्षेत्रों में भारत चीन का विकल्प बनने की तैयारी में जुट गया है। इस अवसर को भुनाने के लिए गुरुवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सभी साझेदारों की बैठक बुलाई है। बैठक में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि होंगे। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिकल आइटम, व्हीकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल व क्लोदिंग एसेसरीज एवं लेदर जैसे क्षेत्रों में भारत विश्व निर्यात बाजार में चीन का प्रतिद्वंद्वी देश है। अभी चीन निर्यात करने में सक्षम नहीं है। चीन की इसी अक्षमता का भारत फायदा उठाना चाह रहा है। इन पांच क्षेत्रों के अलावा झींगा, मिनरल ऑयल, कॉटन फाइबर्स, यार्न और कॉपर जैसे क्षेत्रों में भी नए निर्यात बाजार की तलाश की जा रही है। होमवेयर, लाइफस्टाइल गुड्स, सेरामिक टाइल्स जैसे क्षेत्रों में भी दुनिया के बाजार को भारत से सप्लाई मिलने की उम्मीद है।

वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को प्रस्तावित बैठक में उन आइटम के वैकल्पिक बाजारों की तलाश पर भी विचार किया जाएगा जिनके लिए भारत चीन पर काफी हद तक निर्भर है। इनमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स और दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल (एपीआइ) शामिल हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक वैश्विक सप्लाई चेन में चीन से पैदा हुई रिक्तता को भरने के लिए सिर्फ व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि चीन में 90 फीसद बड़ी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि 60 फीसद प्रवासी श्रमिक अभी चीन में काम पर वापस नहीं आए हैं। चीन सरकार ने मार्च के अंत तक 80 फीसद उत्पादन को दोबारा शुरू करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक चीन के जियांग्सू स्थित फार्मा इंडस्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। भारत ने वर्ष 2019 में दवा निर्माण के लिए 1.8 अरब डॉलर (करीब 12,600 करोड़ रुपये) के कच्चे माल का आयात जियांग्सू से किया था।

इलेक्ट्रिकल्स, व्हीकल्स और केमिकल्स निर्यात बढ़ाने का इरादा है। प्रतीकात्मक

ऑटो के उत्पादन पर विपरीत असर

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के अध्यक्ष राजन वढ़ेरा ने कहा है कि चीन से सप्लाई चेन प्रभावित होने से बीएस-6 के यात्री वाहन, कॉमर्शियल वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन पर विपरीत असर होगा। इससे बीएस-6 वाहनों की सप्लाई प्रभावित होगी। भारत हर साल 4.7 अरब डॉलर (करीब 33,000 करोड़ रुपये) का ऑटो कंपोनेंट भी चीन से आयात करता है जो ऑटो कंपोनेंट के कुल आयात का 27 फीसद है।

ऐसे छोड़ेंगे चीन को पीछे

- वाणिज्य मंत्रालय विश्व बाजार में चीन के गैप को भरने के लिए संबंधित पांच क्षेत्रों के मंत्रालयों के साथ मिलकर प्लान बनाएगा
- सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाएगा
- निर्यात को ध्यान में रखते हुए अधिक उत्पादन किया जाएगा
- भारतीय मैन्यूफैक्चरर्स के लिए बिजनेस2बिजनेस (बी2बी) बैठक आयोजित करने में मदद की जाएगी

फार्मा सेक्टर के लिए ये कदम

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से उत्तरी चीन से फार्मा उत्पाद की शिपमेंट को एयरलिफ्ट करने के लिए दो कार्गो कंपनियों की पहचान की गई है, इन्हें मंजूरी दी जा सकती है
- फार्मा के कच्चे माल के बंद पड़े प्लांट को सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन शुरू करने की मंजूरी मिल सकती है
- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के फार्मा क्लस्टर को इंसेंटिव देने की घोषणा हो सकती है
- उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंजूरी की शर्त में ढील संभव

टेलीकॉम कंपनियों को बकाया भुगतान के लिए मोहलत संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाये पर टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार उन्हें भुगतान के लिए और समय दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी यही बताया जाएगा कि सिर्फ वक्त बढ़ाया जा रहा है, लेकिन राशि पूरी चुकानी होगी। संचार मंत्रालय की ओर से इस आशय का कैबिनेट नोट तैयार किया गया है जिस पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में विचार होने की संभावना है। इस बीच, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बुधवार को दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश से मुलाकात की। मित्तल ने इस मुलाकात में कहा कि एयरटेल पर एजीआर मद में 13,000 करोड़ रुपये की देनदारी बनती है और उसने इसका भुगतान कर दिया है।

एजीआर बकाए पर सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर के फैसले के तहत टेलीकॉम कंपनियों ने कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये के बकाये में से अभी तक मात्र लगभग 26 हजार करोड़ रुपये की राशि दूरसंचार विभाग को अदा की है। जबकि बाकी रकम अदा करने में वे आनाकानी कर रही हैं। वोडाफोन और भारती एयरटेल ने तो अपने आंतरिक आकलन के आधार पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) के आकलन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

हालांकि बकाए को विवादास्पद बनाये रखने का उनका ये पैंतरा सरकार पर चलता नहीं दिख रहा है। बुधवार को लोकसभा में संचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक लगभग 25,900 करोड़ रुपये की रकम का ही भुगतान किया है। लेकिन 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई से पहले सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से पूरी रकम अदा करने को कहा है।

टेलीकॉम सेक्टर में एकाधिकार तथा समूहबंदी पर अंकुश लगाने के लिए एंट-ट्रस्ट कानून बनाए जाने के प्रश्न पर धोत्रे ने कहा कि 'ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।'

तैयारी

- सरकार ने तैयार किया कैबिनेट नोट, शुक्रवार को हो सकता है विचार
- टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक 1.47 लाख करोड़ के बकाये में मात्र 26 हजार करोड़ रुपये चुकाए

यस बैंक में कुछ दूसरे निजी बैंक भी करेंगे निवेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संकट से जूझते यस बैंक को उबारने की योजना तैयार है और इसकी घोषणा अगले दो दिनों के भीतर कर दी जाएगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने मिलकर जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक बैंक में 49 फीसद हिस्सेदारी लेने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई में यस बैंक के कारोबार व इसके ग्राहकों पर नकदी निकासी की पाबंदी शनिवार को हटा ली जाएगी। एसबीआइ फिलहाल प्राइवेट सेक्टर के कुछ दूसरे बैंकों के साथ मिलकर यस बैंक में कुल 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम एसबीआइ करेगा। शेष राशि का इंतजाम देश के कुछ प्रमुख प्राइवेट बैंकों को इक्विटी हस्तांतरित करके किया जाएगा। इस मुद्दे से जुड़े जानकारों के मुताबिक देश के तीन प्रमुख प्राइवेट बैंक आइसीआइसीआइ, एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा के साथ निवेश की संभावना तलाशी जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक एसबीआइ पहले ही यस बैंक में 49 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2,450 करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है। लेकिन यस बैंक में नियमन संबंधी मानकों को पूरा करने और रोजाना के संचालन के लिए फिलहाल 20 हजार करोड़ रुपये की और दरकार होगी। इसमें 10 हजार करोड रुपये का इंतजाम एसबीआइ करेगा जबकि उम्मीद है कि नए निवेशक 10 हजार करोड़ रुपये लगाएंगे। उधर, यस बैंक के बांड्स (एटी-1) में निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों के साथ भी आरबीआइ में विमर्श शुरू हो गया है। इस बांड्स में खुदरा निवेशकों ने 8,800 करोड़ रुपये का निवेश किया है। दोनो पक्षों के बीच पांच एटी-1 बांड्स के बदले यस बैंक का एक इक्विटी शेयर देने के विकल्प पर विचार हो रहा है। विमर्श शुरू होने के बाद इस बांड्स में निवेश करने वाले निवेशकों के समूह ने यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन प्लान के खिलाफ हाई कोर्ट में जाने की योजना फिलहाल टाल दी है।

यस बैंक ने अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए ये बांड्स जारी किए थे। इस बांड्स में खुदरा निवेशकों के अलावा बड़ी राशि निप्पों, लार्सन व टूब्रो जैसे कई म्यूचुअल फंड्स के अलावा एसबीआइ पेंशन फंड्स, एनपीएस ट्रस्ट फंड, आइओसी कर्मचारी भविष्य निधि समेत कई दूसरी कंपनियों ने भी किया है। पिछले शुक्रवार को आरबीआइ की तरफ से जिस रिकंस्ट्रक्शन प्लान का एलान किया गया था, उनमें इन बांड्स निवेशकों का कोई जिक्र नहीं था और यह माना गया है कि 8,800 करोड़ रुपये का निवेश शून्य हो गया है। अब ऐसा लगा रहा है कि अंतिम योजना में इन्हें भी कुछ इक्विटी मिलेगी।

- यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन प्लान का अंतिम मसौदा तैयार
- एसबीआइ के बाद तीन निजी बैंकों ने भी जताई निवेश की इच्छा

प्रतीकात्मक

सस्ते कच्चे तेल की खुशी पर वैश्विक मंदी का भय भारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अगर कोरोना का कहर नहीं होता तो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब 50 फीसद गिरावट से शेयर बाजार में निवेशक चांदी काट रहे होते। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से वैश्विक मंदी का खतरा गहरा रहा है, उसे देखते हुए निवेशक समुदाय में जबरदस्त अनिश्चितता है। इसका असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर दिख भी रहा है। इसके बावजूद सस्ते क्रूड की वजह से केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के दूसरे मोर्चों पर फायदा होना तय है। विशेषज्ञों के मुताबिक सस्ता कच्चे तेल की वजह से अगले वित्त वर्ष के दौरान न सिर्फ चालू खाते में घाटे में कमी आएगी बल्कि महंगाई की दर को थामने में भी काफी आसानी होगी।

बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि रूस और सउदी अरब के बीच कच्चे तेल की कीमत को लेकर आपसी खींचतान अभी जारी रहेगी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरैमको ने बुधवार को फिर कहा है कि वह रोजाना तेल उत्पादन (क्रूड) 10 लाख बैरल बढ़ाकर 1.30 करोड़ बैरल करने जा रही है। सऊदी अरब का पक्ष लेते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने भी क्रूड उत्पादन 10 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की बात कही है। प्रतिद्वंदी रूस पहले ही कह चुका है कि वह अगले करीब छह महीनों तक 30 से 40 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर क्रूड बेच सकता है। इन घोषणाओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एजेंसी गोल्डेन सैक्श ने कहा है कि वर्ष 2020-21 में क्रूड की कीमत 40 डॉलर प्रति बैरल तक रह सकती है। अग्रणी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में सालाना औसत कीमत 40 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय तेल कंपनियों ने बुधवार (11 मार्च, 2020) को अंतरराष्ट्रीय बाजार में 34.52 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड की खरीदारी की है। जबकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में भारतीय कंपनियों ने 48.4 डॉलर प्रति बैरल की दर से क्रूड की बुकिंग की थी।

कोटक महिंद्रा बैंक की इक्विटी शोध टीम की रिपोर्ट कहती है कि भारत की इकोनॉमी को सस्ता क्रूड कई तरह से फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहला तो यह कि चालू खाता घाटा (निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा व आयात पर खर्च विदेशी मुद्रा का अंतर) वर्ष 2020-21 के दौरान 0.75 फीसद तक कम हो सकता है। इसका कहना है कि क्रूड की कीमत 10 डॉलर प्रति बैरल सस्ता होता है तो भारत के आयात बिल में 15 अरब डॉलर (करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये) तक की कमी होगी। साथ ही यह महंगाई की दर में भी 0.30 फीसद कम करने में मदद देता है। सस्ता क्रूड दर्जनों उद्योगों को परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर फायदा देता है। मसलन, यह नागरिक उड्डयन कंपनियों के लिए संचालन लागत को कम करेगा। पेट्रोल-डीजल सस्ता होने से ज्यादा लोग गाड़ी खरीदने पर विचार करते हैं, जिसका फायदा ऑटोमोबाइल कंपनियों को मिलेगा। संचालन लागत कम होने से सीमेंट व उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों जैसे दूसरे सेक्टर को भी परोक्ष तौर पर फायदा होता है। तेल मार्केटिंग कंपनियों की मार्जिन में सुधार होता है। सस्ता क्रूड सरकार के राजस्व में भी इजाफा करता है। यह इसलिए होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोलियम उत्पादों पर स्थिर दर से केंद्र शुल्क लगाया जाता है।

प्रतीकात्मक

क्रूड 10 डॉलर सस्ता होने से

- शेयर बाजार में मंदी, लेकिन क्रूड से सुधरेगा केंद्र का खजाना प्रबंधन
- चालू खाते में घाटे में करीब 1.05 लाख करोड़ रुपये की कमी
- महंगाई की दर में 0.30 फीसद की कमी का अनुमान

खाताधारकों को फायदा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

एसबीआइ ने अपने 44.51 करोड़ बचत खाताधारकों को अपने खाते में निश्चित मासिक राशि रखने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया। अब एसबीआइ के बचत खातधारकों के लिए अपने खाते में न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होगी। अभी ऐसा नहीं करने पर खाताधारकों को पेनाल्टी देना होता है। यह पेनाल्टी 5-15 रुपये तक की होती है जिसमें अलग से टैक्स भी जोड़ा जाता है। एसएमएस सेवा के बदले तिमाही रूप में लगने वाले शुल्क को एसबीआइ ने समाप्त कर दिया है। एसबीआइ के नियम के मुताबिक अभी मेट्रो शहर के बचत खाताधारकों को अपने खाते में मासिक रूप से औसतन 3,000 रुपये रखना अनिवार्य है। वहीं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के खाताधारकों को मासिक रूप से औसतन 2,000 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र के खाताधारकों को अपने खाते में मासिक रूप से औसतन 1,000 रुपये रखना अनिवार्य है। जन धन खातों को पहले से ही न्यूनतम बैलेंस से मुक्त रखा गया है।

फसल करार करने वाला किसान अब उपभोक्ता

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बीज कंपनी की अपील, 25 हजार रुपये हर्जाने का आदेश दिया
- कहा, ऐसे किसानों को उपभोक्ता कानून के दायरे में नहीं मानने का मतलब कानून का मजाक बनाना

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट कहा है कि बीज कंपनी के साथ वापस फसल खरीदने का करार करने वाला किसान उपभोक्ता है और उसे उपभोक्ता कानून के तहत माना जाएगा। कोर्ट ने ऐसे किसान को उपभोक्ता मानने का विरोध कर रही बीज कंपनी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसे किसान को उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर करना कानून के उद्देश्य का मजाक बनाना होगा। कोर्ट ने बीज कंपनियों द्वारा किसानों को बेवजह मुकदमेबाजी में फंसाकर परेशान और प्रताड़ित करने पर कड़ी टिप्पणी करते हुए बीज कंपनी को ऐसे सभी मामलों में 25,000 रुपये हर्जाना भी भरने का आदेश दिया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौडर और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने बीज कंपनी मैसर्स नंदन बायोमैट्रिक्स लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसान को उपभोक्ता विवाद निवारण कानून, 1986 के तहत उपभोक्ता मानने वाले राज्य व राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। कोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम को आदेश दिया है कि वह किसान की शिकायत तीन महीने के भीतर निपटाए। कोर्ट ने बीज कंपनियों की किसानों को बेवजह मुकदमेबाजी में फंसा कर परेशान करने की प्रवृत्ति पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा करके वास्तव में जल्द राहत देने के उपभोक्ता कानून के उद्देश्य को ही निष्फल किया जा रहा है। छोटे-छोटे किसानों की जिला उपभोक्ता फोरम में की गई शिकायत की योग्यता पर ही सवाल उठाकर छोटे किसानों को बेवजह मुकदमेबाजी में घसीटा जाता है। कई बार तो मुकदमेबाजी का खर्च मांगी गई राहत से भी अधिक हो जाता है। इससे किसान प्रताड़ित होते हैं। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में बीज कंपनियों और अन्य बीज निगमों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अपील दाखिल करने वाली बीज कंपनी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगना चाहिए।

कोर्ट ने फैसले में भारत में खेती के क्षेत्र की दिक्कतें और भारत के छोटे किसानों की दुश्वारियों का जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि छोटे किसान कई बार जीवन-यापन की आय जुटाने और थोड़ा लाभ कमाने के लिए बीज कंपनियों के साथ उनकी शर्तों पर फसल उगाने का करार कर लेते हैं। जैसा कि इस मामले में हुआ। यह कहने की जरूरत नहीं कि फसल की सफलता या असफलता किसान को बना या बिगाड़ देती है। कई बार छोटे किसान ऐसा करार करके स्वयं को फंसा हुआ पाते हैं। उन्होंने बीज कंपनी से मंहगा बीज खरीदा होता है और वह बीज खराब निकल जाता है जिससे फसल खराब होती है और किसान गंभीर वित्तीय संकट में आ जाता है। उसकी कर्ज की स्थिति और खराब हो जाती है और कई किसान तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। पिछले कुछ दशकों से किसानों की आत्महत्या एक मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता कानून के तहत संक्षिप्त सुनवाई में मिलने वाली राहत छोटी हो सकती है लेकिन वह परेशानी में फंसे किसान को तत्काल राहत पहुंचाने का बड़ा जरिया है। कोर्ट ने कहा कि बीज कंपनियों के खिलाफ शिकायत रखने वाले किसान दीवानी मुकदमा या बीज अधिनियम 1966 जैसे और भी उपाय अपना सकते हैं लेकिन किसानों को उपभोक्ता कानून के दायरे से बाहर करना उपभोक्ता कानून के उद्देश्य को पूरी तरह मजाक बनाने जैसा होगा।

क्या था मामला : यह मामला केरल की महिला किसान का था जिसने 2003 में बीज कंपनी का विज्ञापन देखकर उसके साथ सफेद मुसली की फसल उगाने का करार किया। इसमें महिला ने 400 रुपये प्रति किलो की दर से 750 किलो मुसली का बीज खरीदा और बोया। बीज कंपनी को कम से कम 1,000 रुपये प्रति किलो की दर से वापस फसल खरीदनी थी। किसान का आरोप था कि बीज कंपनी ने वापस फसल खरीदने के करार का पालन नहीं किया। किसान ने कंपनी के खिलाफ केरल की कोझीकोड जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटीएन पर उठाए 17 सवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस द्वारा तैयार किए गए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के 17 हिस्सों को लेकर असंतोष जताया है। मंत्रालय का कहना है कि इन खामियों के चलते कारोबारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा नेटवर्क के तहत जम्मू कश्मीर के करदाताओं, आधार सत्यापन और सर्वर की मापन क्षमता जैसी खामियां सामने आ रही हैं। इस संबंध में सफाई देने के लिए कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणि को 14 मार्च को जीएसटी काउंसिल में तलब किया गया है।

इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि कुछ नेटवर्क के कुछ दूसरे हिस्सों में भी सुधार नहीं किया गया है या देर से सुधार हुआ है। कुछ सॉफ्टवेयर अभी तक डिलीवर नहीं किए गए हैं। मंत्रालय ने देश से बाहर प्वांइट ऑफ सेल के लिए नए कोड की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। इस संबंध में पिछले वर्ष की शुरुआत में ही फैसला लिया गया था। जीएसटी नेटवर्क बनाने के लिए इन्फोसिस को 2015 में चुना गया था। तब से अब तक कई बार मंत्रालय इस नेटवर्क में खामियों की बात कह चुका है। कुछ सुधार तो पिछले दो वर्ष से लंबित हैं। इन्फोसिस से कहा गया है कि वह तुरंत ही इन खामियों को दूर करे और 17 अन्य क्षेत्रों में भी सुधार करने का प्रबंध करे। मंत्रालय ने इस संबंध में कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलेकणि को तलब कर शनिवार को जीएसटी काउंसिल की प्रस्तावित बैठक में शामिल होने और सुधार के लिए प्रस्तुति देने को कहा गया है। सरकार ने इन्फोसिस को चेताया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीएसटीएन की गड़बड़ियों के चलते करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इन्फोसिस जैसी अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी से इस तरह की गड़बड़ियों की उम्मीद नहीं की जाती है।

- इन्फोसिस को व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा गया
- कंपनी के चेयरमैन 14 मार्च को जीएसटी काउंसिल में तलब

राहत

सोमवार की भारी गिरावट के बाद बुधवार को सेंसेक्स 62 अंक सुधरा, वैश्विक चिंता के चलते शुरुआती तेजी नहीं रह सकी बरकरार

निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी से घरेलू शेयर बाजारों में दिखा सुधार

मुंबई, प्रेट्र : घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली। इस दौरान देश के प्रमुख शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार समाप्त होने की घंटी बजने के समय बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 62.45 अंकों की बढ़त के साथ 35,697.40 के स्तर पर था। हालांकि इंट्रा-डे के दौरान इसमें 386 अंकों की बढ़त देखी गई। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी सकारात्मक रहा। यह 6.95 अंक सुधार के साथ 10,458.40 के स्तर पर थमा। सोमवार को दुनियाभर के शेयर बाजारों में कोरोना का कहर दिखा और सेंसेक्स 1,941.67 अंक लुढक गया था।

मंगलवार को होली के अवसर पर बंद रहने के बाद बुधवार को सेंसेक्स पैक में हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आइसीआइसीआइ बैंक और एलएंडटी के शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एसबीआइ और इन्फोसिस के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। बीएसई के सेक्टोरल इंडेक्स में एनर्जी, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स में 2.11 परसेंट सुधार देखने को मिला। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, मेटल, आइटी और कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के शेयर लाल निशान पर रहे।

जानकारों के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी पर कोरोना के प्रभाव की चिंता निवेशकों को खरीदारी से रोक रही है। निचले स्तर पर होने के बावजूद शेयर बाजारों में अधिक खरीदारी नहीं हुई। कारोबारी सत्र में 386 अंक चढ़ने के बाद सेंसेक्स अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल नहीं हो सका। इसके अलावा देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से भी बाजार में निराशा देखने को मिल रही है। इस दौरान एशिया सहित दुनियाभर के शेयर बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है। बुधवार को शंघाई, हांगकांग, सियोल और टोक्यो के शेयर बाजार एक बार फिर गिरावट का शिकार हुए।

सोना गिरा, चांदी संभली

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरपट दौड़ रहे सोने के भाव में बुधवार को विदेशी बाजारों की नजर लग गई। दिन के कारोबार के आखिर में सोना 516 रुपये की गिरावट के बाद 44,517 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं चांदी के भाव में सुधार देखने को मिला। यह 146 रुपये की बढ़त के साथ 47,234 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। जानकारों के मुताबिक डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में सुधार के चलते सोना कुछ कमजोर हुआ। बुधवार को ग्लोबल मार्केट में सोना 1,661 डॉलर और चांदी 17.03 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

इन शेयरों में रही गहमागहमी

आरआइएल : पिछले सत्र की भारी गिरावट से उबरते हुए बुधवार को कंपनी के शेयर बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। बीएसई में आरआइएल के शेयर 3.60 परसेंट की तेजी के साथ 1,153.25 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके। एनएसई में भी कंपनी के शेयरों में 3.40 परसेंट का उछाल देखने को मिला। इससे पहले सोमवार को इसके शेयरों में 12 परसेंट तक की गिरावट दर्ज की गई थी।

यस बैंक : यस बैंक का मौजूदा संकट जल्द खत्म होने की उम्मीदों के बीच पिछले दो कारोबारी सत्रों से निवेशकों ने बैंक के शेयरों ने अच्छी वापसी की है। बुधवार को बीएसई में बैंक के शेयर 35.53 परसेंट उछाल के साथ 28.80 रुपये और एनएसई में 36.71 परसेंट की तेजी के साथ 29.05 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। पिछले सत्र के दौरान भी इनमें 31 परसेंट तक की तेजी देखने को मिली थी। गौरतलब है कि इस संकटग्रस्त बैंक को उबारने का जिम्मा एसबीआइ ने अपने हाथों में ले लिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

टाटा : टाटा मोटर्स के शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को लगातार पांचवे में सत्र में कंपनी के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई में इसके शेयर 6.43 परसेंट लुढ़ककर 99 रुपये और एनएसई में 6.95 परसेंट की गिरावट के साथ 98.35 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए। इस महीने की चार तारीख से टाटा मोटर्स के शेयर लाल निशान पर बने हुए हैं। तब से अब तक इसके शेयरों 24 परसेंट तक खिसक गए हैं।

अन्य शेयर बाजारों का हाल

- गिरावट से चिंतित दक्षिण कोरिया ने शॉर्ट सेलिंग पर लगाई रोक
- पिछले महीने कोस्पी छह परसेंट और इस महीने अब तक चार परसेंट गिरा
- इंडोनेशिया ने तेज गिरावट से निपटने के लिए कारोबारी सत्र के दौरान विराम की नीति अपनाई
- इंडोनेशिया का प्रमुख सूचकांक इस सप्ताह 5.7 परसेंट और फरवरी के दौरान आठ परसेंट का लगा चुका है गोता।
- अमेरिकी शेयर बाजार भी गिरावट से नहीं हैं अछूते, – सोमवार को डाऊ जोन्स 2,000 अंक तक था खिसका
- ताइवान भी कर रहा शॉर्ट सेलिंग पर पाबंदी लगाने का विचार

रूस में व्लादिमीर पुतिन ताजिंदगी राष्ट्रपति !

2036 तक बने रह सकते हैं पद पर

संसद ने पारित किया प्रस्ताव

मॉस्को, रायटर : रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सन 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस समय वह 67 साल के हैं, इस लिहाज से वह 83 साल की उम्र तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। सैन्य क्षमता में दुनिया के दूसरे शक्तिशाली देश रूस में यह संवैधानिक बदलाव कुछ वैसे ही हुआ है जैसे कि दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति चीन में शी चिनफिंग के जीवन भर राष्ट्रपति बने रहने को लेकर हुआ था। जाहिर है... रूस में पुतिन की मजबूती से अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा।

रूस में राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का दूसरा कार्यकाल 2024 में पूरा होने वाला है। रूस की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन बुधवार को देश की संसद के निचले सदन ड्यूमा ने एक प्रस्ताव पारित कर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बनाए रखने पर मुहर लगा दी। प्रस्ताव के समर्थन में 383 मत पड़े, विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। 43 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया जबकि 24 सदस्य सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहे। कुछ घंटों बाद 170 सदस्यों वाले उच्च सदन फेडरल काउंसिल ने भी यह प्रस्ताव पारित कर दिया। वहां पर प्रस्ताव के समर्थन में 160 मत पड़े जबकि विरोध में एक। तीन सदस्य मतदान से दूर रहे। इस प्रस्ताव के अनुसार पुतिन के राष्ट्रपति पद के पिछले सारे कार्यकालों को शून्य घोषित कर दिया गया है, हालांकि किसी अन्य व्यक्ति के लिए अधिकतम दो बार राष्ट्रपति बने रहने का प्रावधान बरकरार है। प्रस्ताव पारित होने के बाद ड्यूमा के स्पीकर याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा, देश के विकास के लिए पुतिन का राष्ट्रपति बने रहना जरूरी है। इसीलिए राष्ट्रहित में ड्यूमा ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

मॉस्को में बुधवार को ड्यूमा ने प्रस्ताव पारित कर व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बनाए रखने पर मुहर लगा दी। रायटर

जनवरी में दिए थे संकेत, विपक्ष का विरोध

पुतिन ने संवैधानिक बदलाव की घोषणा जनवरी में तभी कर दी थी जब दिमित्री मेदवेदेव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा लिया गया था। लेकिन तब यह भी कहा था कि वह 2024 के बाद राष्ट्रपति पद पर नहीं रहना चाहते। लेकिन अब 2024 में उनके फिर से दो कार्यकाल (12 वर्ष) के लिए राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि पुतिन कहते रहे हैं कि वह सोवियत कालीन नेतृत्व परंपरा के विरोधी हैं जिसमें राष्ट्रपति के पास ताजिंदगी पद रहता था। पुतिन के आलोचक विपक्ष के नेता एलेक्सेई नावेल्नी ने इसे पुतिन के पर्यंत राष्ट्रपति बने रहने की कोशिश करार दिया है। संयुक्त विपक्ष ने शुक्रवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन का एलान किया है।

पांच हजार तालिबान कैदियों को रिहा करेगी अफगान सरकार

शांति समझौता

- राष्ट्रपति गनी ने तालिबान कैदियों की रिहाई के आदेश पर किए दस्तखत
- तालिबान ने रिहाई प्रक्रिया में लगाई गई शर्त को मानने से किया इन्कार

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान सरकार अमेरिका और आतंकी संगठन तालिबान के बीच फरवरी में हुए शांति समझौते के तहत तालिबान के पांच हजार कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान कैदियों की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस आदेश के तहत आगामी 15 दिनों में 1,500 कैदी रिहा किए जाएंगे। बाकी कैदियों की रिहाई अफगान शांति वार्ता में प्रगति और हिंसा में कमी दिखने पर होगी। तालिबान ने हालांकि इस शर्त को मानने से इन्कार कर दिया है और इसे समझौते का उल्लंघन बताया है।

दो पेज के रिहाई आदेश के मुताबिक, रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों को लिखित गारंटी देना अनिवार्य होगा कि वे दोबारा युद्ध के मैदान में कदम नहीं रखेंगे। तालिबान कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया अगले चार दिनों में शुरू हो जाएगी। 15 दिनों तक रोजाना 100 कैदी छोड़े जाएंगे। इस दौरान तालिबान भी बंधक बनाए गए एक हजार अफगान सैनिकों को छोड़ेगा।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की फाइल फोटो। रायटर

क्या है अमेरिका-तालिबान समझौता : अफगानिस्तान में 19 वर्ष से जारी खूनी संघर्ष को खत्म करने के प्रयास में अमेरिका और तालिबान के बीच गत 29 फरवरी को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में अफगानिस्तान से अमेरिका की अगुआई वाली विदेशी सेना की चरणबद्ध वापसी और अफगान और तालिबान के बीच सीधी शांति वार्ता की बात कही गई है। तालिबान ने यह वादा किया है कि उसके पांच हजार कैदियों की रिहाई होने पर अफगान सरकार के साथ बातचीत होगी।

सुरक्षा परिषद ने शांति समझौते का किया समर्थन : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका और तालिबान के बीच हुए शांति समझौते का समर्थन किया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को सर्वसम्मिति से समझौते को स्वीकार किया। परिषद में यह समझौता अमेरिका ने पेश किया था।

न्यूज गैलरी

अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश पर चार भारतीय गिरफ्तार

न्यूयॉर्क : अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने पर चार भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिकी सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते अवैध तरीके से देश की सीमा में दाखिल हुए छह लोगों को पकड़ा गया था, इनमें चार भारतीय हैं। इन लोगों को कनाडा सीमा से सटे न्यूयॉर्क प्रांत में पकड़ा गया था। न्यूयॉर्क स्थित मसेना बॉर्डर पेट्रोल अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए लोग दो कार में सवार थे। उनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कार ड्राइवरों पर मानव तस्करी का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। मसेना स्टेशन के गश्ती दल के प्रमुख वेड लॉगमैन के अनुसार, पिछले कई महीनों से अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। (प्रेट्र)

होटल के मलबे से 69 घंटे बाद जिंदा निकला चीनी नागरिक

बीजिंग : चीन में ढही होटल की इमारत के मलबे से 69 घंटे बाद एक व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। क्वांझू शहर में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को निगरानी के लिए इस होटल में रखा गया था। सोमवार आधी रात को होटल के ढह जाने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। नौ लोग अभी लापता हैं। मलबे से निकाला गया व्यक्ति बुरी तरह घायल है। (एपी)

इटली में लगाई गईं राष्ट्रव्यापी पाबंदियां

प्रकोप ▸ दक्षिण कोरिया में बुधवार को 242 नए मामलों की हुई पुष्टि

अमेरिका में भी कोरोना वायरस से 31 की गई जान

जेनेवा, एजेंसियां : कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रमुख एंजेलो बोरेली ने बताया कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले 90 फीसद लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के थे। वायरस के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए छह करोड़ की आबादी वाले इस यूरोपीय देश में राष्ट्रव्यापी पाबंदियां लगाई गई हैं। सभी खेल आयोजनों को रद करने के साथ ही स्कूलों, विश्वविद्यालयों, सिनेमाघर और संग्रहालयों को बंद कर दिया गया है। स्पेन और पुर्तगाल समेत कई देशों ने इटली आने-जाने वाले विमानों और ट्रेनों पर दो हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।

अमेरिका के 30 राज्यों में पहुंचा वायरस: अमेरिका में 30 से ज्यादा राज्यों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। नतीजन कई राज्यों ने इमरजेंसी का एलान कर दिया है। वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। अब तक 1,037 लोग संक्रमित पाए गए हैं।

दक्षिण कोरिया में फिर बढ़े नए मामले : दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के नए मामलों में 11 दिन की गिरावट के बाद फिर तेजी आ गई है। बुधवार को 242 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक दिन पहले महज 35 मामले सामने आए थे। नए मामलों में से करीब 90 सियोल में पाए गए। इनमें से 62 का संबंध एक कॉल सेंटर से बताया जा रहा है।

इटली की सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले यह प्रतिबंध उत्तरी इटली पर लागू था। तस्वीर मिलान शहर की एक सब-वे ट्रेन की है। आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण इटली के मिलान, रोम और वेनिस में सन्नाटा पसरा है। एपी

सबसे प्रभावित देश		
देश	मौत	संक्रमित
चीन	3161	80,909
इटली	827	10,149
ईरान	291	8042
दक्षिण कोरिया	60	7755
स्पेन	36	1695
फ्रांस	33	1784
अमेरिका	31	1037
जापान	17	1283

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कोरोना वायरस प्रभावित वुहान शहर का दौरान किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को उनके घरों में रखने के लिए वुहान कम्युनिटी का आभार जताया। जिनपिंग ने हाथ हिलाकर इन लोगों का भी अभिवादन स्वीकार किया। रायटर

वुहान में कामकाज बहाल करने की अनुमति

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कोरोना वायरस के केंद्र वुहान शहर का दौरा किया और चिकित्सा स्टाफ व अधिकारियों के प्रयासों की तारीफ की। बुधवार को चीन में 22 मौत हुईं और 31 नए मामले सामने आए। नए मामलों में गिरावट के मद्देनजर मध्य चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में बंद पड़े कामकाज को दोबारा शुरू करने को कहा गया है। कई कारोबार को कहा गया है कि वे अपना कामकाज दोबारा शुरू कर सकते हैं। चीन ने छह करोड़ की आबादी वाले हुबेई में आवाजाही बंद करने के साथ तमाम पाबंदियां लगा दी थीं। इसी शहर से पूरे चीन समेत दुनियाभर में वायरस फैला है।

डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के करीब बिडेन

मशिगन सहित तीन राज्यों के प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन। रायटर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में पूर्व उप राष्ट्रपति जो बिडेन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के और करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने मंगलवार को मिशिगन समेत तीन राज्यों के प्राइमरी चुनाव में जीत दर्ज की।

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति उम्मीदवारी की होड़ में बिडेन को बर्नी सैंडर्स से चुनौती मिल रही थी। लेकिन तीन मार्च को 14 राज्यों के प्राइमरी चुनावों में बिडेन ने सैंडर्स पर बढ़त बनाई थी। मंगलवार को मिशिगन, मिसिसिपी और मिसौरी में हुए प्राइमरी चुनावों में जीत के बाद बिडेन का समर्थन करने वाले डेलीगेट्स की संख्या बढ़कर 788 हो गई। जबकि 78 वर्षीय सैंडर्स को अब तक 633 डेलीगेट्स का समर्थन मिला है। डेमोक्रेटिक पार्टी में कुल 3,979 डेलीगेट्स हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पाने के लिए 1991 डेलीगेट्स का समर्थन पाना जरूरी है। अमेरिका में इस साल तीन नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है।

दुष्कर्म के दोषी हार्वे विंस्टीन को 23 साल कैद की सजा

न्यूयॉर्क, रायटर : जघन्य दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के दो मामलों में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने हॉलीवुड के प्रख्यात फिल्मकार रहे हार्वे विंस्टीन को 23 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उसे दो सप्ताह पहले दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया था। अमेरिका में जब कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के निर्माता रहे विंस्टीन का मामला खुला तो कई देशों की 100 से ज्यादा अभिनेत्रियों और महिलाओं ने सामने आकर अपनी आपबीती दुनिया को बताई। विंस्टीन ने पहले तो आरोपों से इन्कार किया लेकिन बाद में कहा कि उसने सहमति से यौन संबंध बनाए। इसी के बाद दुनिया में मी टू...अभियान शुरू हुआ जिसमें कई देशों में नामी लोगों द्वारा किए गए यौन शोषण की कहानी सामने आई।

जिन दो मामलों में विंस्टीन को सजा सुनाई गई है उनमें से एक में फिल्म निर्माता ने अपनी प्रोडक्शन असिस्टेंट मिमी हैली का यौन उत्पीड़न किया। अन्य मामले में विंस्टीन ने हीरोइन बनने का प्रयास कर रही जेसिका मान के साथ जघन्य दुष्कर्म किया। इन मामलों में उसे अधिकतम 29 साल के कारावास की सजा हो सकती थी। सजा के एलान के समय जज जेम्स बर्क ने बचाव पक्ष की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि विंस्टीन के स्वास्थ्य की दशा बहुत खराब है, इसलिए उसे पांच साल की ही सजा दी जाए। सजा के एलान के समय वे सभी छह महिलाएं कोर्ट में मौजूद थीं जिन्होंने विंस्टीन के खिलाफ गवाही दी थी।

हार्वे विंस्टीन। फाइल

इससे पहले विंस्टीन को हथकड़ी डालकर और व्हील चेयर पर बैठाकर कोर्ट में पेश किया गया। बीते हफ्ते वह जेल में गिरकर बेहोश हो गया था, तब उसके शरीर में स्टेंट डालकर उसके हृदय में रक्त का संचालन सुचारु किया गया था। आरोपों और मुकदमे की सुनवाई के दौरान विंस्टीन का कारोबार बंद हो गया, उसके बिजनेस पार्टनरों ने उससे नाता तोड़ लिया और पत्नी ने तलाक दे दिया।

अलगाववादी के बेटे जुनैद ने आतंकवाद पर बेपर्दा किया पाकिस्तान का चेहरा

- यूरोपीय थिंक टैंक ने यूएनएचआरसी में पेश की रिपोर्ट
- कहा-पाकिस्तान में दशकों पुरानी व्यवस्था जस की तस कायम है

जिनेवा, एएनआइ : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में यूरोपीय थिंक टैंक ने बुधवार को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का चेहरा बेपर्दा कर दिया। यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी ने परिषद में पेश अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से मानवाधिकारों के हनन के बारे में बताया है। जुनैद जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी और 1971 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरणकर्ता हाशिम कुरैशी के बेटे हैं।

जुनैद ने रिपोर्ट के जरिये कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की सख्ती के चलते हाल के महीनों में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों की मदद के अपने तरीके में बदलाव किया है। लेकिन जमीनी हालात ज्यादा नहीं बदले हैं। पाकिस्तान में दशकों पुरानी व्यवस्था जस की तस कायम है। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान का एहसानुल्ला एहसन और अंतरराष्ट्रीय आतंकी मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना सुरक्षित स्थानों पर छिपकर रह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते लश्कर ए तैयबा सरगना हाफिज सईद जेल में डाला गया है लेकिन वह ज्यादा समय के लिए वहां नहीं है। जैसे ही दबाव कम होगा-वह जेल से बाहर होगा। देश की असली तस्वीर फिर से सामने होगी। जम्मू-कश्मीर में फिर से सीमापार आतंकवाद का कहर बरपने लगेगा। इसलिए एफएटीएफ और अंतरराष्ट्रीय बिरादरी ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे पाकिस्तान के ऊपर हमेशा कड़ी नजर रहे और वह आतंकियों को पालने-पोसने और उनके इस्तेमाल की नीति को अंजाम न दे पाए।

जुनैद कुरैशी। फाइल

नसीहत देना बंद करे हर मामले में विफल पाकिस्तान

पाकिस्तान हर मामले में विफल राष्ट्र है। वह जम्मू-कश्मीर मामले में भारत को नसीहत देना और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने गलत तस्वीर पेश करना बंद करे। यह तल्ख टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्रालय की निदेशक रचिता भंडारी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रचार पर कही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दुनिया भलीभांति जानती है और आतंकवाद के समर्थन के उसके ट्रैक रिकॉर्ड को भी जानती है। इसलिए वह खुद में सुधार करे।

पाक में एफ-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमान एफ-16 बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रायटर

इस्लामाबाद, रायटर : पाकिस्तान की वायुसेना का एक एफ-16 लड़ाकू विमान बुधवार को राजधानी इस्लामाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई। यह दुर्घटना 23 मार्च को होने वाले पाकिस्तान दिवस की परेड के लिए हो रहे अभ्यास के दौरान हुई। पाकिस्तान वायुसेना ने इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में हुए इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। वायुसेना के प्रवक्ता ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में सिर्फ एक पायलट मौजूद था। सामने आए घटना के वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका निर्मित एफ-16 विमान अचानक आसमान से सीधे परेड मैदान में जा गिरता है।

हर साल 23 मार्च को मनाए जाने वाले पाकिस्तान दिवस के मौके पर पाक वायुसेना अपने कौशल का प्रदर्शन करती है। इसी के तहत यह लड़ाकू विमान भी अभ्यास में जुटा था।

दुबई, कनाडा भेजने के नाम पर 21 लाख की ठगी

विनय कोछड़, बटाला (गुरदासपुर)

जिला गुरदासपुर में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी मारने का धंधा एजेंटों द्वारा जोरशोर से चलाया जा रहा है। खासकर इन ठगों के शिकार ज्यादातर गरीब मजदूर और किसान बन रहे हैं। ऐसे ही तीन मामले जिला गुरदासपुर, तहसील बटाला में सामने आए हैं। एक महिला सहित छह फर्जी एजेंटों ने पांच युवाओं को दुबई और कनाडा भेजने के नाम पर लगभग 21 लाख रुपये की ठगी मारी है। आरोपित एजेंट जिला गुरदासपुर, अमृतसर व तरनतारन के रहने वाले हैं।

जिला तरनतारन के गांव मुरादपुर के एजेंट जसपाल सिंह और गांव फत्तोपीला, जिला अमृतसर के रहने वाले लाभ सिंह के खिलाफ हस्सनपुरा निवासी कोमलप्रीत सिंह और उसके भाई के बयान पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इन (आरोपितों) पर 10.70 लाख रुपये हड़पने के आरोप है। इसी तरह बटाला के मलाबे दी कोठी के रहने वाले दो भाइयों की शिकायत पर बटाला के रहने वाले एजेंटों के खिलाफ थाना सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। उक्त एजेंटों पर दुबई भेजने के नाम पर 90 हजार लेकर पैसे हड़पने का आरोप है।

इसी प्रकार श्री हरगोबिंदपुर पुलिस ने धारीवाल निवासी गुरनाम सिंह के बयान पर अमृतसर जिले के तरसीका निवासी नेहचल सिंह, सुखवंत सिंह और बलविंदर कौर के खिलाफ 9.40 लाख रुपये कनाडा भेजने के नाम पर ठगी के आरोप में केस दर्ज किया है। इन्होंने युवाओं को फर्जी वीजा थमा दिए। इस बात का राजफाश इमीग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान किया। फिलहाल संबंधित थाना इन सब केस के आरोपितों के खिलाफ मामला दर्जकर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

इस तरह युवाओं को अपने जाल में फंसाया : पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त एजेंटों ने घर में ऑफिस खोलकर युवाओं को विदेश भेजने के लिए एक ड्रामा रचा। उसके लिए विभिन्न अखबारों में विज्ञापन दिए गए। विज्ञापनों में विवरण किया गया कि दुबई और कनाडा की एक निजी कंपनी को नौकरी के लिए विभिन्न पदों पर रखने के लिए युवाओं की जरूरत है। कंपनी उन्हें प्रतिमाह अच्छी पगार भी देगी।

पैसों का लेनदेन बैंक से और नकदी में हुआ : शातिर दिमाग के एजेंटों ने पैसे नकद मांगे। मगर, कुछ ने इस तरह से पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने दो तरीके अपनाए। इनमें से कुछ से पीड़ितों को अपने ऑफिस बुलाकर नकद पैसे लिए, जबकि कुछ से देना बैंक की समाध रोड स्थित शाखा से खाते द्वारा पैसे लिए। बाद में सभी के हाथ फर्जी वीजा थमा दिया गया।

इन देशों में जुड़े हैं तार : पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित एजेंटों के दुबई, इंग्लैड, कनाड़ा, यूरोप के कुछ संदिग्ध लोगों के साथ तार जुड़े हैं। फिलहाल, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस इंटरपोल की भी मदद लेने जा रही है।

पुलिस टीमें गठित

मामले को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन किया है। थाना सिटी, थाना सिविल लाइन और श्री हरगोबिंपुर पुलिस ने अन्य राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है। क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद आरोपित एजेंट अपने ठिकाने से फरार हो गए हैं। पुलिस की छापेमारी जारी है।

ठगी के मामले बढ़ना गंभीर मामला है। इसके लिए उनकी पुलिस टीमें विभिन्न पहलुओं पर कार्य कर रही हैं। इसके लिए एक अलग यूनिट बनाया गया। इसका कार्य एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करना है।

-उपिंदरजीत सिंह घुम्मण, एसएसपी।

आरटीआइ : महिला वकील का आइपीएस के साथ शादी का दावा खारिज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- महिला के आरोप लगाने के बाद डॉ. अजयपाल शर्मा ने आरटीआइ के माध्यम से मांगी थी जानकारी
- गाजियाबाद एआइजी स्टांप कार्यालय ने जवाब में कहा, ऐसा कोई विवाह विभाग में पंजीकृत नहीं

साल 2016 का रिकॉर्ड खंगालने के बाद डॉ. अजयपाल शर्मा द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का जवाब भेजा गया है। विवाह के संबंध में कोई जानकारी विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं पाई गई है।

केके मिश्र, एआइजी स्टांप

मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है। महिला बार-बार बयान बदलकर शादी का दावा करती है। मैंने इस संबंध में आरटीआइ के तहत सूचना मांगी थी।

डॉ. अजयपाल शर्मा

महिला वकील का आइपीएस अधिकारी डॉ. अजय पाल शर्मा के साथ विवाह पंजीकृत करने का दावा एआइजी स्टांप कार्यालय से खारिज हो गया है। महिला द्वारा शादी करने का दावा करने के बाद डॉ. अजयपाल शर्मा ने आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी थी। बुधवार को आरटीआइ के जवाब में बताया गया कि 2016 के रिकॉर्ड में महिला का कोई पंजीयन नहीं है।

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित आस्था अपार्टमेंट में रहने वाली वकील दीप्ति शर्मा ने हाल में राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में आइपीएस डॉ. अजयपाल शर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। दावा किया था कि वर्ष 2016 में आइपीएस ने उन्होंने शादी की थी। उस समय वह एसपी सिटी गाजियाबाद के पद पर तैनात थे। दावा किया था कि उनकी शादी गाजियाबाद में पंजीकृत है। डॉ. अजय पाल के अन्य महिलाओं से संबंध होने के चलते उनके रिश्तों में दरार आ गई। इसके बाद अजयपाल ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया। दीप्ति ने महिला आयोग, पुलिस विभाग, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने शादी के कथित सुबूत भी दिए थे। आरोप है कि 18 सितंबर 2019 को रामपुर जनपद के सिविल लाइन थाने के बृजेश राना व कुछ अन्य लोग उनके घर आए और लैपटॉप, डीवीआर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जबरन उठा ले गए। दीप्ति के शादी करने के दावे के मामले में डॉ. अजयपाल शर्मा ने वकील के माध्यम से गाजियाबाद स्थित एआइजी स्टांप कार्यालय से विवाह पंजीयन की सूचना मांगी थी।

ये भी जानिए
विराट को वनडे में 12000 रन पूरे करने के लिए 133 रन की जरूरत है। उन्होंने 239 पारियां खेली हैं। इस आंकड़े को सबसे कम पारियों में छूने का रिकॉर्ड सचिन (300 पारी) के नाम है।

पांड्या और जडेजा पर भरोसा कायम रखे प्रबंधन

के श्रीकांत

कलम से

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के नतीजे के बाद एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि टीम में छठे नंबर पर एक बेहतरीन ऑलराउंडर की कितनी अहमियत होती है। हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया में वापसी अच्छी खबर है। इससे टीम का हर विभाग में मजबूती मिलेगी। उम्मीद है कि हार्दिक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का अधिक से अधिक फायदा उठा सकेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज और आइपीएल से हमें पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम क्या रहने वाली है। रोहित शर्मा को छोड़ दें तो चयनकर्ता यही सर्वश्रेष्ठ टीम चुन सकते थे। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत एक या दो खिलाड़ियों के कभी भी इधर-उधर होने की गुंजाइश रहती है। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को छठे और रवींद्र जडेजा को सातवें नंबर पर पक्का कर देना चाहिए। इसके बाद चार विशेषज्ञ गेंदबाज होने से तो कप्तान छह फुल टाइम गेंदबाजी विकल्प के साथ मैच में जा सकेंगे। कुछ एक मौकों पर बल्लेबाजी विभाग से छेड़छाड़ विपक्षी टीम को चौंकाने के लिए ठीक रहती है, लेकिन वनडे क्रिकेट का इतिहास बताता है कि एक व्यवस्थित शीर्ष क्रम अधिक सफल रहता है। एक बार जब पांड्या और जडेजा को उनकी भूमिका बता दी जाएगी तो ये टीम जीत की पटरी पर लौट जाएगी। वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने में असफल रही है। हालांकि इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन पांड्या और जडेजा की मौजूदगी से टीम को जरूरी संतुलन मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि टीम प्रबंधन पांड्या और जडेजा पर भरोसा बरकरार रखे। केएल राहुल, श्रेयस अय्यर की मौजूदगी में शीर्ष क्रम व्यवस्थित लग रहा है। मनीष पांडे भी बैकअप के तौर पर उपलब्ध हैं। चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार भी टीम को अतिरिक्त विकल्प मुहैया कराते हैं। भुवी भले ही तेज न हों, लेकिन गेंद को स्विंग कराने की काबिलियत और डेथ ओवरों में अपनी मर्जी से यॉर्कर फेंकने की क्षमता उन्हें औरों से अलग करती है। उन्हें टीम में शामिल करने से गेंदबाजी आक्रमण को विविधता मिलेगी। वहीं जहां तक दक्षिण अफ्रीकी टीम की बात है तो उन्होंने सीमित ओवर प्रारूप में भारत में हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं खुद भी बहुत उत्साहित हूं और ये देखने को बेताब भी कि पांड्या इस स्तर पर किस तरह की वापसी करते हैं।

आज के मैच में ACC KAMAAL KA MOMENT कौन जीतेगा? ACC OFFICIAL PARTNER

पांच हार के बाद एक अदद जीत की तलाश

दक्षिण अफ्रीका के साथ | पहला वनडे मैच आज | कोरोना के खतरे व बारिश की संभावना के बीच खेला जाएगा मैच

मुनीष गारिया ● धर्मशाला

कोरोना वायरस के खतरे और बारिश की संभावना के बीच विराट कोहली की अगुआई वाली टीम इंडिया जब गुरुवार को यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में उतरेगी तो उसका इरादा जीत की राह पर वापसी करने का होगा। भारतीय टीम का हाल में खत्म हुआ न्यूजीलैंड दौरा बेहद निराशाजनक रहा था। पांच टी-20 मैचों की सीरीज जीतने के बाद उसे लगातार तीन वनडे और दो टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा। लगातार पांच हार के बाद टीम इंडिया एक अदद जीत की तलाश में है। वहीं, दक्षिण अफ्रीकी टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और उसने हाल में घरेलू वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का 3-0 से सफाया किया है।

इस सीरीज में जीत हासिल करने के लिए भारतीय टीम ने अपनी गेंदबाजी को आधार बनाया है। इसी के दम पर टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम करना चाहती है। हालांकि टीम मुख्य रूप से टी-20 विश्व कप पर फोकस कर रही है और इसके लिए लंबे समय से प्रयोग जारी हैं। यह बात तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भी स्पष्ट की है। वहीं, क्विंटन डिकॉक की टीम अपने मध्यक्रम पर ध्यान दे रही है।

कोहली, राहुल व पांड्या ने नहीं किया अभ्यास: भारतीय टीम ने बुधवार को सुबह के सत्र में अभ्यास किया। इस दौरान विराट कोहली, केएल राहुल व हार्दिक पांड्या शामिल नहीं हुए। नेट प्रैक्टिस के दौरान शिखर धवन, श्रेयस अय्यर व पृथ्वी शॉ ने करीब आधा घंटा अभ्यास किया। पृथ्वी शॉ ने मिश्रित गेंदबाजी पर खेलते हुए भुवनेश्वर, जसप्रीत बुमराह व एचपीसीए (हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ) के खिलाड़ियों की गेंदबाजी का सामना किया। वहीं, गेंदबाजी में कुलदीप व जडेजा ने नेट बदल-बदलकर अभ्यास किया।

बाउंसर से पार पाने पर धवन व अय्यर का ध्यान: ओपनर शिखर धवन व मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बाउंसर से पार पाने पर ध्यान दिया। दोनों ने अधिकतर समय बाउंसर गेंदें खेलने का अभ्यास किया। शिखर धवन की चोट से ठीक होने के बाद वापसी हुई है और रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में वह शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल के साथ ओपनिंग करने उतर सकते हैं, जबकि पृथ्वी शॉ को इंतजार करना पड़ सकता है। राहुल विकेटकीपर की भी भूमिका में नजर आ सकते हैं। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली, नंबर चार पर श्रेयस अय्यर व नंबर पांच पर मनीष पांडे को जिम्मेदारी मिल सकती है। तेज गेंदबाजी की बागडोर टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के अलावा जसप्रीत बुमराह और युवा सैनी संभाल सकते हैं। इस तिकड़ी को हार्दिक पांड्या का साथ मिलेगा।

दक्षिण अफ्रीका का मध्यक्रम पर जोर: दूसरे सत्र में अभ्यास करने पहुंची दक्षिण अफ्रीकी टीम ने मध्यक्रम पर फोकस किया। वार्मअप के बाद डेविड मिलर, तेंबा बाबुमा व हेनरिक क्लासेन ने लंबे समय तक बल्लेबाजी की। इसके बाद बारिश के चलते टीम को अभ्यास के लिए इनडोर का रुख करना पड़ा।

हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को कैचिंग का अभ्यास करते भारतीय टीम के खिलाड़ी ● एएफपी

बीसीसीआई की सलाह

- पानी व साबुन से कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ धोएं।
- सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें।
- छींकने के दौरान मुंह को ढकें।
- बुखार, खांसी या कोई अन्य बीमारी होने पर तुरंत मेडिकल टीम से संपर्क करें।
- अच्छी तरह से हाथ धोने से पहले चेहरे, मुंह, नाक और आंखों को छूने से बचें।
- बाहर के व्यक्ति के नजदीक जाने या उससे बातें करने से बचें। अंजान व्यक्ति के साथ हाथ मिलाने और सेल्फी लेने से बचें।

गेंद को चमकाने के लिए लार का सीमित इस्तेमाल करेंगे : भुवनेश्वर

धर्मशाला: भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने संकेत दिए हैं कि घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुरुवार को यहां होने वाले पहले वनडे मैच में वे सफेद गेंद को चमकाने के लिए लार का सीमित इस्तेमाल कर सकते हैं। भुवनेश्वर ने कहा कि इस पर फैसला बुधवार को बैठक के दौरान टीम डॉक्टर करेंगे। स्पोर्ट्स हर्निया से उबरने के बाद टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर ने कहा, 'हमने इस बारे (लार का इस्तेमाल नहीं करने पर) में सोचा, लेकिन मैं अभी यह नहीं कह सकता कि हम लार का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम लार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर गेंद को चमकाएंगे कैसे। ऐसा नहीं करने पर हमारे खिलाफ रन बनेंगे और फिर आप लोग बोलोगे कि हम अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन, यह वैध मुद्दा है और देखते हैं कि टीम बैठक में क्या होता है और हमें जो भी निर्देश मिलेंगे या जो भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, हम वह करेंगे।' उन्होंने आइपीएल पर कोरोना के असर को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया।

भारत: विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र सिंह चहल, जसप्रीत बुमराह, सैनी, कुलदीप, शुभमन गिल।

दक्षिण अफ्रीका: डिकॉक (कप्तान), तेंबा बावुमा, रेसे वेन डेर डुसेन, डुप्लेसिस, वेरिएने, क्लासेन, मिलर, जॉन-जॉन स्मट्स, फेलुक्वायो, नगिदी, सिपामला, हेंड्रिक्स, एनरिक नॉर्जे, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज।

चोट के बाद फाफ डुप्लेसिस की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को डुप्लेसिस के अनुभव का फायदा मिलेगा। डेविड मिलर, डुप्लेसिस बड़े खिलाड़ी हैं तथा उन्हें बड़े मैच खेलने का अनुभव भी है। टीम में उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। मैच के दौरान हमारी टीम द्वारा निश्चित तौर पर गेंद की चमक के लिए लार का प्रयोग किया जाएगा।
क्विंटन डिकॉक, कप्तान, दक्षिण अफ्रीका

बारिश का खतरा

धर्मशाला: वनडे सीरीज के पहले मैच पर बारिश के खलल का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ग्राउंड स्टाफ का दावा है कि उन्होंने मैदान को सूखा रखने के लिए पूरे प्रबंध किए हैं। अगर दोपहर 12 बजे तक बारिश रुक जाए तो भी मैच संभव है। इसके बाद मैच होना मुश्किल है।

बारिश के कारण ढका मैदान ● एएनआइ

2015 में दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को उसके घर में वनडे सीरीज में 3-2 से शिकस्त दी थी। इस बार भारतीय टीम उसका बदला लेने के इरादे से उतरेगी

84 वनडे अब तक दोनों टीमों के बीच हुए हैं जिसमें 35 भारत तो 46 दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं। तीन टाई रहे हैं

डिकॉक को पसंद आता है भारतीय गेंदबाजी आक्रमण

सुनील गावस्कर

कलम से

दक्षिण अफ्रीकी टीम नए कप्तान क्विंटन डि कॉक के नेतृत्व में तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए वापस भारत आ चुकी है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ होगा मगर डिकॉक पहले दो मैचों में रन नहीं बना सके और मिशेल स्टार्क ने उन्हें आउट कर दिया। जैसे ही स्टार्क तीसरे वनडे से पहले अपनी पत्नी एलिसा हिली का ऑस्ट्रेलियाई महिला टी-20 विश्व कप का फाइनल मैच देखने गए, उनका बल्ला रन बनाने लगा। शायद यहां भी उन पर दबाव नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है कि वह अपने पसंदीदा गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ खेल रहे हैं। ऐसे आक्रमण के खिलाफ जहां उन्होंने मजाक-मजाक में शतक बनाए हैं।

फाफ डु प्लेसिस ने भी टीम में वापसी की है और उम्मीद है कि ब्रेक के बाद वह तरोताजा होंगे और भारत को उनकी वही बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अब उन पर कप्तानी का भी दबाव नहीं है, ऐसे में हमें कुछ महीने पहले आए डु प्लेसिस से अलग खिलाड़ी देखने को मिलेगा। कुछ नए खिलाड़ी भी टीम में शामिल हुए हैं और जानेमन (मुझे यह नाम बहुत पसंद आया) मलान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बनाया। इसके अलावा क्लासेन भी टीम में हैं, जो कुछ समय पहले भी भारत आए थे, लेकिन बहुत ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। रबादा के बिना गेंदबाजी थोड़ी कमजोर दिख रही है, लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं खेलने वाले लुंगी नगिदी ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की थी। यहां भी उनके खेल पर नजर रहेगी।

रोहित शर्मा टीम में नहीं हैं और यह बड़ा झटका है लेकिन शिखर धवन टीम में वापस आ चुके हैं और राहुल जिस ढंग की फॉर्म में हैं, उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। न्यूजीलैंड में रन नहीं बनाने वाले कप्तान कोहली यहां उसकी भरपाई करना चाहेंगे, ऐसे में प्रोटियास के लिए चीजें आसान नहीं होंगी क्योंकि श्रेयस अय्यर भी यह दिखा चुके हैं कि चौथे नंबर का बल्लेबाज स्थान उन्हें चाहिए। यह देखना काफी रोचक होगा कि हार्दिक पांड्या कैसे वापसी करते हैं। वह सितंबर से मैदान से बाहर हैं। यह सीरीज उनके लिए काफी अहम होगी। उन्हें दिखाना होगा कि वह पूरी तरह से फिट हैं। यह अच्छी बात है कि यह सीरीज भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के जैसी ही है।

Protinex
बेहतरीन स्वाद

मुक्केबाजी में हासिल किए रिकॉर्ड कोटे

विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मनीष के साथ कुल नौ भारतीय मुक्केबाजों ने हासिल किए ओलंपिक कोटे

एशियन क्वालीफायर्स

अम्मान, प्रेट्र: विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज मनीष कौशिक (63 किग्रा) ने यहां एशियन क्वालीफायर्स में ऑस्ट्रेलिया के हैरिसन गारसिडे को हराकर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। कौशिक टोक्यो ओलंपिक में जगह पक्की करने वाले नौवें भारतीय मुक्केबाज हैं। भारत का मुक्केबाजी में ओलंपिक के इतिहास में अब तक के यह सबसे ज्यादा कोटे हैं। भारत ने इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में आठ कोटे हासिल किए थे।

कौशिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त गारसिडे को 4-1 से हराकर पहली बार ओलंपिक में जगह बनाई। भारतीय मुक्केबाज ने शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया और ऑस्ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी पर करारे प्रहार किए जिससे उनका खून भी निकल आया। यह 2018 के कॉमनवेल्थ फाइनल की पुनरावृत्ति थी। अंतर इतना था कि इस बार कौशिक विजेता बने। वर्तमान टूर्नामेंट से 63 किग्रा में शीर्ष छह मुक्केबाज ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर सकते थे। कौशिक और गारसिडे दोनों क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। इसके बाद उन्हें बॉक्स ऑफ बाउट मुकाबले में खेलने का मौका मिला। कौशिक ने बॉक्स ऑफ बाउट मुकाबले में जीत दर्ज करके ओलंपिक कोटा पा लिया। वहीं, अन्य भारतीय मुक्केबाज सचिन 81 किग्रा के बॉक्स ऑफ फाइनल मुकाबले में ताजिकिस्तान के शाबोस नेगमातुएलोव से 0-5 से हार गए।

इससे पहले ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन विकास कृष्णन (69 किग्रा) बुधवार को आंख में चोट के कारण क्वालीफायर के फाइनल से बाहर हो गए जिससे उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। विश्व और एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता विकास को खिताबी मुकाबले में जेयाद ईशाश से भिड़ना था। विकास ने मंगलवार को सेमीफाइनल में विश्व चैंपियनशिप के दो बार के कांस्य पदक विजेता कजाखिस्तान के दूसरे वरीय अबलइखान जुसुपोव को हराया था।

प्रदर्शन मायने रखता है : मेरी कॉम

नई दिल्ली: स्टार मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ने दूसरी बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने के बाद अपने आलोचकों और प्रतिस्पर्धियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खेलों में राजनीति को लेकर आते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि आपका प्रदर्शन विरासत तैयार करता है, बड़े बयान नहीं। मेरी कॉम ने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को साबित कर दिया है। यह काफी मायने रखता है और मैं राहत महसूस कर रही हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि इससे उन लोगों की मानसिकता बदलेगी जो मेरे खिलाफ हैं, जो लोग चीजों में हेरफेर का प्रयास करते हैं और खेल में राजनीति को लेकर आते हैं। रिंग के बाहर बात करने से आप सिर्फ सुर्खियां बना सकते हो।' मेरी कॉम चयन विवाद के संदर्भ में बोल रही थीं जब पूर्व विश्व जूनियर चैंपियन निखत जरीन ने इस मुक्केबाज के खिलाफ ट्रायल की मांग की थी।

74 भारतीय खिलाड़ी कर चुके हैं क्वालीफाई, नौ मुक्केबाजों व भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल ने बढ़ाई संख्या

भारत ने अब तक हासिल किए 41 ओलंपिक कोटे

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

भारत ने 24 जुलाई से नौ अगस्त तक होने वाले टोक्यो ओलंपिक के कोटे में इजाफा करते हुए इसकी संख्या 41 तक पहुंचा दी है। इसके साथ ही 74 भारतीय खिलाड़ियों ने खेलों के महाकुंभ के लिए अपनी सीट पक्की कर ली है। फरवरी तक भारत ने 31 कोटे हासिल किए थे, लेकिन नौ भारतीय मुक्केबाजों और भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह ने अपने-अपने वर्गों में ओलंपिक कोटा हासिल करके इस संख्या को बढ़ा दिया। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम और कुछ टीम गेम में क्वालीफाई करने के कारण 74 खिलाड़ी तो कम से कम ओलंपिक में जाएंगे ही। इसमें 42 पुरुष और 32 महिला खिलाड़ी हैं। ओलंपिक-2016 में 117 भारतीय खिलाड़ी रियो गए थे जिन्होंने 15 अलग-अलग खेलों में हिस्सा लिया था। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत को तीरंदाजी (04), एथलेटिक्स (06), कुश्ती (04), घुड़सवारी (01), हॉकी (02), मुक्केबाजी (09) और निशानेबाजी (15) में कोटे मिले हैं। जिन खिलाड़ियों ने कोटे दिलाए हैं, उनके जाने पर फैसला महासंघों को करना है। घुड़सवारी में फवाद मिर्जा ने कोटा दिलाया, जबकि हॉकी में पुरुष और महिला टीमें यह हासिल कर चुकी हैं।

शिवपाल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया

पोचेफस्ट्रूम (दक्षिण अफ्रीका): भारत के भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह ने यहां एक प्रतियोगिता के दौरान टोक्यो ओलंपिक का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करके अपने पहले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया। स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बाद 24 साल के शिवपाल टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले भारत के दूसरे भाला फेंक खिलाड़ी हैं। शिवपाल ने मंगलवार को मैकआर्थर स्टेडियम में एसीएनडब्ल्यू प्रतियोगिता के दौरान अपने पांचवें प्रयास में 85.47 मीटर के स्तर के साथ स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक के लिए जगह बनाई। ओलंपिक का क्वालीफाइंग स्तर 85 मीटर है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ट्वीट किया, 'शिवपाल सिंह ने दक्षिण अफ्रीका में पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में 85.47 मीटर के प्रयास के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।' एक अन्य भारतीय अक्षदीप सिंह 75 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे। स्पर्धा में चार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चोपड़ा ने यहां जनवरी में एसीएनडब्ल्यू लीग में ही 87.86 मीटर के प्रयास के साथ टोक्यो ओलंपिक में जगह बनाई थी। चोपड़ा और शिवपाल दोनों यहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। शिवपाल का निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 86.23 मीटर है जो उन्होंने पिछले साल दोहा में एशियाई चैंपियशिप में रजत पदक जीतने के दौरान बनाया था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनु रानी ने भी महिला भाला फेंक में साल की अपनी पहली स्पर्धा में 61.15 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता।

एथलेटिक्स: पुरुषों की 20 किमी पैदल चाल में इरफान थोडी, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपलचेज में अविनाश साबले, पुरुषों के भाला फेंक में नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह, महिलाओं की 20 किमी पैदलचाल में भावना जाट, चार गुणा 400 मीटर रिले टीम में मुहम्मद अनस, वीके विस्मया, जिस्ना मैथ्यू और निर्मल नोह की चौकड़ी ने कोटा दिलाया।

निशानेबाजी: पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश सिंह पंवार और दीपक कुमार, पुरुषों की 50 मीटर राइफल-थ्री पोजीशन में संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा, पुरुषों के स्कीट में अंगद वीर सिंह बाजवा और मैराज अहमद खान ने कोटा दिलाया है। वहीं, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में अंजुम मौदगिल और अपूर्वी चंदेला, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर और यशस्विनी सिंह देसवाल, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में राही सरनोबत और चिंकी यादव, महिलाओं की 50 मीटर राइफल-थ्री पोजीशन में तेजस्विनी सावंत कोटा दिला चुकी हैं।

कुश्ती: पुरुषों में रवि कुमार (57 किग्रा), बजरंग पूनिया (65 किग्रा), दीपक पूनिया (86 किग्रा) ने देश को कोटा दिलाया है, जबकि विनेश फोगाट (53 किग्रा) ने महिलाओं में यह कोटा दिलाया।

मुक्केबाजी: मनीष कौशिक (63 किग्रा), विकास कृष्णन (69 किग्रा), एमसी मेरी कॉम (51 किग्रा), सिमरनजीत कौर (60 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा), पूजा रानी (75 किग्रा), अमित पंघाल (52 किग्रा), आशीष कुमार (75 किग्रा) और सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) कोटा हासिल किया है।

कोरोना वायरस | क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट को लेकर भारतीय बैडमिंटन संघ और बीडब्ल्यूएफ ने लिया फैसला

दर्शकों के बिना होगा इंडिया ओपन बैडमिंटन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन संघ (बाई) ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए दिल्ली में होने वाला इंडिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट दर्शकों की गैरमौजूदगी में खेला जाएगा। कोरोना के कारण इस टूर्नामेंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के क्वालीफिकेशन के लिए अहम टूर्नामेंट है।

बाई और विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी करके स्पष्ट किया कि यह टूर्नामेंट पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 24 से 29 मार्च तक राजधानी के केडी जाधव स्टेडियम में होगा। टूर्नामेंट के आयोजन के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। बाई के महासचिव अजय के. सिंघानिया ने कहा, 'इंडिया ओपन केडी जाधव हॉल में होगा, लेकिन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने इस बार किसी दर्शक को आने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में प्रशंसक यूट्यूब पर मैच देख सकते हैं।' इंडिया ओपन के ड्रॉ में एशियाई देशों के कई खिलाड़ी शामिल हैं जिसमें ही बिंगजाओ, शी यु की और लिन डैन जैसे चीन के खिलाड़ी भी हैं। इन्हें यूरोप में आगामी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर टूर्नामेंट में खेलने की स्वीकृति दी गई है। बीडब्ल्यूएफ ने दोहराया कि वह कोरोना को लेकर सभी आधिकारिक अपडेट लेता रहेगा।

चैंपियंस लीग में जुवेंटस-ल्योन के मैच से गायब रहेंगे प्रशंसक

ल्योन: कोरोना वायरस के चलते जुवेंटस और ल्योन का अगले सप्ताह होने वाला यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम-16 के दूसरे चरण का मुकाबला दर्शकों के बिना होगा। फ्रेंच क्लब के अध्यक्ष जीन-मिशेल एल्स ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूएफा से हमें पत्र मिला है कि यह मैच दर्शकों की गैरमौजूदगी में आयोजित होगा। दोनों टीमों के बीच मैच 18 मार्च को होगा और ल्योन ने पहले चरण का मैच 1-0 से जीता था। वहीं, पीएसजी और ल्योन के बीच चार अप्रैल को होने वाला फ्रेंच लीग कप का फाइनल को स्थगित करना पड़ा। दोनों ही टीमों ने दर्शकों के बिना मैच खेलने को लेकर अपनी असहमति जताई थी जिसके बाद मैच को स्थगित करने का फैसला किया गया।

साई दक्षिण केंद्र ने बाहरी लोगों पर लगाई रोक

नई दिल्ली: भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के दक्षिण केंद्र ने कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियात के तौर पर बाहरी लोगों के आने और उनके खेलने को लेकर रोक लगा दी है। इसके अलावा खिलाड़ियों को बाहर जाने और बाहर का खाना नहीं खाने के लिए भी कहा गया है। साई के एक सूत्र ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण चल रहा है इसलिए हमने ये फैसले लिए हैं।

ईपीएल में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच स्थगित

लंदन: मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच बुधवार को होना वाला इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) का मैच कोरोना वायरस के चलते स्थगित कर दिया गया। पहली बार ईपीएल का कोई मैच कोरोना के कारण स्थगित हुआ है।

बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण ले रहे हैं चीनी एथलीट: टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले चीनी एथलीट बंद दरवाजों के पीछे प्रशिक्षण ले रहे हैं और साथ ही दिन में तीन बार अपने तापमान की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा वे कोरोना वायरस के खिलाफ सख्त उपायों के तहत डाइनिंग टेबल भी साझा नहीं कर रहे जिसके कारण वे अकेले ही खाना खा रहे हैं। महिलाओं की शॉट पुट में दो बार की विश्व चैंपियन गोंग लिजियाओ ने कहा कि दोस्तों और परिवार से दूर रहने से उनकी तैयारियों को फायदा पहुंचा है और वह अधिक केंद्रित हुई हैं।

फॉर्मूला वन सहयोगी सदस्यों के लिए टेस्ट आयोजित: ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्रि के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि तीन फॉर्मूला वन टीम के सहयोगी सदस्यों को अलग कर दिया गया है जबकि कोरोना वायरस को लेकर टेस्ट आयोजित किया गए हैं। दो सहयोगी सदस्यों में कोरोना को लेकर कुछ लक्षण दिखाई दिए गए और इसलिए उन्होंने खुद को यहां से अलग कर लिया लेकिन उनके टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। इस वायरस के कारण चाइनीज ग्रांप्रि को रद करना पड़ा था।

पिच विवाद के बीच बंगाल की कोशिशें जारी

राजकोट, प्रेट्र: पिच विवाद और सीमित डीआरएस के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच बंगाल क्रिकेट टीम रणजी फाइनल में सौराष्ट्र के पहली पारी में बनाए गए 425 रनों के स्कोर से 291 रन पीछे है।

फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बंगाल ने तीन विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। बंगाल के ओपनर सुदीप कुमार घरमी (26) और कप्तान अभिमन्यू ईश्वरन (09) अपनी टीम को सधी शुरुआत देने में असफल रहे। हालांकि इसके बाद सुदीप चटर्जी (नाबाद 47) और मनोज तिवारी (35) ने टीम को राहत देने की कोशिश की लेकिन जानी ने तिवारी को आउट करके मेहमानों को एक और झटका दिया। भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा चार रन बनाकर नाबाद हैं।

क्यूरेटर ने पिच को बताया सही: बंगाल के कोच अरुण लाल ने फाइनल मुकाबले के पहले ही दिन सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम की पिच को बहुत खराब करार दिया था जिसके बाद यहां के क्यूरेटर महेंद्र राजदेव ने कहा कि अरुण ने कुछ ज्यादा ही जल्दी बयान दे दिया। बंगाल के गेंदबाजों की उम्मीदों के मुताबिक पिच पर ज्यादा उछाल नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पिच खराब है। अरुण का बयान गलत है।

कोरोना को लेकर आइपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

संकट
- आइपीएल को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में दायर हुई यात्रिका
- महाराष्ट्र सरकार ने टिकट की बिक्री पर लगाई रोक

आइपीएल की गवर्निंग काउंसिल शनिवार को मुंबई में कोरोना वायरस को लेकर बैठक करेगी। काउंसिल ने यह फैसला उस समय लिया जब महाराष्ट्र सरकार ने आइपीएल के मैचों को बंद दरवाजों के पीछे कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की जिसमें सत्र का उद्घाटन व फाइनल मैच शामिल थे। इस बैठक की अगुआई बृजेश पटेल करेंगे। इस बैठक में बीसीसीआइ के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह भी शामिल हो सकते हैं। एक फ्रेंचाइजी के सदस्य ने बताया कि नहीं खेलने से बेहतर खाली स्टैंड में खेलना बेहतर है।

केंद्र की अपील: वहीं, मद्रास हाई कोर्ट में दायर याचिका में कोरोना वायरस को लेकर 29 मार्च से शुरू हो रहे आइपीएल के मैचों को आयोजित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की अपील की गई है। वकील जी एलेक्स बेंजीगर द्वारा दायर याचिका न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और कृष्णा रामास्वामी की डिवीजन बेंच के सामने 12 मार्च को सुनवाई के लिए आ सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा, 'विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट के मुताबिक, अब तक कोरोना को रोकने या इलाज के लिए कोई दवा नहीं है। कोरोना पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है और एक गंभीर महामारी का संकट पैदा कर रहा है। फुटबॉल मैच बंद दरवाजों के पीछे खेले जा रहे हैं और इटली की सरकार ने तीन अप्रैल तक फुटबॉल मैदान में किसी दर्शक को जाने की इजाजत नहीं दी है।'

असमंजस में कर्नाटक: महाराष्ट्र सरकार ने आइपीएल के टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी। रोड सेफ्टी विश्व टी-20 सीरीज मुंबई में चल रही है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और द. अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। इन मैचों में भी वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा रहता है। वहीं, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक सरकार असमंजस में है और उसने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। कर्नाटक के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा, 'मैंने केंद्र सरकार से पूछा है कि कर्नाटक में आइपीएल को लेकर हमे क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए।

महिला वनडे विश्व कप के फाइनल व सेमीफाइनल के लिए होगा रिजर्व दिन

वेलिंगटन, प्रेट्र: भारत के खिलाफ टी-20 महिला विश्व कप सेमीफाइनल में मैदान पर उतरे बिना ही इंग्लैंड के बाहर होने से सबक लेते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने न्यूजीलैंड में होने वाले 2021 वनडे विश्व कप के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व दिन का आवंटन किया है। आइसीसी ने न्यूजीलैंड में छह फरवरी से सात मार्च तक होने वाले टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया है, जिसमें 31 मैच खेले जाएंगे। तीनों नॉकआउट मैचों के अगले दिन रिजर्व दिन का प्रावधान रखा गया है।

पिछले हफ्ते भारत के खिलाफ महिला टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल बारिश की भेंट चढ़ने के बाद इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। भारत ने ग्रुप चरण में बेहतर रैंकिंग के कारण फाइनल में जगह बनाई थी। महिला टी-20 विश्व कप के लिए रिजर्व दिन नहीं रखने के कारण आइसीसी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। महिला वनडे विश्व कप छह स्थलों पर खेला जाएगा, जिसमें ऑकलैंड का ईडन पार्क, तौरंगा का बे ओवल, हैमिल्टन का सेडन पार्क, डुनेडिन का यूनिवर्सिटी ओवल, वेलिंगटन का बेसिन रिजर्व और क्राइस्टचर्च का हेगले ओवल शामिल हैं।

पीवी सिंधू ऑल इंग्लैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंचीं

लंदन : भारत की अनुभवी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंग्लैंड ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया जबकि किदांबी श्रीकांत को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सिंधू ने बुधवार को महिला सिंगल्स के अपने पहले दौर में अमेरिका की झांग बीवन को सीधे गेम में 21-14, 21-17 से मात दी।

मैं प्रशंसकों से माफी मांगती हूं कि हम टी-20 विश्व कप की विजेता ट्रॉफी नहीं जीत पाए।
– स्मृति मंधाना, भारतीय महिला बल्लेबाज

न्यूज गैलरी

बुखार के बाद पुजारा पीठ दर्द से परेशान

राजकोट : बीमारी से उबरने के बाद सौराष्ट्र के लिए बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल में महत्वपूर्ण पारी खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा अब पीठ दर्द से परेशान हैं और वह जरूरत पड़ने पर ही दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे। पुजारा की पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण तीसरे दिन क्षेत्ररक्षण के लिए नहीं उतरे। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के अध्यक्ष जयदेव शाह ने कहा कि वार्म अप के दौरान पुजारा की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। वह जरूरत पड़ने पर ही बल्लेबाजी करेंगे। पुजारा और अर्पित बासवदा ने दूसरे दिन पांच घंटे तक बल्लेबाजी करके सौराष्ट्र का स्कोर 425 तक पहुंचाने में मदद की थी। पहले दिन पुजारा बुखार के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। (प्रेट्र)

एमेच्योर हुनार मित्तल को पहले दौर में बढ़त

गुरुग्राम : 15 वर्षीय एमेज्योर हुनार मित्तल ने आखिरी क्षणों में दो बोगी की लेकिन इसके बावजूद वह महिला प्रो गोल्फ टूर के छठे चरण के पहले दिन सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाने वाली खिलाड़ी रही। हुनार ने चार बर्डी और चार बोगी की और उनका स्कोर इवन पार 72 रहा। वह वाणी कपूर और नेहा त्रिपाठी से एक शॉट आगे हैं। एक अन्य एमेज्योर अस्मिता सतीश और गौरिका बिश्नोई ने 74 का स्कोर बनाया और वे संयुक्त चौथे स्थान पर हैं। (प्रेट्र)

शतरंज खिलाड़ी हरिका को स्टीफानोवा ने हराया

लुसाने : भारतीय ग्रैंडमास्टर डी हरिका को फिडे महिला ग्रां प्रि शतरंज टूर्नामेंट के आठवें दौर में बुल्गारिया की एंटोनेटा स्टीफानोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद हरिका चार अंक के साथ सातवें स्थान पर खिसक गई हैं। मंगलवार देर रात तक चली बाजी में कम रैंकिंग वाली स्टीफानोवा (ईएलओ रेटिंग 2453) ने भारत की दूसरे नंबर की खिलाड़ी हरिका (ईएलओ रेटिंग 2518) को 95 चाल में हराया। इस जीत के साथ स्टीफानोवा के 3 .5 अंक हो गए हैं। सातवें दौर के बाद। एलेक्सांद्रा गोरयाचकिना के साथ शीर्ष पर चल रही एलिना को जू वेनजुन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एलिना अब 4 .5 अंक के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। (प्रेट्र)

हम शॉर्ट पिच गेंदों के खराब खिलाड़ी नहीं

क्रिकेट डायरी ▶ भारतीय बल्लेबाज रहाणे ने कहा, न्यूजीलैंड में असफलता का मुख्य कारण हवा का बहाव था

अजिंक्य ने यह भी कहा कि वह अपनी खराब फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं

बुधवार को मुंबई के एक कार्यक्रम में मौजूद भारतीय टेस्ट बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे। प्रेट्र

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान अंजिक्य रहाणे ने बुधवार को कहा कि भारतीय बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों के सामने खराब खिलाड़ी नहीं हैं और न्यूजीलैंड में उनकी असफलता का मुख्य कारण हवा का बहाव था। स्टार बल्लेबाज रहाणे ने कहा कि यह आलोचना बेमतलब है कि वे शॉर्ट पिच गेंदों को अच्छी तरह से नहीं खेल पाते हैं।

उन्होंने कहा, 'लोग इसके (शॉर्ट पिच गेंदों कें में बहुत बातें कर रहे हैं। अगर आप मेलबर्न की पारी देखो तो हमने दबदबा बनाया था। हमने सभी शॉर्ट पिच गेंदों को अच्छी तरह से खेला था। एक मैच से आप शॉर्ट पिच गेंदों के खराब खिलाड़ी नहीं बन जाते हो। उन्होंने (न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने) हवा के बहाव का बहुत अच्छा उपयोग किया क्योंकि न्यूजीलैंड में यह सबसे बड़ा कारक है। तिरछे रनअप के साथ एक कोण से गेंदबाजी करना और तेजी महत्वपूर्ण कारक था। हमें सकारात्मक बने रहना होगा और अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में है। अभी इसमें समय है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं। हमने पिछले तीन-चार वर्षों में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। अब टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस यात्रा में आप कुछ मैच जीतेंगे तो कुछ में हार मिलेगी।'

रहाणे ने इसके साथ ही कहा कि वह अपनी खराब फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मैं इसको लेकर बहुत नहीं सोच रहा हूं। टेस्ट चैंपियनशिप एक समय में एक मैच और एक सीरीज से जुड़ी है क्योंकि इसमें अंक जुड़े हुए हैं। एक या दो खराब मैच से आप बुरी टीम नहीं बन जाओगे। हमने न्यूजीलैंड सीरीज से काफी कुछ सीखा है। वे अच्छा खेले। एक टीम के तौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई के लिए यह अच्छी सीख रही।'

इरफान की तूफानी पारी से जीता इंडिया लीजेंड्स

मुंबई, आइएएनएस : ऑलराउंडर इरफान पठान (नाबाद 57) की तूफानी पारी के दम पर इंडिया लीजेंड्स ने मंगलवार को यहां डीवाई पाटिल स्टेडियम में श्रीलंका लीजेंड्स को पांच विकेट से हराकर अनअकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली।

इंडिया लीजेंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका लेजेंडस को 20 ओवर में आठ विकेट पर 138 रन पर रोक दिया और फिर 18.4 ओवर में पांच विकेट पर 139 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

इंडिया लीजेंड्स की शुरुआत खराब रही। पिछले मैच में शानदार अर्धशतक बनाने वाले वीरेंदर सहवाग (03) और कप्तान सचिन तेंदुलकर (00) सस्ते में आउट हुए। युवराज सिंह (01) भी कुछ खास नहीं कर सके। मुहम्मद कैफ (46) और संजय बांगर (18) ने चौथे विकेट के लिए 43 रन जोड़े। तभी बांगर 19 गेंदों पर दो चौके लगाकर 62 के टीम स्कोर पर रंगना हेराथ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। कुछ देर बाद ही कैफ भी 81 के टीम स्कोर पर पांचवें बल्लेबाज के रूप में आउट हो गए। कैफ ने 45 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का लगाया। उन्हें सचित्रा सेनानायके ने अंजता मेंडिस के हाथों कैच कराया। इंडिया लेजेंडस को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 55 रन बनाने थे और पठान के मनप्रीत गोनी (नाबाद 11) के साथ छठे विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी करके इंडिया लेजेंडस को पांच विकेट से शानदार जीत दिला दी। पठान ने 31 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए। श्रीलंका लेंजेंडस की ओर से चमिंडा वास ने दो और हेराथ तथा सेनानायके ने एक-एक विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज आज से

सिडनी, रायटर : ऑस्ट्रेलिया की टीम जब शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतरेगी तो वह अपने शीर्षक्रम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी और साथ ही पांच मैचों से चले आ रहे अपने हार के अभियान को भी समाप्त करना चाहेगी।

दक्षिण अफ्रीका ने इस महीने की शुरुआत में आरोन फिंच की टीम का सफाया करते हुए 3-0 से सीरीज जीती थी, जब उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 12 महीनों के दौरान क्रिकेट की अधिकता के कारण ऑस्ट्रेलिया का शीर्षक्रम थका हुआ नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड में उसका सामना आत्मविश्वास से भरी टीम से होगा, जिसने हाल में भारत का टेस्ट व वनडे सीरीज दोनों में सफाया किया था। सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने इस बात से सहमति जताई है कि चैपल-हेडली ट्रॉफी को हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

टोक्यो में हमारे पास पदक जीतने का सर्वश्रेष्ठ मौका : विवेक

बेंगलुरु, आइएएनएस : भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद ने कहा है कि टीम के पास आगामी टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का सबसे अच्छा मौका है। विवेक ने कहा, 'टीम का मानना है कि टोक्यो 2020 में हमारे पास ओलंपिक पदक जीतने का सर्वश्रेष्ठ मौका है।' भारत ने पिछली बार 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से भारत आठ बार ओलंपिक खेलों में भाग ले चुका है और एक बार भी पदक नहीं जीता है। भारतीय टीम पिछले रियो ओलंपिक में आठवें नंबर पर रही थी।

विवेक को हाल में हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार (श्रेष्ठ अंडर-21 पुरुष खिलाड़ी) के लिए चुना गया है और उन्हें 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि भी मिली है।

विवेक के अलावा लालरेमसियामी को हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार (श्रेष्ठ अंडर-21 महिला खिलाड़ी) प्रदान किया गया और उन्हें भी 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि दी गई। लालरेमसियामी ने कहा, 'करियर की शुरुआत में ही एक बड़ी राशि से सम्मानित किया जाना, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और इस पैसे से वास्तव में हमारे परिवार को वित्तीय संघर्षों से उबरने में मदद करेगा। इसके अलावा मेरे गृहनगर में भी अब कई लोग यह मानने लगे हैं कि हॉकी एक पेशेवर करियर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें वित्तीय लाभ भी है। हॉकी इंडिया का यह प्रयास खेल को शीर्ष स्तर पर ले जाएगा।'

विश्व कप 2022 क्वालीफायर्स के लिए मेसी अर्जेंटीनी टीम में

- बोलीविया और इक्वाडोर के साथ होने वाले मैचों के लिए टीम घोषित
- मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले एग्वेरो और डायबाला को भी किया शामिल

ब्यूनस आयर्स, आइएएनएस : बोलीविया और इक्वाडोर के साथ होने वाले फीफा विश्व कप 2022 क्वालीफायर मुकाबलों के लिए दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी को अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। 23 सदस्यीय टीम में 32 साल के मेसी के अलावा मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले सर्गियो एग्वेरो, जुवेंटस के फॉरवर्ड पाउलो डायबाला और इंटर मिलान के लाउटारो मार्टिनेज को भी जगह मिली है। अर्जेंटीनी टीम को इक्वाडोर के साथ ब्यूनस आयर्स में 26 मार्च और ला पाज में पांच दिनों बाद बोलीविया से दक्षिण अफ्रीका जोन क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के तहत भिड़ना है। मेसी अभी प्रतिबंधित हैं और इसी कारण वह इक्वाडोर के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे। मुख्य कोच लियोन स्कैलोनी ने कोरोना वायरस के बढ़ते दुष्प्रभाव के बावजूद इस टीम में पांच ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिनका संबंध इटली से है। इटली की सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर टूर्नामेंटों में दर्शकों के आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

बांग्लादेश ने जिंबाब्वे से टी-20 सीरीज जीती

- बांग्लादेशी टीम ने जिंबाब्वे को दूसरे टी-20 मैच में हराया
- लिटन ने 45 गेंदों पर खेली नाबाद 60 रनों की अर्धशतकीय पारी

ढाका, प्रेट्र : सलामी बल्लेबाज लिटन दास के शानदार अर्धशतक की मदद से बांग्लादेश ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में बुधवार को यहां जिंबाब्वे को नौ विकेट से करारी शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ली। लिटन ने 45 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए। उनका यह लगातार दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले उन्होंने वनडे सीरीज में दो शतक लगाए थे। जिंबाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 119 रन बनाए थे। बांग्लादेश ने लिटन की पारी की मदद से 15.5 ओवर में एक विकेट पर 120 रन बनाकर जीत दर्ज की। लिटन ने अपनी पारी में आठ चौके लगाए तथा मुहम्मद नईम (33) के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। सौम्य सरकार 20 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले जिंबाब्वे की पारी सलामी बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर के इर्द गिर्द घूमती रही जिन्होंने 48 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए थे। बांग्लादेश के लिए अल अमीन हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने दो-दो विकेट लिए।

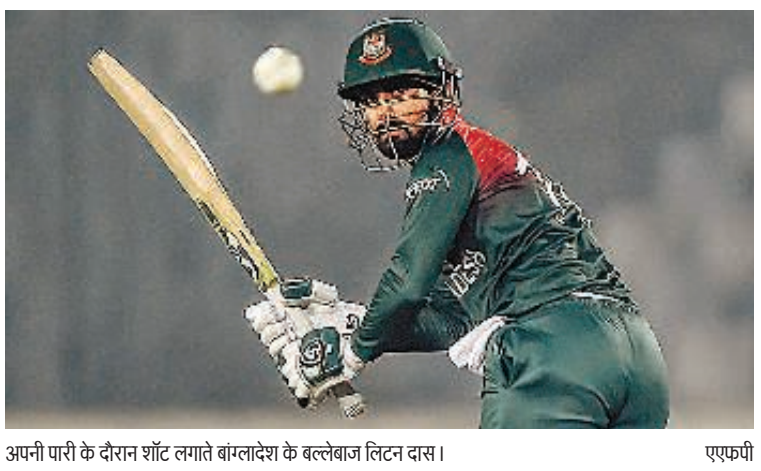

अपनी पारी के दौरान शॉट लगाते बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास। एएफपी

विविध

चार-पांच लोग तैयार करते थे फर्जी डिग्रियां

रमेश सिंगटा, शिमला

फर्जी डिग्रियां कहीं और नहीं मानव भारती विश्वविद्यालय में ही तैयार होती थीं। एसआइटी को इस बारे में पुख्ता सुबूत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार चार-पांच लोग सुल्तानपुर में ही विश्वविद्यालय में बैठकर एक कमरे में यह धंधा चलाते थे। जिस कंप्यूटर और मशीन पर यह कार्य होता था, वह एसआइटी के कब्जे में आ गई हैं। संस्थान का ही स्टाफ इसमें संलिप्त रहा है। इनके तार किस-किस से जुड़े थे, इसका भी जल्द राजफाश होगा। इन्होंने पुलिस विभाग में भी सेंध लगा रखी थी। यही कारण है कि इन्हें पुलिस कार्रवाई होने की सूचना कहीं से पहले ही मिल गई थी। धर्मपुर में एफआइआर दर्ज होने से चार दिन पहले ही कर्ताधर्ताओं को भनक लगी तो उन्होंने हिमाचल का जाली डिग्रियों का रिकॉर्ड राजस्थान के माधव विश्वविद्यालय पहुंचा दिया।

मंगलवार आधी रात को हिमाचल पुलिस ने राजस्थान के माउंटआबू में छापा मारा। कई घंटे तक स्थानीय पुलिस ने एसआइटी को सहयोग नहीं किया। कार्रवाई 10 बजे आरंभ होनी थी, वह एक बजे संभव हो सकी। जिले के संबंधित पुलिस प्रमुख ने भी रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद वहां के आइजी के हस्तक्षेप से एसआइटी उस जगह प्रवेश कर पाई जहां मानव भारती का रिकॉर्ड रखा हुआ था। इसे एक क्वार्टर के कमरे में रखा हुआ था। इसमें दो कंप्यूटर भी शामिल हैं।

पुलिस पर दबाव : हिमाचल पुलिस की एसआइटी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार संस्थान के कर्ताधर्ताओं ने इसमें सियासी रसूख का इस्तेमाल किया है। पुलिस से कहा गया है कि उसने केस दर्ज क्यों किया?

एसआइटी ने फर्जीवाड़े को लेकर कई संदिग्धों से पूछताछ की है। अभी पुलिस का फोकस और ज्यादा सुबूत जुटाने पर है। गिरफ्तारियां का सिलसिला बाद में शुरू होगा। आरोपितों में से ज्यादातर का ताल्लुक हरियाणा से है। फर्जी डिग्री तैयार करने में भी इन्हीं का हाथ है। ये संस्थान के चेयरमैन राजकुमार राणा के खास आदमी बताए जा रहे हैं।

महिलाओं की भूमिका संदिग्ध : फर्जीवाड़े में एक महिला की भूमिका भी संदिग्ध रही है। एसआइटी को सूचना मिली है कि इसी के माध्यम से डिग्रियों के बदले पैसे एकत्र किए जाते थे। दो अन्य महिलाएं भी संदेह के घेरे में हैं।

एसआइटी ने हरियाणा से की एक और गिरफ्तारी

जागरण संवाददाता, सोलन : मानव भारती विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए गठित एसआइटी ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने हरियाणा के करनाल क्षेत्र से प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया है, जो विश्वविद्यालय में कई अहम पदों पर कार्यरत रहा है। पुलिस की पकड़ में आने के बाद प्रमोद कुमार ने कई अहम राज खोले हैं जिसके आधार पर अब पुलिस मानव भारती विश्वविद्यालय के साथ ही राजस्थान स्थित माधव विश्वविद्यालय तक भी पहुंची है। इस मामले में पहले मनीष गोयल नाम के सहायक रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी की पुष्टि एएसपी सोलन डॉ. शिव कुमार ने की।

मानव भारती विश्वविद्यालय के चेयरमैन राजकुमार राणा कुछ दिन से संपर्क में नहीं हैं। एसआइटी की टीम ने अब तक मालिक की तलाश में कई ठिकानों में दबिश दी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। बुधवार को उनके वकील ने अतिरिक्त जिला सत्र न्यायलय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है। इस मामले में फैसले को सुरक्षित रखा गया है।

एसआइटी प्रमुख व एसपी सोलन अभिषेक यादव ने कहा कि प्रमोद कुमार को जांच में शामिल होने के लिए मानव भारती परिसर में प्रस्तुत किया गया था। सवाल जवाब में उसे धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रमोद को विश्वविद्यालय में बतौर डाटा ऑपरेटर भर्ती किया गया था, लेकिन उससे विवि में और भी कई कार्य करवाए जा रहे थे। फर्जी डिग्री मामले में पकड़े गए दोनों आरोपित अब पुलिस रिमांड पर हैं। अभिषेक यादव ने बताया कि एसआइटी की जांच राजस्थान स्थित माधव विश्वविद्यालय तक भी पहुंची है। यहां विश्वविद्यालय के कुछ संबंधित ब्लॉक सील किए गए हैं और मानव भारती विश्वविद्यालय का रिकार्ड उक्त विश्वविद्यालय से पुलिस ने बरामद किया है।

सीबीआइ ने खुलवाई जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक

जागरण संवाददाता, बागपत : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआइ की टीम ने जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक खुलवाकर घटनास्थल और गटर को देखा। हत्या के बाद इसी गटर से पिस्टल व कारतूस बरामद हुए थे। टीम ने स्टाफ से घटना के दौरान जेल में मौजूद बंदियों व कर्मचारियों की सूची भी हासिल की।

नौ जुलाई 2018 की सुबह बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन जेलर यूपी सिंह ने कुख्यात सुनील राठी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हत्या की साजिश में पांच लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने इन पांचों को क्लीनचिट देते हुए सुनील के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। इस कार्रवाई के खिलाफ सीमा की मांग पर हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। नौ मार्च को सीबीआइ की टीम ने जेल पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। मंगलवार को सीबीआइ दो बार जेल आई। बुधवार दोपहर टीम ने स्थानीय कोर्ट में केस से संबंधित कागजात लेने के लिए अर्जी डाली और शाम को फिर जेल में पहुंचकर उक्त बैरक से सुबूत एकत्रित किए।

गैरसैंण परिषद पर स्पीकर नाखुश, विधेयक टला

रविंद्र बड़थ्वाल, देहरादून

- गैरसैंण विकास परिषद अध्यक्ष पद का जिम्मा हटाने से असहमत हैं स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल
- उत्तराखंड कैबिनेट ने 22 फरवरी को विधेयक को दी थी मंजूरी, सदन में पेश नहीं हुआ विधेयक

गैरसैंण विकास परिषद अध्यक्ष पद की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। परिषद के दो सदस्यों में शामिल स्थानीय विधायक भी सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं। विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को व्यवस्था यथावत रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से यही अनुरोध किया है। इसके बाद भी सरकार विधेयक सदन में लाती है तो उस पर सदन निर्णय लेगा।
–प्रेमचंद अग्रवाल, अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड

गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन के उत्तराखंड सरकार के फैसले से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल नाखुश हैं। उनके रुख की वजह से फिलहाल गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन संबंधी विधेयक को सरकार विधानसभा में पेश नहीं कर पाई है। सरकार ने परिषद के अध्यक्ष पद का जिम्मा विधानसभा अध्यक्ष से छीनकर इसे आवास मंत्री के सुपुर्द किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।

राज्य मंत्रिमंडल की 22 फरवरी को हुई बैठक में गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन को हरी झंडी दी गई थी। दरअसल, सरकार का मानना है कि गैरसैंण विकास परिषद का दायरा, कार्यक्षेत्र और उससे संबंधित फैसले उसकी परिधि में है। मंत्रिमंडल ने यह जिम्मा आवास मंत्री को सुपुर्द किया। परिषद अध्यक्ष पद लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल इससे संबंधित संशोधित विधेयक को मंजूरी दे चुका है।

गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के सरकार के फैसले का पुरजोर समर्थन कर चुके विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल गैरसैंण विकास परिषद में संशोधन के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सरकार तीन से सात मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करना चाहती थी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की असहमति देखते हुए कदम पीछे खींचे गए हैं। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि गैरसैंण विकास परिषद का कार्य सरकार के दायरे में है। इस वजह से मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। इस पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर भी किया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार इस सत्र में उक्त विधेयक लाना चाहती थी। ऐसा नहीं हुआ। जल्द ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।

छिटपुट बारिश के बीच ठंड बरकरार

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जहां छिटपुट हुई बारिश ठंड का एहसास करा रही है वहीं पहाड़ों में भी बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है। मार्च माह में इस बार मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही बिगड़ा है। बारिश का जो सिलसिला इस महीने के साथ शुरू हुआ, वह रुक-रुक कर जारी है।

उप्र में बूंदाबादी : उप्र में मंगलवार को होली के दिन बौछारें पड़ीं। बुधवार को भी कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते बदली और बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। 14 मार्च तक बादलों की आवाजाही के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी। 15 मार्च से इस पर विराम के आसार हैं। बारिश के चलते तापमान भी कम रहेगा, जिससे फिलहाल ठंड बनी रहेगी।

दिल्ली में भी मौसम सर्द : पश्चिमी विक्षोभ के असर से हो रही बारिश और चल रही तेज हवा ने दिल्ली के मौसम को दोबारा सर्द बना दिया है। दिल्लीवासी न केवल फिर गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं बल्कि तापमान भी सामान्य से नीचे ही चल रहा है। सप्ताहांत तक ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

चारधाम में बर्फबारी : होली के बाद उत्तराखंड में भी मौसम ने फिर करवट बदली ली है। बादलों के डेरा डालने के साथ ही बारिश और बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिन भी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश और 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बादल घिर आए और हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। चारधाम समेत अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में शाम के समय बारिश के बाद हिमपात शुरू हो गया। जो देर शाम तक कई दौर में चलता रहा। इसके अलावा मैदानों में भी दिनभर धूप और बादलों के आने-जाने का सिलसिला लगा रहा।

जम्मू-कश्मीर में मौसम फिर बिगड़ा : जम्मू कश्मीर में पिछले दो दिन राहत देने के बाद मौसम के मिजाज फिर बिगड़ गए हैं। बुधवार को जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश हुई। जबकि लद्दाख में बादल छाये रहे। कहीं भी बर्फबारी नहीं हुई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दिनभर खुला रहा, लेकिन पहले जगह-जगह फंसे को निकाला गया। अभी भी दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हैं।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की थी जनहित याचिका

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुरक्षाबलों को बड़ी राहत देते हुए पैलेट गन पर रोक लगाने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर की डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि हिंसा, आगजनी और दंगे की आशंका तक भीड़ पर नियंत्रण के लिए बल प्रयोग जरूरी है। किस समय किस तरह का बल प्रयोग किया जाए, यह अधिकारी ही हालात का संज्ञान लेते हुए तय कर सकते हैं। अदालत तय नहीं कर सकती कि किस परिस्थिति और घटना विशेष के समय बल प्रयोग ज्यादा था या कम।

वर्ष 2016 में वादी में हुए हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस व अर्धसैनिकबलों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, जिससे कई लोग जख्मी हुए थे। कुछ लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई थी। इसके बाद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि मौजूदा हालात और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 26 जुलाई 2016 को पैलेट गन का विकल्प तलाशने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से पहले और सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला लिए जाने तक अदालत विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगा सकती।

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में घने बादल रहेंगे। अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा और बर्फबारी रुक-रुक कर होगी। पंजाब, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। ओलावृष्टि भी संभव है।

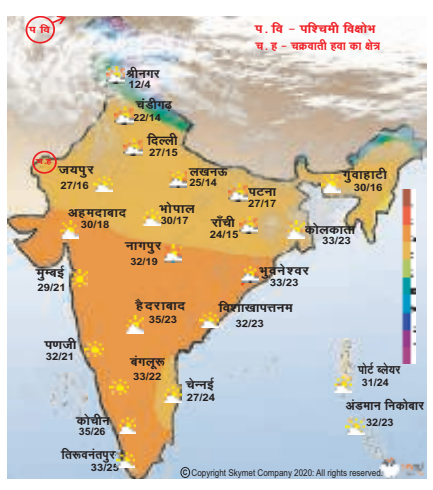

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

गुरुवार 12 मार्च 2020

आजकल

16

www.jagran.com

जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में फैली रेडियोधर्मिता

2011 में आज ही भारी भूकंप से उपजी सुनामी की वजह से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में धमाका हुआ। वहां के माहौल में रेडियोएक्टिविटी फैल गई। चेर्नोबिल के बाद यह दूसरा बड़ा ऐसा हादसा था। 860 एकड़ में बने इस संयंत्र को बंद करना पड़ा था।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए सीरियल बम धमाके

1993 में आज ही मुंबई की रफ्तार रोक देने वाले सीरियल बम धमाके हुए थे। 257 से ज्यादा लोग मारे गए और 700 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम और उसका शार्गिद टाइगर मेमन था।

सुरीली आवाज की मल्लिका हैं श्रेया घोषाल

अपनी सुरीली आवाज से कानों में मिसरी घोलने वाली बेमिसाल गायिका श्रेया घोषाल का जन्म 1984 में आज ही पश्चिम बंगाल में हुआ था। वह हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, मराठी, पंजाबी , गुजराती और असमी भाषाओं में गाने गा चुकी हैं। सा रे गा मा में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बनाई और अपना पहला गाना देवदास के लिए गाया। नेशनल और फिल्मफेयर अवार्ड विजेता श्रेया के नाम पर अमेरिका के ओहियो में 26 जून का दिन श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाया जाता है जहां उनके ही गीत सुने जाते हैं।

इधर-उधर की

शेर समझ कुत्ते के पीछे लगी स्पेन में पुलिस

मैड्रिड, एजेंसी : भागो, शेर आया..शेर आया। स्पेन के मोलिना डी सेगुरा इलाके में पुलिस के पास जब इस आशय की कई फोन कॉल आए तो उसके कान खड़े हो गए। लोगों ने आवासीय इलाके में शेर के घूमने की बात कही। मुस्तैद पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी कर दी। प्रयास रंग भी लाया और तथाकथित शेर पकड़ा गया। अब चौंकने की बारी पुलिस महकमे की थी। उन्होंने जिस जीव को पकड़ने के लिए इतना सारा जाल फैलाया था, दरअसल वह एक कुत्ता था। पकड़े जाने पर उसके शरीर पर लगी चिप से सारा विवरण मालूम हुआ। बड़े आकार के इस कुत्ते के बालों को इस तरह से काटा गया था, कि दूर से देखने पर वह हूबहू शेर दिखता था। सारी जानकारी हासिल करने के बाद कुत्ते को उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया गया। इस आशय की गई ट्वीट वायरल हुई है। 2500 बार रिट्वीट हो चुकी है।

शिशुओं के व्यवहार पर बुरा असर डालती है कच्ची नींद

अध्ययन ▶ बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा

कम सोने वाले बच्चे हो जाते हैं गुस्सैल

लंदन, प्रेट्र : अगर आपका बच्चा कम समय के लिए सोता है या फिर सोने में देरी करता है या फिर रात में बार-बार जागता है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इससे आगे चलकर उसे कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

दरअसल एक अध्ययन में यह सामने आया है कि ऐसे बच्चों में बचपन के बाद भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक दिखाई देती हैं। ब्रिटेन स्थित बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि शिशुओं में नींद की समस्याओं और 24 महीने की उम्र में भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं के बीच स्पष्ट संबंध है। बीएमजे पीडियाट्रिक्स ओपन नामक पत्रिका में प्रकाशित

प्रतीकात्मक।

अध्ययन में पहली बार दिखाया गया है कि बचपन में नींद की समस्या का किस तरह से भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं से जुड़ाव होता है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह निष्कर्ष प्रारंभिक अवस्था में शिशु की नींद की समस्या पर ध्यान रखने की जरूरत पर बल देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन के निष्कर्ष यह बताते हैं कि बच्चों की नींद की समस्या की अगर शुरुआती दौर में ही पहचान कर ली जाए तो भविष्य में उनके व्यवहार और भावनाओं को काबू किया जा सकेगा। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने नींद से संबंधित दो तरह की प्रश्नावली माता-पिता से भरवाईं। इसमें करीब 1700 माता-पिता को शामिल किया गया। उनसे 3, 8, 18 और 24 महीने की उम्र में बच्चों की नींद के बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद इन परिणामों की तुलना भावनात्मक और व्यवहार संबंधी लक्षणों पर अलग से तैयार प्रश्नावली के साथ की गई। उन्होंने पाया कि तीन महीने की उम्र में बार-बार रात में जागने वाले बच्चे ज्यादा भावुक दिखे और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा दिखा। कम सोने वाले बच्चे 24 माह की उम्र में गुस्सैल हो जाते हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि शिशु में नींद की समस्या कई कारणों से होती है जिनमें आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं। नींद का प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है।

ब्रेन फेल्योर के रोगियों के इलाज में मददगार होता है संगीत

वाशिंगटन, प्रेट्र : संगीत से कई रोगों का इलाज संभव है, यह बात तो वैज्ञानिक कई बार साबित कर चुके हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है उनके इलाज में भी संगीत कारगर साबित हो सकता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को धीमा संगीत सुनाया जाए तो उसे धीरे-धीरे दर्दनिवारक दवाओं की जरूरत कम होती जाती है। साथ ही उसकी बेहोशी की अवधि भी कम होती जाती है।

अमेरिका स्थित रिजेंस्ट्रीफ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कहा कि वेंटिलेटर पर रखे गए रोगियों में दर्द, चिंता और शारीरिक तनाव देखने को मिलता है। इसे दूर करने के लिए आमतौर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जिससे रोगी बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि संगीत इन रोगियों को शारीरिक इलाज कराने में सक्षम कर सकता है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि ध्वनि काफी कम रहे।

फोटो न्यूज

चमकीला चांद

न्यूयॉर्क के विलियम्सबर्ग वाटर फ्रंट के ऊपर सुपरमून की यह खूबसूरत तस्वीर अमेरिकी फोटोग्राफर एरिक पेंड्जिच ने होली की रात को अपने कैमरे में कैद की। 10 मार्च को मंगलवार की रात चांद अपने सामान्य आकार से बड़ा और बेहद चमकीला था। पूर्णिमा के चांद की तुलना में यह 14 गुना बड़ा और 28 फीसद ज्यादा चमकदार था। एएफपी

65 से 70 फीसद तक बचा सकेंगे पानी

प्रदीप शर्मा, करनाल

- डिजिटल वे ऑफ स्मार्ट फार्म तकनीक से होगा ऐसा संभव
- फसल उत्पादन में त्री 20 से 25 फीसद बढ़ोतरी का किया जा रहा दावा

गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान में किसानों को डिजिटल वे आफ स्मार्ट फार्म तकनीक की जानकारी देते डॉ. दुष्यंत बादल। जागरण

डिजिटल वे ऑफ स्मार्ट फार्म तकनीक से सामान्य तौर पर किसी भी फसल में उपयोग होने वाले पानी का 65 से 70 फीसद बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं इस तकनीक से फसल के उत्पादन में भी 20 से 25 फीसद वृद्धि की जा सकती है। यह दावा करनाल के गन्ना प्रजनन संस्थान में आयोजित कृषि मेले के दौरान हिसार की गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करने वाले छात्र प्रशांत बादल ने किया है। प्रशांत ने इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट शुगर केन रिसर्च लखनऊ के विज्ञानियों के साथ मिलकर काम किया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को खुद बनाया और गन्ने की फसल के लिए इनपुट संबंधित संस्थान के वैज्ञानिकों से लिए। इस तकनीक को डिजिटल वे ऑफ स्मार्ट फार्म नाम दिया गया है। मेले में बकायदा इसका मॉडल भी प्रस्तुत किया गया।

देखा जाए तो हरियाणा में गन्ने की फसल का रकबा 2 लाख 87 हजार 500 एकड़ का है। सामान्य रूप से एक एकड़ गन्ने की फसल सिंचाई करने पर 48 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इस तकनीक से महज 1.44 लाख लीटर पानी में काम चल सकता है। ऐसे में प्रति एकड़ 70 फीसद यानी 33.60 लाख लीटर पानी की बचत होगी। पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था अगर लागू हो तो 9.66 खरब लीटर पानी की बचत एक फसल पर हम कर सकते हैं।

छह तरह के लाभ देती है तकनीक : यह स्मार्ट तकनीक किसान को जमीन के छह तरह के लाभ प्रदान करती है। इसमें नमी, तापमान, आद्रता, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी व लाइट, इंटेनसिटी। इससे किसान को यह पता चला जाता है कि उसकी फसल किस वातावरण में फल-फूल रही है।

दावा- हर फसल के लिए कारगर : प्रशांत बादल व उनके गुरु डॉ. दुष्यंत बादल ने कहा कि गन्ने पर हमने शोध किया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, शाहजहां पुर, फरूर्खाबाद व लखीमपुर में शोध सफल रहा। करनाल के गन्ना प्रजनन संस्थान में भी इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया। जिस भी फसल में इस तकनीक का सभी में कारगर रहा।

जानिये कैसे काम करती है तकनीक : डॉ. दुष्यंत बादल के मुताबिक डिजिटल वे आफ स्मार्ट फार्म तकनीक में पांच मीटर बनाए गए हैं। एक मुख्य मीटर होता है, जो एक एकड़ जमीन के बिल्कुल मध्य में स्थापित किया जाता है। चार सब मीटर एकड़ के चारों कोनों में लगाए जाते हैं। मुख्य मीटर को खेत के ट्यूबवेल से कनेक्ट किया जाता है। चारों कोनों पर लगे मीटर जमीन की नमी लेकर मुख्य मीटर तक ट्रांसमीट करते हैं। फसल को नमी की जितनी जरूरत होती है, अगर उतनी हो गई है तो मुख्य मीटर सेंसर से ट्यूबवेल को बंद कर देगा। अगर नमी पूरी नही है तो ट्यूबवेल चलता रहेगा। इस विधि से लगभग 70 फीसद पानी की बचत होती है।

झीलों के गर्म होने का पूर्वानुमान लगाने की प्रणाली विकसित

लंदन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की झीलों के भविष्य के गर्म होने की बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए एक नई प्रणाली विकसित की है। इससे ठंडे पानी में रहने वाली मछली की प्रजातियों के लिए संभावित खतरे का पहले से ही अंदाजा लगाया जा सकेगा।

यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी (यूकेसीईएच) के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वर्ष 2100 तक झीलों के तापमान में औसतन चार डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा।

नेचर कम्यूनिकेशंस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि वैश्विक स्तर पर 66 फीसद झीलों को अब से ज्यादा गर्म तापीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा। शोधकर्ताओं ने यह प्रणाली पहली बार तैयार की है। इसमें विश्व के सभी झीलों को वर्गीकृत किया गया है और उन्हें नौ तापीय क्षेत्रों में बांटा गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि सतह के पानी के तापमान के आधार पर झीलों को समूहों में बांटा गया है।

सबसे ठंडे तापीय क्षेत्र में अलास्का, कनाडा, उत्तरी रूस और चीन की झीलों को

प्रतीकात्मक

शामिल किया गया है जबकि भूमध्यरेखीय दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया की झीलों को सबसे गर्म झीलों में रखा गया है।

यूकेसीईएच के प्रोफेसर स्टीफन माबेरली ने कहा, '16 सालों से महीने में दो बार सेटेलाइट के जरिये ली गई तस्वीरों के आधार पर अत्याधुनिक विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर हमने पहली बार वैश्विक झील तापमान वर्गीकरण योजना बनाई। माबेरली ने कहा कि इसके आधार पर हमने यह पहचान की है कि ब्रिटेन के उत्तरी इलाकों की झीलें जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

इंग्लैंड में आंत के कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ी

शोध अनुसंधान

ब्रिस्टल : हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि इंग्लैंड में 50 साल से कम उम्र के लोगों में आंत के कैंसर की जबर्दस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 40 वर्षों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएस) के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के एडम चैंबर्स के नेतृत्व में हुए शोध में यह पता चला है। शोध में बताया गया है कि पिछले 40 वर्षों में इस बीमारी की चपेट में करीब 55,000 लोग आए। यह शोध ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी में प्रकाशित हुआ है। एडम चैंबर्स ने कहा कि आंत का कैंसर सामान्य तौर पर 60 वर्ष की उम्र के बाद ही देखने को मिलता है। यही कारण है कि देश में वृद्ध लोगों में इसकी स्क्रीनिंग की जाती रही है। लेकिन इस शोध ने पाया कि अब यह 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी शिकार बना रहा है। इसलिए सरकार को इस आयु वर्ग के लोगों की भी स्क्रीनिंग की योजना बनानी चाहिए। -एएनआइ

बीमारियों से बचाता है नियमित अंतराल पर उपवास रखना

इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी एक-एक दिन के अंतराल पर उपवास रखना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। विशेषरूप से यह उपवास लिवर के लिए बहुत लाभदायक है। यह एक ऐसे प्रोटीन के स्राव को बढ़ाता है, जो लिवर के कई जीन की गतिविधियों को प्रभावित करने में सक्षम है। चूहों पर किए गए प्रयोग में वैज्ञानिकों ने लिवर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग का असर जांचा। शोधकर्ता डॉ. लारेंस ने कहा, 'हम जानते हैं कि समय-समय पर उपवास से बीमारियों के इलाज में और लिवर की सेहत सही रखने में मदद मिलती है। हालांकि हम यह नहीं जानते थे कि उपवास किस तरह लिवर के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रोटीन को प्रभावित करता है। हालिया शोध से हमें इस प्रक्रिया को समझने में मदद मिली है।' वैज्ञानिकों का कहना है कि हर एक दिन के अंतराल पर अनाज का सेवन नहीं करना लिवर में फैटी एसिड से जुड़े मेटाबॉलिज्म को बदलने की क्षमता रखता है। - एएनआइ

फिल्म रिव्यू

★★★

अंग्रेजी मीडियम

मुख्य कलाकार : इरफान, करीना कपूर खान, दीपक डोबरियाल, राधिका मदान, डिंपल कपाड़िया, किकू शारदा, पंकज त्रिपाठी, रणवीर शौरी
निर्देशक : होमी अदजानिया
अवधि : 2 घंटा 26 मिनट

मुद्दे में अटकती-भटकती फिल्म

वर्ष 2017 में आई 'हिंदी मीडियम' की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हुए 'अंग्रेजी मीडियम' को बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इरफान फिल्म 'कारवां' के दो वर्ष बाद पर्दे पर नजर आ रहे हैं। न्यूरोइंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से वह एक साल तक लंदन में अपना इलाज करा रहे थे। फिल्म की कहानी शुरू होती है उदयपुर से। चंपक बंसल (इरफान) अपनी बेटी तारिका (राधिका मदान) को पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले पालता है। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। चंपक की मिठाई की दुकान है। सामने उसके भाई गोपी बंसल (दीपक डोबरियाल) की भी मिठाई की दुकान है। दोनों के बीच पारिवारिक नाम घसीटेराम को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। तारिका बचपन से विदेश में पढ़ाई का सपना देखती है। उसे लंदन की ट्रूफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। उसके कॉलेज से उसे यह मौका मिलता है, लेकिन वह उसके पिता की वजह से हाथ से निकल जाता है। बेटी के लंदन में पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए एक पिता किस तरह का संघर्ष करता है, फिल्म इसी को लेकर आगे बढ़ती है।

'हिंदी मीडियम' फिल्म ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के बीच के अंतर और हर बच्चे को शिक्षा मिलने के अधिकारों की बात की थी। 'अंग्रेजी मीडियम' अंग्रेजी भाषा की नहीं, बल्कि विदेश की अंग्रेजी संस्कृति पर प्रकाश डालती है। हालांकि उसे दर्शाने के लिए काफी लंबा रास्ता लिया गया है। पहले हिस्से में ज्यादा वक्त चंपक और गोपी के बीच खानदानी नाम को लेकर हो रहे झगड़े में निकाल दिया गया है। विदेश में रह रहे भारतीयों का संघर्ष, 18 साल का होने के बाद वहां के युवाओं का माता-पिता को छोड़कर अकेले रहने की संस्कृति, भारतीय विद्यार्थियों का अपना खर्च वहन करने के लिए पार्टटाइम जॉब करने जैसे कई मुद्दों को उठाने के चक्कर में असल कहानी गुम होती नजर आई। वीजा रद होने के बाद दोबारा लंदन जाने के लिए जो रास्ता चंपक और गोपी अपनाते हैं, वह बचकाना लगता है।

इन सबके बीच पिता और बेटी के रिश्तों को खूबसूरती से दर्शाया गया है। बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पिता किस हद तक जा सकता है, उसका चित्रण करने की कोशिश की गई है। कोशिश इसलिए, क्योंकि बिखरे हुए स्क्रीनप्ले और बेवजह के दृश्यों की वजह से निर्देशक होमी अदजानिया उन पलों को समेट नहीं पाए हैं। बिंग सायरस, कॉकटेल जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके होमी के लिए हार्टलैंड की कहानी को उकेर पाना मुश्किल लगा। हालांकि लंदन में यह फिल्म रफ्तार पकड़ती है। इरफान हर बार की तरह वह अपने अभिनय में बेजोड़ नजर आए। पिता का संघर्ष उनके चेहरे पर नजर आता है। करीना जितनी बार पर्दे पर आती हैं, नजरें उन पर रुक जाती हैं। राधिका मदान की मेहनत पर्दे पर दिखी। वह वाकई 17 साल की लगती हैं। दीपक डोबरियाल अपने अंदाज में दिखे हैं। पंकज त्रिपाठी कैमियो किरदार में जंचे हैं। डिंपल कपाड़िया, रणवीर शौरी और किकू शारदा की प्रतिभा का सही इस्तेमाल निर्देशक नहीं कर पाए हैं। सचिन-जिगर का कूड़ी नू नचने दे.... गाना कर्णप्रिय है। -प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

होली के रंग में रंगा हिंदी सिनेमा

इस बार हिंदी सिनेमा भी होली के रंग में रंगा नजर आया। कुछ सितारों ने परिवार के साथ होली मनाई, तो कुछ ने फिल्मों के सेट पर। वहीं कुछ सितारों ने होली पार्टी में शामिल होकर जश्न मनाया। अमिताभ बच्चन ने पुराने दिनों की होली को याद करते हुए सोशल मीडिया पर आरके स्टूडियोज में मनाई जाने वाली होली की एक तस्वीर साझा की। इस पुरानी तस्वीर में वह राज कपूर और शम्मी कपूर के साथ होली मना रहे हैं। आरके स्टूडियोज की होली को उन्होंने बेहतरीन बताया। आमिर खान ने बेटे आजाद के साथ होली खेलते हुए पत्नी किरण राव की तस्वीर साझा करके होली की शुभकामनाएं दीं, जबकि शाह रुख खान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक सेल्फी साझा करके होली की शुभकामनाएं दीं। मंगलवार को होली के साथ प्रीती जिंटा ने पति जीन गुडइनफ का जन्मदिन भी मनाया। उन्होंने जीन के साथ होली की

तस्वीरें साझा करके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। प्रियंका चोपड़ा जोनास इन दिनों अपने पति निक जोनास के साथ होली के खूब मजे ले रही हैं। हाल ही में वह ईशा अंबानी की होली पार्टी में रंगों में भीगी नजर आई थीं। निक के साथ रंगों में भीगी एक तस्वीर साझा करते हुए प्रियंका ने इस होली को विशेष बताया। शिल्पा शेट्टी ने गुलाल से रंगे चेहरे के साथ सोशल मीडिया पर होली की बधाई देते हुए एक वीडियो साझा किया। करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों-समीरा और किआन के साथ होली खेलते हुए तस्वीरें साझा कीं।

लूडो से हुई शारवरी और सिद्धांत में बांडिंग

वेब शो 'द फॉरगॉटन आर्मी' से नवोदित शारवरी वाघ ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। अब यशराज बैनर की फिल्म 'बंटी और बबली 2' से अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें उनके अपोजिट सिद्धांत चतुर्वेदी हैं। यह फिल्म वर्ष 2005 में आई 'बंटी और बबली' की सीक्वल है। उसमें रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन प्रमुख भूमिका में थे। फिल्म में शारवरी बबली बनी हैं, जबकि सिद्धांत बंटी। असल जिंदगी में सिद्धांत और शारवरी दोनों का ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। दोनों की पसंद काफी मिलती है। इस वजह से दोनों की सेट पर बांडिंग अच्छी हो गई थी। इस बारे में

शारवरी का कहना है कि मैं और मेरी टीम खाली समय में लूडो खेलते थे। लूडो वाकई मजेदार खेल है। सेट पर जो लोग इस खेल को खेलना चाहते थे, हम उन्हें भी आमंत्रित करते थे। एक दिन सिद्धांत और उनकी टीम हमें खेल में टक्कर देने के लिए मैदान में उतरी। वहां से हमारी बांडिंग काफी अच्छी हो गई।

'द बर्निंग ट्रेन' और 'गजनी' की बनेगी रीमेक

पुरानी फिल्मों को रीमेक करने और हिट फिल्मों को नई कहानी के साथ सीक्वल में लाने का आजकल एक ट्रेंड हिंदी सिनेमा में देखा जा रहा है। बुधवार को भी एक फिल्म के रीमेक और एक फिल्म की सीक्वल बनाने की घोषणा की गई। इस क्रम में साल 1980 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' की रीमेक जैकी भगनानी और बीआर फिल्म्स के क्रिएटिव प्रोड्यूसर जूनो चोपड़ा मिलकर बनाने वाले हैं। वहीं, 'गजनी' के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर गजनी की सीक्वल बनाने की ओर इशारा किया है। फिल्म 'द बर्निंग ट्रेन' के सीक्वल को लेकर जैकी भगनानी का कहना है कि इस फिल्म को देखकर वह बड़े हुए हैं। यह बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म है और वह अपने दोस्त जूनो के साथ मिलकर इसे दोबारा बनाने की तैयारी में हैं। फिल्म के निर्देशक और मुख्य किरदारों को साइन करने की बात चल रही है। 'द बर्निंग ट्रेन' फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, परवीन बॉबी, जीतेंद्र और नीतू सिंह सहित कई दिग्गज मुख्य भूमिकाओं में थे। इसी तरह, साल 2008 में रिलीज हुई आमिर खान अभिनीत फिल्म 'गजनी' का सीक्वल बनाने की ओर फिल्म के मेकर्स ने इशारा किया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट ने अपने सोशल मीडिया पर 'गजनी' को लेकर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें आमिर खान को भी टैग किया गया है।

जब मीरा ने लिखा एसके...लोगों ने कहा शाह रुख या सलमान

सितारों के साथ अक्सर उनके परिवार वाले भी सोशल मीडिया पर यूजर्स के निशाने पर आ जाते हैं। बात करें अगर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की, तो वह भी सोशल मीडिया पर काफी छाई रहती हैं। सेलेब्स की होली की तस्वीरों में मीरा की तस्वीर ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया। लेकिन इन तस्वीरों पर सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली। दरअसल, मीरा ने होली के मौके पर एक तस्वीर साझा की थी। उन्होंने रंगीन शर्ट पहन रखी थी और अपनी गर्दन पर उन्होंने एसके लिखा था। उसके नीचे उन्होंने एक दिल भी बनाया था। एसके का मतलब जैसा कि सभी जानते हैं कि उनके पति शाहिद कपूर हैं। इस तस्वीर को साझा करते हुए मीरा ने शाहिद के लिए अपना प्यार जताते हुए लिखा,

'प्यार भरा जीवन टेक्नीकलर में।' मीरा के इस तस्वीर को पोस्ट करते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने एसके अक्षर पर अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। मीरा की इस तस्वीर पर चुटकी लेते हुए एसके का मतलब लोगों ने कभी शाह रुख खान तो कभी सलमान खान को बताया। एक यूजर ने तो यह भी लिख दिया कि एसके का मतलब शाहिद और करीना भी हो सकता है। साथ ही, मीरा के फैंस ने उन्हें होली की बधाई भी दी।

टल सकती है 'सूर्यवंशी' की रिलीज तारीख

कोरोना वायरस अंतरराष्ट्रीय सिनेमा इंडस्ट्री के साथ-साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर भी कहर ढा रहा है। पिछले दिनों कई फिल्मों की शूटिंग लोकेशंस में बदलाव किए गए हैं। कई इवेंट्स रद कर दिए गए। सितारों ने विदेश जाने की योजना में बदलाव किए हैं। इसी के चलते बीते दिनों दीपिका पादुकोण ने अपनी पेरिस यात्रा को रद कर दिया था। अब इस महीने रिलीज होने वाली दो बड़ी फिल्में 'सूर्यवंशी' और '83' की रिलीज तारीख में बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल, कोरोना के चलते 11 मार्च को फिल्म '83' का मुंबई में आयोजित होने वाला ट्रेलर लॉन्च रद कर दिया गया। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की अगली तारीख की अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। कोरोना के हालातों को देखते हुए 'सूर्यवंशी'

और '83' की रिलीज तारीख बदलने पर विचार किया जा सकता है। अक्षय कुमार अभिनीत 'सूर्यवंशी' 24 मार्च को रिलीज होनी है। निर्माताओं का कहना है कि फिलहाल रिलीज की तारीख में बदलाव का कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। कोरोना के चलते अगर हालात बेहतर नहीं हुए, तो फिल्म की रिलीज तारीख आगे बढ़ सकती है। हालांकि कोरोना वायरस के डर के बावजूद पिछले सप्ताह रिलीज टाइगर श्रॉफ अभिनीत फिल्म 'बागी 3' पांच दिनों में 76.94 करोड़ कमाने में कामयाब रही है।